सम्पादकीय

बंगाल में दिए ओबीसी कोटे में मुस्लिमों के आरक्षण को रद्द करने के फैसले का विरोध गैर संवैधानिक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी भारत गणराज्य के किसी राज्य की सीएम है वे देश के कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने तो मुस्लिम तुष्टिकरण की हद कर दी। चुनावी फायदे के लिए गैर संवैधानिक रूप से बंगाल में ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगाई। क्योंकि 22 मई को कोलकाता हाईकोर्ट ने 41 मुस्लिम जातियों को ओबीसी से जोड़कर उन्हें नौकरियों में आरक्षण देने के ममता सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। साथ ही साल 2010 के बाद जारी किए करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिए हैं। इस फैसले के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वह इस फैसले को नहीं मानती और मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण जारी रहेगा। ममता को फैसले पर आपत्ति है, तो उन्हें हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए सार्वजनिक रूप से फैसला नहीं मानने की घोषणा न करे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानने की बात कहने वाली ममता बैनर्जी पर हाईकोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार तो देश में न्याय व्यवस्था का कोई भी मखौल उड़ा देगा। ममता कि यह टिप्पणी भी आपत्तिजनक है कि वह कोर्ट के फैसले को इसलिए स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि ये भाजपा के पक्ष में है। लोकसभा चुनाव के दो चरणों से पहले ये फैसला आना भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से फायदे का सौदा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आया, तो वह ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगा। जैसा पहले ही पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चल रहा है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से उनके आरोप को और ताकत मिली है। अब वह और जोश के साथ पिछड़ों का आरक्षण मुसलमान को नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा का नारा बुलंद कर रहे हैं। शायद इसीलिए इसमें ममता को भाजपा का रोल नजर आ रहा है। उन्होंने एक रैली में कहा कि भाजपा के कुछ लोग ओबीसी हितों पर प्रहार करने के अदालत गए और याचिकाएं की और यह मामला सामने आया। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी फैसले में यह भी कहा है कि ओबीसी में मुसलमानों का आरक्षण चुनाव में फायदे के लिए किया गया है और आरक्षण जाति नहीं बल्कि धर्म के आधार पर दिया गया है। मुसलमानों को आरक्षण देना पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति है और इस समुदाय का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए वस्तु की तरह किया गया है। ये पूरे समुदाय और लोकतंत्र का अपमान है। इसमें कोई शक नहीं की कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल हमेशा वोट बैंक की तरह किया है। खुद कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता समय-समय पर ये पीड़ा जाहिर करते रहे हैं। जबकि भाजपा ने मुसलमानों के नाम पर हिंदू वोटों के धुर्वीकरण की राजनीति की है। जब तक केंद्र में और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, मुसलमान उसके समर्थक थे और उसे ही वोट देते थे। भाजपा ने कभी भी मुस्लिम वोटों की परवाह नहीं की। वह तो मुस्लिम उम्मीदवारों को भी भूले-भटके ही चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन जब से राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत होने लगे हैं, मुस्लिम वोट बैंक जहां कांग्रेस कमजोर है गई, तो उससे छिटककर उनके साथ चला गया।

रोजगार के योग्य बने रहने के लिए छात्रों को अपने विषय की परवाह किए बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना चाहिए

हेरियट-वाट यूनिवर्सिटी के वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी का कहना है कि कंप्यूटर साइंस और एआई जैसे विषय आज के छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। अध्ययन के अन्य दो लोकप्रिय क्षेत्र डेटा विज्ञान और डेटा एनालिटिक्स हैं। हमारे पास इस पर मास्टर स्तर और स्नातक स्तर के कार्यक्र म हैं। इसके अलावा डिजाइन आधारित विषयों को भी महत्व मिल रहा है। हेरियट-वाट सटैम डिज़ाइन और व्यावसायिक कार्यक्र मों में विशेषज्ञ हैं। डिज़ाइन और फैशन के केंद्र दुबई में डिज़ाइन प्रबंधन, संचार डिज़ाइन जैसे विषय तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं,'' एवरेस्ट कहते हैं। इसके अलावा, मार्केटिंग के साथ साइकोलॉजी, फिनटेक के साथ सस्टेनेबल फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, डेटा साइंस के साथ एक्चुरियल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी के साथ कंप्यूटर साइंस में एमएससी और बिजनेस एंड ऑर्गनाइजेशन साइकोलॉजी जैसे विषय छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं।

विजय गर्ग

रोजगार योग्य बने रहने के लिए छात्रों को अपने विषय की परवाह किए बिना एआई के बारे में सीखना चाहिए एआई और रोबोटिक्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों ने नौकरी के खतरों को बढ़ा दिया है और शैक्षणिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम को फिर से डिजाइन करने के लिए मजबूर किया है। दुबई में उच्च शिक्षा संस्थान उभरती प्रौद्योगिकियों के आधार पर उद्योग की मांगों के अनुसार पाठ्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। भारत और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों के हजारों छात्रों के लिए एक शिक्षा केंद्र, दुबई में विश्वविद्यालय छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए लगभग सभी धाराओं में एआई को एकीकृत कर रहे हैं। हेरियट-वाट यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यूके में स्थित एक सार्वजनिक शोध विश्वविद्यालय, 2005 में दुबई परिसर खोलने वाला पहला ब्रिटिश विश्वविद्यालय था, जिसका लक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना और नवाचार को बढ़ावा देना था। इसकी निकटता के कारण यह भारत से अधिकतम संख्या में छात्रों को समायोजित करता है। प्रोफेसर हीदर ने हाल ही में भारतीय संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग बनाने के लिए दिल्ली और मुंबई का दौरा किया, जिससे दोनों देशों के छात्रों को लाभ होगा। प्रोफ़ेसर कहते हैं, एआई एक उपकरण है जो हमें चीजों को बेहतर तरीके से करने में मदद करता है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र जीवन के सभी पहलुओं में एआई की क्षमता का पता लगाएं। हमारे कुछ छात्रों को एआई को कोड करने और सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, और हमारे कई शोधकर्ता सुचारू संचालन के लिए एआई के नए स्तर भी विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एआई अब आपके लिए अकाउंटिंग कर सकता है, लेकिन, हमें अभी भी अपने अकाउंटेंसी छात्रों को फ्री कैश फ्लो लिखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि अगर वे कंप्यूटर में गलत धारणाएं डालते हैं, तो एआई पूरी तरह से बकवास नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगा। और नकदी प्रवाह लागत अग्रेषित करें। इसलिए, बिजनेस छात्र को यह जानना होगा कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी के साथ अकाउंटेंसी को कैसे एकीकृत किया जाए। इससे उन्हें सही अनुमान लगाने के लिए एआई का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद मिलेगी और एआई का उपयोग करके बहुत अच्छा काम मिलेगा। इससे उन्हें समय बचाने में मदद मिलेगी, वह आगे कहती हैं। दुबई में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और यूके सहित 53 राष्ट्रीयताओं के संकाय हैं। हालाँकि, संकाय का सबसे बड़ा समूह स्कॉटलैंड से आता है, जो छात्रों को परिसर में विविधता का स्वाद देता है जो अंततः उन्हें पेशेवर रूप से बढ़ने में मदद करेगा।

प्रौद्योगिकी विषय लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं एवरेस्ट का कहना है, प्रौद्योगिकी उद्योग को बड़े पैमाने पर बाधित कर रही है, जिससे नौकरी बाजार में बदलाव आ रहा है। इंजीनियरिंग स्नातकों के अलावा, प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल के छात्रों को अपने दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सीखना होगाप्रौद्योगिकी ने शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया है। एआई ने आज कौशल सेट को बदल दिया है। इसलिए, छात्रों को यह समझने के लिए अनुकूलन क्षमता के उस स्तर से लैस होना होगा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाए, चाहे वह इंजीनियरिंग में हो या डिजाइन में या व्यवसाय में, वह आगे कहती हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या कौशल-आधारित विषय पारंपरिक विषयों की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त कर रहे हैं, एवरेस्ट कहते हैं, कौशल-आधारित शिक्षा के अलावा, उद्योग सेटिंग में पाठ्यक्रमों के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, गणित में एक मजबूत नींव अभी भी व्यवसाय या इंजीनियरिंग जैसे कई विषयों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। छात्रों को प्रौद्योगिकी या मुख्य विषयों की मूल बातें पता होनी चाहिए, लेकिन उन्हें व्यावहारिक और व्यावहारिक ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। प्रौद्योगिकी अब सीखने की गुणवत्ता को बढ़ा रही है। विश्वविद्यालयों में अब सीखने का हर एक पहलू प्रौद्योगिकी-सक्षम है। यह आभासी सीखने के माहौल के अत्याधुनिक होने के बारे में है और यह भी है कि छात्र परियोजनाओं पर टीमों में अपने समय में कैसे सीखते हैं। आज, पुस्तकालय किताबों के बारे में नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के बारे में है, यह इस बारे में है कि हम छात्रों की व्यस्तता को कैसे ट्रैक करते हैं और समझते हैं, उदाहरण के लिए, विभिन्न डेटा बिंदुओं के उपयोग के माध्यम से वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं यह समझने के लिए कि वे कहां संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर रही है, वह आगे कहती हैं। प्रोफ़ेसर कहते हैं, यह कौशल अंतर नहीं है, हम जो देख रहे हैं वह श्रम प्रणाली में बदलाव है। तो औद्योगिक क्रांति की तरह, जहां हमने शारीरिक श्रम का उपयोग करना बंद कर दिया और भाप बनाने वाले लोगों के बजाय संज्ञानात्मक श्रम का उपयोग करना शुरू कर दिया, आपके पास ऐसे इंजन थे जो भाप बना सकते थे, लेकिन किसी को इंजन को डिजाइन करना था और जानना था कि यह कैसे काम करता है। इसी तरह, अब हम जो देख रहे हैं वह संज्ञानात्मक श्रम से भावनात्मक श्रम की ओर एक कदम है। अब, संज्ञानात्मक श्रम कुछ ऐसा है जो एआई द्वारा किया जाएगा। तो, ऐआई हमारे लिए सोच सकता है, लेकिन आपको अभी भी इसकी व्याख्या करनी होगी। भावनात्मक श्रम व्याख्या के रूप में, अनुकूलन में, यह जानने में आता है कि उसके साथ क्या करना संभव है। इसलिए, संज्ञानात्मक श्रम उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित लोगों को अब भावनात्मक श्रम उत्पन्न करना होगा। प्रमुख भारतीय कंपनियों के साथ हमारी हालिया बैठकों में, हमें अच्छे संचार कौशल, नेतृत्व कौशल और टीम के खिलाड़ियों वाले प्रबंधकों की आवश्यकता का एहसास हुआ। इसलिए, छात्रों को अपने संचार और प्रस्तुति कौशल पर काम करना चाहिए। भविष्य के पेशेवरों के पास विभिन्न संस्कृतियों और बहु-पीढ़ी के कार्यक्षेत्रों में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। दुबई में हमारे परिसर को विविध और अंतरसांस्कृतिक बनाने के लिए इसमें 126 देशों के छात्र हैं, वह आगे कहती हैं। ऐसी दुनिया में जहां छात्र निबंध लिखने के लिए एआई प्राप्त कर सकते हैं, हमें उन्हें एक मजबूत प्रस्तुति देने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए सीएचटीजीपीटी नहीं मिल पाता; यह उनका और उनके ज्ञान का आकलन करने का एक अच्छा तरीका होगा। पहली चीज जो हम छात्रों को सिखाते हैं वह यह है कि खुद को कैसे अभिव्यक्त करना है, कैसे परिभाषित करना है कि वे अपने काम के माध्यम से दुनिया पर किस तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं, अपना सीवी और लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे लिखें, प्रोफेसर हीदर कहते हैं। भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग हमने यूजीसी के साथ भारत में एक कैंपस खोलने की संभावनाओं पर चर्चा की। फिलहाल, हम सही बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक भागीदार की तलाश कर रहे हैं।

हमारा लक्ष्य भारतीय संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, संयुक्त कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग के अवसर तलाशना है। वर्तमान में, चिकित्सा प्रौद्योगिकी सहित विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों पर सहयोग के छोटे क्षेत्र हैं। घिसावहम साझेदारी पर काम कर रहे हैं ताकि भारतीय संस्थान के छात्र भी हेरियट-वाट में प्रगति कर सकें और पूर्ण मान्यता प्राप्त कर सकें, विश्वविद्यालय भू-ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए झरझरा सामग्री में प्रवाह प्रक्रियाओं के डिजिटल विश्लेषण पर अनुसंधान सहयोग के लिए आईआईटी भुवनेश्वर के साथ साझेदारी कर रहा है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक सहयोग है, वेल्लोर एक शोध सहयोग पर एक साथ आया है।

आज का इतिहास

26 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- नार्वे में चर्च में 1822 में आग लग जाने के कारण 122 लोगों की मौत हो गई थी।
- ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को 1950 में खत्म कर दिया गया। इससे पहले हर व्यक्ति को
- पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था।
- जापान में 1983 में आए भूकंप में 104 लोगों की मौत हो गई थी।
- जापान ने 1998 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 50,016 ब्रिटिश सिपाहियों को बंदी बनाया था जिनमें से
- 12,433 की या तो मौत हो गई या उन्हें कैद में मार दिया गया।
- दक्षिण लेबनान से इसराइली सुरक्षा बलों के हटने पर लाखों हिज़्बुल्लाह समर्थकों ने 2000 में अपने नेता शेख़ हसन नसरल्लाह के साथ विजय रैली निकाली।
- चीन का विमान 2002 में समुद्र में गिरा, 225 लोग मरे।
- विज्ञान जगत् में 2006 में एक शोध के मुताबिक एड्स का विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चिपैंजिओं से फैला है।
- भारत और जर्मनी के बीच 2007 में रक्षा समझौता सम्पन्न हुआ।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज व खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के सम्बन्ध में अधिसूचना 2008 में जारी की।

26 मई को जन्मे व्यक्ति

- प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक छगनराज चौपासनी वाला का जन्म 1912 में हुआ।
- 'भारतीय जनता पार्टी' (भाजपा) के नेता सरताज सिंह का जन्म 1940 में हुआ।
- अरुणा रॉय का जन्म 1946 में हुआ वो भारत की उन महिलाओं में से एक, जो बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ राजनीतिज्ञ भी हैं।
- 'बीजिंग ओलिंपिक' खेलों में भारत के लिए 'कांस्य पदक' जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार का जन्म 1983 में हुआ।
- दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा (तमिल अभिनेत्री) का जन्म 1937 में हुआ।

26 मई को हुए निधन

- के.पी.एस.गिल का निधन 2017 में हुआ वो पंजाब के दो बार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रहे थे।
- हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन 1986 में हुआ।

विशेष आलेख

बंगाल में चुनावी हिंसा केवल आज ही नहीं, इस हिंसा का पुराना है इतिहास

अशोक भाटिया

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। छठे चरण के दौरान पूर्वी मिदनापुर के तामलुक में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद उसके शव को तालाब में फेंक दिया गया। टीएमसी ने इसका आरोपभाजपा पर लगाया है। मृतक का नाम शेख माइबुल बताया गया है।जानकारी के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ता शुक्रवार रात करीब 11 बजे बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में ही उस पर कई लोगों ने हमला कर दिया। धारदार हथियार से उसकी हत्या के बाद उसे तालाब में फेंक दिया गया। सुबह जब लोग तालाब के बाद पहुंचे को इसकी जानकारी मिली। पुलिस उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों 22 मई को नंदीग्राम में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इसका आरोप टीएमसी पर लगा था। हत्या के विरोध में जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालिया घटनाक्रमों की वजह से नंदीग्राम में वोटिंग से ठीक पहले काफी तनाव पसर गया था।भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की घटना में 7 कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। दरअसल देखा जाय तो पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी पश्चिम बंगाल में राजनीति की बात होती है तो पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है। देश के करीब-करीब हर राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती हैं। यानी सभी राज्यों में हिंसा चुनावी होती है। वहीं, पश्चिम बंगाल में हिंसा का नाता चुनाव से नहीं राजनीति से हो गया है। पश्चिम बंगाल में दशकों से राजनीतिक हिंसा आम बात है।

आजादी के बाद से बंगाल ने कई राजनीतिक दलों के नेतृत्व वाली सरकारें देखी हैं। जिनमें दो दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस और तीन दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा शामिल हैं। ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) मौजूदा सरकार का नेतृत्व करती है। इन सभी शासनों में, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हिंसक झड़पों की संस्कृति पिछले कुछ वर्षों में ही पनपी है। इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को सुर्खियों में दिया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत नक्सल आंदोलन के साथ हुई। 1960 से 1970 के बीच शुरू हुई नक्सली हिंसा धीरे-धीरे राजनीतिक हिंसा में बदल गई। एक सरकारी आंकड़े की मानें तो इन पांच दशकों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में करीब 30 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सूबे में राजनीतिक हिंसा का दौर आज भी जारी है। पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा मौत सिंगुर और नंदीग्राम आंदोलन में हुईं। राजनीतिक जानकार इस बात से भी डरे हुए थे कि जैसे-जैसे राज्य में आम चुनाव होंगे राजनीतिक हिंसा में बढोतरी होगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर 1960 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद 1967 में राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकार आई जो 2011 तक यानी 34 साल तक रही। एक आंकड़े के मुताबिक इन 34 वर्षों के दौरान राज्य में राजनीतिक हिंसा में 28 हजार लोग मारे गए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए नंदीग्राम और सिंगुर आंदोलन को पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस हिंसात्मक तरीके से दबाया वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और 34 साल की लेफ्ट सरकार का पतन हुआ। लोगों को उम्मीद जगी कि अब

सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा-लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल में हिंसा कम नहीं हुई। अब तो बिना किसी चुनाव के भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पर हमला आम बात हो गई है। बताया जाता है कि चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक हिंसा अब इस हद तक बढ़ गई है कि कई सरकारी कर्मचारियों ने ऐसे कर्तव्यों से जुड़े जोखिमों के कारण चुनाव कर्तव्यों से बचने के लिए स्वयं नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। हिंसा का केंद्र रहे बीरभूम जिले में, कई ब्लॉकों में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से अधिक है। तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता बताते हैं, %%करीबी लड़ाई वाले चुनाव में एक या दो वोट खराब होने से नतीजा बदल सकता है। हम समझना चाहते थे कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। हमें पता चला कि सभी निर्दलीय उम्मीदवार स्कूल शिक्षक हैं। उन्होंने हमें बताया कि चूंकि वे मतदान कर्मी नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। वे न तो प्रचार करेंगे और न ही वोट मांगेंगे। स्कूल शिक्षक राजकुमार रॉय, जिन्हें उत्तर दिनाजपुर जिले में पिछले पंचायत चुनावों में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था, पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा चिंताओं और अनियमितताओं के बारे में मुखर रहे थे। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद वह लापता हो गये। बाद में उनका शव रायगंज के सोनाडिंगी में पाया गया, जो इटाहार ब्लॉक में उनके निर्धारित पद से लगभग 20 किमी दूर था। जबकि पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या के मामले के रूप में वर्गीकृत किया था, स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। राजकुमार की पत्नी अर्पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामला अभी भी चल रहा है। आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक पेपर के मुताबिक लोकतंत्र और हिंसा का सहजीवी संबंध है। यहां तक कि दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी इस तरह के गहरे संबंध को खत्म करने में असमर्थ रहे हैं। उदाहरण के लिए, 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के बीच, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों में वामपंथी और दक्षिणपंथी चरमपंथी समूहों की ओर से राजनीतिक हिंसा का विस्फोट देखा गया। हाल के वर्षों में, दुनिया ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) में ब्रेक्सिट मुद्दे, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और 2020 के अमेरिकी चुनावों पर राजनीतिक हिंसा की घटनाएं देखीं। हालांकि, कोई यह कह सकता है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में राजनीतिक हिंसा अधिक आम है। बंगाल में लेफ्ट के 34 साल और ममता बनर्जी के 13 साल के कार्यकाल में राजनीतिक हिंसा की तस्वीर बदलती नजर नहीं आई। ऐसे में लोगों की उम्मीद अब किसी तीसरे विकल्प पर है।

पंजाब के शिक्षण संस्थानों के लिए सुनहरा है अकादमिक सत्र 2024-25

डा. एस.के. मिश्रा

पंजाब के शिक्षण संस्थानों के लिए साल 2003 से 2013 तक के 10 साल सुनहरे पन्नों से रहे। इस दौर ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को आगे बढने के खूब अवसर दिए। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थान आई.आई.टी. रोपड़, आई.आई.एम. अमृतसर के साथ-साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी खुलीं। विभिन्न राज्यों सहित छोटे अविकसित देशों से भी स्टूडैंट्स ने पंजाब के शिक्षण संस्थानों में दाखिला लिया। शिक्षा के क्षेत्र ने पंजाब की आर्थिकता को इन दस सालों में बेहद मजबूत किया। मगर 1980 के दशक का ओवरसीज एजुकेशन (विदेश पढ़ाई को जाने) का रुझान 2010 के बाद से एकदम से बड़ा और पंजाबी स्टूडैंट्स ने कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यू.के., यूनाइटेड स्टेट्स (यू.एस.ए.) सहित विभिन्न विकसित, कम आबादी वाले एवं अधिक रोजगार वाले देशों को रुख किया। पंजाब की आर्थिकता पर यह दौर भारी पड़ा, खासकर शिक्षण संस्थानों पर। अब पंजाब के शिक्षण संस्थानों के लिए अकादमिक सत्र 2024-25, जो इस माह से शुरू है और अगस्त तक जारी रहेगा, सुनहरा है। इसके कारण कई हैं, मगर अहम हैं कि इस अकादमिक सत्र को पंजाब के शिक्षण संस्थान अगर क्वालिटी एजुकेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नव अवसरों से संभाल लेंगे तो पंजाब के शिक्षण संस्थान फिर से गुलजार होंगे और सालों तक स्थिरता बनी रहेगी। विदेश में पढ़ाई के लिए मेजबान संस्थान को दी जाती ट्यूशन एवं अन्य फीस इस बार बढ़ी है। विभिन्न फॉरेन एजुकेशन पोर्टल्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में स्नातक की डिग्री के लिए ट्यूशन फीस प्रतिवर्ष 30,000 से 50,000 (भारतीय करंसी में लगभग 25 लाख प्रतिवर्ष से 50 लाख प्रतिवर्ष) तक हो गई है, जो बीते पांच वर्ष में दोगुना हुई है। कोविड-19 के बाद से ही इसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इंश्योरैंस, लिविंग कॉस्ट में जर्मन एवं स्विट्जरलैंड ने भी फीस में भारी इजाफा किया है। इन देशों के इमीग्रेशन, स्टडी वीजा नियम इनकी अधिकृत वैबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकतर कैटेगरी में वर्तमान बढ़ौतरी प्रतिशतता एवं बीते इजाफे से तुलना कर दी गई है। बहुत से देशों के वीजा नियम बदलाव से स्टडी लोन प्रावधान भी मुश्किल हुआ है। कनाडा में भी अब मुद्रास्फीति पाई जा रही है। महंगाई बढ़ी है और वह दर जिस पर उपभोक्ता की दैनिक जरूरत निर्भर करती है, के मूल्य भी बढ़े हैं। कोरोना वायरस लॉकडाऊन के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए कनाडा को इसे बढ़ाना पड़ा है। कनाडा में विदेशी स्टूडैंट्स की बड़ी आमद ने उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ाई है, वैश्विक उत्पाद आपूर्ति मुश्किल हुई है, उत्पाद की कमी और बढ़ती तेल की कीमतों ने वहां रहना महंगा कर दिया है। जनवरी 2024 से प्रभावी स्टूडैंट वीजा के लिए कनाडा ने जी.आई.सी. (गारंटिड इन्वैस्टमैंट सर्टीफिकेट) राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। ऐसे में ओवरसीज एजुकेशन भले ही ट्रैंड में हो, पर पॉकेट से बाहर होती जा रही है! पंजाब राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत से संस्थान तो ओवरसीज एजुकेशन के साथ मिलकर ड्यूल मोड (दोनों देशों में रहकर पढ़ाई के अवसर) दाखिले दे रहे हैं। प्रदेश में लगभग 10 स्टेट (सरकारी) यूनिवर्सिटी हैं। इनसे जुड़े कैम्पस, कॉलेजिस ऐसे ड्यूल डिग्री कोर्सिस ऑफर कर रहे हैं, जहां कम खर्च में भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की जा सकती है। आई.के.गुजराल पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी (आई.के.जी पी.टी.यू.) जालंधर-कपूरथला प्रदेश की बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी है, इसके खुद के छह कैम्पस एवं 200 से अधिक एफिलिएटेड कालेज हैं! प्रतिवर्ष यूनिवर्सिटी एवं इसके कालेजों में लगभग 1 लाख विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। इस बार इन कालेजों में सूचना डैस्क पर क्वेरी (पूछताछ) बढ़ी है। विद्यार्थी अब कम खर्च में अपने प्रदेश में रहकर प्रोफैशनल कोर्स करने के इच्छुक हैं। इस बार विद्यार्थी बीते सालों के मुकाबले ज्यादा दाखिला लेंगे, ऐसा तथ्यों से स्पष्ट है। पंजाब के कालेजों, यूनिवर्सिटीज में नए समय के नए कोर्स जैसे ए.आई. (आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस), रोबोटिक साइंस, डाटा साइंस, क्लाऊड कम्प्यूटिंग इत्यादि कोर्सिस में इंजीनियरिंग की नई एवं ग्लोबल डिमांड वाली स्ट्रीम उपलब्ध हैं, जिनमें करियर के अवसर हर विकसित एवं विकासशील देश में मौजूद हैं। यह समय शिक्षण संस्थानों के लिए अवसर हैं, अवलोकन का, बीते समय में किए लालच एवं गलत प्रैक्टिस को छोड़कर नए दाखिला सत्र में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करने का है! समय शक्ति है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

वृष
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

मिथुन
किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

कर्क
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

सिंह
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

कन्या
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

वृश्चिक
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

धनु
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

मकर
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

कुंभ
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

मीन
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

यूपी में सातवां चरण: जहां 2019 में पूरी तरह अस्त हो गया था समाजवाद का सूरज

वहीं 13 सीटों में से चार पर बसपा तो दो पर सपा का कभी नहीं खुला खाता

-संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस सातवें चरण में देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिये सबसे हाई प्रोफाइल सीट समझी जाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट भी शामिल है। यहां से पूरे देश में बीजेपी को 400 सीट दिलाने का दम भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मैदान में हैं। इसी चरण में सूबे के सीएम और सबसे कद्दावर नेताओं में से एक आदित्यनाथ योगी के गढ़ गोरखपुर में भी मतदान होना है। जिन 13 सीटों पर पहली जून को मतदान होना है उसमें से छह: सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कभी खाता नहीं खुल पाया है। इसमें विशेष रूप से वाराणसी की भी सीट शामिल है। वाराणसी के अलावा कुशीनगर में सपा-बसपा का कभी खाता नहीं खुला है तो वहीं महाराजगंज,गोरखपुर,बलिया और बांसगांव में बसपा कभी भी जीत नहीं पाई है। सातवें चरण की 13 सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में 09 सीटों पर बीजेपी,दो-दो सीटों पर अपना दल और बसपा को जीत हासिल हुई थी। सपा का यहां खाता भी नहीं खुल पाया था। अबकी बार सातवें चरण में महिला प्रत्याशियों की संख्या काफी कम है। मात्र 10 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी हैं। अभी तक के छह चरणों के चुनाव के मुकाबले सातवें चरण में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम है। बात वाराणसी लोकसभा सीट के स्वभाव की कि जाये तो यहां कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला बराबरी का रहा है दोनों ने सात-सात बार सीट दर्ज की है जनता पार्टी,जनता दल और सीपीआईएम को भी यहां से एक-एक बार जी मिली है। पिछले तीन लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी जीतती आई है। यहां से सपा-बसपा को कभी भी जीत नहीं हासिल हुई है। इसी श्रेणी में कुशीनगर सीट भी आती है यह सीट 2008 के अस्तित्व में आई थी पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था,जो कांग्रेस ने जीता था। उसके पश्चात पिछले दो लोकसभा चुनावों से यह सीट भाजपा के कब्जे में है। यहां से भी सपा-बसपा का कभी खाता नहीं खुल पाया है।

इसके अलावा सातवें चरण की चार सीट ऐसी हैं जहां से बसपा को कभी भी जीत हासिल नहीं हो पाई है इस श्रेणी में महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया और बांसगांव की सीट आती हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट पर अब तक भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा ने यहां से 6 बार तो कांग्रेस ने पांच बार जीत हासिल की है,वहीं तीन बार निर्दलीय और इसके अलावा यहां से जनता पार्टी,जनता दल और सपा को एक-एक बार ही जीत हासिल हो पाई है। कभी योगी आदित्यनाथ के गुरु और राजनेता महंत अवैद्यनाथ जो गोरखनाथ मन्दिर के तत्कालीन पीठाधीश्वर का सियासी दबदबा था। वे गोरखपुर लोकसभा से चौथी लोकसभा के लिये हिंदू महासभा से सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। इसके बाद नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं लोकसभा के लिये भी निर्वाचित हुए थे। गोरखपुर में भाजपा ने आठ बार जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच बार यहां से सांसद रह चुके हैं। एक बार उप चुनाव में यह सीट सपा के खाते में भी जा चुकी है तो एक बार यहां से जनता पार्टी को भी जीत हासिल हुई थी। फिलहाल यहां से भाजपा के रवि किशन सांसद हैं यहां भी बसपा का कभी भी खाता नहीं खुला है। बसपा के लिये यहां भी हमेशा सियासी सूखा रहा।

समाजवाद का गढ़ और पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की जन्म स्थली रही बलिया की लोकसभा सीट पर सबसे पहले चुनाव सोशलिस्ट पार्टी ही जीती थी। जनता पार्टी और जनता दल ने भी एक-एक बार जीत हासिल की थी। इसके पश्चात चन्द्रशेखर जी यहां से पांच बार सांसद चुने गये। 2008 के उप चुनाव और 2009 के आम चुनाव में यहां से सपा के टिकट से पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को जीत हासिल हुई थी। भाजपा यहां पिछले दो बार से ही चुनाव जीत रही है। वीरेंद्र मस्त यहां से बीजेपी के सांसद हैं।बसपा को यहां कभी जीत हासिल नहीं हुई। बांसगांव लोकसभा सीट पर भी बसपा का कभी खाता नहीं खुल पाया है। यहां से भाजपा और कांग्रेस दोनों छहः-छहः बार जीत चुके हैं।जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक-एक बार चुनाव जीत चुकी है।1996 में यहां से सपा की सुभावती चौहान चुनाव जीतने में सफल रहीं थीं।2009 से यहां भाजपा का कब्जा है और कमलेश पासवान लगातार तीन बार के सांसद हैं।

वहीं, सातवें चरण का चुनाव लड़ रहे 144 उम्मीदवारों के चाल चरित्र चेहरे की बात की जाये तो 36 उम्मीदवारों पर आपराधिक व 30 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 22 आपराधिक मामले बसपा की टिकट पर बलिया से चुनाव लड़ रहे लल्लन सिंह यादव पर दर्ज हैं, जबकि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर 18 और कुशीनगर से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्या पर नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं।इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के 13 में से पांच, भाजपा के 10 में से तीन, सपा के नौ में से सात, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी छह में से दो, कांग्रेस के चार में से दो उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के पांच, भाजपा के एक, सपा के छह, कांग्रेस के दो उम्मीदवारों गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स के अनुसार सातवें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदोंली, वाराणसी, मिजार्पुर और राबर्ट्सगंज से लड़ रहे 144 उम्मीदवारों में केवल 10 महिला उम्मीदवार हैं। इस चरण में 55 करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के 10 में से 10, सपा नौ में नौ, कांग्रेस के चार में चार, बसपा के 13 में से सात, अपना दल (सोनेलाल) के दो में से दो, अपना दल(कमेरावादी) के दो में से दो उम्मीदवार करोड़पति हैं। घोसी से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजीव राय सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। इनकी संपत्ति लगभग 49 करोड़ के है। वहीं, गोरखपुर से भाजपा से चुनाव लड़ रहे फिल्म अभिनेता व भाजपा नेता रवि किशन (रवीन्द्र शुक्ला) की संपत्ति 43 करोड़ है। तीसरे नंबर पर महाराजगंज से भाजपा के उम्मीदवार पंकज चौधरी हैं, जिनकी संपत्ति 41 करोड है। वहीं सबसे कम सम्पति वाले उम्मीदवारों में गोरखपुर से अल हिन्द पार्टी से चुनाव लड़ रहे राम प्रसाद की कुल संपत्ति 25,000 रुपये हैं। दूसरे नंबर पर चंदौली से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे संतोष कुमार की संपत्ति 38,000 और तीसरे नंबर पर महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामप्रीत की संपत्ति 50, 000 रुपये है। पढ़ाई-लिखाई की बात की जाये तो 144 में से 54 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता पांचवीं और 12वीं के बीच है, जबकि जबकि 82 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा है। तीन उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं। वहीं चार उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता साक्षर है। सातवें चरण में 25 से 40 आयु वर्ष के बीच के 47 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 41 से 60 आयु वर्ष के 69 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच है।

बंगाल में चुनावी हिंसा केवल आज ही नहीं, इस हिंसा का पुराना है इतिहास

अशोक भाटिया

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। छठे चरण के दौरान पूर्वी मिदनापुर के तामलुक में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद उसके शव को तालाब में फेंक दिया गया। टीएमसी ने इसका आरोपभाजपा पर लगाया है। मृतक का नाम शेख माइबुल बताया गया है।जानकारी के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ता शुक्रवार रात करीब 11 बजे बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में ही उस पर कई लोगों ने हमला कर दिया। धारदार हथियार से उसकी हत्या के बाद उसे तालाब में फेंक दिया गया। सुबह जब लोग तालाब के बाद पहुंचे को इसकी जानकारी मिली। पुलिस उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों 22 मई को नंदीग्राम में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इसका आरोप टीएमसी पर लगा था। हत्या के विरोध में जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालिया घटनाक्रमों की वजह से नंदीग्राम में वोटिंग से ठीक पहले काफी तनाव पसर गया था।भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की घटना में 7 कार्यकर्ता घायल भी हुए थे।

दरअसल देखा जाय तो पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी पश्चिम बंगाल में राजनीति की बात होती है तो पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है। देश के करीब-करीब हर राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती हैं। यानी सभी राज्यों में हिंसा चुनावी होती है। वहीं, पश्चिम बंगाल में हिंसा का नाता चुनाव से नहीं राजनीति से हो गया है। पश्चिम बंगाल में दशकों से राजनीतिक हिंसा आम बात है।

आजादी के बाद से बंगाल ने कई राजनीतिक दलों के नेतृत्व वाली सरकारें देखी हैं। जिनमें दो दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस और तीन दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा शामिल हैं। ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) मौजूदा सरकार का नेतृत्व करती है। इन सभी शासनों में, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हिंसक झड़पों की संस्कृति पिछले कुछ वर्षों में ही पनपी है। इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को सुखियों में दिया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरूआत नक्सल आंदोलन के साथ हुई। 1960 से 1970 के बीच शुरू हुई नक्सली हिंसा धीरे-धीरे राजनीतिक हिंसा में बदल गई। एक सरकारी आंकड़े की मानें तो इन पांच दशकों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में करीब 30 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सूबे में राजनीतिक हिंसा का दौर आज भी जारी है। पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा मौत सिंगुर और नंदीग्राम आंदोलन में हुईं। राजनीतिक जानकार इस बात से भी डरे हुए थे कि जैसे-जैसे राज्य में आम चुनाव होंगे राजनीतिक हिंसा में बढोतरी होगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर 1960 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद 1967 में राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकार आई जो 2011 तक यानी 34 साल तक रही। एक आंकड़े के मुताबिक इन 34 वर्षों के दौरान राज्य में राजनीतिक हिंसा में 28 हजार लोग मारे गए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए नंदीग्राम और सिंगुर आंदोलन को पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस हिंसात्मक तरीके से दबाया वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और 34 साल की लेफ्ट सरकार का पतन हुआ। लोगों को उम्मीद जगी कि अब सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा-लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल में हिंसा कम नहीं हुई। अब तो बिना किसी चुनाव के भी राजनीतिक कार्यकताओं की हत्या और उन पर हमला आम बात हो गई है। बताया जाता है कि चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक हिंसा अब इस हद तक बढ़ गई है कि कई सरकारी कर्मचारियों ने ऐसे कर्तव्यों से जुड़े जोखिमों के कारण चुनाव कर्तव्यों से बचने के लिए स्वयं नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। हिंसा का केंद्र रहे बीरभूम जिले में, कई ब्लॉकों में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से अधिक है। तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता बताते हैं, "करीबी लड़ाई वाले चुनाव में एक या दो वोट खराब होने से नतीजा बदल सकता है। हम समझना चाहते थे कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। हमें पता चला कि सभी निर्दलीय उम्मीदवार स्कूल शिक्षक हैं। उन्होंने हमें बताया कि चूंकि वे मतदान कर्मी नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। वे न तो प्रचार करेंगे और न ही वोट मांगेंगे। स्कूल शिक्षक राजकुमार रॉय, जिन्हें उत्तर दिनाजपुर जिले में पिछले पंचायत चुनावों में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था, पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा चिंताओं और अनियमितताओं के बारे में मुखर रहे थे। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद वह लापता हो गये। बाद में उनका शव रायगंज के सोनाडिंगी में पाया गया, जो इटाहार ब्लॉक में उनके निर्धारित पद से लगभग 20 किमी दूर था। जबकि पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या के मामले के रूप में वगीकृत किया था, स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।

राजकुमार की पत्नी अर्पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामला अभी भी चल रहा है। आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक पेपर के मुताबिक लोकतंत्र और हिंसा का सहजीवी संबंध है। यहां तक कि दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी इस तरह के गहरे संबंध को खत्म करने में असमर्थ रहे हैं। उदाहरण के लिए, 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के बीच, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों में वामपंथी और दक्षिणपंथी चरमपंथी समूहों की ओर से राजनीतिक हिंसा का विस्फोट देखा गया। हाल के वर्षों में, दुनिया ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) में ब्रेक्सिट मुद्दे, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन और 2020 के अमेरिकी चुनावों पर राजनीतिक हिंसा की घटनाएं देखीं। हालांकि, कोई यह कह सकता है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में राजनीतिक हिंसा अधिक आम है। बंगाल में लेफ्ट के 34 साल और ममता बनर्जी के 13 साल के कार्यकाल में राजनीतिक हिंसा की तस्वीर बदलती नजर नहीं आई। ऐसे में लोगों की उम्मीद अब किसी तीसरे विकल्प पर है। यह विकल्प 2026 के विधानसभा चुनावों में तय होगा। साफ है कि पश्चिम बंगाल की जनता के सामने लेफ्ट और कांग्रेस, टीएमसी और भाजपा तीन विकल्प होगें। जिनमें कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी का विकल्प वहां की जनता पहले ही आजमा चुकी है। ऐसे में भाजपा अपने आप को राज्य में मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। शायद इसीलिए भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है।

108 दानों की जप माला का महात्म्य

-आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

हमारे पौराणिक शास्त्रों में देवी देवता को प्रसन्न करने हेतु माला का विशेष महत्व दिया गया है। मंत्र जप के लिये तुलसी, स्फटिक, मोती, रूद्राक्ष आदि की माला करने का विधान है जिसमें माला में 108 की सॅख्या के दाने की माला की जाती है। वेद-पुराण और उपनिषदों में अनेक स्थानों पर मंत्र जप का उल्लेख किया गया है वही ज्योतिष एवं वैज्ञानिक मान्यताओं भी इससे जुड़ गयी है। शिवपुराण, शिवसंहिता, देवीपुराण में रूद्राक्ष को महादेव का प्रतीक मानकर रूद्राक्ष की माला मंत्र का जाप को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वमंगलमयी बताते हुये साधक के कल्याण के मार्ग की विधि बतायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी, स्फटिक, मोती या नगरों से बनी मालाओं का जाप भी प्राचीन काल से चला आ रहा है जिसमें साधक इनके प्रयोग से अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक एवं ऊॅर्जा से भरा आभासित कर शरीर में तेजोमय कंपन व संचार मेहसूस कर आनन्द से परिपूर्ण होना स्वीकारते है।

माला जप का विधान एवं महत्वः-

माला मंत्र जप करने के शास्त्रोक्त नियम बताये गये है जिसमें अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर गिनने, फिर कनिष्ठा के मूल से अग्रभाग तक गिनने का विधान है। इसके पश्चात अनामिका और मध्यमा के अग्रभाग होकर तर्जनी के मूल तक गिनती की जाती है जो अनामिका के दो, कनिष्ठा के तीन, पुनः अनामिका का एक, मध्यमा का एक और तर्जनी के तीन पर्व कुल मिलाकर दस सॅख्या होती है। शास्त्रोक्त मत देखे-आरम्भ्यानामिका मध्यम पर्वानयुक्तान्यनुक्रमात। तर्जनीमूलपर्यन्तं जपेददशसु पर्वसु।। मध्यमागुलिमूले तु यतपर्व द्वितयं भवत्। तं वै मेरूं विजानीयज्जप्येतं नालिलंघयेत।। अर्थात -अंगुली के मध्य पोर से आरम्भ कर के क्रमंशः 10 पोरों पर बराबर जपे, लेकिन मध्यम अंगुली के जड़. के दो पोरों तक छोड़ दे, क्योंकि वे अंगुली के मेरू है और जप में मेरू का लंघन नहीं किया जाता है। देवी अनुष्ठानों में कुछ विशिष्ट अनुष्ठान में अनामिका के दो पर्व/पोर, कनिष्ठा के तीन पोर, पुनः अनामिका के अग्रभाग का एक पोर मध्यमा के तीन, और तर्जनी के मूल का एक पोर कुल मिलाकर दस सॅख्या होती है।

मंत्र जप एवं इष्ट सिद्धि के लिये माला का प्रयोग के कई कारगर परिणाम भी प्राप्त किये गये है तभी इष्ट सिद्धि के लिये शीघ्र फल प्राप्ति हेतु माला जाप का प्रचलन बढ़ा है। माला जाप का मंत्रों की गणना आसानी से करने हेतु सजगता आवश्यक है जिसे सहज ही पालन करने वाला अपने लक्ष्य को पा जाता हैं चूंकि माला के तीन प्रकार बताये गये है- करमाला, वर्ण माला एवं तीसरा-मणि माला।कर माला- का जाप करते समय अगुलियों के पौरों से निश्चित क्रम द्वारा क्रंमशः बढ़ते क्रम में माला के दानों को आगे बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है जिससे लम्बी अवधि के लिये साधना या मंत्र मंत्रजाप किया जाता है, कुछेक विदवान लम्बी अवधि के जाप का निशेष करते है। जब मंत्र जप हजारों लाखों की सॅख्या में करने हो तो माला करना कष्टप्रद होता है। कर माला का प्रयोग दैनिक जप में या छोटी सॅख्या के जप में किया जाता है, ऐसे साधकों के लिये कर माला करने बाबत शास्त्रों में नियम बताये गये है। अनामिता के मध्य भाग से नीचे की ओर दानों को गिनने, फिर कनिष्ठा के मूल से अग्रंवाल तक गिना जाता है। करमाला पर मंत्र जप के नियम- कर माला पर जप करते समय अंगुलिया परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई रखने का विधान है न कि उन्हें अलग-अलग रखा जाये। हथेली को थोड़ा अन्दर की तरफ मुड़ा रखने तथा माला फेरते/जपते समय मेरू का उल्लघंन न किये जाने हेतु मध्यमा के दो पोर जिसे मेरू कहा है का ध्यान रखा जाये एवं माला करते समय पोरों की संधि का स्पर्श नही करें और हाथों को हृदय के सामने अंगुलियों को थोड़ी झुकाकर और वस्त्र ढ़ककर ही जप करें। दस की सॅख्या में किये जाने वाले जप की गिनती करने के लिये लाख अर्थात लक्ष, सिन्दूर और गौ के सूखे कण्डे-उपले का चूर्ण कर के इन सबके मिश्रण की गोलिया बनाकर इनसे गणना की जा सकती है। यहाँ यह विशेष ध्यान दिलाया गया है कि अक्षत, अंगुली, पुष्प, चन्दन, मिट्टी, कंकड आदि का प्रयोग गणना हेतु पूर्णतया वर्जित है, जिसे साधकों की सॅख्या अधिक होने पर उनके हाथ में कर माला न होने पर कुछेक स्थानों पर प्रयोग किया जाता है।

वर्णमाला-माला जप करते समय वर्णमाला का प्रयोग अन्तर जप और बहिर जप दोनों प्रकार के जप में समान रूप से किये जाने का नियम है जिसमें वर्णमाला जप अर्थात अक्षरों के अक्षरों के द्वारा सॅख्या की गणना करना, इसके जप करने का विधान यह बताया है कि पहले वर्णमाला का एक अक्षर बिन्दु लगाकर उच्चारण करें, फिर मंत्र का, जिसके कारण मंत्रजप की सॅख्या 50 होगी। अ-वर्ग के सोलह वर्ण है जो इस प्रकार है-अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ, लृ, लॄ, ए ऐ ओ औ अं अः। इसी क्रम में-क वर्ग के पच्चीस वर्ण होते है जो-क ख ग घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट,ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न , प, फ, ब, भ, म है तथा य वर्ग से ह कार तक आठ वर्ण है जो य र ल व श ष स ह है। इस प्रकार क से प तक के लिये पच्चीस, य से ह तक के लिये आठ एवं पुनः एक लकार के लिये एक कुल 50 की सॅख्या प्राप्त होगी। फिर लकार से लौटकर अकार तक आने पर पचास इस तरह कुल सॅख्या 100 पूर्ण होती है। वर्णमाला में क्ष को सुमेरू माना जाता है अतः इसका उल्लंघन निषिद्ध है। संस्कृत में त्र और ज्ञ को स्वतंत्र अक्षर नहीं माना जाकर संयुक्त अक्षर माना जाता है इसलिये इन अक्षरों की गणना नहीं की जाती है। परिणामस्वरूप गणना में सात वर्ग की जगह आठ वर्ग होते है। आठवा वर्ग शकार से प्रारम्भ होता है इसके द्वारा अं कं चं टं तं पं यं शं यह गणना करके आठ बार ओर जप करना बताया गया है, तभी जप की सॅख्या 108 पूर्ण मानी गयी है जिसे अक्षरमाला के मणि रूप की संज्ञा दी गयी है। इनका मूल सूत्र कुण्डलिनी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र से आज्ञचक्र तक सूत्र रूप में है जो जप करते समय आरोह-अवरोह अर्थात ऊपर से नीचे, पुनः नीचे से ऊपर होता है इस प्रकार जप पूर्ण एवं सिद्धि प्रदान करने वाला होता है।

माला के 108 दानों का रहस्य-

माला के दानों की सॅख्या 108 सम्पूर्ण ब्रम्हाड का प्रतिनिधित्व करती है एवं सूर्य की 21600 कलाओं का प्रतीक है। एक स्वस्थ्य मनुष्य 24 घन्टे में 21600बार सॉस लेता है , दिन के 24 घन्टों में वह 12 घन्टे अपने दैनिक कार्यो में व्यस्त होता है तथा शेष 12 घटे 10800 सॉस लेता है, इस प्रकार सूर्य भी एक वर्ष में दो बार स्थिति बदलता है और छह माह तक उत्तरायण और छह माह दक्षिणायन रहता है जिसमें प्रत्येक स्थिति में वह छह माह में 10800 बार कलायें बदलता है। स्वस्थ्य मनुष्य के 12 घन्टे में ली गयी सॉस 10800 एवं सूर्य की छह माह एक स्थिति में बदली गयी 10800 कलाओं में हमारे ऋषिमुनियों ने इस सॅख्या के आखिरी तीन शून्य हटाकर 108 दाने निर्धारित कर दिये है। माला का एक एक दाना सूर्य की एक-एक कला का प्रतीक है और साधक द्वारा जप करने पर वह साधक को सूर्य के समान तेजस्वी बनाकर शक्ति संचार कर उसका कल्याण करते है। सूर्य जगत का एकमात्र साक्षात दिखने वाला देवता है इसी लिये उसकी कलाओं को आधार मानकर जप के लिये माला में 108 दानों को निर्धारित किया गया है।

साधक को 108 दानों की माला रखनी चाहिये जो पूर्ण मानी गयी हैं। कहीं-कहीं कुछेक अपवाद के रूप में कुछेक साधक 19, 36, 78 और 95 दाने की माला जप करते है जो कदापि नहीं करनी चाहिये। किसी भी प्रकार के मंत्र जाप के लिये 108 दाने की माला पूर्णरूप से आवश्यक है । माला के दोनों शिरों को जोड़कर वहाँ एक विशिष्ठ दाना अवश्य लगाना चाहिये उसे सुमेरू कहते है। सुमेरू के अभाव में माला निष्प्राण, व्यर्थ और निष्प्रभावी समझा जाता है। 108 की सॅख्या एक आध्यात्मिक तत्व है। जो अपने आप में रहस्यमय है। श्वास और प्रश्वास की क्रिया एक प्राकृतिक व्यवस्था है।यदि माला जपते समय साधक श्वास-प्रश्वास की गति को अनुकरण करते हुये प्रति श्वास पर एक मंत्र पढ़े और उसी के साथ एक दाना आगे से पीछे सरकाये तो 1 घन्टें मे 900 और 12 घन्टे में 10800 जप हो जायेगा। उपांशु जप से नियमानुसार यदि कोई साधक केवल 108 बार ही जप करता है तो उसे 10800 की सॅख्या का जप केवल 108 जप में शूद्रतापूर्वक करने के लिये 108 दाने की माला उपयोगी समझी जाती है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सम्पूर्ण ब्रम्हाड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन है। इन 12 राशियों में नौ ग्रह सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते है जिसमें इन ग्रहों की सॅख्या 9 एवं राशियों कीसॅख्या 12 में गुणा करने पर 108 की सॅख्या प्राप्त होती है, अतः ज्योतिष के आधार पर जप की माला के दाने 108 तय किये गये है। खगोल विज्ञान के मत से ही ब्रम्हाण्ड स्थित 27 नक्षत्रों के चरणों का स्पर्श करने के लिये 108 बार जप करना चाहिये। ऐसे जप से सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड में व्याप्त नक्षत्रीय क्षेत्र, वायुमण्डल से साधक का सम्पर्क हो जाता है। जबकि नक्षत्र के चार चरण होते है अतः 27 नक्षत्र 108 चरणों के माध्यम से ब्रम्हाण्ड का स्पर्श करने के लिये 108 बार की जप क्रिया करनी चाहिये, तभी जप सुविधापूर्वक सम्पन्न होती है जब माला में 108 दाने हो। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि जप के पूर्व माला के सुमेरू पर मंत्र के अधिष्ठातृ देवी या देवता का ध्यानपूर्वक आवाहन कर लेना चाहिये, तभी सफलता निश्चित है।

देवी भागवत पुराण में अंक नौ का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रभावशाली माना गया है। न जाने कितने पौराणिक वैदिक प्रसंग नौ अक से जुडे हुये है। ग्रहों की सॅख्या 9 है। नवार्ण मंत्र 9 है। नवरात्र के 9 दिन है।भगवती दुर्गा के भी 9 रूप है। कितने ही प्रसंग ऐसे है जिनकी सॅख्या में 18, 1800 या 18000 की प्रधानता है। गणना करके देखें तो स्पष्ट होता है कि सभी सॅख्याओं का मूल 9 अंक ही है और इसी के विस्तार से उपरोक्त सॅख्यायें निर्मित हुई है। इसी प्रकार विशेषण गणतीय सिद्धान्तों के आधार पर 108 की सॅख्या की माला के सन्दर्भ में सर्वश्रेष्ठ मानकर मनको की सॅख्या भी 108 रखी गयी है। माला में सूत के प्रयोग को लेकर भी बताया गया है कि वशीकरण में लाल रंग के सूत, शांति कर्म में सफेद-श्वेत वर्ग के सूत, अभिचार कर्म में कृष्ण वर्ग के काले सूत की माला लाभकारी है वही सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं सम्पत्ति प्राप्ति के लिये रेशमी सूत से बनी माला का प्रयोग करना बताया है। यहाँ कुछ विदवानों के मतानुसार ब्राम्हण वर्ग को श्वेत, क्षत्रिय वर्ग को रक्त, वेश्य वर्ग को पीत एवं शूद्र वर्ग को कृष्ण वर्ण के सूत्र की माला करना श्रेष्ठकर कहा है।

मणिमाला-

मणिमाला अर्थात मनिया या मनकों से पिराई गयी माला मणिमाला कहलाती है इसके प्रयोग के सम्बन्ध में कहा गया है कि जिन साधकों को अधिक सॅख्या में जप करना हो तब उन्हें मणिमाला का प्रयोग करना उचित होगा। यह काला रत्न, रूद्राक्ष, तुलसी, चन्दन, शंख, कमलगट्टा, सुवर्ण, पुत्रजीवा के बीज, चान्दी, कुशमूल, स्फटिक, मोती, हल्दी, आदि पदार्थों की बनाई जाती है जिसमें वैष्णव तुलसी तथा शैव शाक्त रूद्राक्ष की माला को जप के लिये सर्वोत्तम मानते है। 108 मनकों के साथ । सुमेरू अलग होने का विधान है तथा जिस देवी-देवता की आराधना कर सिद्धि प्राप्त करना है उसके लिये अलग-अलग पदार्थो की माला प्रयोग का नियम है। चूंकि मनकों की माला एवं जप के लिये अनेक प्रकार की सावधानियाँ एवं सिद्धि हेतु उपाय भी बताये गये है। माला के प्रयोग होने वाला धागा अगर ब्राम्हण की कुंवारी कन्या द्वारा सूत काटकर बनाने पर त्वरित सिद्धि देने वाला माना है वही रूद्राक्ष के दानों की माला बनाते समय मनके पिरोते समय रूद्राक्ष के मुंह और पुच्छ का ध्यान देने को भी चेताया गया है कि रूद्राक्ष में मुहँ का भाग कुछ ऊँचा होता है और पुच्छ भाग नीचा होता है, इसलिये इसकी माला बनाते समय रूद्राक्ष दानों के मुँह से मुँह और पुच्छ से पुच्छ मिलाने का नियम है।

मंत्र साधना और उससे सम्बन्धित जितनी भी क्रियायें और उपासनायें है वे सभी तांत्रिक संस्कृति के अंग है। तांत्रिक संस्कृति भारत की आदि संस्कृति है और तांत्रिक साधना है, आदि साधना। मंत्र तत्व , मंत्र शक्ति, मंत्र साधना आदि को समझने के लिये तांत्रिक संस्कृति , तांत्रिक साधना और साधक की, विषय की गंभीरता से परिचित होना आवश्यक है। विश्व में जितने भी धर्म प्रचलित है, जितनी भी उपासना की पद्धतियाँ आर्विभूत है उन सभी का मूत्रस्त्रोत संस्कृति की उपासना है। संस्कृति का अर्थ है मन और हृदय की वृत्तियों का संस्कार आभ्यंतरिक तत्व होता है। तांत्रिक संस्कृति का मूल सूत्र न धर्म है, न भाषा है और ही भौगालिक खण्ड है। वृत्तियों को उदात्त बनाना और सुधारने का जो भी कार्य है उसे साधक अपनाकर तांत्रिक साधना और माला के 108 मनकों की सॅख्या द्वारा अपना लक्ष्य बनाकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है व साथ ही शारीरिक, मानसिक तथा आत्मशक्ति का विकास का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट से भविष्य में नौकरियों को खतरा ?

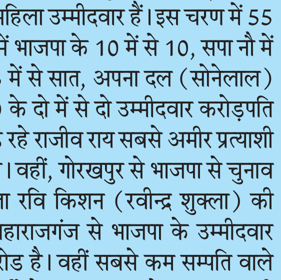

संजीव ठाकुर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के भारतीय संदर्भ में जहां जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी है और बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है ज्यादा प्रयोग से लोगों की नौकरियां जाने का बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह बात दुनिया के बड़े अरबपति कारोबारी टेस्ला और एक्स के कारोबारी एलन मस्क ने स्टार्टअप के एक कार्यक्रम में फ्रांस में महत्वपूर्ण अंदाज में कहीं, भविष्य के लिए यह बात एकदम सटीक एवं सार्थक है। एक अन्य अरबपति कारोबारी इयान बैंक्स ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई है। यह बात सभी विकासशील देशों के लिए भी लागू हो सकती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नफ्ज पढ़कर आपके मस्तिष्क की बात तुरंत पकड़कर उस पर अमल करने लगेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पल्स रेट द्वारा आपके मन की हर बात जानने में सक्षम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को वैज्ञानिकों ने मानव की सहायता के लिए और देश की बेहतरी के लिए अविष्कार किया है। अभी तक तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजरायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काफी आगे पर अब खाड़ी के देशों विगत 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति केवल तेल के कुए पर न रह कर अन्य योजनाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया है और आश्चर्यजनक रूप से यूएई ,सऊदीअरबिया, कतर, मिस्त्र ,जॉर्डन, मोरक्को और अन्य देशों में यूरोप की तुलना में अब और ज्यादा खर्च करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को अपने देश में बहुत मजबूत बना लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने फायदे हैं उससे ज्यादा विकासशील देशों के लिए यह नुकसान देह भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पल्स रीडिंग और मानसिक विचारधारा को केवल थंब इंप्रेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिवाइस पढ़ कर उस पर अमल कर सकता है इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका तथा यूरोपीय देश अब तक दुश्मन की अनेक सूचनाएं बड़ी आसानी से प्राप्त कर उसका सामरिक उपयोग करने में लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रूस अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मिसाइल दागने में यूक्रेन यूक्रेन के विरुद्ध कर रहा है और अब तक यूक्रेन यूरोपीय तथा नाटो देश की मदद से इसी तकनीक के सहारे रूस के विरुद्ध अब तक टिका हुआ है वैसे तो यूक्रेन और रूस का युद्ध में काफी नुकसान हुआ है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैं। विकासशील देशों में इस टेक्नोलॉजी का विकास अभी काफी एडवांस नहीं है इन परिस्थितियों में उनके लिए उनके सामरिक महत्व की चीजें छुपाना दुश्मन देशों के सामने कठिन हो जाएगा और उनकी खुफिया जानकारी शक्तिशाली देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक सूत्र प्राप्त करने के बाद ही पूरी प्राप्त कर सकते हैं.

खाड़ी के देश जिनमें सऊदी अरबिया, कतर ,मिस्त्र, जॉर्डन, यूएई अपने बजट का 34% बढ़ा हुआ हिस्सा एआई तकनीक पर लगातार कर रहे हैं। खाड़ी के देश इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी भविष्य की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे वे तेल की कमाई से हटकर अन्य साधनों से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकें' यूं एई पहला देश है जिसने 2017 ने इस तकनीक को अपनाया था इसके बाद खाड़ी के देशों में अब टेक्नोलॉजी को अपनाने में होड़ हो गई है' यह सभी देश एआई टेक्नोलॉजी पर लगभग 3 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं' दूसरी तरफ यदि इसका इस्तेमाल अति विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया तो इसका दुरुपयोग जिन देशों के पास इन टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है वह पूरी जानकारी निकालने में सक्षम होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यूरोपीय देश न सिर्फ सामरिक महत्व की चीजों में कर रहे हैं बल्कि मेडिकल साइंस और अंतरिक्ष विज्ञान में भी पूरी तरह हो रहा है और इससे बहुत फायदे भी मिल रहे हैं' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव प्रजाति के लिए जितना फायदेमंद है दूसरी तरफ उतना ही नुकसान दे और इससे वैश्विक शांति को खतरा भी हो सकता है' राइट एक्टिविस्ट मानते हैं कि रोबोट की तरह इस तरह की विज्ञान पर आधारित चीजें माननीय प्रजाति को खत्म कर सकती है बल्कि उनकी चिंता डेटा सुरक्षा प्रपो गेंडा सर्विलांस के विरुद्ध होने वाले नुकसान पर भी ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खाड़ी के देशों ने एआई के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश तय कर उसे जारी किया है हालांकि इस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है फिर भी इसका दुरुपयोग होने से मानव को खतरा भी हो सकता है यह एक वैश्विक चिंता की बात है।

सरसों तेल के साथ मसाले में जीरे ने भी लगाया दाम का तड़का

अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री शंकर ठक्कर ने बताया पहले दाल और अब तेल और मसाले में जीरे के भाव बढ़ रहे हैं। जो लोगों की जेब पर सेंध लगने वाली है। हालांकि तेल और मसालों के भाव में अचानक आई तेजी स्थायी नहीं रहेगी। भाव आगे गिर भी सकता है। पिछले दिनों दाल के भाव चढ़ने के बाद सरसों का तेल और जीरा का भी भाव चढ़ रहा है। एक माह में जीरा 260 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 385 रुपया प्रति किलो पहुंच गया। जीरा के भाव में तेजी पर थोक मसाला कारोबारी का कहना है कि जीरा की पैदावार अधिकतर गुजरात में होती है। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष पैदावार भी अच्छी हुई है। पिछले वर्ष के भाव को देखते हुए कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनीओ ने भंडारण और किसानों ने जीरा बाजारों में आने से रोक लिया है। इसके कारण जीरा के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। सरसों के तेल का भाव भी बढ़ रहा है। पिछले 15 दिनों में सरसों के तेल में 16 रुपया प्रति किलो की तेजी आई है। सरसों का तेल 1030 रुपया प्रति 10 किलो से बढ़कर 1190 रुपया प्रति 10 किलो पहुंच गया है। ज्यादा मांग यानी की शादियों की सीजन न होने और गर्मियों के दिनों में वैसे ही लोग खाना काम खाते हैं के बावजूद तेल मसालों में तेजी लोगों के जेब पर भारी पड़ सकती है। शंकर ठक्कर ने आगे कहा सरसों तेलों में अचानक से तेजी आने की वजह कुछ बड़े खिलाड़ियों द्वारा ४खेला४ किया गया है ऐसा दिख रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेलों के दामों में बड़ी वृद्धि नहीं हुई है लेकिन देसी तेल जिसमें खासकर मूंगफली और सरसों के दामों में बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है हालांकि चुनावी सर गर्मियों के बीच सरकारी सरकारी एजेंसियों ने आक्रामकता से सरसों की खरीदी की है जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है और दाम एमएसपी के करीब पहुंच गए हैं।

एक संसदीय क्षेत्र में अमूमन 2000 मतदान केंद्र होते हैं-मतलब 2000 फार्म 17सी। एक स्कैनर की लागत? इन्हें 30.000 की मदद से 2 घंटे से भी कम समय में स्कैन किया जा सकता है। पूरे देश में इस सब पर कुल लागत होगी 1.6 करोड़ रुपये। इतना भर करके चुनाव आयोग संदिग्ध मतदाताओं द्वारा मतदान के मामलों का पर्दाफाश कर सकता है।

— अंजलि भारद्वाज, आरटीआई कार्यकर्ता @AnjaliB_

ऐसी राह जहां सामाजिक प्रगति जुड़े

बेहतर दुनिया

भारत डोगरा

आधुनिक समाजों की एक विसंगति यह है कि एक ओर अति सफल, अति संपन्न और विख्यात कुछ व्यक्तियों की चकाचौंध है, तो दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने को उपेक्षित और हाशिए पर धकेला हुआ महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति से हट कर हमें यथासंभव ऐसी राह निकालनी चाहिए जहां अधिक से अधिक व्यक्ति अपनी प्रगति की ऐसी राह अपनाएं जो पूरे समाज की प्रगति से जुड़ती हो।

इस के लिए जो एक बहुत बुनियादी जीवन-मूल्य चाहिए, जो बहुत महत्त्वपूर्ण होते हुए बहुत सरल भी है। वह यह है कि हम कभी भी दूसरों को दुख देने का कुप्रयास न करें तथा यथासंभव दूसरों के दुख-दर्द कम करने का ही प्रयास करें। बेशक, दूसरों का दुख-दर्द कम करने की हमारी क्षमता बहुत सीमित हो सकती है, पर इस सीमा के बीच हम दूसरों का दुख-दर्द कम करने का प्रयास जरूर करें। इसके लिए अपनी क्षमताएं विकसित भी करें। इस बारे में कोई भी व्यक्ति यदि बहुत सावाान रहता है कि मुझे किसी को दुख नहीं पहुचाना है, तो वह अपने वाणी, कार्य, सोच को, इस तरह ही अनुशासित करता है, ढालता है। इस तरह अकि से अकि लोग प्रयास करते रहें तो बहुत से व्यक्ति स्वयं बेहतर इंसान बनते रहते हैं, और पूरा समाज भी बेहतर बनता रहता है। इससे जुड़ा हुआ दूसरा जीवन-मूल्य है कि हम सभी मनुष्यों की बहुत बुनियादी समानता में विश्वास रखें तथा शर्म, जाति, क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता तथा लिंग आधारित भेदभावों से ऊपर उठकर इंसानियत की सोच या विश्व के सभी लोगों की बराबरी और सम्मान की सोच पर आधारित जीवन जिएं तथा इस तरह की राह बहुत से लोगों की सम्मिलित सोच को विश्व स्तर पर अमन-शांति की सोच से जोड़ें। इस सोच में तरह-तरह की दुश्मनियों, वैर-द्वेष और भेदभाव को जीवन भर पाले रखने का कोई अर्थ नहीं है और यदि ऐसी कोई संकीर्ण सोच पहले से है तो इससे चिपटे रहने के स्थान पर इससे बाहर निकल कर इंसानियत की सोच, सभी लोगों को समता और गरिमा की सोच को अपनाने में ही प्रगति है।

तीसरा जरूरी जीवन-मूल्य ईमानदारी है, जिसके साथ यह भी जरूरी है कि मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई से ही संतुष्ट रहे और बेईमानी, हर तरह के जुए, दूसरों के हक छीनने की प्रवृत्ति से दूर रहे। विभिन्न अपराधों से अपने को दूर रखना व जो टैक्स देने हों उन्हें समय पर देना भी जरूरी है। ईमानदारी का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष है कि अपने विभिन्न रिश्तों में भी ईमानदारी अपनाना और धोखा देने का कुप्रयास कभी न करना। इससे जुड़ी हुई बात है कि मनुष्य को फिजूलखर्ची और भोग-विलास से बचना चाहिए। अपनी सभी जरूरतों को पूरा करना, कुछ आराम के साधन जुटाना, कठिन समय के लिए कुछ बचत करना-यह सब तो उचित है पर भोग-विलास पर अधिक खर्च करना अनुचित है। ऐसा करने पर पर्यावरण की भी क्षति होती है और समाज के अधिक जरूरतमंद लोगों का हक छिनता है। यदि मनुष्य फिजूलखर्ची से बचेगा तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो धन उसके पास बचेगा उसका उपयोग वह सार्थक सामाजिक कार्यों के लिए कर सकता है। जैसे निर्धन लोगों की सहायता करना, पर्यावरण रक्षा के कार्य करना आदि। विशेष तौर पर सभी तरह के नशे से अपने को दूर रखना जरूरी है क्योंकि विभिन्न तरह के नशे व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर तबाही की प्रमुख वजह है। शराब, तंबाकू, गुटखे, सिगरेट-बीड़ी, तरह-तरह के ड्रग्स सभी से दूर रहना जरूरी है। शराब की तबाही सबसे अधिक है और शराब से दूर रहना बहुत जरूरी है।

व्यापक सच्चाई तो यह है कि कई तरह के हिंसक कार्य को ही नहीं अपितु हिंसक सोच को भी समाप्त करने का नियंत्रित और अनुशासित प्रयास सभी मनुष्यों की प्रगति के लिए आवश्यक है। इस तरह के प्रयास व्यापक स्तर पर होंगे तो समाज, राष्ट्रों और विश्व स्तर पर अमन-शांति की स्थिति अपने आप बेहतर होगी, अमन-शांति के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार होगी। बहुत बुनियादी बात यह है कि नैतिकता की कसौटी पर अपनी सोच और अपने कार्यों को परखते रहना सभी मनुष्यों के लिए जरूरी है। जब अधिकांश मनुष्य सोचने लगते हैं कि उन्हें केवल अपने हित का ख्याल नहीं रखना है, दूसरों के हित का भी ख्याल रखना है, मुझे जाने-अनजाने ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिनसे समाज की क्षति होती है तो इस राह पर चलते हुए ही व्यक्तिगत प्रगति और पूरे समाज की प्रगति में परस्पर सामंजस्य एकता स्थापित होने लगती है

आधुनिक तकनीकी ने जीवन में बहुत कुछ नया प्रवेश कर दिया है, और लोग इसमें मस्त हो गए हैं, रम गए हैं। कोई दिन भर फोन से चिपका है, तो कोई कंप्यूटर से। इस स्थिति में यह समझ बहुत जरूरी है कि किसी आधुनिक तकनीक या उपकरण के उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि उसे अपने पर हावी होने दिया जाए। अपने जीवन की सही प्राथमिकताओं को बनाए रखते हुए विभिन्न नई तकनीकों और उपकरणों का सीमित उपयोग ही करना चाहिए और इनसे होने वाली हानि के प्रति भी सावधानी से दूर रहना चाहिए।

परिवार समाज की सबसे बुनियादी इकाई है और परिवार की भलाई से निरंतर जुड़े रहना, परिवार की बुनियादी इकाई को न्याय आधारित मजबूती देना, परिवार का मानवीय सहयोग और आपसी सहायता, सुख-दुख के साथ की बुनियादी इकाई बनाना बहुत जरूरी है। परिवार एक जीवन-आधार भी है और शिक्षा संस्थान भी है। परिवार की सही स्थिति और सहयोग के आधार पर ही मनुष्यों को समाज में व्यापक स्तर पर उपयोगी भूमिका निभाने में बहुत मदद मिलती है। इसी तरह आस-पड़ौस में नजदीकी समुदाय से बेहतर संबंध बनाना और उसकी भलाई में न्यायोचित सहयोग देना, विभिन्न मित्रता के संबंधों को निभाना और समाज की भलाई से जोड़ते हुए आगे ले जाना भी महत्त्वपूर्ण है। आठवीं आवश्यकता यह है कि परिवार में और परिवार के बाहर अधिक व्यापक सामाजिक स्तर पर महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाए, उनसे उचित और गरिमामय व्यवहार हो तथा उन्हें अपनी प्रतिभाओं के अनुकूल प्रगति के उचित अवसर मिलें। पुरुषों के उनसे संबंध न्यायसंगत, समानता और सहयोग के होने चाहिए न कि आधिपत्य और अपना स्वार्थ साधने के। विशेष ध्यान देने की बात है कि महिलाओं के प्रति हिंसा और दमन को समाप्त करने को घर और समाज, दोनों स्तरों पर उच्च प्राथमिकता मिले।

व्यापक सच्चाई तो यह है कि कई तरह के हिंसक कार्य को ही नहीं अपितु हिंसक सोच को भी समाप्त करने का नियंत्रित और अनुशासित प्रयास सभी मनुष्यों की प्रगति के लिए आवश्यक है। इस तरह के प्रयास व्यापक स्तर पर होंगे तो समाज, राष्ट्रों और विश्व स्तर पर अमन-शांति की स्थिति अपने आप बेहतर होगी, अमन-शांति के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार होगी। अंतिम और बहुत बुनियादी बात यह है कि नैतिकता की कसौटी पर अपनी सोच और अपने कार्यों को परखते रहना सभी मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। जब अधिकांश मनुष्य यह सोचने लगते हैं कि मुझे केवल अपने हित का ख्याल नहीं रखना है, दूसरों के हित का भी ख्याल रखना है, मुझे जाने-अनजाने ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिनसे समाज की क्षति होती है तो इस राह पर चलते हुए ही व्यक्तिगत प्रगति और पूरे समाज की प्रगति में परस्पर सामंजस्य एकता स्थापित होने लगती है।

यदि इन सभी दस सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए तो व्यक्तिगत प्रगति की राह और सामाजिक प्रगति की राह बहुत कुछ एक सी होने लगती है, व्यक्ति का अपना विकास समाज के व्यापक विकास से जुड़ जाता है। जहां तक संभव हो इस आदर्श स्थिति के नजदीक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।

खटाखट की राजनीति

मीडिया

सुधीश पचौरी

राजनीति के 'उपभोक्ताकरण' के समकालीन दौर में एक नई 'उपभोक्ता राजनीति' भी आई है :'खटाखट की राजनीति'! 'क्रीम/शेंपू' के लिए तो बंदे को 'पे' करना पड़ता है लेकिन दलों के ब्रांड यानी 'वायदे' एक एकदम 'फ्री' होते हैं। इन दिनों ऐसा 'खटाखट समाजवाद' बेचा जा रहा है जिसमें सब कुछ फ्री है

इन दिनों मीडिया की अधिकांश खबरें दुखदायी दिखती हैं। उनके मुकाबले 'विज्ञापन' अधिक सुखदायी लगते हैं। इसलिए मैं अक्सर विज्ञापन देखता रहता हूं और उन्हीं से समाज के मिजाज की खबर लेता देता रहता हूं। मेरा मानना है कि हर विज्ञापन दुख से सुख तक की सैर कराता है। वह दुख के नाम पर क्षणिक सुख की पुड़िया देता है। कुछ विज्ञापन देखें : -अगर चेहरे पर दाग ध्ब्बे हैं तो इस ब्रांड की क्रीम लगाइए और महीने भर में त्वचा को बेदाग होता पाइए...एक लड़की पहले काली सी दिखती है। वही क्रीम लगाकर चमकने लगती है। यह सब पंद्रह से बीस सेकंड में हो जाता है।-'बालों का टूटना मना है' कहने वाले ब्रांड का शेंपू/तेल को कुछ दिन लगाइए। एक सुंदरी हाथ में डंडा लिए आती है। दो गुंडों को चलते-चलते उड़ा देती है। फिर उसके बाल एक दरवाजे में उलझ जाते हैं। वह गरदन से झटका देकर बालों को दरवाजे की पकड़ से मुक्त करती है। कैमरामैन पूछता है मैडम, आप ठीक तो हैं तो वह मुस्कुरा कर कहती है कि जब ये ब्रांड है तब तक बालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह एक मकान पर धूल जमती है। एक पंडित आकर बताते हैं कि इस ब्रांड का 'पेंट' लगाओ तो धूल तो होगी लेकिन टिकेगी नहीं और हम देखते हैं कि धूल आती है लेकिन टिक नहीं पाती है।

इसी तरह एक विज्ञापन जून से पहले ही एक महिला को एक लाख देता दिखता है। एक लाख पाने की बात सुनकर दूसरी औरत बेहद खुश होकर दौड़ती चली जाती है। अंत एक दल का 'ब्रांड चिह्न' (चुनाव चिह्न) आता है। उसकी कैचलाइन भी आती है...। इसी तरह एक अस्पताल में एक पिता दाखिल है। एक भाई पैसा जुटाने के लिए चिंतित दिखता है तो बहन कहती है कि तू ये क्या कर रहा है। अब सरकार इलाज के लिए पच्चीस लाख दे रही है...। उसके बाद भाई खुशी से एकदम गद हुआ दिखता है। इसी तरह एक युवक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। माता-पिता पूछते हैं क्या हुआ, तो बेटा गद होकर कहता है कि पक्की नौकरी लग गई है। अंत में विज्ञापन देने वाले दल का 'ब्रांड चिह्न' आता है। ऐसे ही एक विज्ञापन में अपनी दुकान पर खड़ा युवा अपने पापा से कहता है जिसने हमें 'ऑनलाइन पेमेंट' की सुविधा दी क्या उसके लिए हम वोट भी देने नहीं जा सकते तो पापा खुश होकर कहता है हां, बारी-बारी से वोट डालने चलेंगे। फिर एक दल का 'ब्रांड चिह्न' आता है। सब कुछ पंद्रह सेकंड हो जाता है।

ऐसे ही एक विज्ञापन में कई किसान भी उसे वोट देने को कहते हैं जिसने उन्हें खुशहाली दी है। फिर दल का 'ब्रांड चिह्न' आता है। पंद्रह सेकंड में सब खुश नजर आते हैं...। चाहे उपभोक्ता वस्तुओं के 'ब्रांड' हों या 'दलों' के ब्रांड हों, सभी पंद्रह से बीस सेकंड में समस्या का समाधान करते हैं। हर ब्रांड ऐसे ही 'तुरंता सुख' देता है। जिस तरह से 'क्रीम/शेंपू' की भाषा तुरंता सुख की गारंटी देती है, उसी भाषा में राजनीतिक दलों के विज्ञापन भी देते हैं। आज हम जिस तरह से उपभोक्ता वस्तुओं का 'उपभोग' कर सुखी महूसस करते हैं, उसी तरह से आज राजनीति का 'उपभोग' करते हैं। स्पष्ट है कि अब हम पुरानी तरह की 'विचारधारात्मक' राजनीति में नहीं रहते। दलों के 'ब्रांड चिह्नों' में रहते हैं। अब हम विचार नहीं 'चुनते', दलों के 'ब्रांड चिह्नों' के वायदों को 'खाते-पीते' हैं। मारकेट के 'ब्रांडों' की तरह राजनीतिक दल भी हर सीजन में अपनी 'रिब्रांडिग' और 'रिलॉन्चिंग' करते रहते हैं। इसीलिए उनकी 'कैचलाइन' यानी 'नारे' बदलते रहते हैं लेकिन मूल धुन पुरानी ही रहती है।

हर उपभोक्ता ब्रांड हमें क्षणिक सुख तो देता है लेकिन स्थायी सुख नहीं देता। इसीलिए हम उसको फिर फिर खरीद कर अपने को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी तरह तुष्ट कभी नहीं होते! राजनीति के 'उपभोक्ताकरण' के समकालीन दौर में एक नई 'उपभोक्ता राजनीति' भी आई है :'खटाखट की राजनीति'! 'क्रीम/शेंपू' के लिए तो बंदे को 'पे' करना पड़ता है लेकिन दलों के ब्रांड यानी 'वायदे' एक एकदम 'फ्री' होते हैं। इन दिनों ऐसा 'खटाखट समाजवाद' बेचा जा रहा है जिसमें सब कुछ फ्री है लेकिन ये 'फ्री' कहां से आएगा। इसकी परवाह किसी को नहीं। 'अंधेर नगरी चौपट राजा' में तो सब माल एक भाव था। 'टका सेर भाजी' थी और 'टका सेर' ही 'खाजा' था। यहां तो भाजी भी फ्री है और खाजा भी फ्री। राजनीति का हम उपभोग कर रहे हैं या कि राजनीति ही हमारा उपभोग कर रही है। इसका पता ही नहीं चलता।

मोदी तीन-० की विदेश नीति

वैश्विकी

डॉ. दिलीप चौबे

यदि नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने यह सवाल होगा कि नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाएं। डोभाल की आयु करीब 80 साल है जो एनएसए के बड़े दायित्व को निभाने में बाधा बन सकती है। हालांकि उनके अनुभव और कार्यदक्षता को देखते हुए उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

भारत में अगले महीने की शुरुआत में सरकार गठन का काम संपन्न होगा जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत का भरोसेमंद दोस्त रूस चाहेगा कि नई सरकार की नीतियों में निरंतरता कायम रहे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात पर नजर रखेंगे कि अगला विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने। कहना न होगा कि एस. जयशंकर को लेकर पश्चिमी देश असहज हैं। लेकिन फिर भी उनका मानना है कि जयशंकर के साथ काम किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल उन देशों की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर अमेरिका ने जो जाल बुना है उसका निशाना डोभाल ही हैं। यदि नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने यह सवाल होगा कि नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाएं। डोभाल की आयु करीब 80 साल है जो एनएसए के बड़े दायित्व को निभाने में बाधा बन सकती है। हालांकि उनके अनुभव और कार्यदक्षता को देखते हुए उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि मोदी डोभाल को किसी अन्य दायित्व के साथ सलाहकार बनाए रखें तथा एनएसए के रूप में किसी अपेक्षाकृत कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त करें। इस नई व्यवस्था में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार की नीतियों की धार बनी रहे। विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की नियुक्ति प्रायः निश्चित है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अमेरिका ने विदेश मंत्री नटवर सिंह को पद से हटाने के लिए दबाव डाला था। तत्कालीन सरकार ने कथित घोटाले के नाम पर नटवर सिंह को उनके पद से हटा दिया था। इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख स्वयं नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक में किया है। दशकों पूर्व जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पश्चिमी देशों ने कृष्ण मेनन को भी ऐसे ही निशाना बनाया था। लेकिन मोदी सरकार किसी दबाव में झुकेगी इसकी संभावना नहीं है।

इस बीच जयशंकर ने एक राजनीतिक नेता जैसे तेवर अपना लिये हैं। अपने ताजा साक्षात्कार में उन्होंने 'इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग' का उल्लेख किया। यह गैंग भारत में ऐसे ही तत्वों के साथ मिलकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। जयशंकर के अनुसार इस गैंग में पश्चिमी देशों की मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, थिंक टैंक और मझोले दर्जे के सरकारी अधिकारी शामिल हैं। यह पहले अवसर है कि जब जयशंकर ने मोदी विरोधी तबके में सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की बात कही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रशासन ने जयशंकर के इस कथन पर मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। प्रकारांतर से जयशंकर ने इन देशों को आगाह किया है कि भारत की राजनीति में दखलंदाजी करने से बाज आएं। अमेरिका इस चेतावनी के मद्देनजर अपनी नीति में बदलाव करता है अथवा मौजूदा नीति पर ही अमल जारी रखता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। इस बीच चेक गणराज्य में गिरफ्तार निखिल गुप्ता की अमेरिका प्रत्यर्पण की कार्रवाई अंतिम चरण में है। गुप्ता के अमेरिका पहुंचने के बाद वहां अदालती कार्रवाई तेज हो जाएगी। अमेरिका पन्नू की कथित हत्या के प्रयास के सिलसिले में प्रथम साजिशकर्ता के प्रत्यर्पण की मांग भी कर सकता है। अमेरिका के अनुसार प्रथम साजिशकर्ता कथित रूप से भारत की विदेश खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) का अधिकारी था। नई सरकार अमेरिकी की इस मांग को निश्चित रूप से ठुकरा देगी। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि इस पेचीदा मामले से कैसे निपटा जाए। इस बीच चाबहार बंदरगाह और अफगानिस्तान फिर चर्चा में आ गए हैं। अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने भारत चाबहार समझौते का स्वागत किया है। नए घटनाक्रम में रूस ने चेतावनी दी है कि अमेरिका इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों में फिर सक्रिय कर सकते हैं। ये आतंकी गुट रूस और ईरान को निशाना बना सकते हैं और चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारे को निशाना बना सकते हैं।

एआई तकनीक से ही रुकेंगे हादसे

हिट एंड रन

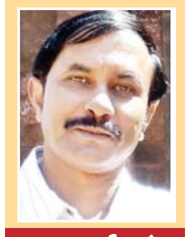

ऋतुपर्ण दवे

पुणे घटना की आज देश भर में चर्चा है। इस घटना का दूसरा पहलू भी है। आरोपी नाबालिग ने दोस्तों संग दो पबों में 69 हजार रुपयों का जाम छलकाया जिसके सबूत भी मिले। लेकिन हैरानी है कि मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव आई। अब पुणे में अवैध पब ढहाए जा रहे हैं, ये जिम्मेदारों को पहले क्यों नहीं दिखे? कैसे नाबालिगों को शराब परोसी गई? कानून की धज्जियां उड़ाने वाले सवालों की श्रृंखला में कई कड़ी हैं। दुर्घटना करने वाली 2 करोड़ से ज्यादा की पोर्स कार के रजिस्ट्रेशन के बारे में महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट विभाग का हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया। महज 1,758 रुपये की फीस नहीं चुकाने से कार का रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग था और विभाग खामोश। अब कहा जा रहा है कि आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस उम्र 25 साल पूरा तक नहीं बनेगा। लेकिन यह क्यों नहीं कोई बताता कि बिना लाइसेंस रईसजादा कैसे सड़क पर बेखौफ फर्राटे भर रहा था? क्या रईसजादोंको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती? क्या उन पर उम्र का बंधन नहीं होता? कानून के रक्षकों के शायद इसी दोहरे रवैये से रईस नाबालिगों के हिट एंड रन के हैरान करने वाले मामले सामने आते हैं, जो आम लोगों से भेदभाव करते हैं। लगता नहीं कि अपराध की गंभीरता देखी जानी चाहिए न कि उम्र? नये दौर में कानून में ऐसे सुधारों की दरकार है जिनमें आयु की जगह अपराध की गंभीरता और मंशा अहम हों। नाबालिगों के ऐसे-ऐसे अपराध सामने आने लगे हैं जो चिंताजनक हैं।

उन्नत तकनीक का दौर है। गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर के जंजाल से लेकर हर कहीं सैटेलाइट्स की जद है। टोलब्रिज पर फास्टटैग से भुगतान और वाहन के सारे डिटेल्स सर्वर को चंद सेकंड में मिल जाते हैं। अब असंभव नहीं कि हर शहर, कस्बे, सड़क, राजमार्ग पर इसी तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित हाई रिजॉल्यूशन स्पीड ट्रैप कैमरे, सेंसर और जरूरी उपकरण लगें, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर वक्त-बेवक्त ड्रोन कैमरों से सतत निगरानी हो। सारा कुछ जिम्मेदार विभाग या शहर, नगर, कस्बे, पंचायत और स्थानीय पुलिस थानों में बड़े स्क्रीनों पर देखा जा सके। पुलिस को बजाय सड़कों पर खड़ा करने के नियंत्रण कक्ष से ही सारी गतिविधियां ऑन कैमरा परखी-जांची जाएं। एआई तकनीक का ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम भी संदिग्ध, ओवरस्पीडिंग, बिना नंबर, बिना हेलमेट, या बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन निष्पक्षता और पारदर्शिता से ट्रैप कर पलक झपकते चाहे शहर हों या राजमार्ग, सारी सूचनाएं सर्वर, करीबी गश्ती दल, थाने या नाके तक पहुंचाएं। जरा सी भी आशंका पर अगले ठिकाने में संदिग्ध या कानून तोड़ता वाहन भी डिजिटल प्रमाणों के चलते जद में होगा।

लेकिन लगता नहीं कि यह अत्याधुनिक तकनीकों का दौर है। नियंत्रण कक्षों में उन्नत यंत्रों से आ रही सूचनाओं को देखना, जांचना और कार्रवाई संबंधी प्रणाली विकसित करना चाहिए ताकि कोई भी बेखौफ, रसूखदार, नशेड़ी, अपराधी एआई की निगाह से न बच पाए। रिकॉर्ड की नियमित उच्चस्तरीय ऑडिट, जांच-परख भी हो ताकि भेदभाव की गुंजाइश न रहे। यकीनन, संजयरूपी तीसरी आंख बिना भेदभाव काम करेगी जिसकी जद में सब होंगे तो क्या राजा, क्या रंक सब को अपनी हदों या औकात का पता होगा। लगता है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं या हिट एंड रन को रोकने के लिए यही सस्ता, प्रभावी और निष्पक्ष उपाय ही कारगर हो सकता है।

जान बचाकर भाग रहा जो

बतंगड़ बेतुक

विभांशु दिव्याल

वह हांफ रहा था, कांप रहा था मगर भाग रहा था, एक हाथ से उसने कसकर अपना लंगोट पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ जैसे खुद अपने वजूद पर जकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रहीं थीं, न जाने कैसी-कैसी झांइयां पड़ रहीं थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे, राष्ट्रीय झंडे की तरह कंपकंपा रहे थे। वह झल्लन की बगल से गुजरा तो झल्लन ने उसे रोक लिया, उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, 'भइया, कहां से आ रहे हो और बदहवास से कहां दौड़े जा रहे हो?' वह बोला, 'मुझे रोको मत झल्लन भाई, मुझे डर के पसीने आ रहे हैं, वे सब के सब मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं।' झल्लन बोला, 'गजब बात करते हो भाई, वे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ लगा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें डर के पसीने आ रहे हैं।' वह बोला, 'तुम नहीं समझ रहे हो झल्लन भाई, अगर उन्होंने अपने तरीके से मुझे पकड़ लिया और बचा लिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, जरूर मर जाऊंगा, इसलिए सोच रहा हूं कि किसी ऊंची पहाड़ी से खाई में छलांग लगा दूं और अपनी जान बचा लूं।' झल्लन बोला, 'भाई, या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो, ये क्या बात हुई कि खाई में कूदकर अपनी जान बचा रहे हो?'

वह बोला, 'देखो भाई, उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया है, मेरी आत्मा मार दी है, मेरी इज्जत उतार दी है, मेरे विचारों का खून कर दिया है, मेरे सारे कपड़े उतारकर मुझे नंगा कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ यह लंगोट बचा है जिसे मैं बचाना चाहता हूं, किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहता हूं।' झल्लन बोला, 'एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि वे तुम्हें बचाने आ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो तुम उनसे अपना लंगोट बचाने भाग रहे हो, ये उलटवासी क्यों दाग रहे हो?' वह बोला, 'झल्लन भाई, वे मुझे बचाने आ रहे हैं इसीलिए मैं उनसे बच रहा हूं और तुमसे जो कुछ कह रहा हूं, सच कह रहा हूं।'

झल्लन के चेहरे पर असंमजस के भाव उभर आये जो उस भागते व्यक्ति की नजर से बच नहीं पाये, वह बोला, 'भाई, मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा हूं, जो सच है वही तुम्हें बता रहा हूं। वे इसीलिए मुझे बचाने आ रहे हैं कि मुझे बचाकर मेरा लंगोट भी उतार ले जायें और मेरे पास अपनी इज्जत बचाने के लिए तिनके और तार तक न रह जायें।' झल्लन की समझ में कुछ नहीं आया, उसने अपना सर खुजाया और बोला, 'पर भाई, वे कौन हैं जिनसे तुम दूर भाग रहे हो, और वे कहीं तुम्हें बचा न लें इसलिए उनसे बचना चाह रहे हो?' वह बोला, 'तुम देख नहीं रहे हो, वे सब जो मेरे पीछे आ रहे हैं, सब अपने अलग-अलग झंडे लहरा रहे हैं, सब एक-दूसरे पर चीख-चिल्ला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि किसी दूसरे को मुझे बचाने का मौका नहीं देंगे, भले ही मेरा कुछ भी हो जाये मुझे बचाएंगे तो वे ही बचाएंगे और अगर कोई दूसरा बचाने की कोशिश करेगा तो उसकी जान पर आ जाएंगे।'

वह बदहवास सा इंसान अब उधर देख रहा था जिधर से तरह-तरह के मुंडों-मुस्टंडों, झंड़ों-डंडों वाली भीड़ बढ़ती चली आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि यह भीड़ नाच-गा रही थी या युद्ध की भेरी बजा रही थी। झल्लन ने ध्यान से देखा भीड़ में लाल, नीले, हरे, पीले झंडे लहरा रहे थे और सब अलग-अलग सुर-ताल में अपने-अपने झंडे झटकाते हुए नारे लगा रहे थे, सब एक-दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे थे और सब अपने-अपने अलग-अलग सुर-ताल में चिल्ला रहे थे कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे और लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम सत्ता में आएंगे। झल्लन बोला, 'भाई, ये तो सब इस मुल्क के राजनीतिक दल हैं जो इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि वे तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं?' वह बोला, 'झल्लन भाई, अब तो मुझे पहचानो, मैं वही अभागा लोकतंत्र हूं जो इनसे बचने के लिए भाग रहा हूं, अगर अब इनसे नहीं बच पाऊंगा तो अपनी लंगोटी भी नहीं बचा पाऊंगा और जीते जी मारा जाऊंगा।'

वह बदहवास सा इंसान अब उधर देख रहा था जिधर से तरह-तरह के मुंडों-मुस्टंडों, झंड़ों-डंडों वाली भीड़ बढ़ती चली आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि यह भीड़ नाच-गा रही थी या युद्ध की भेरी बजा रही थी। झल्लन ने ध्यान से देखा भीड़ में लाल, नीले, हरे, पीले झंडे लहरा रहे थे और सब अलग-अलग सुर-ताल में अपने-अपने झंडे झटकाते हुए नारे लगा रहे थे, सब एक-दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे थे और सब अपने-अपने अलग-अलग सुर-ताल में चिल्ला रहे थे कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे और लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम सत्ता में आएंगे। झल्लन बोला, 'भाई, ये तो सब इस मुल्क के राजनीतिक दल हैं जो मुल्क के लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि वे तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं?' वह बोला, 'झल्लन भाई, अब तो मुझे पहचानो, मैं वही अभागा लोकतंत्र हूं जो इनसे बचने के लिए भाग रहा हूं, अगर अब इनसे नहीं बच पाऊंगा तो...

तल्खी -

लिये कटारी नाच रही है राजनीति ता ता थैया
जान बचाकर भाग रहा जो लोकतंत्र ही है भैया
लंबी यात्रा पर निकला है बैठ गया है गाड़ी में
वो ही गाड़ी जिस गाड़ी का पंचर है पहिया पहिया
कौन तय करे घटिया थोथी क्षुद्र सियासत है किसकी
सबकी थू थू है औरों पर, खुद हो-हो हैया-हैया
चीख-चीख कर भीड़ जुटा ले यह जम्हूरियत उसकी है
बाकी तो सब मजबूरी में खेल रहे खो-खो खैया
अपने घर की हैवत उनको जन्नत जैसी लगती है
उधर अगर आवाज उठे तो हाय-हाय दैया-दैया
जो विचारधारा ले कूदे उसमें कहीं विचार नहीं
कोई यदि आइना दिखा दे चीख उठें मैया मैया

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 282 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

अपनी आर्थिक नाकामियों को ढांपने की गरज से नेहरूवादी कांग्रेस ने हिन्दू विकास दर ईजाद की थी। मोदी वास्तविक हिन्दू आर्थिक उभार ले आए। राहुल अर्थव्यवस्था की पुरानी समाजवादी अवधारणा की ओर लौटना चाहते हैं। हिन्दुओं से संपत्ति लेकर इसे सोरोस एंड कंपनी को सौंप दिया जाएगा।
—डेविड फ्राउले, धर्मज्ञ@davidfrawleyved

योग निद्रा

संजीव चतुर्वेदी

अवचेतन मन में छुपा है स्वास्थ्य का राज

हमेशा से ही समाज अपयोगनिद्रा-अवचेने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है, और उसके लिए विभिन्न उपाय भी करता है। आधुनिक विश्व पटल पर भी हम पाते हैं कि लोग स्वस्थ रहने के लिए अपनी सुविधानुसार उपलब्ध चिकित्सा पद्धतियों को अपनाते हैं। हालांकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने बहुत उन्नति की है, और बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम करने में सहायता भी मिल रही है लेकिन उन्नत आधुनिक चिकित्सा के बावजूद ज्यादातर लोगों को पैसा खर्च करने के बाद भी राहत नहीं मिल पाती। या तो उन्हें प्राण से हाथ धोना पड़ता है या बीमारियों के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। उन्नत तकनीक द्वारा बीमारियों का पता लगा कर जरूरत के अनुसार उपचार किया जाता है। कभी दवा दी जाती है तो कभी सर्जरी की जाती है। सही समय पर बीमारी का पता चल जाए तो उपचार द्वारा ठीक हो सकता है लेकिन बहुत से मामलों में पता ही नहीं चलता है। खासकर कोविड महामारी के बाद कम उम्र के लोगों में भी हृदयाघात की समस्या आम हो गई है क्योंकि ज्यादातर बीमारियां मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक अस्थिरता के कारण होती हैं, जिनका सटीक इलाज आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं कर पा रही है। इसलिए लोग या तो असमंजस में हैं, या असहाय महसूस कर रहे हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा और जीवन पद्धति

ज्यादातर शोधों से पता चलता है कि गलत खान-पान और रहन-सहन या दिनचर्या ही बीमारियों के मुख्य कारण हैं। हम अपने खान-पान और दिनचर्या को सही कर लें तो बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यौगिक जीवन पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए खान-पान और दैनिक क्रियाकलाप को व्यवस्थित करके कुछ योग अभ्यासों को अपनी नियमित दिनचर्या में सम्मलित करना आवश्यक है।

योग निद्रा क्या है

महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अनुसार जो पांचवा अंग है उसे प्रत्याहार कहते हैं। योग निद्रा प्रत्याहार का एक अभ्यास है, जिसमें इन्द्रियों का मन से संबंध विच्छेद हो जाता है। योग निद्रा का शाब्दिक अर्थ है सजगतापूर्वक निद्रा की अवस्था, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं।

हमारे मन की तीन अवस्था होती हैं-चेतन, अवचेतन और अचेतन। अवचेतन मन को स्वप्नावस्था भी कह सकते हैं। यह हमारे मन की सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है, जिसका उपयोग हम व्यक्तित्व को स्वस्थ और सकारात्मक बनाने में कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने मुख द्वारा स्थूल आहार लेते हैं, और वो पाचन तंत्र की सहायता से ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार इन्द्रियों की सहायता से भी हमारा मन सूक्ष्म आहार ग्रहण करता है, जिसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। इन्द्रियां जो भी ग्रहण करती हैं, वो हमारे अवचेतन और अचेतन मन में विचारों, भावनाओं, दृश्य या घटनाओं अथवा यादाश्त के रूप में संग्रहित रहता है। इसका प्रभाव हमेशा हमारे मन और शरीर पर बना रहता है। यह नकारात्मक हुआ तो इसका बुरा प्रभाव हमें मानसिक और शारीरिक बीमारियों के रूप में नजर आता है। हमेशा नकारात्मक विचारों या घटनाओं से मानसिक रूप से जुड़े रहने के कारण ही लोग अनिंद्रा, डर, तनाव, भावनात्मक अस्थिरता, उच्च रक्तचाप,मधुमेह, अपच, कब्ज, कैंसर, डिप्रेशन, हृदयरोग, मस्तिष्काघात आदि से पीड़ित होते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति मरीजों को बचाने का प्रयास करती है लेकिन बीमारियों को जड़ से खत्म करने में अपने को असमर्थ पाती है और मरीजों को पूरी जिंदगी दवा के सहारे अपनी नियति मान कर बितानी पड़ती है, और बहुत से लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है।

योग निद्रा के अभ्यास द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं से अपने मन को अलग कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा मन और शरीर इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किए गए आहार के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रहते हैं, और हम शांत, स्थिर, शिथिल और ऊर्जावान महसूस करते हैं।

योग निद्रा की विधि

योग निद्रा करने की विधि सरल और सुविधाजनक है। शिक्षक के साथ की जा सकती है। शिक्षक उपलब्ध न होने पर रिकार्डेड ऑडियो निर्देश द्वारा भी की जा सकती है। इसका अभ्यास हम कहीं भी शांत और साफ-सुथरी जगह पर पीठ के बल लेटकर (शवासन) या बैठकर भी कर सकते हैं क्योंकि इस अभ्यास के निर्देशों का पालन सिर्फ मानसिक रूप से करना होता है, इसलिए बच्चे, जवान, बूढ़े, मरीज या गर्भवती महिलाएं भी आसानीपूर्वक कर सकते हैं। खासकर वैसे मरीज जिनका सर्जरी हुई हो, कैंसर या हृदयरोगी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के रोगी और वैसे मरीज जो शारीरिक रूप से सक्षम न हों, वो भी कर सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक-मानसिक रूप से शांत और शिथिल हो जाता है।

नकारात्मक और अनियंत्रित विचारों से मुक्त होने के कारण अच्छी नींद आती है, जिससे हमारी तंत्रिका प्रणाली तथा हॉर्मोन के स्राव में सामंजस्य स्थापित होता है। वैसे तो योग निद्रा का पूर्ण अभ्यास 30-45 मिनट का होता है लेकिन जरूरत के अनुसार इसका संक्षिप्त रूप भी किया जा सकता है। नियमित रूप से इसका अभ्यास न सिर्फ नकारात्मक विचार और भावनाओं से मुक्ति दिलाकर विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन में काम आता है, बल्कि स्वस्थ और सकारात्मक व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है।

योग निद्रा का उपयोग सभी उम्र और वर्गों के लिए जरूरत के अनुसार किया जा सकता है। जब हम अपने अवचेतन और अचेतन मन में पूर्व की संग्रहित नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाते हैं। तब हमारा अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है तथा हम जो भी सकारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक विचार का बीजारोपण करते हैं, वही हमें स्वस्थ, प्रसन्नचित और रचनात्मक व्यक्तित्व का फल प्रदान करता है। कोई शिक्षक उपलब्ध न हो तो आप इसे यूट्यूब या अन्य माध्यमों की सहायता से भी कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऑडियो-वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन मेरी समझ के अनुसार स्वामी सत्यानंदजी एवं स्वामी निरंजन जी (जो बिहार स्कूल के संस्थापक भी हैं) द्वारा निर्देशित योग निद्रा का अभ्यास ज्यादा सटीक है।

(लेखक थाईलैंड स्थित 'डिवाइन योग' के सह संस्थापक हैं) ■

हमारे मन की तीन अवस्था होती हैं-चेतन, अवचेतन और अचेतन। अवचेतन मन को स्वप्नावस्था भी कह सकते हैं। यह हमारे मन की सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है, जिसका उपयोग हम अपने व्यक्तित्व को स्वस्थ और सकारात्मक बनाने में कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने मुख द्वारा स्थूल आहार लेते हैं, और वो पाचन तंत्र की सहायता से ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार इन्द्रियों की सहायता से भी हमारा मन सूक्ष्म आहार ग्रहण करता है, जिसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। इन्द्रियां जो भी ग्रहण करती हैं, वो हमारे अवचेतन और अचेतन मन में विचारों, भावनाओं, दृश्य या घटनाओं अथवा यादाश्त के रूप में संग्रहित रहता है, जिनका प्रभाव मन-शरीर पर बना रहता है। यह नकारात्मक हुआ तो इसका बुरा प्रभाव मानसिक-शारीरिक बीमारियों के रूप में दिखता है

यात्रा वृत्तांत

डॉ. अनिल चन्दोला

अद्भुत है आदि कैलाश यात्रा

समुद्र तल से लगभग 5945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश भारत के उत्तराखंड राज्य में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में चीन सीमा के नजदीक है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध ओम पर्वत भी स्थित है। आदि कैलाश देखने में बिल्कुल कैलाश की ही तरह दिखता है। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदि कैलाश में भगवान शिव एवं माता पार्वती का निवास स्थान है और आदि कैलाश के समीप पार्वती सरोवर है। कहा जाता है कि माता पार्वती इस सरोवर में स्नान के लिए आती थीं। पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आदि कैलाश दर्शन और पार्वती सरोवर/मंदिर की यात्रा करने से पिथौरागढ़ जिले में स्थित इस शिव धाम की देश-दुनिया में व्यापक ब्रांडिंग हुई है। कैलाश के प्रवेशद्वार गुंजी गांव में शिवधाम बनाने की योजना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसके लिए 75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

गूंजी से बाई ओर लगभग 40 किमी. दूरी पर आदि कैलाश और दाई ओर लगभग 18 किमी. की दूरी पर ओम पर्वत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी यही मार्ग रहा है और 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़-धारचूला-लिपुलेख से होकर चलती थी। 2019 के पचात इस मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद होने से अब यात्री भारी संख्या में आदि कैलाश की यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा अप्रैल/मई से अक्टूबर तक संचालित होती है। गत वर्ष 13 हजार से अधिक यात्रियों ने आदि कैलाश की यात्रा की है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरह ही आदि कैलाश यात्रा का महत्त्व है और यह पंच कैलाशों में एक कैलाश है। स्कन्ध पुराण के मानसखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को कैलाश-मानसरोवर यात्रा के बराबर का महत्त्व दिया गया है। आदि कैलाश की यात्रा के लिए हल्द्वानी-काठगोदाम-अल्मोड़ा होकर पिथौरागढ़ या फिर टनकपुर-चम्पावत होकर पिथौरागढ़ आना पड़ता है। यहां से धारचूला आते हैं। धारचूला तहसील मुख्यालय है और यहां से गुंजी की दूरी लगभग 72 किमी. है। गुंजी से ही आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा आगे बढ़ती है। इनर लाइन में होने के कारण इस क्षेत्र की यात्रा बाहरी व्यक्ति/यात्री परमिट लेकर ही करते हैं। एसडीएम कार्यालय धारचूला से परमिट प्राप्त किया जाता है। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी 90 किमी. है।

धारचूला से उच्च हिमालयी क्षेत्र की अदभुत रोमांचकारी यात्रा शुरू होती है। पहाड़ी के नीचे कल कल बहती काली नदी यात्रा का रोमांच और भी बढ़ा देती है। छियालेख में स्थित आईटीबीपी की चैक पोस्ट पर यात्रियों के परमिट की जांच कर ही आगे यात्रा की अनुमति दी जाती है। छियालेख से सड़क बिल्कुल नीचे पाताल की तरफ जाती है, जिसमें कई मोड़ यात्रा का रोमांच और भी बढ़ा देते हैं। अनेक मोड़ से गुजरने के पश्चात ब्यास घाटी के गर्बियांग, बूंदी गुंजी, नाबि, कुटी, नपलच्यूं आदि गांव आते हैं। ब्यास घाटी में 7 गांव हैं, जिनमें अंतिम गांव कुटी है। शीत ऋतु में इन गांवों के निवासी धारचूला चले जाते हैं। गुंजी/नपल्यूं में काली नदी का संगम कुटी नदी से होता है, स्थानीय भाषा में नदी को यागंति कहते हैं। गुंजी से लगभग 02 किलोमीटर की दूरी पर नाबि गांव है, जहां यात्रा काल में खूब रौनक रहती है। आदि कैलाश की यात्रा के लिए नाबि गांव से आगे बढ़ा जाता है, जहां पर इस घाटी का अंतिम गांव कुटी आता है, कुटी से बर्फीले मार्ग से आगे बढ़ते हुए 4572 मी. की ऊंचाई पर ज्योलीकांग आता है, जहां से बिल्कुल सामने आदि कैलाश के दर्शन होते हैं।

हिमाच्छित चोटियों के मध्य भगवान शिव का यह धाम छोटा कैलाश अद्भुत है, जो ब्रहम पर्वत के समीप स्थित है। ज्योलीकांग में सेना का शिविर है। ज्योलिकांग का तापमान शून्य डिग्री से नीचे रहता है। ज्योलीकांग से ट्रैकिंग करते हुए लगभग 3 से 4 किमी. दूर पर पार्वती सरोवर है और इसके पास ही एक मंदिर है। इसके पास ही गौरीकुंड है।

पार्वतीकुंड उच्च हिमालयी क्षेत्र में 4497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पार्वती मंदिर/कुंड से बिल्कुल सामने आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। इस वर्ष ओम पर्वत एवं आदि कैलाश हवाई दर्शन की योजना भी शुरू हो गई है। नैनीसैनी हवाई पट्टी (जनपद पिथौरागढ़) हवाई पट्टी से यात्रियों को इन स्थलों के हैलीकाप्टर से दर्शन कराए जा रहे हैं। ब्यास घाटी का यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। केंद्र एवं राज्य सरकार इसके विकास के लिए पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। इस क्षेत्र में एक पावर हाउस का निर्माण अंतिम चरण पर है, जिससे इस क्षेत्र में एक नई रोशनी पहुंचेगी। अभी इन गांवों में सोलर प्रकाश की व्यवस्था है। ■

तृप्ति मित्रा : इप्टा के इब्तिदाई दौर की अदाकारा

तृप्ति मित्रा, भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा से इब्तिदाई दौर में जुड़ने वाली अदाकारा में से एक हैं। 25 अक्टूबर, 1925 को पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में जन्मी तृप्ति मित्रा की शुरु आती तालीम दिनाजपुर में हुई। उन्होंने अपनी आला तालीम कोलकाता में हासिल की। उन्होंने पहली बार 1943 में बिजन भट्टाचार्य, जो रिश्ते में उनके चचेरे भाई लगते थे, के नाटक 'अगुन' (फायर) में अभिनय किया। यह वह दौर था, जब 'इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन' यानी इप्टा की स्थापना हुई। 1943 में बंगाल के अंदर भयानक अकाल पड़ा। अकाल पीड़ितों की मदद के लिए इप्टा आगे आया। बिजन भट्टाचार्य ने इन हालात को केंद्र में रख कर 'जबानबंदी' और 'नबान्न' जैसे संवेदनशील ड्रामे लिखे। इन दोनों नाटक में तृप्ति मित्रा ने भी अभिनय किया। नाटक के आखिर में अकाल पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता, जिसमें लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते।

आगे चलकर जब भारतीय जन नाट्य संघ ने अपनी पहली फिल्म 'धरती के लाल' बनाने का फैसला किया, तो निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने शंभु मित्रा के साथ तृप्ति मित्रा को भी फिल्म के अहम किरदार के तौर पर चुना। बिजन भट्टाचार्य के नाटक 'नबान्न' और अफसाना निगार कृश्न चंदर की कहानी 'अन्नदाता' पर केंद्रित यह फिल्म व्यावसायिक तौर पर तो कामयाब नहीं रही, लेकिन इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। देश की यह पहली यथार्थवादी फिल्म थी, जिससे सत्यजित राय भी बेहद प्रभावित थे। 'धरती के लाल' के बाद, तृप्ति मित्रा के लिए रंगमंच के साथ-साथ सिनेमा के भी रास्ते खुल गए। वे दोनों जगह अदाकारी करती रहीं। दिसम्बर, 1945 में तृप्ति ने 'नबान्न' के अपने साथी कलाकार शंभु मित्रा से शादी कर ली।

1948 में शंभु मित्रा और तृप्ति मित्रा ने 'बहुरूपी' नाम से अपना खुद का थिएटर समूह स्थापित कर लिया। अपने पति शंभु मित्रा के साथ तृप्ति मित्रा ने तकरीबन तीन दशक तक थिएटर किया। 1953 में उनकी पहली बांग्ला फिल्म 'पथिक' आई। उन्होंने एक के बाद एक कई बांग्ला फिल्मों में अदाकारी की। 'मोयला कागज' (1954), 'रिक्शा-वाला' (1955), 'आशा' (1956), 'शुभविवाह' (1959), 'माणिक' (1961), 'सूर्यस्नान' (1962), 'कंचनरंगा' (1964), 'सेबा' (1967) तृप्ति मित्रा की कुछ अहम फिल्में हैं। 'गोपीनाथ', 'मुन्ना' अहम हिन्दी फिल्म थीं। मित्रा ने उर्दू जबान की एक अहम फिल्म 'जागो हुआ सवेरा' में भी अदाकारी की। 1962 में उन्हें 'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' के लिए चुना गया, तो साल 1971 में तृप्ति मित्रा को 'पद्मश्री' सम्मान से नवाजा गया। 24 मई, 1989 को चौंसठ साल की उम्र में तृप्ति मित्रा का निधन हो गया।

प्रस्तुति : जाहिद खान ■

राग रंग आलोक पराड़कर

गंगा तट, पूर्णिमा और संगीत

बनारस में गंगा तट और संगीत की स्वरलहरियों का गहरा रिश्ता रहा है। घाट किनारे बने मंदिरों में संगीत समारोहों की परंपरा रही है, बुढ़वा मंगल जैसे आयोजन गंगा में नौकाओं पर होते रहे हैं। आज भी संगीतप्रेमी अक्सर नौकाओं पर निकल जाते हैं, और गाते-बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गंगा किनारे बालाजी मंदिर में घंटों रियाज किया करते थे और बाद में जब यहां नहीं आ पाते थे तो इन दिनों को याद कर भावुक हो उठते थे। राजेंद्र प्रसाद घाट पर बने मंच पर लंबे समय तक आयोजित हुए गंगा महोत्सव में कलाकारों के लिए यह परिवेश भी आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। प्रख्यात संतूर वादक पं. शिव कुमार शर्मा तो पीछे गंगा और आगे घाट की सीढ़ियों पर बैठे संगीत रसिकों के बीच वादन को अविस्मरणीय मानते रहे हैं, और बनारस के बाहर भी अक्सर इसका जिक्र करते थे। अब यह महोत्सव रविदास घाट की ओर चला गया है। उधर, आज भी अस्सी घाट पर सुबह-ए-बनारस का आयोजन प्रति दिन होता है, जिसमें कलाकार गंगा तट पर संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

बनारस, गंगा का तट और संगीत की स्वरलहरियों का मिलाप राम छाटपार शिल्प न्यास में हर माह आयोजित होने वाले संगीत पूर्णिमा में भी होता है, जब पूर्णिमा में पूरे खिले चांद की चांदनी के साथ स्वरलहरियां अठखेलियां करती हैं। न्यास का सामने घाट स्थित परिसर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय से सेवानिवृत्त नगर के शिल्पकार मदन लाल के परिश्रम का प्रतिफल है, जिन्होंने गंगा किनारे एक ऐसी जगह विकसित की है, जहां देश-विदेश के कलाकार जुटते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, कलाओं पर चर्चा करते हैं, और सहोदर कलाओं के रूप में संगीत, रंगमंच से जुड़े आयोजन भी होते हैं। करीब तीन दशकों की यात्रा के बाद न्यास का यह परिसर अब इस रूप में प्रशंसित हो चला है कि जहां कलाकारों को अपनी कलाओं के प्रदर्शन और न्यास की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता से फख्र होता है। यह परिसर अक्सर युवा एवं वरिष्ठ, उभरते और नामचीन कलाकारों की उपस्थिति से गुलजार रहता है।

राम छाटपार ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से मूर्तिकला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की थी। उन्होंने करीब सात वर्ष तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय में पढ़ाया लेकिन उन्हें महज 34 वर्ष की अल्प आयु मिली। मदनलाल उनके छात्र रहे। 1978 में राम छाटपार के निधन के बाद 1989 में इस न्यास का गठन हुआ और फिर धीरे-धीरे इसने आज का यह स्वरूप हासिल किया जिसमें कलाकृतियों के महत्त्वपूर्ण संग्रहालय के साथ ही कला गतिविधियों के कलादीर्घाएं और मुक्ताकाशी मंच हैं, जिनमें कला प्रदर्शनियां, संगोष्ठी, संगीत एवं रंगमंच के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। न्यास की इस यात्रा में शंखो चौधरी सहित देश-विदेश के कई कलाकारों का सहयोग मिला है। न्यास की योजना गुरुकुल अकादमी, पुस्तकालय आदि की भी है। कलाकारों के लिए आर्टिस्ट रेजीडेंसी भी है। कला प्रदर्शनियों, शिल्पोत्सव, रेत संगोष्ठी, बाल कला दिवस के साथ ही न्यास का मासिक आयोजन संगीत पूर्णिमा का है, जिसमें देश-विदेश के कलाकार हिस्सा लेते हैं।

गंगा किनारे न्यास के परिसर में संगीत पूर्णिमा के आयोजन ने भी लंबी यात्रा कर ली है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर इसके कार्यक्रम श्रृंखला की 34वीं कड़ी थी। संगीत पूर्णिमा के पिछले आयोजनों में के. शशि कुमार, मधुमिता भट्टाचार्य, चंदा रानी, मधुछंदा दत्ता, सिद्धार्थ मिश्र, आशुतोष भट्टाचार्य, श्रद्धा गुप्त,मैत्रेयी मजुमदार, तन्वी गोस्वामी (सभी गायन), वी. बालाजी-अनंत रमन (वायलिन जुगलबंदी), राजेश शाह-अंजलि शर्मा (सितार जुगलबंदी), अभिजीत राय चौधरी (सरोद), पुंडलिक कृष्ण भागवत (एकल तबला), कमला शंकर (गिटार), निर्मल सैनी (गिटार),भूषण कोस्ती (सुरबहार), कुमार सारंग (संतूर), श्रीरंजनी एस (भरतनाट्यम), आली प्रकाश (कथक) सहित कई कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी हैं। जापानी कलाकारों ने भी यहां भारतीय संगीत का प्रदर्शन किया है।

बुद्ध पूर्णिमा पर 23 मई को आयोजित संगीत पूर्णिमा का कार्यक्रम मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित था जिसमें वर्षा की हल्की फुहारों के कारण व्यवधान भी आया और फिर इसका स्थान बदलना पड़ा लेकिन इसमें संगीत प्रेमियों ने देर तक संगीत कार्यक्रमों का आनंद लिया। संगीत पूर्णिमा का पहला कार्यक्रम सूरत से आए निषाद मिस्त्री का सितार वादन था। उन्होंने 'पूरिया कल्याण' राग में आलाप, जोड़, झाला तथा तीन ताल में गतें प्रस्तुत कीं। ज्ञानस्वरूप मुखर्जी की तबला संगति थी। बाद में मंगलूर की शुचिता होला का गायन हुआ जिन्होंने कर्नाटक संगीत प्रस्तुत किया। उनके साथ वायलिन पर सुखदेव प्रसाद मिश्र और मृदंगम पर बी. सत्यवार प्रसाद ने संगत की। संगीत पूर्णिमा के आयोजन के साथ ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग से सेवानिवृत्त डी.पी. मोहंती के चित्रों की एकल प्रदर्शनी 'मिस्टीरियस वाराणसी' का भी आयोजन था। इन कार्यक्रमों विजय सिंह, अजय उपासनी, राजेश शाह, सुनील विश्वकर्मा, ब्रजराज पांडेय, सुरेश चंद्र जांगिड़ सहित कई संस्कृतिकर्मी उपस्थित थे। संचालन आदित्य दीप ने किया। ■

कैनवस जय त्रिपाठी

अर्थ से भरी प्रकृति

कला की सबसे बड़ी सीमा यह होती है कि इसकी दृष्टि आत्मपरक होती है। जिसे कला की संपूर्णता तो नहीं कह सकते परंतु कला की यह विशेषता होती है कि उसकी कलात्मक भाषा पारिभाषिक शब्दावली से मुक्त होती है। कला में रचनात्मक रहना कलाकार की दृष्टि व उससे उपजे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और जब दृश्य कलाकार के दृष्टिकोण में वैचारिक तत्व उसके रचनात्मक प्रवाह में परिवर्तन लाते हैं तो युवा महिला चित्रकार **तवलीन कौर लाल** के अमूर्त चित्रों से एक मूल्य चेतना जागृत होती है।

विगत सप्ताह नई दिल्ली की श्रीधरानी कला दीर्घा में प्रकृति के करीब पहुंच कर अपनी वेदनाओं को गढ़ती तवलीन लाल के अंर्तमन से उपजे रंगों के एक अमूर्त संसार को दर्शाते चित्रों की एकल प्रदर्शनी 'सेंटरिक ब्लैक' शीर्षक से प्रदर्शित थी। प्रदर्शनी के क्यूरेटर वरिष्ठ कलाकार मोहन सिंह थे जो कि तवलीन के मैंटौर भी हैं। युवा चित्रकार अपनी रचनात्मक दृष्टि के माध्यम से अमुर्त चित्रों में काले स्याह रंग का जिस तकनीक और अन्य रंगों का प्रयोग करके करती हैं वह उनकी कला समझ को दर्शाते हैं। चित्रकार की कलात्मक विधा और कला तत्वों के स्तर पर चित्रों की रचनात्मकता कई तरह के आंतरिक संकेतों को आत्मसात किए हुए है। कलाकार ने अमूर्त कला के माध्यम से रंगों की कई सतहों के ऊपर काले रंग का पारदर्शी प्रयोग करके अपने अतंर्मन और प्रकृति जैसे भारतीय दर्शन से अपनी कला अभिव्यक्ति को रचा। जब हम दर्शन की बात करते है तो दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना यह सामान्य देखना ही नही है , बल्कि हम किसी वस्तु को किस तरफ या किस तरह से देख पाते हैं। यह विचार चित्रकार तवलीन के चित्रों में रहता है।

कलाकार को अपनी कलाकृति के माध्यम से खुद को जानना समझना सीखना होता है क्योंकि खुद को जानने की इच्छा का कोई अंत नहीं है वैसा ही इनके के चित्रों को देखकर प्रतीत होता है। इस कलाकार का माध्यम ड्राइंग हो अथवा पेंटिग,यह अपने-अपने माध्यमों में प्रभाव पैदा करते हैं। युवा तवलीन लाल अपने रचनात्मक कला विस्तार व प्रतिबद्धता को कलात्मकता से रचती दिखाई देती हैं। विषय की गम्भीर पकड़, कलाकार की कलात्मक क्षमता व रचनात्मक दृष्टि को दर्शाती है। कई रंगों की परतों में स्याह आकृतियों के रूप कलाकार की एक अनोखी छाया प्रकाश की रची दुनिया में दर्शक को ले जाते है। उजले और स्याह टोन के साथ परत-दर-परत रंगों की भाषा कृतियां में प्रकृति के कई तरह के अर्थ को दर्शाती है। अर्थ से भरी चित्रकार की अमूर्तता दृश्य और भाव में एक सामान्तर आकृति के रूप में भी विविधता लिये हुए है,संभवतः यहीं अर्थ चित्रकार को नयी रचना गढ़ने के लिये प्रेरित करता है।

पवन कुमार डी के चित्रों को देखपर यह विचार आता है कि हर वस्तु कला है और वह हर वस्तु में कला देखते हैं। उनके नवीनतम लैंडस्केप देखकर लगता है प्रकृति और रोजमर्री के परिवेश को ध्यान से देखते हैं। कलाकार पवन को सुंदरता देखना पसंद है अतः यह अपने आस-पास की चीज़ों को सुंदर और आकर्षक रूप में रचते हैं। क्योंकि उनके चित्र दिलचस्प लगते हैं और प्रेक्षक देखकर उनसे जुड़ाव महसूस करता है अतः'एटेलियर' शीर्षक से प्रदर्शित पवन कुमार की यह एकल चित्र प्रदर्शनी मुख्यतः जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। विषय को बांधना और चित्रण को नियंत्रित करना इस युवा कलाकार की अच्छी समझ को दर्शाता है। प्रकृति और लोगों के बीच के कला अतंराल का अभ्यास कर रहे पवन वर्तमान में गढ़ी आर्टिस्ट स्टूडियो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में काम कर रहे हैं। यह युवा कलाकार अपने आस-पास के दृश्यों को चित्रित करता है,एवं लाल, अल्ट्रामरीन नीला, पीला और नारंगी आदि जैसे जीवंत रंगों का प्रयोग करके दृश्य को गढ़ता है। पवन लिए अनुभव का अर्थ अधिक समय व्यतीत करना और उस समय भावनाओं को तेजी से रंगों के माध्यम से अनुवाद करने के लिए कड़ी मेहनत करना है।

पवन की कलाकृतियां रंगों के विविध व सूक्ष्म प्रयोग और आकृतियों से दर्शक को आकर्षित करती हैं। चटख रंग और टैक्चर के प्रयोग के साथ आकृतियों में जीवंतता लाती हैं। प्रकृति के प्रति संवेदनशील चित्रकार पवन कुमार आज के समय में भी प्राकृतिक रूप से प्रकृति के करीब दिखते हैं, ऐसे में जब यह कलाकार अपनी इस अनुभूति को रचनात्मकता के साथ तथा प्रकृति और मनुष्य के संबंधों की प्रगाढ़ता को चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास करे तो कलाकार की अंर्तवेदना का भाव उसकी कृतियों में आना स्वाभाविक है। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की एनक्सी गैलरी की दीर्घा में 'एटेलियर' शीर्षक से प्रदर्शित एकल चित्र प्रदर्शनी में कलाकार कुमार के मूर्त चित्रों में रंगों का प्रयोग सुखद वातावरण का अहसास कराते हैं। इनके चित्रों में रोज दिखाई देने वाले के साथ-साथ दृश्य गढ़ी स्टूडियो के अंदर और बाहर के दृश्य भी हैं। प्रकृतिवादी, चिंतन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्त्व मानती है, इसी मूल तत्व को कलाकार ने अपने चित्रों में रंगों के कलात्मकता प्रयोग से अपनी रचनात्मक शैली में चित्रित किया है। ■

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

अकेला पड़ रहा इजराइल

यूरोप के तीन देशों द्वारा फिलीस्तीन को मान्यता देने से आग बबूला इजराइल ने इन तीनों देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। ये घटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर अब इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जिद के चलते वह गाजा पर हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका भी अब उसकी मदद को ज्यादा उत्सुक नहीं है। खास बात यह है कि जिन तीन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उनमें से स्पेन और स्वीडन तो अमेरिकी सैन्य संगठन नाटो के सदस्य हैं। मंगलवार को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने घोषणा की है कि वो औपचारिक रूप से अगले सप्ताह से फ़िलस्तीन को एक राष्ट्र रूप में मान्यता दे देंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गार स्तोर ने कहा कि उनका देश फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर 28 मई को मान्यता देगा। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा है कि इसराइल दो-राष्ट्र समाधान को जोखिम में डाल रहा है। उन्होंने फ़िलस्तीन पर इसराइल की नीति को दर्द और तबाही की नीति कहा है। इसराइल ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इन तीन देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। इसराइली सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मान्यता दिए जाने से न तो फ़िलस्तीनी लोगों को मदद मिलेगी और न ही इसराइलियों को। इसराइल के विदेश मंत्री काट्ज़ ने कहा कि ये 'हमास के हत्यारों को स्वर्ण पदक देने' जैसा है। वहीं हमास और फ़िलस्तीनी अथॉरिटी ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है। अरब देशों ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया है। दरअसल हमास द्वारा अक्टूबर में इजराइल पर किए हमले और दो सौ से अधिक लोगों को बंदी बनाए जाने के बाद इजराइल के प्रति जो सहानुभूति दुनिया भर में उपजी थी, वह अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 1200 इजराइलियों के बदले वो 35 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार चुका है। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं, जिनका हमास की आंतकी गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं है। इस नरसंहार के चलते दुनिया भर से इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करने की अपनी जिद से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सवाल यह है कि यह सब कब तक चलेगा। आखिर फिलिस्तीनी समस्या का कोई तो समाधान करना होगा। उन्हें कभी तो अपना देश देना होगा। आज दुनिया के ज्यादातर देश, जिनमें भारत भी शामिल है, फिलिस्तीनी समस्या के शांतिपूर्ण हल और दो राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में हैं। इसका अर्थ यही है कि विश्व के नक्शे पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश रहें और उनमें सौहार्द्रपूर्ण रिश्ता हो। लेकिन इजराइल इस सिद्धांत का हमेशा विरोध करता आया है। इसके पीछे उसके अपने स्वार्थ और आशंकाएं हैं। वह केवल वेस्ट बैंक को ही फिलिस्तीन स्वीकार करेगा। गाजा पट्टी को पूरी तरह हथियाना चाहता है ताकि उसकी पश्चिमी सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। लेकिन यह एक तरह से दूसरे देश पर कब्जा करना ही है। यह सोच सही नहीं है। फिलिस्तीन जैसे जटिल मसले का हल सकारात्मक सोच के साथ ही हो सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अहंमन्यता का आलम यह है कि अब वो उस अमेरिका की भी बात नहीं सुन रहे, जो हमेशा इजराइल के बचाव में आगे रहा है। खुद इजराइल में लोगों ने बड़े पैमाने पर नेतन्याहू के खिलाफ जंगी प्रदर्शन हुए हैं। इसके बाद भी नेतन्याहू अपनी जिद से रत्ती भर भी टस से मस नहीं हो रहे। अगर ऐसा ही रहा तो दुनिया में इजराइल के दोस्त भी साथ छोड़ जाएंगे।

'मुठभेड़' में उलझ चुका है आदिवासियों का जीवन

पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ में जो भी मारे जा रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो सीने पर गोली खाने को तैयार जंगलों में घूम रहे हैं? सरकारों के पास आत्मसमर्पण कराने के बाद उनके लिए क्या योजनाएं हैं? हसदेव जंगल का ही मामला उठा लीजिए। कोई नया मामला नहीं है। एक दशक से भी ऊपर हो गया इस मामले को चलते हुए ।तब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की ही सरकारें बनती आई है

विवेकरंजन सिंह

जंगल के असली हकदारों की सुध आखिर किसे है। सबकी गिद्ध नजरें इसी पर टिकी हैं कि कैसे उनके जमीनों को कब्जाया जाए और उनमें छिपे खजानों को निकालकर मालामाल बना जाए। आजादी के बाद से अब तक अगर किसी का जीवन आज भी सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त है तो वो है आदिवासियों का। सरकारें जो भी आई सबने अपने अपने अनुकूल उनका उपयोग किया, झांसे में रखा और विकास के नाम पर उनका शोषण किया। सत्तर के दशक में उठा एक जनविद्रोह जो नक्सल मूवमेंट के रूप में जाना गया,आज उसपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर यह विद्रोह शुरू हुआ था वह आज सत्ता विरोध और वोट के बहिष्कार तक सीमित हो चुका है।

पिछले एक महीने में देखा जाए तो सुरक्षा बलों द्वारा सौ से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया है। सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है और दावा कर रही है कि आने वाले समय में नक्सलवाद का नामों निशान नहीं रहेगा। आदिवासी अस्मिता को नजरंदाज कर जिस तरह का खेल माओवादियों और सरकार के बीच चल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि आदिवासियों को इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। छत्तीसगढ़ के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों से माओवादियों के आत्मसमर्पण की घटनाएं आती रहती हैं। मीडिया भी इस घटना को सरकार के नजरिए से पेश करने में लगी है। आज की मीडिया के लिए माओवादी आंतरिक खतरा बन चुके हैं, मगर कभी मीडिया हसदेव जंगल कटने को लेकर उन आदिवासियों के बेबस चेहरे उजागर नहीं करती जो सदियों से इन जंगलों में रहते आए हैं और अपनी विशिष्ट संस्कृति और रहन सहन को बचाए हुए हैं। विश्व में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां जनजातियों की बहुलता हैं,जिसमे भारत का नाम भी आता है।मगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो कई जनजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंचने को हैं और जो हैं वो लगातार अपनी पहचान के लिए जूझ रही हैं। पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ में जो भी मारे जा रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो सीने पर गोली खाने को तैयार जंगलों में घूम रहे हैं? सरकारों के पास आत्मसमर्पण कराने के बाद उनके लिए क्या योजनाएं हैं? हसदेव जंगल का ही मामला उठा लीजिए। कोई नया मामला नहीं है। एक दशक से भी ऊपर हो गया इस मामले को चलते हुए।तब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की ही सरकारें बनती आई हैं। 2010 से ही इस जंगल को न काटने के लिए आंदोलन चलता आ रहा है। सरकारों ने बस आश्वासन दिए मगर दूसरी ओर अडानी जैसे उद्योगपतियों को भी कहा कि वो आरी कुल्हाड़ी लेकर तैयार रहे। आदिवासी आंदोलन करते रहे और आज भी कर रहे। बीजेपी ने तो अपने घोषणा पत्र में हसदेव जंगल कटने को 'धोखा' बताया मगर सत्ता में आने के बाद वही काम शुरू कर दिया।

आदिवासियों की लड़ाइयां,उनके विद्रोह को हमेशा से ही छिपाया और दबाया जाता रहा है। वो बस एक मोहरा रहे सरकारों के लिए। जबरन गांव खाली कराने, नक्सली घोषित कर मार दिए जाने जैसी हजार घटनाएं आंखों से सामने से गुजर चुकी हैं मगर उनके मूल विकास को कभी ध्यान नहीं दिया गया। प्राथमिकता में वो कभी नहीं रहे बल्कि रही तो उनकी जमीन और उनके जंगल। नून भात खाकर गुजारा कर लेने वाले ये आदिवासी सरकार के करोड़ों बजट का रत्ती भर भी हिस्सा नहीं मांगते,और सरकार भी उनकी इस भावना का फायदा उठाती है। वो बस सुकून चाहते हैं कि उन्हें उनके जंगल से वंचित न किया जाए। एक बात हमें आपको खुद से पूछनी होगी कि हम नागर समाज के लोग अरण्य की संस्कृति को कितना अच्छे से जानते हैं? हमारी संवेदनाएं क्या उनके इलाकों तक पहुंच पाती हैं? क्या उनकी खबरें हमें विचलित करती हैं? फिर हम कैसे एकतरफा उनको दोषी मान लेते हैं कि वो विकास के धुर विरोधी हैं? यही बात हमें माओवादी या जिन्हें नक्सलवादी कहा जाता है, उनके प्रति भी सोचनी होगी। हम सरकार के बयानों को अपना आधार बनाकर कैसे किसी के बारे में धारणा बना सकते हैं। मेरा कहना यह बिलकुल नहीं कि मैं नक्सलियों के कार्य व्यवहार का पक्षधर हूं मगर हमें उनकी इस हालत के जिम्मेदार लोगों को ढूंढना होगा। उन तत्वों की खोज करनी होगी जिन्होंने उन्हें ऐसा बनने पर विवश किया।

सोनभद्र के उम्भा गांव की घटना याद है आपको? आदिवासी जमीनों को कैसे आला अधिकारियों ने घूस और पैसे खाकर उनकी जमीनों की खरीद फरोख्त की और स्थिति ये आ गई कि कई आदिवासियों को जान गंवानी पड़ी। अब सरकारें बाद में मुआवजा देकर मामले को घुमा देने या शून्य बना देने में माहिर हो चुकी हैं।

जंगलों की बात करने वाले दलों या आदिवासियों की सहायता करने वाले, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को सरकार जनता की नजर में अपराधी और माओवादी या अर्बन नक्सल करार दे रही है। वो ऐसी छवि गढ़ने में लगी है कि कल हक और अधिकार मांगने वाले को मार भी दिया जाए तो जनता उसे सरकार का सही और उचित कदम ठहराए और ऐसा होने भी लगा है। नक्सल और माओवादियों के बारे में सतही ज्ञान रखने वाले लोग फिल्में बनाकर जनता में एक नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। ये दौर एजेंडा बनाकर मलाई खाने का दौर है।छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार को अब जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस के समय में आदिवासियों के साथ 'धोखा' उनकी सरकार में 'भला' कैसे हो गया। जबकि जंगल पर नजर रखे उद्योगपतियों को दोनों ने ही अपनी गोदी में खिलाया है। राजस्थान सरकार को बिजली की कमी पड़ी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जंगल कटा कर खुदाई शुरू कर दी। ठीक बात है कि विकास के लिए कुछ नुकसान झेलना होता है और कुछ दोस्ती भी निभानी पड़ती है।

मगर हर बार नुकसान आदिवासी ही क्यों उठाएं। जब खबर इसकी लगती है कि फला जगह कोयला है,फला जगह सोना है या फला जगह हीरा हैं तभी सरकार क्यों उत्साहित होती है अपने विकास का रथ इन आदिवासी इलाकों में ले जाने को। तभी इनकी सड़कें, इनकी गाड़ियां इनके डंपर,इनके बुलडोजर या बड़ी बड़ी मशीनें जंगलों में पहुंच जाती हैं। बड़े बड़े अस्थाई घर बन जाते हैं। क्यों इससे पहले नहीं दिखती उनको आदिवासियों की बेबसी,विकास की राह देखती उनकी आंखें। सवाल माओवादियों पर भी उठता है कि ऐसी घटनाओं पर उनकी चुप्पी क्या संकेत देती है? सिर्फ चुनाव का बहिष्कार करना या फिर कांग्रेस भाजपा का झूठा विरोध करना उनका काम रह गया है? उनकी जो खूनी लड़ाई जंगलों के बीच चोरी चुपके,छिपते छिपाते चल रही उनको चाहिए कि हथियार त्याग कर वो एक नागरिक की तरह सही मायनों में आदिवासियों का साथ दें। मगर ऐसी उम्मीद करना भी ख्याली पुलाव जैसा ही है। सरकारें इसे बनाए रखना चाहती हैं जिससे आदिवासी और उनकी जमीन को डर और भय का माहौल बनाकर लूटा जाता रहे।

सरकारों की बयानबाजियों और रोज होती मुठभेड़ में आदिवासी जीवन पिसता जा रहा है। उन्हें पुलिस का भी भय है और माओवादियों का भी भय है। ऐसे में वो खुद जंगलों को छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। उनको दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। अब इनके अधिकारों के लिए लड़ने वालों की संख्या भी सिमटती जा रही है। मुश्किल ही है कि कोई महाश्वेता देवी आए जिनको ये मां कह सकें। शहरों में सांस ले रहे और बिजली से सुख का जीवन भोग रहे लोगों को इनके अंधेरे जीवन का दर्द कब महसूस होगा, चिंता का विषय है।

अध्यात्म

जब बुद्ध ने जूठा आम खाया

मगध की राजधानी में भगवान् बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में मगध लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए।

थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया।

अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहाँ से जाने की घोषणा कर दी।

यह सुनकर नगरवासी दुःखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा माँगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।

नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ-न-कुछ भेंट दें।

बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ।

जो भी भेंट आती, बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक ओर रखवा देते।

तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह जूठा आम रखकर बोली, भगवान् ! मेरे पास यही समस्त पूँजी है।

मैं धन्य होऊँगी, यदि आप इसे स्वीकार करेंगे।

बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया।

नगरवासियों ने पूछा, भगवान् ! उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया ?

जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक ओर रखवा दिए।

तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूँजी थी, वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया।

तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है।

आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान, दाता व याचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है।

सान्निध्य की स्नेहिल छांव से दूर हो रहे बुजुर्ग

बुजुर्ग बच्चों को सिर्फ प्यार-दुलार से ही मात्र सिंचित नहीं करते, बल्कि एक प्रभावी संस्कार का भी बीजारोपण करते हैं। नानी, दादी की लोरियों के माध्यम से लोक संस्कृति के विविध विधियों से रूबरू कराने की विधा बच्चों के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दिया करती थी। आज भी देखा जा सकता है कि नानी-दादी बच्चों को वात्सल्य की शक्ति पुंज के सहारे पारंपरिक खाने खिलाती हैं। बच्चे घर के बुजुर्गों के साथ खेल-कूद करते थे, हंसी मजाक करके बहुत कुछ सीख लिया करते थे। बच्चों ने अगर कोई गलती या भूल की तो बड़े-बुजुर्ग उसे तुरंत टोक कर सुधार कराते थे। एक खास बात यह थी कि घर के वरिष्ठ जनों का समय बच्चों के साथ बहुत ही आसानी और तेजी से बीत जाया करता था।

भारतीय सामाजिक परंपराओं की शृंखला में बुजुर्गों की भूमिका अद्भुत रही है। घर आंगन में उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूर्व से स्थापित विरासतीय ताने-बाने परिवार में एक सबल और प्रबल तरंग की मनोहर छटा बिखेरे रहती थी। ये बुजुर्ग दादा-दादी और नाना-नानी के रूप में घर के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। पूरे परिवार को यह विश्वास रहता था कि पारिवारिक परिवेश में कभी भी प्रतिकूलता आने पर बुजुर्ग अपने दीर्घकाल के अनुभव के आधार पर उसे संभाल लेंगे।

संयुक्त परिवार के संचालन में बुजुर्गों के निर्णय अंतिम हुआ करते थे, क्योंकि इसके पीछे दूरगामी दृष्टिकोण माना जाता था। कालचक्र के प्रवाह ने जब जीवन अध्याय के सभी पन्नों को पलट कर रख दिया है, तो स्वाभाविक है कि हमारे बुजुर्गों की विभिन्न भूमिकाएं भी बहुत हद तक सीमित हुई हैं। आज की युवा पीढ़ी की तीव्र भागम-भाग की जिंदगी जब अतिशय करवटें बदल रही है, तो यही हमें सचेत भी होने की जरूरत है कि भौतिक व्यामोह की यात्रा में हम इतना आगे न निकल जाएं, जहां से वापसी मुश्किल हो जाए।

गर्मी की छुट्टी या किसी पर्व-त्योहार में नानी घर जाकर उधम मचाने की एक अलग चंचल घड़ी हुआ करती थी। उन पलों में एक भावनात्मक अनुभूति की सुपाच्य खुराक हुआ करती थी। वर्तमान समय में एकल परिवार की स्थिति ने पुरानी परंपराओं के प्रतिमान रहे नाना, नानी, दादा, दादी के साहचर्य को सीमित कर दिया है।

देश-विदेश में नौकरी करने वाले बेटे-बेटियों का घर आना अब सीमित हो गया है तो बुजुर्ग ही अपनी सुविधा के तहत बच्चों के पास जाकर स्नेहिल वातावरण से जुड़ने की विवशता में हैं। जीवन के सांध्य बेला में जी रहे बुजुर्गों के लिए अब ऐसी स्थिति भी दुर्लभ है, क्योंकि वे उम्रजनित व्याधियों के चलते बाहर आ-जा नहीं सकते। इस परिवर्तन से पूरी दुनिया आक्रांत है, लेकिन बात करें भारतीय सामाजिक संस्कृति की तो कभी बच्चे अपने माता-पिता की एक पीढ़ी पूर्व वाले नाना-नानी, दादा-दादी के साथ रहकर जीवन के वे पूरे सबक सीख लिया करते थे, जिनसे उन्हें भावी जीवन में रूबरू होना पड़ता था।

देश के कुछ वृद्धाश्रमों में वहां के बुजुर्गों के साथ सप्ताह में एक या दो दिन बच्चे समय बिता रहे हैं। इस प्रयोग से स्नेह और वात्सल्य से वंचित रह गए बच्चों को ऐसे वक्त से सांवेगिक अनुभूति जरूर मिल रही है और इसके अनेक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही समाज में संयुक्त परिवार की अवधारणा अपने देश सहित पड़ोसी देशों में भी रही है। ज्यों-ज्यों समाज अपने विकास की यात्रा में गतिमान होता गया, घर-आंगन के सदस्य रोजी-रोटी कमाने बाहर जाने को बाध्य हुए।

ऐसी स्थिति ने परिवार के बुजुर्गों के लिए विकट एकाकीपन ला दिया है और उनका अकेले रहना उनकी मजबूरी बन गई है। संयुक्त परिवार में छोटे बच्चों का लालन-पालन बड़ी सहजता के साथ हो जाता था और वे मानसिक तौर पर स्वस्थ और प्रसन्न रहते थे। कई शोध पत्रों ने यह निष्कर्ष

निरूपित किया है कि जो बच्चे बुजुर्गों की छाया में पलते हुए बड़े होते हैं, उनके व्यवहार में शालीनता और सरलता देखी गई है।

बुजुर्ग बच्चों को सिर्फ प्यार-दुलार से ही मात्र सिंचित नहीं करते, बल्कि एक प्रभावी संस्कार का भी बीजारोपण करते हैं। नानी, दादी की लोरियों के माध्यम से लोक संस्कृति के विविध विधियों से रूबरू कराने की विधा बच्चों के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दिया करती थी। आज भी देखा जा सकता है कि नानी-दादी बच्चों को वात्सल्य की शक्ति पुंज के सहारे पारंपरिक खाने खिलाती हैं।

बच्चे घर के बुजुर्गों के साथ खेल-कूद करते थे, हंसी मजाक करके बहुत कुछ सीख लिया करते थे। बच्चों ने अगर कोई गलती या भूल की तो बड़े-बुजुर्ग उसे तुरंत टोक कर सुधार कराते थे। एक खास बात यह थी कि घर के वरिष्ठ जनों का समय बच्चों के साथ बहुत ही आसानी और तेजी से बीत जाया करता था।

आज के दौर में भी अधिकांश नाना-दादा बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने में अपना समय व्यतीत कर स्वस्थ्य रहकर सदा सक्रिय बने रहते हैं। किस्से-कहानियों के द्वारा बच्चे अपना मनोरंजन भी किया करते थे और अपनी कल्पना शक्ति को विकसित भी किया करते थे। यह विधान समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता था।

एक अच्छे नागरिक बनने की प्रथम पाठशाला कभी घर ही हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसके क्षरण और कमी ने इंसान के निर्माण में बेहद कमी ला दी है। एकल परिवार की अवधारणा ने एकल संतान तक ही सीमित रहने की मनोवृत्ति भी विकसित की है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि एकल बच्चे को जब अपने घर-आंगन में किसी भाई-बहन का साथ नहीं मिलता तो वे बच्चे अपने स्कूल में भी अन्य बच्चों से अधिक मेलजोल नहीं बढ़ा पाते।

आगे चलकर अधिकांश ऐसे बच्चे अंतर्मुखी होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में घर के नाना-नानी, दादा-दादी का सान्निध्य बच्चों को इस एकांत और संकोची मानस से विलग कर तरोताजा महसूस कराता है। माता-पिता का भी प्रयास होना चाहिए कि गाहे-बगाहे नजदीकी रिश्तेदार के बच्चों के साथ घुलने-मिलने का अवसर दिया जाए।

बुजुर्गों के प्यार से वंचित बच्चे अब छोटी-मोटी बीमारियों के लिए भी चिकित्सक के पास जाने को बाध्य हो गए हैं, जबकि पुराने जमाने में बच्चों की स्वास्थ्य की लघु समस्याएं दादी-नानी हल कर लिया करती थीं। नवजात शिशु को कैसे उठाएं, कैसे सुलाएं, कैसे मालिश करें, क्या पहनाएं और किस मौसम में कौन-सी प्राकृतिक जड़ी-बूटी का सेवन कराएं, ये सभी सिद्ध किए प्रयोग नानी-दादी के लिए अत्यंत उपयोगी हुआ करते थे।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष
आज आप बहुत कुछ एक साथ करना चाहेंगे। इसके कारण आप सम्भवत: वह कार्य न कर पायें जिसका आपने लक्ष्य निर्धारित किया है।

वृषभ
आज आप काफी आक्रामक हो सकते हैं। व्यवसाय में बड़ा बदलाव करने से आपको बचना चाहिये। दूसरों के मामलों में आप ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं।

मिथुन
भविष्य को लेकर योजना न बनायें। विदेश में शिक्षा ले रहे लोगों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों के ऊपर अति विश्वास करना उचित नहीं होगा।

कर्क
परिजनों के लिये आप महँगी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। आप दिखावे में ज्यादा धन खर्च न करें। जल्दबाजी में लिये गये निर्णयों से हानि हो सकती है।

सिंह
आज यात्राओं के लिये काफी अनुकूल दिन है। व्यवसाय में आप काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रुके हुये कार्यों में अचानक प्रगति से होने से उत्साहित रहेंगे।

कन्या
आज लोग आपकी बातों से काफी प्रभावित हो सकते हैं। आज आपको काफी सम्भल कर लोगों से व्यवहार करना चाहिये। धन को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं।

तुला
बौद्धिक लोगों के बीच आपकी साख मजबूत होगी। ऐसे किसी भी कार्य की तरफ प्रवृत्त न हो जो आपको भविष्य में नुकसान पहुँचाये।

वृश्चिक
आज आपका मन कुछ अप्रसन्न हो सकता है। यात्रा के दौरान बाहर का भोजन करने से बचें। व्यापार में कुछ बड़े बदलाव करने से आपको बचना चाहिये।

धनु
उधार दिया हुआ धन वापस लौटने के योग बन रहे हैं। आज आप कुछ बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोग अपने प्रतिद्वन्दियों पर भारी पड़ने वाले हैं।

मकर
आप कुछ नया सीखने को लेकर उत्सुक रहेंगे। जॉब में आय बढ़ने के योग बन रहे हैं। यदि आप अपने काम के लिये किसी सहयोगी पार्टनर को जोड़ना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है।

कुंभ
लोगों के बीच में आपके विषय में काफी चर्चा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में नये हैं तो आपको लोग परेशान कर सकते हैं। आपको अपने आप विश्वास बनाये रखना चाहिये।

मीन
आज का दिन आपके लिये तनावपूर्ण हो सकता है। अपनी रहस्य की बातों को गोपनीय रखें। आपके द्वारा की हुयी गलतियों पर गौर करें और तुरन्त उसे दूर कर लें।

चीन का ताइवान स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास

चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अचानक दो दिनों का युद्धाभ्यास करके न केवल ताइवान को कड़ा संकेत दिया है बल्कि इस पूरे क्षेत्र की संवेदनशीलता को फिर से रेखांकित कर दिया है। युद्धाभ्यास का मकसद खुद चीनी सेना ने इस द्वीप की सत्ता पर कब्जा करने की अपनी क्षमता जांचना बताया है। युद्धाभ्यास ऐसे समय किया गया, जब ताइवान में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने सत्ता संभाली ही है। लाई ताइवान में स्वायत्त नीतियों के पक्षधर माने जाते रहे हैं और चीन उन्हें 'खतरनाक अलगाववादी' बताता रहा है। युद्धाभ्यास के पीछे भी तात्कालिक कारण सोमवार को पद संभालने के बाद दिए गए उनके पहले भाषण को माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने चीन से कहा था कि वह ताइवान को डराने-धमकाने की नीति से बाज आए। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। वह कह चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक भी चीन उस पर कब्जा कर लेगा। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ताइवान को चीन में मिलाने के काम को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ, ताइवान लोकतांत्रिक देश है और वहां के ज्यादातर लोग कम्युनिस्ट चीन के साथ जाने को तैयार नहीं हैं। वहां चीन विरोधी मानी जाने वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर सत्ता में आई है। यह बात भी सही है कि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। फिर भी ताइवान से अनौपचारिक तौर पर इन देशों के करीबी संबंध हैं। हाल के वर्षों में चीन की बढ़ी हुई आक्रामकता के मद्देनजर यह करीबी बढ़ी है। खासकर अमेरिका ने यहां न केवल हथियारों की सप्लाई बढ़ाई है बल्कि कई उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल भी भेजे। इस पर चीन अपनी नापसंदगी जाहिर करता रहा है। चीन पहले भी इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास के जरिए अपना असंतोष प्रकट करता रहा है, लेकिन इस बार का युद्धाभ्यास पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक माना जा रहा है। कई जानकारों का कहना है कि इसके जरिए चीन ताइवान और उसके मित्र देशों को यह दिखाना चाहता है कि वह इस द्वीप पर जब चाहे कब्जा कर सकता है। संकेत गंभीर इसलिए है कि ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिहाज से तो दुनिया के लिए अहम है ही, एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में भी ताइवान स्ट्रेट महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ना या किसी तरह से संघर्ष की स्थिति बनना खतरनाक साबित होगा। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में किसी तरह का तनाव या संघर्ष भड़कने की आशंका के खिलाफ सचेत किया है।

सत्ता की बहार के लिए बिहार में कशमकश

अतुल सिन्हा

बिहार ऐसा राज्य है जिसमें सभी सात चरणों में चुनाव हो रहे हैं यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक। छठे दौर में 8 और आखिरी दौर में भी 8 सीटें बाकी हैं। नीतीश के पाला बदलने से भाजपा के दोबारा सरकार में आने के बाद पार्टी के पास सत्ता की ताकत भी है और मशीनरी भी, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से उम्मीदें भी। उधर आरजेडी की बढ़ती ताकत, कांग्रेस का पुनर्जीवन और राहुल गांधी की मेहनत का असर दिख रहा है। यहां जातिगत जनगणना का भी असर है और तेजस्वी के सरकार में रहते नौकरी देने का रिकॉर्ड का मुद्दा भी प्रभावी है। बिहार की राजनीति लगातार कई उतार-चढ़ावों से होकर गुजरती रही है। यहां वैचारिक और सैद्धांतिक राजनीति का बेशक एक दौर था, लेकिन करीब चार दशक से सारे समीकरण पूरी तरह सत्ता केन्द्रित और जाति आधारित होते गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में होने वाली चुनावी सभाओं पर गौर करें तो यहां उनके निशाने पर सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव होते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी दूसरे नंबर पर होते हैं और यहां की जातिगत और परिवारवादी राजनीति तीसरे नंबर पर। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने राहुल गांधी की तरह शहजादे का खिताब दे रखा है और इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचार, गुंडाराज और जातिगत जनगणना के सवाल पर बांटने वाला गठबंधन करार दिया है। उधर अपने चुनावी गणित और रणनीति की वजह से चर्चा में रहने वाले प्रशांत किशोर भी पांच दौर के चुनावों के बाद ये दावा करने से नहीं चूक रहे कि बिहार में अब भी मोदी या केन्द्र की सरकार को लेकर कोई गुस्सा नहीं है, मोदी लहर भले ही इस बार न हो लेकिन प्रशांत किशोर को इस बार भी मोदी सरकार बनती दिख रही है और खासकर बिहार में नीतीश कुमार के पलटू राम वाली छवि के बावजूद एनडीए को कोई खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है। जबकि चुनाव विश्लेषक और किसी जमाने में सटीक चुनावी भविष्यवाणियां करने वाले सैफोलॉजिस्ट योगेन्द्र यादव इस बार एनडीए को ढाई सौ के नीचे देख रहे हैं। सबके अपने-अपने चश्में हैं और अपना-अपना नजरिया है जबकि असली फैसला खामोश वोटर यानी जनता को करना है।

इंडिया गठबंधन जिन अंतर्विरोधों के बाद बना और आखिरी वक्त तक सीटों के बंटवारे को लेकर जो असमंजस रहा, उसे भाजपा और जेडीयू अपने पक्ष में मान रही है और अपनी चुनावी सभाओं में इसे लेकर अब तक गठबंधन पर सवाल उठाती है। भाजपा के 400 पार के दावे में बिहार की 40 सीटें भी शामिल हैं। 2019 में भाजपा ने यहां से जो 17 उम्मीदवार उतारे थे, वह सभी जीते थे जबकि जेडीयू के 17 में से 16 उम्मीदवार जीते थे। एनडीए के अन्य घटकों में लोक जनशक्ति पार्टी के भी सभी 6 उम्मीदवार जीत गए थे। पिछले आम चुनाव में यानी एनडीए को कुल 40 में से 39 सीटें मिली थीं जबकि एक सीट कांग्रेस ने जीती थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भाजपा अपनी सभी सीटें बचा पाएगी, क्या नीतीश की मौकापरस्ती जेडीयू को फिर से पिछली बार जितनी सीटें दिला पाएगी और क्या इस बार एनडीए 39 के आंकड़े तक पहुंच पाएगा?

बिहार ऐसा राज्य है जिसमें सभी सात चरणों में चुनाव हो रहे हैं यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक। छठे दौर में 8 और आखिरी दौर में भी 8 सीटें बाकी हैं। नीतीश के पाला बदलने से भाजपा के दोबारा सरकार में आने के बाद पार्टी के पास सत्ता की ताकत भी है और मशीनरी भी, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से उम्मीदें भी। उधर आरजेडी की बढ़ती ताकत, कांग्रेस का पुनर्जीवन और राहुल गांधी की मेहनत का असर दिख रहा है। यहां जातिगत जनगणना का भी असर है और तेजस्वी के सरकार में रहते नौकरी देने का रिकॉर्ड का मुद्दा भी प्रभावी है।

बिहार की राजनीति लगातार कई उतार-चढ़ावों से होकर गुजरती रही है। यहां वैचारिक और सैद्धांतिक राजनीति का बेशक एक दौर था, लेकिन करीब चार दशक से सारे समीकरण पूरी तरह सत्ता केन्द्रित और जाति आधारित होते गए। वर्ष 1974 के जेपी आंदोलन ने जिस नई राजनीति की नींव रखी थी और जिन मूल्यों और सिद्धांतों की बात होती थी, उसे सत्ता के खेल ने ध्वस्त कर दिया। मौजूदा राजनीति में शीर्ष पर बैठे तमाम नेता खुद को उस दौर के आंदोलनकारी बताते हैं। जेपी ने उन्हें तत्कालीन कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी की निरंकुशता और इमरजेंसी जैसे कदमों के खिलाफ एकजुट करके सत्ता की राह दिखाई, लेकिन सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि उस दौर के तमाम नेता भ्रष्टाचार, जातिगत समीकरण और जोड़-तोड़ के खेल में लगे रहे।

लेकिन अब युवा नेतृत्व में आई राजनीतिक परिपक्वता और एक ईमानदार, साफ-सुथरी राजनीति की उम्मीद से आम लोगों में बदलाव की चाहत दिखने लगी है। ये नेता अपने भाषणों में मोदी सरकार के वादों के साथ उनकी निरंकुश वाली छवि को उभारने और लोगों के मन में बैठाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दरअसल भाजपा का कट्टर हिन्दुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दे बिहार में उतने असरदार नहीं दिखते, इसलिए यहां मोदी को भी इन नेताओं पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के अलावा कोई बड़ा दांव नहीं दिख रहा, अपनी सरकार की उपलब्धियों में पांच किलो मुफ्त अनाज की गारंटी को भाजपा तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जिस तरह बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर विपक्ष मोदी को घेर रहा है, उनकी योजनाओं और गारंटियों की असलियत बता रहा है, उससे उनकी रैलियों में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है।

बिहार में चुनाव आम तौर पर जातिगत आधार पर ही लड़े जाते रहे हैं और भाजपा समेत सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार उसी गणित के आधार पर उतारती रही हैं, इस बार भी यही स्थिति है। 2019 में जिस तरह एनडीए को लगभग 54 फीसदी वोट मिले थे, इस बार इसमें भले ही कुछ गिरावट हो लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलग अलग लड़ने से कहीं न कहीं वोट बंटने का फायदा उसे ही होता दिख रहा है। यह गणित प्रशांत किशोर का है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में मुख्य तौर पर आरजेडी, कांग्रेस के साथ सीपीआई (एमएल), वीआईपी, भाकपा, माकपा हैं जिसमें इस बार बेशक तेजस्वी और राहुल की सभाओं में उमड़ती भीड़ ने यह तो साबित कर ही दिया है कि इस बार टक्कर आसान नहीं है। जीत का अंतर काफी कम होने वाला है और कोई ताज्जुब नहीं कि खामोश वोटर हवा का रुख बदल भी सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ममता सरकार संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर नहीं

योगेंद्र योगी

हाईकोर्ट ने ओबीसी के मामले में सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद तो मानो ममता का पारा उछल गया। ममता ने अदालत पर मनमाने आरोप लगा दिए। उच्च न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीशों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक न्यायाधीश कह रहा है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, दूसरा भाजपा में शामिल हो जाता है... आप इस तरह से न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं और अदालतों की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुश्री बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि अदालत का फैसला तपशिली समुदाय के लिए आरक्षण रद्द करने के भाजपा के प्रयासों का हिस्सा है। ममता के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को खारिज कर दिया।

पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी बन गई है जिसका देश के संविधान और न्यायपालिका में भरोसा नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शगल बन गया है। ममता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नजर आती है, इसके लिए बेशक कानून की कितनी ही धज्जियां क्यों न उठानी पड़ी। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का। इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों पर भी केंद्र की भाजपा सरकार की खिलाफत की है। कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के हाईकमान ने भी कभी ऐसे आरोप केंद्र की भाजपा सरकार पर नहीं लगाए, जैसे कि ममता बनर्जी लगाती रही हैं।

ममता ने भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, राजनीतिक आधार पर बंदरबाट जैसे मुद्दों पर अदालतों से जितनी फटकार खाई है, उतनी देश के किसी राजनीतिक दल की सरकार ने नहीं खाई। इतना सब कुछ होने के बावजूद ममता बनर्जी अपनी आदतों से बाज नहीं आई हैं। नया मामला पश्चिमी बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को अदालत द्वारा रद्द करने का है। इस आदेश को सदाशयता से मान कर अपील करने की दलील देने के बजाए मुख्यमंत्री ममता ने ही फैसला देने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर भाजपा समर्थक होने का आरोप लगा दिया। ऐसा करके ममता ने बगैर किसी भय के सरेआम अदालत की अवमानना कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी, जो तपशिली समुदाय को दिए गए अधिकार छीन लेगा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस प्रशासन के तहत 2011 से बंगाल में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रमाण पत्रों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, हालांकि, इससे वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी या सीटें रखने वाले या जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दाखिल करने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। उस रिपोर्ट में देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में विस्तृत बातें की गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5 फीसदी ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर 2010 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। इस तरह उस वक्त करीब 87.1 फीसदी मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन, 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका। फिर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। ममता की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया, जिसमें से 33 मुस्लिम समुदाय की जातियां थीं। साथ ही तृणमूल सरकार ने भी राज्य में ओबीसी आरक्षण सात फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया। ममता सरकार के इस कानून की वजह से राज्य की 92 फीसदी मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा।

हाईकोर्ट ने ओबीसी के मामले में सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद तो मानो ममता का पारा उछल गया। ममता ने अदालत पर मनमाने आरोप लगा दिए। उच्च न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीशों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक न्यायाधीश कह रहा है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, दूसरा भाजपा में शामिल हो जाता है... आप इस तरह से न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं और अदालतों की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुश्री बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि अदालत का फैसला तपशिली समुदाय के लिए आरक्षण रद्द करने के भाजपा के प्रयासों का हिस्सा है। ममता के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। शाह ने कहा कि ममता जी ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं - क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जो अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दे? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वेक्षण के 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया। कोई अदालत में चला गया। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटना चाहती हैं और मुस्लिम जातियों को आरक्षण देना चाहती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जो फैसले हैं, वो बताते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी।

ममता बनर्जी ने वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करने में कसर बाकी नहीं रखी। मुद्दा चाहे रामनवमी पर हिंसा का हो या संदेशखाली में हिन्दू महिलाओं के साथ अत्याचारों का। राज्य में शीर्ष संवैधानिक पद पर रहते हुए भी ममता बनर्जी ने मुसलमानों के वोट बैंक को रिझाने के लिए उल्टे भाजपा और दूसरे विपक्षी दलों पर ही निशाने साधे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के मौजूदा और पूर्व कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का तांडव जम कर हुआ। शारदा घोटाला और नारद स्टिंग खुलासे, कोयला और मवेशी तस्करी, राशन घोटाले और सरकारी परियोजनाओं के लिए फंड से लिए गए कट मनी के आरोपों के बावजूद ममता सरकार में कोई सुधार नहीं दिखा। इससे जाहिर है कि ममता बनर्जी मनमानी करने पर आमदा हैं।

बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी मामला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला व राशन वितरण घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक नेता मंत्री सलाखों के पीछे हैं। इनमें पूर्व मंत्री व विधायक पार्थ चटर्जी, विधायक अनुब्रत मंडल, विधायक मानिक भट्टाचार्य, विधायक जिबनकृष्ण साहा प्रमुख हैं। इस कड़ी में वन मंत्री व पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का नाम जुड़ गया है। करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में तृणमूल के तत्कालीन राज्यसभा सदस्य सृंजय बोस और तृणमूल के विधायक और तत्कालीन परिवहन मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार किया गया था। मित्रा और बोस दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बंगाल पुलिस ने शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी के प्रवक्ता और पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष को गिरफ्तार किया था। ममता सरकार की सर्वाधिक किरकिरी संदेशखाली की शर्मनाक वारदात में हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया और पूछा था कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कैसे संपर्क कर सकती है? जहां तक वोटों की राजनीति और बहुमत पाने से काले कारनामों के धुल जाने का सवाल है तो लालू यादव बहुमत के बावजूद जेल गए थे। लोकतंत्र में कानून से खिलवाड़ करने के लिए बहुमत को आधार नहीं माना जा सकता। ममता बनर्जी को इससे सबक लेना चाहिए।

सुभाषित

श्रीकृष्ण संक्षिप्तमें बोले जिसके शब्द और अर्थ परस्पर नपे-तुले रहे और चुप हो गये। वस्तुतः बड़े लोगोंका यह स्वभाव ही है कि वे मितभाषी हुआ करते हैं। ❐ **शिशुपाल वध**

बंगालमें सर्वाधिक उत्साह

लोकसभा चुनावके छठें चरणमें शनिवारको सात राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेशकी ५८ सीटोंके लिए मतदानका कार्य सम्पन्न हो गया। अबतक लोकसभाकी ४८७ सीटोंके लिए मतदान पूर्ण हो गये। एक जूनको सातवें अन्तिम चरणमें ५६ सीटोंके लिए मतदान होंगे। नवतपाकी भीषण गमर्मीके साथ ही छिटपुट झड़पोंके बीच छठें चरणमें लगभग ५८ प्रतिशत मतदान हुए। ईवीएम मशीनको लेकर शिकायतोंकी संख्या अधिक रही। राजनीतिक कार्यक्रमोंके बीच मारपीटकी घटनाएं भी हुईं। उत्तर प्रदेशके संत कबीरनगरमें वोट डालने पहुंची एक महिलाकी मृत्यु हो गयी। राज्यकी १४ सीटोंमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोहीमें मतदान कमाबेश शान्तिपूर्ण रहा। नौवीं बार सांसद बननेके लिए जहां मेनका गांधी सुल्तानपुरसे मैदानमें हैं वहीं डुमरियागंजसे जगदम्बिका पाल पांचवीं बार सांसद बननेके लिए भाग्य आजमा रहे हैं। बिहारकी आठ सीटोंमें बाल्मिकीनगर, पश्चिम चम्पारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महराजगंज तथा झारखण्डकी चार सीटों-गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुरमें मतदान सम्पन्न हुए। जम्मू-कश्मीरके अनन्तनाग-राजौरी सीटसे पीडीपी प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ईवीएममें छेड़छाड़के आरोपोंके कारण धरनेपर बैठ गयीं। हरियाणाकी सभी दस, दिल्लीकी सात और ओडिशाकी छह सीटोंके लिए भी मतदान हुए। ओडिशामें राज्य विधानसभाकी ४२ सीटोंके लिए भी मतदान हुए। छठें चरणके मतदानमें तीन केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इन्द्रजीत सिंह भी चुनाव मैदानमें हैं। मौसमकी मारका प्रभाव मतदानपर भी पड़ा, जिसके चलते शुरुआती दौरमें मतदानकी गति धीमी रही लेकिन बादमें तेजी आयी। कड़ी सुरक्षाके बीच मतदानके दौरान मतदाताओंकी सुविधाओंका पूरा ध्यान रखा गया। अनेक केन्द्रोंपर ओरआरएसकी भी व्यवस्था की गयी थी, जिससे कि गर्मीसे पीड़ित मतदाताओंको राहत मिल सके। छठें चरणमें जिन सात राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेशमें मतदान सम्पन्न हुए, उनमें सर्वाधिक उत्साह पश्चिम बंगालमें देखनेको मिला और वहांका मतदान प्रतिशत भी अधिक रहा लेकिन कम मतदानवाले राज्योंमें उत्तर प्रदेशका होना चिन्ताकी बात है, जहां देशमें लोकसभाकी सर्वाधिक ८० सीटें हैं। जम्मू-कश्मीरके अनन्तनागमें भी अच्छा मतदान हुआ। लोगोंने उत्साहके साथ मतदानमें भाग लिया। इस बार लोकसभा चुनावके दौरान मतदानका गिरता प्रतिशत चिन्ताका विषय बन गया है। अब लोकसभा चुनावका अन्तिम सातवां चरण शेष हैं, जो एक जूनको होगा और चार जूनको चुनाव परिणामोंकी घोषणा होगी।

उपयोगी कदम

दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। इसके बावजूद यह घिनौनी कुप्रथा आज भी बेखौफ जारी है। हांलाकि शादीके बाद प्रताड़नाके मामलेमें दहेजका ब्योरा भी बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। दहेजमें मिले सामानोंमें उपहारोंको भी जोड़ दिया जाता है। ऐसेमें बीते मार्चसे इलाहाबाद उच्च न्यायालयने दहेज प्रताड़नाके एक मामलेकी सुनवाई करते हुए आमजनोंको बेहद महत्वपूर्ण सलाह दी है। न्यायालयने दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९८५ का हवाला देते हुए कहा कि शादीमें दूल्हा और दुल्हन दोनोंको ही मिलनेवाले उपहारोंकी सूची बनायी जानी चाहिए। इस सूचीमें यह स्पष्ट होगा कि दोनोंको क्या-क्या उपहार मिले हैं। सूचीपर दोनों पक्षके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इससे शादीके बाद दहेज सम्बन्धी आरोपोंके विवादोंके निबटारेमें आसानी होगी। न्यायालयने राज्य सरकारको भी निर्देश दिया है कि इसपर विचार करे। इस कड़ीमें शुक्रवारको उत्तर प्रदेश सरकारने विवाह प्रमाण-पत्रको लेकर नियमोंमें बदलाव कर उपयोगी कदम उठाया है। अब शादीका प्रमाण-पत्र बनवाते समय वर-वधूको मिले उपहारोंका विवरण भी शपथ-पत्रमें देना होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९८५ को इसी भावनासे बनाया गया था कि भारतमें परिजनों और रिश्तेदारोंकी ओरसे शादियोंमें उपहार देनेका रिवाज है। भारतकी परम्पराको समझते हुए ही उपहारोंको दहेजसे अलग रखा गया है। उच्च न्यायालयके निर्देशको राज्य सरकारें कड़ाईसे पालन करायें। अच्छी स्थिति यह है कि उपहार और दहेजमें मिले सभी सामानोंकी मौकेपर ही सूची बनायी जाय। दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९८५ की उपधारा दोमें शादीके समय मिले उपहारोंकी सूची बनानेकी व्यवस्था है, ताकि दहेजमें मिले सामानका सत्यापन किया जा सके। अधिनियमके तहत शादियोंमें दहेज प्रतिषेध अधिकारियोंकी भी तैनातीका प्रावधान है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं कराया जाता। न्यायालयने राज्य सरकारसे सवाल भी किया है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि दहेजके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रामाणिक सूची बनानेमें वर-वधू पक्षको तत्परता दिखानी चाहिए जिससे भविष्यमें आरोपोंकी सत्यताका पता चल सके और फर्जी दहेज केसोंपर अंकुश लग सके।

लोक संवाद

न्याय व्यवस्थामें देरीका कुप्रभाव

महोदय,-न्याय व्यवस्थाको देखकर लगता है कि न्यायका अधिकार नहीं, बल्कि एक मजबूरी जैसा है, जो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी सही। नक्कारखानेमें तूतीकी आवाज गुम ही रहती है। कुछ उदाहरण देखिये जो फैसलोंपर आधारित हैं। एक व्यक्तिको झूठे बलात्कारके मुकद्दमेमें जेलसे बरी होनेमें २० साल लग गये। मुकद्दमा किसी पीड़ित महिलाने नहीं, बल्कि उसके पति और ससुरने किया था क्योंकि वे उस व्यक्तिको सबक सिखाना चाहते थे, जिसकी इनसे किसी बातपर अनबन थी। इस बीच उसके माता-पिता और दोनों भाई मर गये। अब वह जेलसे छूटनेपर बदहवास है कि क्या करेगा, क्योंकि उसके स्वर्णिम वर्ष समाप्त हो गये थे। क्या न्यायको किसी सचाईतक पहुंचनेमें इतना समय लगता है। एक अन्य मामलेमें २४ गवाहोंमेंसे २२ की जांच एक ही दिनमें कर ली जाती है और दो निर्दोषोंको सजा हो जाती है। बरसों बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है क्योंकि वे दोषी सिद्ध नहीं हो पाते। क्या इतना समय लगना चाहिए, प्रश्न यही है! एक उदाहरण यह भी कि प्रख्यात रंगकर्मी सफदर हाशमीकी हत्यापर फैसला 14 साल बाद आता है, तबतक दो आरोपी मर चुके थे, बाकीको आजीवन कारावास, परन्तु वे यह अवधि तो काट चुके हैं। कई बार यह निर्णय आनेमें उस निर्दोषकी पूरी उम्र ही समाप्त हो जाती है। वकीलोंकी फीस और दूसरे खर्चे किस्मतका लेखा माननेको विवश कर देते हैं। यह विश्वका सबसे बड़ा आंकड़ा है कि हमारे देशमें पांच करोड़से अधिक मुकद्दमे अदालतोंमें पैंडिंग हैं। सोचिये कितने करोड़ लोग न्यायकी आस लगाये बैठे रहते हैं और मृत्यु ही उन्हें न्यायकी उम्मीदसे मुक्ति दिलाती है। जेलोंमें एक ओर सजा पाये लोग हैं लेकिन उनसे कहीं अधिक वे हैं, जिन्हें अंडर ट्रायल कहा जाता है, जो दसियों वर्षतक इंतजार करते हैं कि कब वे अपने खिलाफ काररवाईका सामना करें। निर्णयों और उनके अमलमें देरीका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि अपराधी निश्चिंत रहता है। जब फैसला आयगा, देखा जायगा। अपराध करता भी रहेगा तो भी कोई पूछनेवाला नहीं। एक उदाहरणसे बात स्पष्ट हो जायगी। मुंबईमें मईके महीनेमें अचानक मामूली आंधी आ जानेसे एक पैट्रोल पम्पके पास लगा एक विशालकाय होर्डिंग गिरनेसे लगभग २० लोग मर जाते हैं और सौके आसपास घायल होते हैं। यह होर्डिंग नियमानुसार आकारसे तीन गुना बड़ा था लेकिन सभी सरकारी खानापूर्ति भली-भांति की गयी थी। हादसा हो गया। क्या जिसका होर्डिंग था, उसपर सामूहिक हत्याका मुकद्दमा नहीं चलना चाहिए। लेकिन होगा क्या, सभी जानते हैं। इसी संदर्भमें सभी नियमोंको ताकपर रख कर नोएडामें दो टावर बन जाते हैं। यदि अदालती आदेशके कारण, जो शायद एक अपवाद हो, इसे गिराया नहीं जाता तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अनर्थ उस क्षेत्रवालोंको झेलना पड़ता। इस फैसलेमें भी दसियों वर्ष लगे थे। ऐसे अनगिनत मामले हैं। कुछ लोग अपराधियोंको असली या नकली मुठभेड़में मार गिराये जानेको सही ठहरानेकी वकालत करते हैं, क्योंकि अदालतोंमें ऐसे मामले दस-बीस वर्षतक चल सकते हैं और इन्हें बरी करना पड़ सकता है। यह स्थिति देरसे फैसले आनेसे अधिक खतरनाक है और अराजकताकी ओर बढ़ता कदम है। सबसे पहले तो हमारी न्यायपालिकाके खाली पदोंको ही भर दिया जाय और जो न्यायाधीश हैं, वे किसी भी दबाव, प्रलोभन और लालचसे मुक्त रहनेकी नीतिपर कड़ाईसे अमल करें तो बहुत राहत मिल सकती है। दूसरा यह कि जो गवाह हैं, उनकी सुरक्षाका प्रबंध इस तरहका हो कि अपराधीका उनतक पहुंचना असंभव हो। सचाई यह है कि गवाहोंके अभावमें मुकदमे शुरू ही नहीं हो पाते, जिन्होंने किसी अपराधको सामने होते हुए देखा, वे सामने आनेका साहस नहीं करते क्योंकि उनकी और परिवारकी जान खतरेमें पड़ जाती है। तीसरा, जानबूझकर न्यायमें देरी ऐसे व्यक्तिको, चाहे उसका कैसा भी इतिहास रहा हो, कानूनकी परिधिमें रहकर सजा दी जानी निर्धारित हो। चौथा, झूठे, तर्कहीन, किसीको दबाने या फंसानेके लिए मुकद्दमा करनेवालोंकी पहचान और सजा निर्धारित हो। **-पूरन चंद सरीन, वाया ईमेल।**

सरकारोंसे ऊपर संवैधानिक व्यवस्था

पश्चिम बंगाल सरकार देशमें एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका देशके संविधान और न्यायपालिकामें भरोसा नहीं रहा है। भ्रष्टाचारसे लेकर मनमर्जीका शासन चलाना मुख्य मंत्री ममता बनर्जीका शगल बन गया है। ममताको सिर्फ वोट बैंककी राजनीति नजर आती है, इसके लिए बेशक कानूनकी कितनी ही धज्जियां क्यों न उड़ानी पड़े।

❐ **योगेंद्र**

पश्चिम बंगालकी ममता सरकारका एकमात्र लक्ष्य मुसलमानोंके वोट बैंकको बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानोंके अवैध प्रवेशका हो या फिर बंगलादेशियोंका, इसके लिए ममताने देशकी एकता-अखंडता और सुरक्षासे जुड़े इन मुद्दोंपर भी केन्द्रकी भाजपा सरकारकी खिलाफत की है। कानूनसे खिलवाड़ जितना पश्चिम बंगालमें हुआ है, उतना शायद ही देशके किसी दूसरे राज्यमें हुआ हो। कांग्रेस शासित राज्योंके मुख्य मंत्री और कांग्रेसके हाईकमानने भी कभी ऐसे आरोप केन्द्रकी भाजपा सरकारपर नहीं लगाये, जैसे कि ममता बनर्जी लगाती रही हैं। ममताने भ्रष्टाचार, सरकारी मशीनरीके दुरुपयोग, राजनीतिक आधारपर बंदरबाट जैसे मुद्दोंपर अदालतोंसे जितनी फटकार खायी है, उतनी देशके किसी राजनीतिक दलकी सरकारने नहीं खायी। इतना सब कुछ होनेके बावजूद ममता बनर्जी अपनी आदतोंसे बाज नहीं आई हैं। नया मामला पश्चिम बंगालमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षणको अदालत द्वारा रद करनेका है। इस आदेशको सदाशयतासे मान कर अपील करनेकी दलील देनेके बजाय मुख्य मंत्री ममताने ही फैसला देनेवाले हाईकोर्टके न्यायाधीशपर भाजपा समर्थक होनेका आरोप लगा दिया।

ममता सरकारकी सर्वाधिक किरकिरी संदेशखालीकी शर्मनाक वारदातमें हुई। सुप्रीम कोर्टने संदेशखाली मामलेकी सीबीआई जांचका विरोध करनेपर पश्चिम बंगाल सरकारको फटकार लगायी। कोर्टने सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्तिके हितोंकी रक्षाके लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहताकी बेचने सीबीआई जांचका निर्देश देनेवाले हाईकोर्टके आदेशपर रोक लगानेसे इनकार कर दिया और पूछा कि राज्य सरकार किसी व्यक्तिके हितोंकी रक्षाके लिए सुप्रीम कोर्टसे कैसे संपर्क कर सकती है?

ऐसा करके ममताने बिना किसी भयके सरेआम अदालतकी अवमानना कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जीने कहा है कि वह इस आदेशको स्वीकार नहीं करेंगी, जो तपशिली समुदायको दिये गये अधिकार छीन लेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालयने तृणमूल कांग्रेस प्रशासनके तहत २०११ से बंगालमें जारी अन्य पिछड़ा वर्गके सभी प्रमाणपत्रोंको अवैध बताते हुए रद कर दिया। अदालतने कहा, हालांकि इससे वर्तमानमें शैक्षणिक संस्थानोंमें नौकरी या सीटें रखनेवाले या जाति प्रमाणपत्रके साथ आवेदन दाखिल करनेवाले लोगोंपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगालमें ओबीसी आरक्षणकी पूरी कहानी पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहके कार्यकालमें गठित सच्चर कमेटीकी रिपोर्टपर आधारित है। उस रिपोर्टमें देशमें मुस्लिम समुदायकी स्थितिके बारेमें विस्तृत बातें की गयी थीं। रिपोर्टमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकारके कर्मचारियोंमें केवल ३.५ फीसदी ही मुस्लिम थे। इसीको आधार बनाकर २०१० में पश्चिम बंगालकी वाम मोर्चा सरकारने ५३ जातियोंको ओबीसीकी श्रेणीमें डाल दिया और ओबीसी आरक्षण सात फीसदीसे बढ़ाकर १७ फीसदी कर दिया। इस तरह उस वक्त करीब ८७.१ फीसदी मुस्लिम आबादी आरक्षणके दायरेमें आ गयी। लेकिन २०११ में वाम मोर्चाकी सरकार सत्तासे बाहर हो गयी और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका। फिर राज्यमें तृणमूल कांग्रेसकी सरकार आयी और ममता बनर्जी मुख्य मंत्री बनीं। ममताकी सरकारने इस सूचीको बढ़ाकर ७७ कर दिया। ३५ नयी जातियोंको इस सूचीमें जोड़ा गया, जिनमेंसे ३३ मुस्लिम समुदायकी जातियां थीं। साथ ही तृणमूल सरकारने भी राज्यमें ओबीसी आरक्षण सात फीसदीसे बढ़ाकर १७ फीसदी कर दिया। ममता सरकारके इस कानूनकी वजहसे राज्यकी ९२ फीसदी मुस्लिम आबादीको आरक्षणका लाभ मिलने लगा। हाइकोर्टने ओबीसीके मामलेमें सरकारके फैसलेको निरस्त कर दिया। इसके बाद तो मानो ममताका पारा उछल गया। ममताने अदालतपर मनमाने आरोप लगा दिये। उच्च न्यायालयके विशिष्ट न्यायाधीशोंपर निशाना साधते हुए मुख्य मंत्रीने कहा कि एक न्यायाधीश कह रहा है कि मैं आरएसएसका आदमी हूं, दूसरा भाजपामें शामिल हो जाता है। आप इस तरहसे न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं और अदालतोंकी अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं। पार्टीके वरिष्ठ नेता और सुश्री बनर्जीके भतीजे अभिषेक बनर्जीने भी आरोप लगाया कि अदालतका फैसला तपशिली समुदायके लिए आरक्षण रद करनेके भाजपाके प्रयासोंका हिस्सा है। ममताके आरोपोंके जवाबमें स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहने सुश्री बनर्जीकी टिप्पणियोंको खारिज कर दिया। शाहने कहा कि ममताने कहा कि हम हाईकोर्टके फैसलेको स्वीकार नहीं करते हैं। शाहने कहा कि बंगालके लोगोंसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई मुख्य मंत्री हो सकता है जो अदालतके आदेशको माननेसे इनकार कर दे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जीने बिना किसी सर्वेक्षणके ११८ मुस्लिम जातियोंको ओबीसी आरक्षण दे दिया। कोई अदालतमें चला गया। ममता बनर्जी अपने वोट बैंकके लिए पिछड़े वर्गोंके आरक्षणको लूटना चाहती हैं और मुस्लिम जातियोंको आरक्षण देना चाहती हैं। भाजपाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाने भी एक बयान जारी कर कहा कि ये दोनों ही फैसले बताते हैं कि ममता सरकार गैर-संवैधानिक तरीकेसे तुष्टीकरणकी नीतिको आगे बढ़ा रही थी। ममता बनर्जीने वोटोंके ध्रुवीकरणकी राजनीति करनेमें कसर बाकी नहीं रखी। मुद्दा चाहे रामनवमीपर हिंसाका हो या संदेशखालीमें हिंदू महिलाओंके साथ अत्याचारोंका। राज्यमें शीर्ष संवैधानिक पदपर रहते हुए भी ममता बनर्जीने मुसलमानोंके वोट बैंकको रिझानेके लिए उल्टे भाजपा और दूसरे विपक्षी दलोंपर ही निशाने साधे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जीके मौजूदा और पूर्व कार्यकालके दौरान भ्रष्टाचारका ताडंव जमकर हुआ। शारदा घोटाला और नारद स्टिंग खुलासे, कोयला और मवेशी तस्करी, राशन घोटाले और सरकारी परियोजनाओंके लिए फंडसे लिये गये कट मनीके आरोपोंके बावजूद ममता सरकारमें कोई सुधार नहीं दिखा। इससे जाहिर है कि ममता बनर्जी मनमानी करनेपर आमदा हैं। बंगालमें शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी मामला, नगरपालिका नियुक्ति घोटाला एवं राशन वितरण घोटालेमें तृणमूल कांग्रेसके एक दर्जनसे अधिक नेता एवं मंत्री सलाखोंके पीछे हैं। इनमें पूर्व मंत्री एवं विधायक पार्थ चटर्जी, विधायक अनुब्रत मंडल, विधायक मानिक भट्टाचार्य, विधायक जिबनकृष्ण साहा प्रमुख हैं। इस कड़ीमें वन मंत्री एवं पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिकका नाम जुड़ गया है। करोड़ों रुपयेके शारदा चिट फंड घोटालेमें तृणमूलके तत्कालीन राज्यसभा सदस्य संजय बोस और तृणमूलके विधायक एवं तत्कालीन परिवहनमंत्री मदन मित्राको गिरफ्तार किया गया था। मित्रा और बोस दोनोंको सीबीआईने गिरफ्तार किया था। बंगाल पुलिसने शारदा चिट फंड घोटालेमें टीएमसीके प्रवक्ता और पार्टीके पूर्व राज्यसभा सदस्य कुणाल घोषको गिरफ्तार किया था। ममता सरकारकी सर्वाधिक किरकिरी संदेशखालीकी शर्मनाक वारदातमें हुई। सुप्रीम कोर्टने संदेशखाली मामलेकी सीबीआई जांचका विरोध करनेपर पश्चिम बंगाल सरकारको फटकार लगायी। कोर्टने सवाल किया कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्तिके हितोंकी रक्षाके लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहताकी बेंचने सीबीआई जांचका निर्देश देनेवाले हाईकोर्टके आदेशपर कोई रोक लगानेसे इनकार कर दिया और पूछा था कि राज्य सरकार किसी व्यक्तिके हितोंकी रक्षाके लिए सर्वोच्च न्यायालयसे कैसे संपर्क कर सकती है। जहांतक वोटोंकी राजनीति और बहुमत पानेसे काले कारनामोंके धुल जानेका सवाल है तो लालू यादव बहुमतके बावजूद जेल गये थे। लोकतंत्रमें कानूनसे खिलवाड़ करनेके लिए बहुमतको आधार नहीं माना जा सकता। ममता बनर्जीको इससे अवश्य ही सबक लेना चाहिए।

भारतीय दर्शनमें आनन्दमय जीवनके सूत्र

सत्य, शिव और सौंदर्य अस्तित्वका प्रसाद हैं। मनुष्यने प्रत्यक्ष रूपमें बड़ी उन्नति की है। भौतिक ज्ञान व्यापक हुआ है। विज्ञानके क्षेत्रमें आश्चर्यजनक शोध हुए हैं। भारतीय दर्शनमें आनन्दमय चिंतनके शाश्वत सूत्र हैं।

❐ **हृदयनारायण दीक्षित**

भारतीय दर्शनमें आनंदमय चिन्तनके शाश्वत सूत्र हैं। कला और सौंदर्यबोध भी शिखरपर हैं। सुख, स्वस्ति और आनन्द भी अविरल प्रवाहमान हैं। लेकिन पश्चिम प्रेरित आधुनिकताने जीवनको प्रतिस्पर्धी बनाया है। प्रतिस्पर्धी जीवनके प्रभावमें आनन्दके स्रोत व्यक्तिको आश्वस्ति नहीं देते। प्रसन्न रहना और प्रसन्न होना सभी व्यक्तियोंका मौलिक अधिकार है। प्रसन्नता सहज सुलभ है। लेकिन प्रसन्नताके सूचकांकमें दुनियाके तमाम देशोंकी स्थिति चिन्ताजनक है। पश्चिम प्रेरित आधुनिकतामें धन और भौतिक संसाधनोंको संग्रह करनेकी प्रतिस्पर्धा है। व्यक्तिवाद बढ़ा है। सामाजिक उल्लासके लिए सामूहिक जीवनकी आवश्यकता होती है। सामाजिक उल्लासकी परम्परागत व्यवस्थाका नाम उत्सव है। अकेला व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। एकाकी व्यक्ति उत्सवोंका आयोजन भी नहीं कर सकता। उत्सवोंके आनन्द घटे हैं। जीवनमें प्रसादका अभाव है और अवसादका प्रभाव। अवसाद वस्तुत: पराजित मानसिकताका परिणाम है। मित्रता सुख देती है। मित्र परस्पर सुख-दुख बांटते हैं। लेकिन मित्रता भी स्वार्थ निरपेक्ष नहीं है। एकाकी होनेमें दुख है। एकाकी अनुभव होनेमें और ज्यादा दुख है। बृहदारण्यक उपनिषदमें सृष्टिके विकासका सुन्दर वर्णन है। ऋषि कहते हैं, पहले वह अकेला था। अकेला होनेके कारण उसे आनन्द नहीं मिला। उसे अकेलेमें आनन्द नहीं आया। आकारमें सबसे बड़ी वृहदारण्यक उपनिषद् शतपथ ब्राह्मणका एक हिस्सा है। इसका अध्ययन विचारोत्तेजक है। इसमें सृष्टि सृजनके सम्बंधमें कहते हैं, पहले केवल आत्मा था। वह अकेला था-अह्मस्मि। बताते हैं कि वह भयभीत हुआ। उसने चारों ओर देखा। दूसरा कोई नहीं था। दूसरा कोई नहीं तो डर कैसा। वह निर्भय हो गया। इसका संदेश सुस्पष्ट है। आत्मबोध निर्भय बनाता है। आगे बताते हैं, उस अकेलेको आनन्द नहीं आया-स वै नैव रैमे तस्मात् एकाकी न रमते। वैसे भी अकेलेको आनन्द नहीं आता। एक कोई और हो तो अच्छा लगता है। उसने एक और की इच्छा की। उसने स्वयंको विभाजित कर दिया। वह एकसे दो हो गया। आत्मविश्वासका संकट भी अंतर्मनको आहत करता है। तनाव भी दुखके लिए उत्तरदायी है। अवसादसे अनेक बीमारियां भी बढ़ती हैं। इसका उल्टा भी होता है। लम्बे समयकी बीमारी भी अवसाद बढ़ाती है। अवसाद एक विशेष प्रकारकी मनोदशा है।

इस मनोदशामें स्वयंपर विश्वास नहीं रह जाता। आत्मविश्वासकी कमी अवसादको और भी बढ़ाती है। इसके प्रभावकी गम्भीरताको देखते हुए २०२१ में जापानमें मिनिस्ट्री ऑफ लोनलिनेस मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालयका उद्देश्य लोगोंको अवसादकी दशासे मुक्त करना था। लेकिन इस सरकारी विभागके द्वारा किये गये काम कोई परिणाम नहीं दे सके। दरअसल अवसाद जैसी खतरनाक मनोदशाको दूर करनेके लिए सरकारी विभाग बना देना पर्याप्त नहीं है। निराशा विशेष प्रकारकी मनोदशा है। आशा अभावग्रस्त व्यक्तिको भी दुखी नहीं होने देती। आशाका सीधा अर्थ है कि भविष्यमें सब कुछ अच्छा ही होगा। आशा भविष्यपर विश्वास है। निराशा अपने कर्मोंपर भी विश्वास नहीं करने देती। मनोचिकित्सकोंके लिए यह एक बीमारी है। उनका कहना है कि मस्तिष्कका एक हिस्सा मनुष्यको अपनी सुरक्षाके लिए सावधान करता है और उसके निर्णय लेनेकी विधिको भी प्रभावित करता है। ऊंचाईसे डर लगना या लिफ्टमें घबराहटका अनुभव करना दुख है। अवसादकी स्थितिमें मस्तिष्कका यह हिस्सा व्यवस्थित काम नहीं करता। विश्व स्वास्थ्य संघटनकी एक रिपोर्टके अनुसार भारत अवसादके मरीजोंके मामलोंमें अग्रणी देशोंमें है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय सामाजिक जीवनमें प्राचीन कालसे ही ईश्वर, देवी, देवता जैसे प्रतीक हैं। आशावादी अपनी आस्तिकताके कारण अपने दुख और अवसादसे छुटकारा पानेके लिए देव शक्तियोंपर विश्वास करते हैं। पश्चिम प्रेरित सभ्यता इसे अंधविश्वास कहती है। लेकिन ऐसे देव विश्वास मनुष्य शरीरकी रासायनिक क्षमताको आशावादी बनाते हैं और विषाद प्रसादमें बदल जाता है। भारतीय दर्शन परम्परामें परमसत्ताको समूचे अस्तित्वके लिए कर्ता धर्ता बताया गया है। भारतीय संस्कृतिमें यथार्थवादकी अनेक धाराएं हैं। चार्वाक मत न ईश्वरीय सत्ता मानता है और न पुनर्जन्म। उसकी घोषणा मजेदार है, जबतक जियो सुखसे जियो। उधार लो और घी खाओ-यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत्। ऋणम् कृत्वा, घृतम् पीवेत्। इस देह और संसारके परे कुछ भी नहीं है। इसे नास्तिक दर्शन माना जाता है। लेकिन यह दर्शन सुखकी गारंटी देता है। ऋग्वेदसे लेकर समस्त वैदिक साहित्यमें आनन्दप्राप्तिका दर्शन है। मनुष्य निराशामें आनन्दित नहीं होता और दुखमें भी नहीं। जीवन दृष्टिको आनन्दमार्गी बनाना जरूरी है। आशामें आश्चर्यजनक ऊर्जा होती है। छान्दोग्य उपनिषदकी कथाके अनुसार सम्पूर्ण वैदिक साहित्य और भौतिक विज्ञानकी सभी शाखाएं पढ़ लेनेके बाद भी नारद अशान्त थे। वे उस समयके प्रतिष्ठित विद्वान सनत् कुमारके पास गये। सनत् कुमारने उनके द्वारा पढ़ी सम्पूर्ण विद्याको अपर्याप्त बताया है और कहा कि आशामें बल है। इसमें सुख है। नारदने पूछा, यह सुख क्या है। सनत् कुमारने बताया, जो पूर्ण है, वही सुख है। जो अपूर्ण है वही दुख है। ऋषिने अन्य उपनिषदमें पूर्णका अस्तित्व समझाते हुए कहा है, यह पूर्ण है। वह पूर्ण है। उस पूर्णसे यह पूर्ण प्रकट हुआ है। पूर्णसे पूर्ण घटाओ तो पूर्ण ही बचता है। पूर्णता पूर्ण अनुभूति देती है। ब्रह्म पूर्ण है। ब्रह्मविद ब्रह्म अनुभूति पाते हैं। ब्रह्म अनुभूतिमें ब्रह्मानन्द है। सृष्टि आनन्दसे भरी-पूरी है। देखनेकी सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। नदी तटपर खड़े होकर जल प्रवाह देखना आनन्द है। नदीकी लहरोंका नाद संगीत सुनना आनन्द है। आकाशमें चमकते तारोंको प्रीतिपूर्ण ढंगसे देखना भी आनन्द है। वायुका स्पर्श आनन्ददायी है। मित्रका साथ विशेष आनन्ददाता है। विद्वान आचार्यके पास बैठना आनन्द है। गीत या कविता सुनना आनन्द है। संगीतके सात सुरोंको ध्यानसे सुनना भी आनन्ददायी है। कलाओंका दर्शन आनंददाता है। प्रकृति बहुरुपिया है। सर्वत्र रूप ही रूप हैं। पेड़ोंपर बैठे चहकते गीत गाते पक्षियोंको देखना सुनना आनन्द है। पक्षियोंके छोटे बच्चोंको सहलाना विशेष आनन्द है। बच्चे बिल्लीके हों या कुत्तोंके अथवा अन्य किसी जानवरके, उनको सहलाना, उनके प्राकृतिक व्यवहारको ध्यानसे देखना भी आनन्द है। सूरज उगनेसे पहले लालिमासे भरी पूरी ऊषाको देखना विशेष आनन्द है। माता-पिताका आशीर्वाद प्राप्त करना भी आनन्द है। स्वयंको प्रकृति सृष्टिका अविभाज्य अंग जानना भी आनन्द है। प्रकृतिमें यत्र तत्र सर्वत्र आनन्दके प्रोत्साहक रूप हैं। उन्हें देखना सुनना भी आनन्द है। आनन्द रस आपूरित जीवन दृष्टिमें समूचा ब्रह्माण्ड आनन्दसे भरा-पूरा छलकता अमृतघट होता है। यह सहज सुलभ है। तब विषादकी कोई स्थिति नहीं होती। आनन्दमयतामें जीवन प्रसादसे भर जाता है।

आत्मबोध

प्रभुका स्मरण

❐ **बाबा हरदेव**

एक व्यक्ति पेड़के नीचे बैठकर परमात्मासे शिकायत करने लगा, हे प्रभु तुमने मुझे दुनियामें पैदा ही क्यों किया। यदि पैदा किया है तो थोड़ा-बहुत धन भी दे देता। मुझे गरीब क्यों बनाया। अचानक उसका ध्यान अपने पीछे जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि गाजर खाकर जो उसके पीछेका हिस्सा उसने पीछे फेंका है वह टुकड़ा उठाकर कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है। उस व्यक्तिके पास तो गाजरें भी नहीं हैं। वह इससे भी ज्यादा भूखा था। उसके पास शायद एक पैसा भी नहीं था। इसलिए इसके बचे हुए गाजरके टुकड़े उठा-उठाकर खा रहा है। यह देखकर उस व्यक्तिने परमात्माका लाख-लाख शुक्र किया कि हे प्रभु! तेरा धन्यवाद तूने मुझे खानेको गाजर तो दी है। एक ये आदमी है जिस बेचारेके पास ये भी नहीं है। यह तो मेरेसे भी गरीब है। उसने हंसते हुए बची हुई सारी गाजरें दूसरे व्यक्तिको दे दी। कहनेका भाव यह है कि प्रभुकी मर्जीमें खुश रहें। जितना प्रभुने दिया है उसमें संतोष करें। दुनियाको देखकर अपने मनको व्याकुल न करें कि ऐसी गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान हमारा क्यों नहीं। यदि कोई अमीर है, करोड़पति है, परन्तु उसे अन्दर शांति नहीं, खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं तो उसके अमीर होनेका उसे क्या लाभ। जो खुशीके गीत नहीं गाता, जो प्रभुके गुण नहीं गाता, जो प्रभुका शक्र नहीं मनाता, वह धनवान नहीं है क्योंकि वह संतोष धनसे खाली है। प्रसन्नता दो तरह की होती है। आन्तरिक प्रसन्नता एवं बाहरी प्रसन्नता। बाहरी प्रसन्नताके भी दो भेद हैं। सामाजिक और पारिवारिक। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो किसीकी भी कोई बात अच्छी नहीं लगती, चाहे ऊपरसे सबका मन रखनेको ठीक व्यवहार करते हों। शरीरकी बीमारी एवं कमजोरी पूर्ण प्रसन्नतामें रुकावट बनती है। मानसिक तनाव हो तो भी बाहरी खुशी वास्तविक खुशी नहीं लगती। जो मनसे परेशान है उसे चाहे शादीमें ले जाओ, बाहरसे भले ही वह नाचने लगे परन्तु अन्दरसे मन खुश नहीं है। कुछ अच्छा नहीं लगता। बिना बातके क्रोध आ जाता है, व्याकुलता छायी है। तनका स्वस्थ होना प्रसन्नतासे संबंध रखता है। लेकिन कुछ मनुष्य फिर भी खुश रहते और मुस्कराते रहते हैं। हंसते एवं मुस्कराते रहनेसे दुख भी आधा रह जाता है। क्योंकि वातावरणका मनपर काफी प्रभाव पड़ता है। आप सत्संगमें जाते हैं तो मनकी वृत्ति बदल जाती है, तनाव कम हो जाता है। यदि आप दृढ़तासे ठान लें कि मैं हर हालमें खुश रहूंगा। कोई कैसा भी हो, मुझे परेशान नहीं कर सकता। मैं विचलित नहीं हो सकता। यदि स्वयंको शांत रखना है। कोई बात हो भी जाय तो प्रभुका सुमिरन शक्ति देगा।

भविष्यकी राजनीतिका मापदण्ड बनेगा चुनाव

❐ **शंभु राय**

दुनियाका सबसे बड़ा लोकतन्त्र भारत अपना महापर्व मना रहा है। भारतीय लोकतंत्र भी विभिन्न झंझावातोंको झेलते हुए मजबूत संवैधानिक कवचके तहत जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और मजबूती पाया है, वह दुनियाके लिए एक नजीर है। राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा, सरकारीकरण, गरीबी जैसे मुद्दे इनके एजेंडेमें प्रारम्भमें शामिल रहे और इन मुद्दोंके रथपर सवार हो सत्ताके सिंहासनपर आसीन होते रहे। कालांतरमें अलगाववाद, आतंकवाद पसरने लगा। सत्तापर काबिज लोगोंने पहले तो सत्ता हथियानेमें उसकी मदद ली, फिर बादमें वही उनके लिए भस्मासुर बन बैठे। फिर भी उन भस्मासुरोंके प्रति कठोरता न अपनाकर तत्कालीन सत्ताधारियोंने भूल की और इस मुद्देको मजबूतीसे पकड़ लिया वर्तमान सत्तासीनोंने और जब सत्तापर काबिज हुए तो सख्ती दिखाते हुए अलगाव एवं आतंकवादपर कठोर काररवाई की और करते जा रहे हैं। विकास एवं प्रगतिका महल शांति, सहयोग एवं विश्वासकी बुनियादपर ही खड़ा किया जा सकता है। वर्तमान सत्ताधारीने इस राहपर चल उल्लेखनीय सफलता भी पायी है। सरकारकी निजीकरण एवं उदारीकरणको अपने एजेंडेमें शामिलकर स्टार्टअप एवं निजी उद्योगोंको बढ़ावा दे एवं तमाम वित्तीय सुधार कर विकसित भारतके कतारमें खड़ा करने और विश्वकी पांचवी अर्थव्यवस्था बनानेका प्रयास भी सराहा जा रहा है। राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षापर बेहतर काम हुआ है। विदेश नीति तो वही निर्गुटतावाली परन्तु बड़ी मजबूतीसे सही को सही और गलतको गलत कहनेकी हमारी दृष्टिको दुनियाने सराहा है और हम पंच बननेकी स्थितिमें हैं। यदि हम याद करें तो एक बार बोफोर्स तोप सौदेमें हुए घोटालेके नामपर सरकार भी बदल गयी थी। मंडल-कमंडल भी मुद्दा रहा है। कितने मंडलके मसीहा अपने समाजके वंचितोंके लिए अपनी सुविधा छोड़े। कितने कमंडल धारी भगवान रामके त्याग समर्पण, समावेशी, समदर्शी मार्गके अनुगामी बने? जनता सब देखती है और मौन होकर सत्तापर बैठाती एवं उतारती है। इस चुनावमें भी दलोंने अपने अपने घोषणा-पत्र जारी किये हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अलगाववाद, आतंकवाद सहित विकासके नये कीर्तिमान स्थापित करनेका दिवा स्वप्न दिखानेवाली पार्टियोंमेंसे कितनोंने प्रदूषण जैसे छिपा रुस्तम आतंकवादीसे लड़नेका संकल्प दोहराया है। एकाधको छोड़ दिया जाय तो ऐसे सामयिक मुद्देके प्रति असंवेदनशील रहना इनकी अदूरदर्शिताका परिचायक है। राजनीतिक दलोंने जाति धर्म एवं क्षेत्रवादके नारोंमें उलझा कर सत्तापर काबिज होनेका कुत्सित प्रयास जबसे प्रारंभ किया। घोषणा-पत्र बेमानी लगने लगा परन्तु तब और अबके भारतमें बदलाव आया है। आज राजनीतिक दलोंके लिए घोषणा-पत्र औपचारिकताभर रह गयी हो परन्तु आजका युवा इसकी समीक्षा करना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलोंके जाति धर्मके उकसावे एवं बहकावेमें न पड़ मजबूत, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारतकी सोच रखने लगा है। यह मजबूत, प्रबुद्ध और प्रगतिशील, प्रौढ़ लोकतन्त्रका संकेत है। यदि हम वर्तमान सरकारकी उपलब्धियों और कार्योंकी समीक्षा करें तो पाते हैं कि इसके घोषणा-पत्रके तमाम वादे पूरे हुए। हां, महंगी और बेरोजगारीपर सरकारी आंकड़े जो बोलें परन्तु हकीकत सामने है कि सरकार इसपर नियंत्रण करनेमें असफल रही है। यह भी ध्रुव सत्य है कि किसीके आने जानेसे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जितनी बड़ी जुमलेबाजी चुनावी भाषणोंमें कर ली जाय परन्तु आनेवाली सरकारको इन दोनों मुद्दोंपर संजीदगी दिखानी होगी और कृषि आधारित उद्योग धंधोंको प्राथमिकता देनी ही होगी और कठोर जनसंख्या नीति लागू करनेका जज्बा दिखाना होगा। गांवोंके शिक्षा दुस्वास्थ्यके स्तरको शहरोंके समानांतर और सुलभ एवं सस्ता करना होगा, क्योंकि अब भी भारतकी आत्मा गांवोंमें ही बसती है। तभी शहरोंकी ओर पलायन रुकेगा और विकसित भारतका सपना पूरा होगा। सरकारने अपने घोषणा-पत्रके तमाम वादेको पूरा की, विकसित भारतके राहपर चल रहे सरकारी दलको फिर भी बहुमतके लाले पड़ते दिख रहे हैं जबकि सरकारके मुखियाकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ी है और बढ़त कायम है। यह भी सच है कि पिछले चुनावोंमें वोट उन्हींके नाम एवं अगुवाईमें मिलता रहा है और इस बार भी चेहरा वही हैं। सत्तारूढ़ दलके कार्यकर्ता अपने नेताओंसे उपेक्षाके शिकार हो उत्साहसे लबरेज नहीं हैं तो विपक्षी कार्यकर्ता किसी तरह सत्तातक पहुंचनेके लिए छटपटा रहा है। जनता नाराज है सत्तारूढ़ दलके नेताओंसे परन्तु चाहती है प्रधान सेवककी पुनरावृति। जनता यह भी चाहती है कि भ्रष्टाचारपर प्रहार हो परन्तु अपने-पराये भेद न हो। नीति-नियतमें छेद न हो। गठबंधनके खींचतान और स्थिर सरकार न दे पानेका इतिहास भी वर्तमान सत्तापक्षके लिए सत्ताके पायदानतक पहुंचनेमें संजीवनीका काम करता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती गठबंधनोंका हश्र देख चुका है देश। यह चुनाव भविष्यकी राजनीति एवं नीतिका मापदंड है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

योगी राज में दंगा भी बंद और दंगाई भी बंद: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, सपा राज में खुली जीप में कानून को खुली चुनौती देते थे माफिया, हर महीने होते थे दंगे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/गाजीपुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा है कि योगी सरकार में आज दंगे भी बंद हो चुके हैं और दंगाई भी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा सरकार के समय माफिया खुली जीप में बैठकर कानून को खुलेआम चुनौती देते थे, हर महीने दो से तीन दंगे हुआ करते थे। पीएम मोदी शनिवार को यहां आरटीआई मैदान में पार्टी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह वंचितों, दलितों और पिछड़ों के अधिकार के चौकीदार हैं। उनके रहते कोई भी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध नहीं लगा सकता। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत मां कामाख्या और महाहर धाम को प्रणाम करते हुए कहा कि बनारस वालों के लिए गाजीपुर आना ऐसे ही है जैसे बगल के मोहल्ले में आ गये हों। उन्होंने कहा कि वह गाजीपुर में प्रचार करने नहीं, बल्कि माताओं-बहनों का आशीर्वाद लेने आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजीपुर का सामर्थ्य क्या है ये इतिहासकारों से ज्यादा देश की सीमाओं को पता है। ये पराक्रम और शौर्य की भूमि है। गाजीपुर का गहमर गांव का नाम ही काफी है। यहां के हर घर से जांबाज निकलते हैं, ये गौरव और किसी को नहीं मिला है। पूरा देश इस मिट्टी का ऋणी है। उन्होंने कहा कि सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिये जाते थे। सपा सरकार में हर महीने दो से तीन दंगे होते थे। इसका नुकसान हर एक को होता था। योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद हैं और दंगाई भी बंद है। वोट के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कहा था कि माफिया की इंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर माफिया के चरणों में जाकर बैठ गये। सपा ने माफिया को पाला पोसा और उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकता वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों ने गाजीपुर के साथ विश्वासघात किया है।

आजादी के बाद कांग्रेस ने कसम खा ली थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगी। यहां के लोग गरीबी में घुट घुटकर जीने को मजबूर रहे। यहां की तकलीफ को सबसे पहले हमारे गहमरी बाबू ने उठाया था। उन्होंने आंख में आंसू लेकर नेहरू जी को यहां की स्थिति बताई और कहा कि कैसे यहां के लोग जानवरों के गोबर से गेहूं बीनकर खाते थे। कांग्रेस ने उसमें भी राजनीतिक मौके तलाश लिये। सियासी ड्रामे किये। आंख में धूल झोंकने के लिए पटेल आयोग बना, रिपोर्ट आई और फाइल को धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर गरीब को मुफ्त राशन दे रही है।

सुशासन व विकास का नया मॉडल बनेगा गाजीपुर: मुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गाजीपुर

पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने बदलते भारत को देखा है। 2014 से पहले और 2024 के भारत में जमीन-आसमां का अंतर आया है। 2014 से पहले अविश्वास व पहचान का संकट था, लेकिन आज पहचान का संकट नहीं है। दुनिया भारत को अब सम्मान की दृष्टि से देखती है। पीएम मोदी दुनिया में जहां भी जाते हैं, पलक पांवड़े बिछाकर पूरा देश उनके स्वागत में उमड़ पड़ता है। दुनिया में भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। कोई विदेशी पूछता है कि आप कहां से आए हैं, जवाब में भारत बोलने पर वह सम्मान से कहता है कि अच्छा, मोदी के इंडिया से। उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आरटीआई मैदान में गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय के लिए वोट मांगा। सीएम योगी ने अपील की कि 'अबकी बार-400 पार' में गाजीपुर भी जुड़े। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजीपुर में पांचवीं बार आगमन हुआ है। हर बार वे गाजीपुर को नई पहचान दिलाने आए हैं। यहां आकर कभी महाराज सुहेलदेव के नाम पर नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की तो कभी महर्षि विश्वामित्र के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में आए। विकास के इन्हीं कार्यों की बदौलत पूरा देश कह रहा- फिर एक बार मोदी सरकार, अबकी पार-400 पार। 400 पार की बात सुनते ही कांग्रेस, सपा, राजद समेत इंडी गठबंधन के सभी दल चारों खाने चित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 400 सीटों पर लड़ने का सपना ही नहीं देखा। वहीं मोदी के नेतृत्व में देश के लिए किए गए योगदान की बदौलत जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि एक समय था, जब बेटी-व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। गाजीपुर इसका जीता जागता उदाहरण था। गाजीपुर हो आजमगढ़, मऊ हो या आसपास के जनपद भय और आतंक के साये में जीते थे। आपका आशीर्वाद भाजपा को मिला तो अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और बड़े-बड़े माफिया का रामनाम सत्य भी हुआ। हम बेटी-व्यापारी की सुरक्षा के साथ समाज को संतुलित विकास के मार्ग पर बढ़ाकर आत्मनिर्भर व विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे।

देश की कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं इंडी गठबंधन के दल: योगी

- सीएम ने कहा, ममता के धमकाने वाले बयान का मुंहतोड़ जवाब देंगे भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन के अनुयायी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन जैसी वैश्विक ख्याति की सनातनी-आध्यात्मिक संस्थाओं पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी समेत पूरे इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, राजद, सपा और इंडी गठबंधन के सभी दल हिंदू विरोध की राजनीति करते हैं।

शनिवार पूर्वाह्न लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बलिया रवाना होने से पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और उसके जो भी सहयोगी दल हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, बंगाल में टीएमसी या अन्य ऐसे भी जितने दल हैं, उनकी पूरी राजनीति ही हिंदू विरोध पर आधारित है। उनके लिए देश की तुलना में सत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। देश की कीमत पर ये दल सत्ता चाहते हैं और कोई भारतीय इसे स्वीकार नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन के खिलाफ टीएमसी सरकार की मुखिया ममता बनर्जी के विवादित और धमकी भरे बयान को संदर्भित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ, दोनों भारत की प्रतिष्ठित धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर पूरे देश और दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसी तरह भारत सेवाश्रम संघ भी सनातन हिंदू धर्म की बहुत ही प्रखर आध्यात्मिक संस्था है। स्वामी प्रणवानंद के मूल्यों और आदर्शों को लेकर भारत सेवाश्रम संघ ने देश और दुनिया में भारत के सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इन दोनों संस्थाओं ने सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को भी देश और दुनिया में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के सभी दलों कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी आदि की प्रवृत्ति ही हिंदू विरोधी राजनीति की है। सनातन धर्म का विरोध करना, हिंदू धर्म के मूल्यों और आदर्शों का विरोध ही उनकी नींव है। उसी के अनुरूप उनके बयान और कदम सामने आ रहे हैं। ये बयान उनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करते हैं। योगी ने कहा कि जिस स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिस रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ ने अध्यात्म और संस्कृति के जिस वृहद जागरण अभियान को देश-दुनिया मे बहुत ही अच्छे सेवा प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ाया है।

सीएम ने की गोसेवा, बच्चों पर लुटाया दुलार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में गोसेवा की। मंदिर में दर्शन-पूजन करने आए बच्चों को पास बुलाकर उन पर प्यार-दुलार लुटाता। चॉकलेट देकर और खूब पढ़ने-आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें विदा किया। शुक्रवार को गोरखपुर मंडल में एक के बाद एक पांच चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शाम को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर स्थित अपने आवास में रात्रि प्रवास करने के बाद शनिवार सुबह उनकी दिनचर्या परंपरागत रही। महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर जाकर मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात हर बार की तरह वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते हुए वह गोशाला में पहुंचे। यहां गोवंश को उनके नाम से आवाज देकर अपने पास बुलाया। उन्हें रोटी-गुड खिलाकर उनकी सेवा की। थी उन्होंने गोशाला के स्वयंसेवकों को भीषण गर्मी में गोवंश की देखभाल के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों को लेकर निर्देशित किया।

छठे चरण के चुनाव में जनता ने ईवीएम को कमलमय कर दिया: जेपीएस राठौर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 05 चरणों में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर जो निर्णायक बढ़त बना ली थी, वह छठवें चरण की 14 सीटों में भी बरकरार हैं। अब कहीं कोई संदेह नहीं बचा है मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत गठबंधन देश में 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही हैं। मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन छह चरणों में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है उसने विपक्ष के छक्के छुड़ा दिये हैं।

जेपीएस राठौर ने कहा कि विपक्ष के पास नेता, नीति व नीयत का अभाव है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की योजनाओं तथा निर्णयों पर जनता अपनी मुहर लगा रही है और कमल के फूल से ईवीएम भरती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता के दिल में मोदी जी हैं और मोदी के दिल में देश की जनता है। राठौर ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता अपने बयानों से लोगों को भड़काने का कुकृत्य करने में लगे हैं। स्थिति यह हो गई कि उनकी रैलियों में आने वाले गुंडे और बलवाई अराजकता पर उतारू है। जन विश्वास खो चुके इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बुरी तरह पराजित हो चुके हैं। आज आजमगढ़ में भी सपा प्रमुख के पारिवारिक सदस्य की बुरी तरह पराजय को जनता ने सुनिश्चित कर दिया है। इनके नेताओं की संदिग्ध नीयत और नीति का पर्दाफाश हो चुका है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज के चुनाव में जनता ने ईवीएम को कमलमय कर दिया है। परिणाम भाजपा के पक्ष में है, हताशा और निराशा में सपा और इंडी अलायंस के नेता और समर्थक भी अपनी स्पष्ट हार को देखते हुए वोट देने के लिए नहीं निकले हैं। चुनाव के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर चुनाव आयोग, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों सहित सभी मतदाताओं का अभिनंदन।

चुनाव परिणाम के साथ ही यूपी से भाजपा का हो जाएगा पूरी तरह सफाया: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता अपने आप भाजपा से चुनाव लड़ रही है। यह पहला लोकसभा चुनाव है जब चुनाव के पहले चरण से ही जनता ने अपने हाथों में चुनाव की कमान सम्हाल ली है। जनता के सामने महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, अत्याचार के अलावा भूख, भय, नौकरी, रोजगार के साथ अपना हक और सम्मान के मुद्दे है। इन दिनों जो माहौल है उसमें पीडीए को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम आएंगे तो भाजपा का उत्तर प्रदेश से पूरी तरह सफाया हो चुकेगा। अखिलेश यादव ने आज लोकसभा देवरिया से कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के लिए पथरदेवा में और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की गोरखपुर लोकसभा से प्रत्याशी काजल निषाद के पक्ष में रामगढ़ ताल के निकट विशाल चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की।

अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग 2014 में आए थे 2024 में उनकी विदाई तय है। जो लोग चार सौ पार का नारा दे रहे थे वे चार सौ हार रहे हैं। 140 करोड़ की जनता भाजपा को 140 सीटों पर ही निपटा देगी। भाजपा के प्रति हर तरफ आक्रोश है। लोग भाजपा के झूठे वादों पर भरोसा नहीं कर रहे है। भाजपा के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। उनसे धुआं निकल रहा है।

यादव ने कहा कि भाजपा ने लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाए थे। उनकी हर बात झूठी निकली। उनका हर वादा झूठा निकला। 10 साल की सरकार में भाजपा ने किसानों के लिए संकट पैदा किया है। जो आम लोगों को सुविधाएं मिल रही थी। वह भी नहीं मिल रही है। एक तरफ वे लोग है जो संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते है और एक तरफ वो लोग है जो संविधान बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। उन्हें न तो अपने उत्पाद की सही कीमत मिली और नहीं उनकी आय दुगनी हुई। उल्टे सरकार ने बिजली महंगी कर दी। खाद की बोरी से 5-5 किलो करके 10 किलो खाद चोरी कर ली। डीएपी खाद लेने गए तो नैनो दे दी। इससे किसान की पैदावार चौपट हो गई और नैनो वाले उद्योगपति भारत छोड़ गये। यादव ने कहा कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा की सरकारों ने 10 परीक्षा भर्ती के पेपर लीक करवा दिये जिससे कि नौकरी न देनी पड़े। नौकरी देते तो आरक्षण भी देना पड़ता। भाजपा ने अग्निवीर योजना लाकर सेना की नौकरी को आधी अधूरी नौकरी कर दी। जिसमें शहीद का दर्जा भी नहीं है। नौजवान सेना की भर्ती के जो सपने देखता था उसके सपनों को भाजपा ने तोड़ा है।

इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना बंद करके पुरानी सेना भर्ती चालू की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरूपयोग कर भाजपा ने पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से चंदा वसूली की। कोरोना काल में जो वैक्सीन लगवाई उस कम्पनी से भारी चंदा वसूल लिया। जिन्होंने चंदा दिया उन्होंने जमकर मुनाफा कमाया। इलेक्टोरल बांड के जरिये कम्पनियों से जमकर चंदा वसूली की गई। कम्पनियों ने भाजपा सरकार को इलेक्टोरल बांड देकर जमकर मुनाफा कमाया जिससे हर चीज महंगी हो गयी। प्रदेश में निवेश के नाम पर बड़े-बड़े आयोजन हुए पर न उद्योग लगे नहीं किसी नौजवान को रोजगार मिला। फौज में पक्की नौकरी की जगह 4 साल की नौकरी कर दी। भाजपा कुछ भी कर सकती है। किसी को कुछ भी पता नहीं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लगी क्या किसी को पता था। भाजपा कब क्या कर दे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।

यादव ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को खतरा है। भाजपा पूंजीपतियों की संरक्षक है। भाजपा ने बड़े उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रूपये का कर्ज माफ कर दिया। गरीब किसान का कर्ज नहीं माफ किया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारन्टी दी जाएगी। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा।

पीएम मोदी व सीएम योगी आज मीरजापुर में

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार 26 मई को मीरजापुर, मऊ एवं देवरिया में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे। मीरजापुर में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा में मौजूद रहकर जनता को सम्बोधित करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुबह 9:30 बजे बरकछा कलां, मडिहान रोड़, मीरजापुर में आयोजित मीरजापुर एवं राबर्ट्सगंज लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को सम्बोधित करेंगे तथा दोपहर 11:15 बजे भुडसुरी, मेवाड़ी कलां, रतनपुरा मऊ में आयोजित घोसी, बलिया तथा सलेमपुर लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को सम्बोधित करेंगे। इसके पश्चात् दोपहर 1 बजे पचलडी मार्ग, रूद्रपुर, देवरिया में आयोजित बांसगांव व देवरिया लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को सम्बोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार 26 मई को मीरजापुर, वाराणसी, गाजीपुर व गोरखपुर के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे बरघाकला मझवां, मीरजापुर में आयोजित माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा में सम्मिलित रहेंगे।

तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है: पाठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को घोसी लोकसभा अन्तर्गत बलिया की रसड़ा विधानसभा में विशिष्टजनों की चौपाल को संबोधित किया। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देश में भाजपा का सुशासन स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की रैलियों का मोर्चा अराजक तत्वों ने संभाला है, इसलिए अब जनता इनसे परमानेंट मुक्ति चाहती है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की रैलियों में आजकल अराजक तत्व पहुंच रहे हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि सपा के चाल और चरित्र में कोई बदलाव नहीं आ सका है। कहा कि प्रदेश में खुशहाली का वातावरण है बहन-बेटी सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरियां योग्यता के अनुसार मिल रही हैं। यह सब सपा सरकार की विदाई और भाजपा की जन कल्याणकारी सरकार की बदौलत संभव हुआ है। पाठक ने कहा कि भाजपा ने श्रीराम मंदिर बनाने के लिए वर्षों से संघर्ष जारी रखा और जन आकांक्षाओं के अनुरूप अब अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला, व्यापारी, नौजवानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

यूपी में बिजली खपत का बना नया रिकार्ड

लखनऊ। प्रदेश में बिजली की खपत और एक समय में अधिकतम मांग व आपूर्ति का बीते शुक्रवार को नया रिकार्ड बना। शुक्रवार को प्रदेश में 61 करोड़ 30 लाख 45 हजार यूनिट बिजली का उपभोग लोगों ने किया। वहीं इस दिन रात 8.57 बजे बिजली की अधिकतम मांग 29147 मेगावाट पहुंच गई जो कि अब तक की सर्वाधिक मांग व आपूर्ति का नया रिकार्ड है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल का कहना है कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी माध्यमों से अधिकतम बिजली लिया जा रहा है। बिजली की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। गर्मी को देखते हुए आने वाले दिनों में बिजली की मांग और अधिक बढ़ सकती है।

प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने वाराणसी में किया रोड शो

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ वाराणसी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से मौजूदा सांसद डिंपल यादव ने शनिवार को वाराणसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में रोड शो किया। दोनो नेताओं ने दुर्गाकुंड से लेकर रविदास मंदिर तक लगभग चार किलोमीटर का रोड शो किया। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा, सपा सांसद डिंपल यादव एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी ने रोड शो की शुरुआत में एक्स पर लिखा, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी काशी में रोडशो। वाराणसी में इंडिया की आंधी, जीतेगा इंडिया। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने शहर के दुर्गाकुंड स्थित कुष्मांडा माता के दर्शन पूजन कर रोड शो की शुरुआत की। इसके पूर्व प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बाबतपुर हवाई अड्डे से सीधे बाबा श्री काल भैरव के दरबार पहुंचीं। रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने जगह-जगह रुक कर जनता से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के लिए समर्थन मांगा। रोड शो के दौरान खुली गाड़ी में प्रियंका, डिंपल के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी लोगों का अभिवादन करते हुए दिखे। रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। रास्ते में जगह-जगह गुलाब की पंखुड़ियों से लोगों ने रोड शो का स्वागत किया। सड़क के दोनो और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराते हुए प्रियंका-डिंपल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर प्रियंका और डिंपल भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थीं। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि दोनों महिला नेताओं ने दुर्गा मंदिर से रोड शो की शुरूआत की, जो मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर, संकटमोचन मंदिर, रविदास गेट, लंका महामना प्रतिमा तक पहुंचा। यहां से ट्रॉमा सेंटर के गेट पर पहुंचने पर डिंपल यादव किसी कारणवश रोड शो से निकल कर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं। यहां से प्रियंका गांधी गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के साथ भगवानपुर, छित्तूपुर, सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर तक गईं, जहां दर्शन पूजन के बाद रोड शो समाप्त हो गया। यह रोड शो करीब दो घंटे तक चला। वाराणसी में सातवें चरण के तहत एक जून को मतदान होगा। यहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से है।

जनता ने इंडी गठबंधन को बहुमत देकर भाजपा को चारों खाने चित किया: राजेन्द्र चौधरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि पहले ही पांच चरणों में लोकसभा चुनाव के मतदान में प्रदेश के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत देकर भाजपा को चारो खाने चित कर दिया है। आज 25 मई छठवें चरण के मतदान में मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत देकर भाजपा का पूरी तरह से सफाया कर दिया है।

छठवें चरण के चुनाव में आज सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संतकबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। चौधरी ने कहा कि भाजपा को भी अपनी हार का अंदाजा हो गया है इसलिए वह अराजकता और सत्ता का दुरुपयोग करने पर आमादा हो गई है। लोकतंत्र में भाजपा द्वारा किया जा रहा नंगा नाच शर्मिंदा करने वाला कृत्य है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालना लोकतंत्र को कलंकित करना है। अम्बेडकर नगर में तो टांडा में एक बीएलओ को भाजपाईयों ने पीटा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कराया। यहां से लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा को नज़रबंद रखा गया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

एक्स से

हजारों लोगों की जान लेने वाले युद्ध के बीच हमें एकमात्र इसी विकल्प को जीवित रखना चाहिए, जो इजरायलियों और फलस्तीनियों को समान रूप से राजनीतिक समाधान देता है और वह है, शांति व सुरक्षा के साथ जीते दो पड़ोसी राष्ट्र!- जोनास गहर स्टोर/ प्रधानमंत्री, नॉर्वे

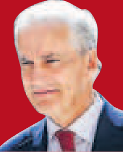

काशी में मोदी पर पूर्वांचल में लड़ाई

पूर्वांचल में काशी को छोड़कर हर सीट पर कड़ा संघर्ष है। कहीं बाहुबल का दबदबा, कहीं विरासत, तो कहीं मंत्री पद का रुतबा कसौटी पर कसा जा रहा है। आगामी 4 जून का फैसला सिर्फ जय-पराजय नहीं, बल्कि नया सियासी चलन भी गढ़ने जा रहा है।

स्कैन करें
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

आजकल

ये पंक्तियां काशी से। पिछले दस साल से यह देश के प्रधानमंत्री की निर्वाचन भूमि रही है। इस नाते देश-दुनिया की निगाहें इस सरजमीं पर आ टिकी हैं।

प्रधानमंत्री ने यहां के लोगों से दिली अपनापा बनाया है, लिहाजा उन्हें कोई खास चुनौती नहीं दिखाई पड़ती। बीएलडब्ल्यू, यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (पूर्व में डीएलडब्ल्यू) के सामने खोखा लगाने वाले रिंकू के बयान से इसकी झलक मिलती है। जब प्रधानमंत्री यहां आते हैं और जितने समय तक रहते हैं, उतने वक्त के लिए रिंकू को अपना खोखा हटाना पड़ता है। उन सहित दर्जनों लोगों के लिए यह व्यावसायिक हानि का मामला है, पर वे क्षुब्ध नहीं हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए इतना तो होना ही चाहिए।

'मोदी भक्ति' में काफी कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर लोगों में वे अकेले नहीं हैं। गुजरे मंगलवार को मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चुनिंदा महिलाओं से मिले थे। उसी दौरान मुझे अचानक शिवदासपुर में कुछ महिलाएं मिलीं। पुलिस के घेरे के पीछे वे मायूस खड़ी थीं। कौतूहलवश मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में ऐसे क्यों खड़ी हैं? उनका जवाब था कि हम मोदी जी से मिलने के लिए जाना चाहते थे, परंतु कुछ देर हो गई और सुरक्षा व्यवस्था लागू हो गई। अब जा तो नहीं सकते, लेकिन वह इस रास्ते से निकलेंगे, इसलिए उनके इंतजार में रुके हुए हैं। उस वक्त तापमान 40 डिग्री से अधिक था और हवा में जानलेवा तपिश थी। मैंने उनसे पूछा कि अभी प्रधानमंत्री को आने में काफी समय लग सकता है, आप तब तक यूं ही खड़ी रहेंगी! जवाब मिला- कोई बात नहीं, अब घर से निकले हैं, तो सोचा कि हाथ हिलाकर उनका अभिवादन ही कर लें।

हालांकि, करौंदी जैसे मोहल्लों में, जहां अतिक्रमण की वजह से लोगों के घर तोड़े गए हैं, कुछ लोग कुपित भी हैं। मगर इससे बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। उनके आवास सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए गए थे, जिससे बड़ी तादाद में राहगीरों को लाभ मिलता है। नई दिल्ली की सरकार ने तरह-तरह के लाभार्थियों की नई फौज खड़ी की है।

कांग्रेस के अजय राय नरेंद्र मोदी के मुकाबिल हैं। वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पुरानी सियासी शख्सियत हैं। उनकी कोशिश है कि वह जीत के अंतर को अधिक से अधिक पाट सकें। उधर, भाजपा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बढ़त की हैट्रिक लगाएं। मोदी ने 2019 के चुनाव में 2014 से ज्यादा वोट हासिल किए थे।

बनारस ऐसा शहर है, जहां वामपंथी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, जातिवादी और संप्रदायवादी चाय या पान की दुकान पर एक-दूसरे की बात काटते नजर आते हैं। ये लोग हार और जीत के अंकगणित से परे हमेशा प्रतिरोध का रसायन रचने में मशगूल रहते हैं। अगस्तकुंडा के चक्रवर्ती मोशाय इन सियासी तुर्कों पर बनारसी पिंगल बोलते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। ये लोग कहें कुछ भी, पर अंत में मोदी को ही वोट दे आते हैं।

कौन कितने मत हासिल करेगा, इसके विमर्श में मैं चाहकर भी अन्य प्रत्याशियों के नाम नहीं ले पा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी ने अतहर जमाल लारी को खड़ा जरूर किया है, पर वह चर्चा के केंद्र में नहीं आ सके हैं।

काशी का अपना रंग-ढंग जो हो, मगर आसपास की शेष 11 सीटों पर रोमांच के तमाम रंगों का साया है। कभी बनारस का ही हिस्सा रहे चंदौली से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लंबा समय महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के निर्वाह में बिताया है। उनकी गिनती गंभीर नेताओं में होती है। इस बार उन्हें 'इंडिया' ब्लॉक से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह चुनौती दे रहे हैं। वह समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न पर लड़ रहे हैं।

चंदौली और वाराणसी से सटी हुई सीट है मिर्जापुर। यहां से मोदी कैबिनेट की एक और सदस्य अनुप्रिया पटेल किस्मत आजमा रही हैं। अनुप्रिया अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पुत्री हैं और केंद्र में मंत्री हैं। वह अपना दल (एस) की अध्यक्ष हैं और एनडीए की सदस्य भी। अनुप्रिया को इंडिया ब्लॉक की ओर से रमेश बिंद चुनौती दे रहे हैं।

पड़ोसी रॉबर्ट्सगंज से अपना दल की रिंकी कोल और भाजपा के पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। रिहंद, अनपरा और बीना जैसी महाकाय परियोजनाओं के बावजूद यहां के आदिवासी आज भी विकास की राह जोह रहे हैं। प्रधानमंत्री की 'हर घर जल' जैसी योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है, पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। कभी विस्तार से उन पर लिखूंगा, फिलहाल चुनावी राजनीति पर लौटते हैं।

अनुप्रिया की तरह भदोही में तृणमूल प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी और बलिया में नीरज शेखर अपनी विरासत को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज फिलहाल राज्यसभा में भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले भी वह दो बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा की चौहद्दी में दाखिल हो चुके हैं। नीरज को समाजवादी पार्टी के सनातन पांडेय से चुनौती मिल रही है। इस सीट पर ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच पुरानी खींचतान है।

समीपस्थ गाजीपुर में मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी ताल ठोक रहे हैं। उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी की जेल में विवादास्पद स्थितियों में हुई मौत के बाद उनके समर्थकों को लगता है कि उन्हें सहानुभूति का लाभ मिलने जा रहा है। अफजाल एक आपराधिक मामले में पहले ही सांसदी गंवा चुके हैं। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अगर उनके खिलाफ गया, तो उनकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी। एहतियातन उन्होंने अपनी बेटी नुसरत को बतौर निर्दलीय मैदान में उतार रखा है। अगर चुनाव पूर्व उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो क्या वह आनन-फानन में अपने सारे मत नुसरत को स्थानांतरित करा पाएंगे? अफजाल को भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय से पुरजोर टक्कर मिल रही है।

आप जब इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, तब तक आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। यहां भी लड़ाई रोचक रही है।

जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने शुरू में बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उतारा था। कहते हैं कि अचानक धनंजय सिंह और नई दिल्ली के सत्ता-सदन के बीच कुछ चर्चाएं शुरू हो गईं। इससे क्षुब्ध मायावती ने श्रीकला की जगह मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को दोबारा टिकट दे दिया। हालांकि, यहां मुख्य लड़ाई इंडिया गठबंधन के बाबू सिंह कुशवाहा और भाजपा के कृपाशंकर सिंह के बीच है। यहां किसी दल से ज्यादा धनंजय के प्रभाव की परीक्षा है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव ने भी 'नेताजी' की विरासत को कायम रखने की पुरजोर कोशिश की है। उन्हें भोजपुरी फिल्मों के सितारे और वर्तमान सांसद निरहुआ से पार पाना है।

मतलब साफ है, पूर्वांचल में काशी को छोड़कर हर सीट पर कड़ा संघर्ष है। कहीं बाहुबल का दबदबा, कहीं विरासत, तो कहीं मंत्री पद का रुतबा कसौटी पर कसा जा रहा है। आगामी 4 जून का फैसला सिर्फ जय-पराजय नहीं, बल्कि नया सियासी चलन भी गढ़ने जा रहा है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीना इसी का नाम है

छवि सिंह राजावत
पहली एमबीए महिला सरपंच

जमीनी बदलाव की वह राह जो राजावत ने दिखाई

अपने गांव से कैसा प्रेम होना चाहिए, छवि ने अपने फौजी दादा से यह सीखा था। सेना में ऊंचे ओहदे से रिटायर होने के बाद ब्रिगेडियर साहब चाहते, तो जयपुर में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते थे, मगर उन्होंने अपने पुरखों की माटी की सेवा की राह चुनी थी।

एक ऐसे समय में, जब देश नए रहनुमाओं को चुन रहा है, जो आने वाले पांच वर्षों में लाखों गांवों पर असरंदाज होने वाली नीतियां बनाएंगे और मुल्क के भविष्य से जुड़े फैसले करेंगे, तब एक नागरिक या मतदाता के मन में यह सवाल उठ सकता है कि अकेला सांसद या विधायक या पार्षद या सरपंच भला क्या कर सकता है? कितना ही बदलाव ला सकता है? छवि सिंह राजावत इन सवालों का जवाब हैं। राजस्थान के टोंक जिले में एक तहसील है मालपुरा, सोडा इसी का एक गांव है। इसी गांव से वाबस्ता एक संपन्न परिवार में 1977 में छवि का जन्म हुआ। हालांकि, वह पैदा जयपुर में हुईं, मगर अपनी जड़ों से खानदान के गहरे लगाव को देख उन्हें बचपन में ही सोडा का महत्व पता चल गया था। दादा ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह राजावत भारत-पाक युद्ध में अपनी जांबाजी के लिए महावीर चक्र से नवाजे जा चुके थे। पूरे इलाके में उनकी बड़ी इज्जत थी। कारोबारी पिता नरेंद्र सिंह व मां हर्ष चौहान अपने सामाजिक कार्यों से उस प्रतिष्ठा को और विस्तार देते रहे।

छवि का बचपन सुविधाओं से पोषित रहा। हालांकि, जब वह मिडिल स्कूल में ही थीं, तभी दादी ने रवायत के मुताबिक उनकी शादी की बात छेड़ी थी, तब ब्रिगेडियर साहब ने पूरे परिवार को हुक्म सुना दिया कि 'छवि को तब तक शादी के लिए कोई परेशान नहीं करेगा, जब तक वह पढ़ना चाहती है।' काश! ऐसी प्रगतिशील सोच हर दादा की होती। इसके बाद आंध्र की ऋषि वैली स्कूल से जो सफर शुरू हुआ, वह अजमेर के मेयो व दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज होते हुए पुणे के प्रबंधन संस्थान आईआईएमएम जाकर पूरा हुआ, जहां से साल 2003 में छवि ने एमबीए की डिग्री हासिल की।

स्कूल ने यह सीख देकर अपना सच्चा धर्म निभाया कि कोई इंसान चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, वह सम्मान का हकदार है, तो वहीं आईआईएमएम ने प्रगति के व्यवस्थित प्रयास का गहरा सबक सिखाया था। इसके बाद का रास्ता कॉरपोरेट दुनिया की ओर ले गया और छवि ने कई नामचीन कंपनियों में काम किया। मगर इस पूरे सफरनामे की सबसे खूबसूरत बात यही रही कि महानगरों की लकदक और चकाचौंध भरी दुनिया में भी सोडा गांव बराबर छवि के भीतर बना रहा। जब कभी भी पेशेवर दुनिया से मोहलत मिलती, वह भागकर बरास्ते जयपुर, सोडा पहुंच जाया करतीं।

दरअसल, अपने गांव से कैसा प्रेम होना चाहिए, छवि ने अपने फौजी दादा से यह जाना था। सेना के ऊंचे मुकाम से रिटायर होने के बाद ब्रिगेडियर साहब चाहते, तो जयपुर में एक आरामदेह जिंदगी गुजार सकते थे, मगर उन्होंने अपने पुरखों की माटी की सेवा की राह चुनी। वह दो बार सोडा के सरपंच मुंतखब हुए। छवि इस विरासत की जिम्मेदारी से कभी गाफिल नहीं थीं। जयपुर से सोडा के रास्ते में दूसरे गांवों से गुजरते हुए

और कई गांवों को तरक्की के नए नजरिये के साथ आगे बढ़ते देखकर उन्हें लगता कि उनका सोडा पिछड़ गया है। गांव वाले भी अक्सर दुखड़ा रोते और ब्रिगेडियर साहब की सरपंची में हुए कामों को याद करते। यह बात छवि के मर्म को छू लेती थी। हालांकि, तब भी सियासत में उतरने या चुनाव लड़ने का कोई ख्याल उनके मन में नहीं आया था।

बात साल 2010 की है। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दिया। संयोग से उनमें सोडा भी आरक्षित हो गया। उसी दौरान छवि जयपुर आईं, तो गांव के करीब 50 बड़े-बुजुर्गों ने उनके घर आकर उनसे गुजारिश की कि वह सरपंच का चुनाव लड़ें। एक तरफ, कॉरपोरेट जगत की अनुशासित, आकर्षक और आरामदेह जीवनशैली थी, तो दूसरी ओर गांव की श्रमसाध्य जिंदगी। अपनी माटी से मोहब्बत और गांवों में काम करने की भरपूर गुंजाइश ने छवि को सोचने के लिए बाध्य कर दिया। छवि मान गईं। नौकरी छोड़ सरपंच के चुनाव-मैदान में उतर पड़ीं और वह चुन भी ली गईं। देश की पहली एमबीए महिला सरपंच बनने के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी खूब चर्चा हुई। मगर चुनाव जीतना और जीतने के बाद जमीन पर बदलाव की बुनियाद रखना दो अलग-अलग चीजें हैं। जैसा कि अमूमन गांवों में होता है, सोडा में भी भू-अतिक्रमण की समस्या बहुत बड़ी थी। पहली ग्रामसभा में ही यह मुद्दा सामने आ गया। अनधिकृत रूप से दशकों से सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को पीछे हटने के लिए राजी करना आसान काम नहीं था। इससे जुड़े महकमे तक हार मान चुके थे।

छवि ने अपने प्रबंधन कौशल का इस्तेमाल करते हुए कब्जेदारों को एक रोडमैप दिया कि आप जमीन खाली करेंगे, तो इससे गांव की सड़कें चौड़ी हो जाएंगी और कई सार्वजनिक निर्माण कार्य होंगे। इससे आप सबको ही नहीं, बल्कि आपके नाती-पोतों को भी सहूलियतें होंगी। नीयत नेक थी, योजनाएं जनहित की थीं, तो बात बन गई। छवि ने समझदारी से सहयोग की एक ऐसी इबारत लिखी कि साढ़े सात हजार की आबादी वाला सोडा गांव विकास की राह पर चल पड़ा।

साल 2010 से 2020 तक के दो कार्यकाल में छवि राजावत ने सोडा को कितना बदला, इसे इन आंकड़ों से आंकिए कि सरकारी व सामुदायिक सहयोग से ग्राम पंचायत के 800 घरों में शौचालय बने, इनमें पानी की पाइपलाइन पहुंचाई गई, कई सारे तालाबों को सूखने से बचाया गया और

अपनी माटी से मोहब्बत और गांवों में काम करने की भरपूर गुंजाइश ने छवि को सोचने के लिए बाध्य कर दिया। छवि नौकरी छोड़ सरपंच के चुनाव-मैदान में उतर पड़ीं और वह चुन भी ली गईं। देश की पहली एमबीए महिला सरपंच बनने के लिए विश्व स्तर पर उनकी खूब चर्चा हुई।

साल भर तक गांव के उपयोग योग्य वर्षा जल के संग्रहण की शुरुआत हुई। पंचायत की छोटी-बड़ी करीब सौ सड़कें बनीं। गांव की महिलाओं के बैंक खाते खुले, उनको छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया। सैकड़ों लड़कियां अब स्कूल में हैं। छवि अब सरपंच नहीं हैं, मगर वह घूम-घूमकर देश भर में लड़कियों को प्रेरित करती रहती हैं। छवि के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अब कई उच्च शिक्षित लड़कियां स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने लगी हैं और कामयाब भी हो रही हैं।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

मंसूर अली खान पटौदी
पूर्व क्रिकेट कप्तान

एक क्रिकेटर जो कभी भाग्य पर नहीं रोया

लेंस लगने से समस्या यह हो गई कि सामने से आती एक गेंद दो दिखने लगती थी। लगता था, छह-छह इंच के अंतर पर दो-दो गेंदें चली आ रही हैं। गौर किया, तो पाया कि दो गेंदों में से बाहर वाली गेंद भ्रम है और अंदर वाली की ही बल्ले से धुनाई करनी है।

कई लोग छोटी-छोटी बात पर हार मान बैठते हैं। भाग्य को कोसने लगते हैं। कुछ लोगों में तो हर बात पर हाय-हाय करने की आदत पाई जाती है। ऐसे लोगों को राई भर कष्ट हो, तो उसका पहाड़ बनाकर पेश कर देते हैं, पर कुछ लोग होते हैं, जो पहाड़ समान समस्या को भी राई मानकर मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं।

ऐसा ही उस क्रिकेटर के जीवन में भी हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की टीम की ओर से खेलने वाले इस युवा ने दिन भर जी-जान से क्षेत्ररक्षण किया था। उस सुहानी शाम को सभी खिलाड़ी स्टेडियम से लौट रहे थे। होटल बस तीन सौ गज दूर था। पांच खिलाड़ियों के समूह में से तीन ने फैसला किया कि पैदल चल पड़ते हैं, पर इस युवक ने तय किया कि विकेटकीपर रोबिन वाटर्स कार चला ही रहे हैं, तो उनके साथ ही चला जाए। कार चंद गज आगे बढ़ी ही थी कि सामने से एक कार काफी तेज गति से आकर भीड़ गई। बचने के लिए युवक ने दाहिना कंधा आगे कर दिया, जिस पर सामने से शीशा आ टकराया। रोबिन को भी खरोचें आईं, पर लगा कि बड़ा हादसा गुजर गया, कुछ न हुआ। दर्द था, पर कमजोर लोग ही रोया करते हैं। मन जोर-जोर से समझा रहा था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। युवा को सिर्फ यही चिंता थी कि यूनिवर्सिटी का मैच कहीं छूट न जाए? सामने वाली टीम को हराना ही है, अपने पिता क्रिकेटर का रिकॉर्ड सामने दिख रहा था। शायद यह चालू मैच छूट जाएगा, तो क्या हुआ? यह दुर्घटना गंभीर नहीं है। जान बच गई, तो सब सलामत।

खैर, एंबुलेंस आई और जब आंख अस्पताल में खुली, तो बताया गया कि आपकी दाहिनी आंख का तत्काल ऑपरेशन कराना होगा। कांच का एक छोटा टुकड़ा आंख में जा घुसा है। खैर, शल्य चिकित्सक को घर से बुलाकर ऑपरेशन किया गया। इलाज चला, चिकित्सक ने कहा, दायीं आंख में कांटेक्ट लेंस लगाना होगा, उससे 90 प्रतिशत रोशनी लौट आएगी। यहां भी युवक ने हार नहीं मानी। चंद सप्ताह बाद ही मैदान पर उतर आया। लेंस लगने से समस्या यह हो गई कि सामने से आती हुई एक गेंद दो दिखने लगती थी। लगता था, छह-छह इंच के अंतर पर दो-दो गेंदें चली आ रही हैं। गौर किया, तो पाया कि दो गेंदों में से बाहर वाली गेंद भ्रम है और अंदर वाली की ही बल्ले से धुनाई करनी है। खास यह भी कि तब दायें हाथ से गेंद फेंकना दुश्वार था, गेंद फेंकते ही कंधा दर्द से चटकने लगता था।

इतना होने पर भी उस क्रिकेटर ने एक पल के लिए भी नकारात्मक नहीं सोचा। यह कभी नहीं सोचा कि अब नहीं खेल पाऊंगा। वह अपने देश लौट आया, पर अभ्यास में कोई कमी नहीं छोड़ी। सामने से आने वाली दो गेंदों की समस्या को खत्म करने के लिए एक ही आंख से देखकर खेलना शुरू किया। हेलमेट का जमाना नहीं था, तो टोपी ही ऐसे पहनने लगे कि दायीं आंख ढक जाती थी। लोग सोचते थे, पटौदी के नवाब साहब स्टाइल मार रहे हैं। खैर, एक आंख के जोर पर ही चौके-छक्के शुरू हुए, लोग उनका खेल देख रुक जाते थे, तो पता चलता था कि नवाब साहब मंसूर अली खान पटौदी खेल रहे हैं। पहले क्षेत्ररक्षण को ज्यादातर खिलाड़ी कमतर काम मानते थे, पर नवाब साहब ने क्षेत्ररक्षण को जिंदा कर दिया। मैदान में सबसे कठिन जगह कवर पर वह क्षेत्ररक्षण करते थे और किसी बाघ की तरह गेंद पर झपटते थे, तो नाम पड़ गया, टाइगर पटौदी।

चूंकि किसी भी तरह के भय, निराशा से वह दूर थे, इसलिए उनका नेतृत्व किसी उदासीन टीम को भी चपलता से भर देता था। उन्होंने भारतीय टीम में चुने जाने के बाद भी ऐसा ही किया। छह टेस्ट खेलने वाले टाइगर पटौदी (1941-2011) को कप्तानी दी गई, तब उनकी उम्र थी 21 साल। वह जितने अच्छे बल्लेबाज थे, उससे कहीं अच्छे क्षेत्ररक्षक और उससे कई गुना अच्छे कप्तान थे। उन्होंने अपनी सुदर्शन उपस्थिति से भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। चालीस टेस्ट में वह भारत के कप्तान रहे। उन्होंने जब शतक जड़ा, तब इंग्लैंड के खिलाफ भारत को पहली श्रृंखला में जीत मिली। सदा नवोन्वेषी, गरिमामय, हंसमुख, शांति और बुद्धिमत्ता से भरपूर टाइगर पटौदी ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पहला दोहरा शतक भी लगाया। भारत को विदेश में पहली जीत उन्हीं के नेतृत्व में मिली। उनके नेतृत्व में ही भारत ने पहली बार वेस्टइंडीज को हराया।

आज जब फटाफट क्रिकेट का दौर है, तब अपने जमाने में टेस्ट में छह शतक लगाने वाले पटौदी को अक्सर याद किया जाता है और कहा जाता है कि वह दोनों आंखों से देखते हुए खेल पाते, तो न जाने कितनी ऊंचाई पर पहुंचते। लोगों को भले अफसोस हो, पर टाइगर पटौदी के शब्दकोश में यह शब्द नहीं था। उन जैसा कप्तान आज भी भारतीय टीम खोज रही है।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

इन लेखकों को किस नाम से पुकारूं

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

सोशल मीडिया पर दिन-रात कुछ न कुछ लिखने वाले आज के लेखकों को मैं किस नाम से पुकारूं? उनको क्या नाम दूं कि सबका नाम बन जाए? आप भी मानेंगे कि यह मेरी ही नहीं, बल्कि आज की आलोचना मात्र की समस्या है और इस तरह आलोचक मात्र की समस्या है।

देर-सबेर सोशल मीडिया के ये लेखक पूछेंगे ही- हे आलोचको, समीक्षको, समालोचको या तुम जो भी हो, यह तो बताओ कि हम आपके हैं कौन? आप हमारे हैं कौन? हम लेखक हैं कि नहीं? हम जो इतना ढेर लिखे हैं, वह आपकी नजर में क्या है? हमारी भूमिका क्या है? हमारा इतिहास क्या है? हमारे इस इतिहास को कौन लिखेगा? हमारा आलोचक कौन है?

यह 'मास लेखन', यानी जन-लेखन का चैलेंज है, जो बहुत दिनों बाद आलोचना को मिला है। यह थोक लेखन का चैलेंज है और यही आलोचना की असली परीक्षा है। अपने दो-चार दोस्तों को आपने लेखक बना दिए तो क्या, इस नए लेखक को समझो, इसका मूल्यांकन करो, तब जानूं?

सच! यह हिंदी की दंभी आलोचना के अवसान की घड़ी है। गनीमत है, अभी सोशल मीडिया के लेखकों ने आलोचकों से कुछ नहीं कहा है या हो सकता है कि वे आलोचक की जरूरत ही न समझते हों। बहरहाल, मैं तो मानता हूं कि आज का सोशल मीडिया लेखन एकदम बिंदास लेखन है। वह एकदम निडर-निर्भय और अपने आप में मगन मस्त लेखन है, जिसका न कोई संपादक है, न सेंसर। न इसका कोई गॉडफादर है, न कोई 'कास्टिंग काउच'; न कोई दलाल है, न कोई एजेंट। इसका कोई गुरु नहीं, बल्कि ये स्वयं गुरुओं के गुरु और पूरे गुरु घंटाल हैं।

यह *परम स्वतंत्र न सिर पर कोई* वाली पीढ़ी है। यह लेखन का पहला उन्मुक्त जनतंत्र है, जिसे सस्ती तकनीक ने सबको दिया है। ये किसी *धर्मयुग, सारिका, ज्ञानोदय* या *तारसप्तक* के गिने-चुने लेखक नहीं, बल्कि ये अनंत हैं और अपने होने के अहंकार में किसी से कम भी नहीं। ये आज इतनी संख्या में हैं कि आप इनकी गिनती तक नहीं कर सकते!

एक बार फिर लेखन आगे है और आलोचना पीछे है। शायद इसीलिए, जो 'साइबर स्पेस' में चौबीस बाई सात के हिसाब से प्रकाशित-प्रसारित हो रहा है, जिसको 'लाइक, व्यू, फॉलो और फॉरवर्ड' करने वाले भी असंख्य हैं, उसके लिए हमारी आलोचना एकदम गैर-तैयार है। यह उसको एकदम अयोग्य व अक्षम दिखती है।

यूं हिंदी में आलोचकों की कमी नहीं। यहां एक से एक 'कॉपी कैट' हैं। कई रामविलास शर्मा की खराब कॉपी हैं, तो कई नामवर सिंह की और कई तो ऐसी कॉपी की कॉपी की कॉपी हैं। इनकी आलोचना भी हमपियाला हमनिवाला वाली है। इनमें से कई की सीमित आलोचना-बुद्धि एक ठर्रे में फर्रे लिखती है और एक शेंपेन की बोतल में कैंपेन चलाती है।

फिर भी, यह सवाल तो रह ही जाता है कि जिस समाज में फेसबुक पर लाखों रोज लिखते हों, जिनको उनके जुटाए 'फ्रेंड्स क्लब' सराहते और कराहते हों, जिनके यू-ट्यूब के वीडियो को अनंत लोग देखते हों, फॉलो करते हों, आगे बढ़ाते हों, जिनको दुश्मन ट्रोल करते हों, जो हर वक्त किसी न किसी वाट्सएप या इंस्टाग्राम ग्रुप में सक्रिय हों, जो बात-बात पर कमेंट करते हों, कविता-कहानी डालते हों, उनको क्या नाम दूं?

इनको सोशल मीडिया लेखक कहूं या साइबर लेखक कहूं? ऑनलाइन लेखक कहूं या डिजिटल लेखक कहूं और इनकी फ्रेंड्स लिस्ट को इनका पाठक और इनके 'व्यूअर्स' या 'फॉलोअर्स' को इनकी नई आलोचनात्मक पदावली मानूं? यूं कोई इस पीढ़ी को 'जेनरेशन नोव्हेअर' कहता है, तो कोई इसे 'अनएजूकेटेड पीढ़ी' कहता है, तो कोई इसे 'इलिटरेट लेखक पीढ़ी' कहता है, लेकिन मेरी नजर में ये सभी पोस्ट लेखक हैं, ये 'उत्तर लेखक हैं। उत्तर कवि, कथाकार और आलोचक हैं।'

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

खुशी का पहला उपाय-पुरानी बातों को ज्यादा न सोचें

बदलता कश्मीर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनावों को लेकर यह जिज्ञासा देश में ही नहीं, दुनिया के भी कुछ हिस्सों में थी कि इस केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के प्रति लोगों का कैसा रुझान रहेगा? यह जिज्ञासा कश्मीर घाटी के निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर अधिक थी, क्योंकि इसके पहले एक तो सघन सुरक्षा के साए में चुनाव कराने पड़ते थे और दूसरे, तमाम तैयारियों के बावजूद मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कहीं कम रहता था। यह उत्साहजनक है कि इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आई। घाटी की तीनों लोकसभा सीटों श्रीनगर, बारामुला के बाद अनंतनाग-राजौरी में भी अच्छा-खासा मतदान हुआ। इन तीनों सीटों पर बढ़े हुए मतदान प्रतिशत ने चुनावों में लोगों की कम भागीदारी की आशंका को तो दूर किया ही, इस पर भी मुहर लगाई कि यहां के लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। यह भरोसा कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करने का काम करेगा। कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती मिलने का मतलब है यहां के लोगों की राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने के प्रति ललक बढ़ना। यह उल्लेखनीय है कि श्रीनगर, बारामुला और अनंतनाग-राजौरी में लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। कुछ जगह तो राष्ट्रीय औसत के बराबर मतदान देखने को मिला। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान भी घाटी में अतिरिक्त उत्साह नजर आया।

इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीर में अलगाववादी संगठनों से जुड़े नेताओं और उनके प्रभाव में रहने वाले लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। इसका सीधा अर्थ है कि कश्मीर के लोगों में यह संदेश पहुंच चुका है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी ही उनकी अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। यह एक शुभ संदेश है और इसे देखते हुए जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाने चाहिए। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। ऐसा किया जाना समय की मांग भी है। निःसंदेह केवल इसलिए नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस वर्ष सितंबर के पहले इस राज्य में विधानसभा चुनाव करा लिए जाने चाहिए। विधानसभा चुनाव जितनी जल्दी संभव हो, इसलिए भी कराए जाने चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के प्रति लोगों का भरोसा और अधिक बढ़े और उन्हें चुनी हुई सरकार भी हासिल हो सके। निश्चित रूप से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से अलगाववाद एवं आतंकवाद से पीड़ित रही कश्मीर घाटी का माहौल बदला है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यहां की स्थितियां पूरी तरह सुधर गई हैं। घाटी में अभी काफी कुछ बदलाव शेष है। यह शेष बदलाव तब अच्छे से पूरा होता हुआ दिखेगा, जब कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट सकेंगे।

चिंताजनक

इंटरनेट पर गेम खेलते हुए विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के प्रकरण ने एक बार फिर स्मार्ट फोन के बच्चों द्वारा दुरुपयोग और इसे लेकर अभिभावकों की गंभीरता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विद्यालय को ई-मेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जांच में जो तथ्य उभरकर आए वह परेशान करने वाले हैं। यह ई-मेल महाराष्ट्र के चार बच्चों ने आनलाइन गेम खेलने के दौरान मिले टास्क को पूरा करने के इरादे से किया था। बच्चों एवं उनके अभिभावकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसे लेकर सभी को चिंतित होना चाहिए। अब यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चों को स्मार्ट फोन से दूर रखना चाहिए। कोविड काल के बाद यह एक तरह से अनिवार्य बन चुका है। आज 90 प्रतिशत बच्चों के पास स्मार्ट फोन हैं। स्मार्ट फोन के अन्य भी कई लाभ हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, किंतु बालमन की चंचलता पर अभिभावकों के अंकुश की आवश्यकता को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चों एवं किशोरों द्वारा स्मार्ट फोन के प्रयोग की पूरी निगरानी रखे। ऐसे कई गैजेट हैं जो फोन पर बच्चों की गतिविधियों की निगरानी में सहायक हैं। अभिभावक अपने बच्चों को फोन तो दे देते हैं, लेकिन उन पर निगरानी रखने वाले पैरेंटल एप्स की या तो जानकारी ही नहीं रखते या इसे एक अनावश्यक कार्य मानकर दूसरी व्यस्तताओं में खो जाते हैं। अक्सर परिणाम वही होता है जो इस मामले में सामने आया। नियामक एजेंसियों को भी ऐसे आनलाइन गेम्स की पहचान कर सही समय पर प्रतिबंध लगाने की चिंता करनी चाहिए जो दूसरों की परेशानी का कारण बन सकते हैं। पबजी गेम से लेकर आनलाइन गेम डिकोड तक ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस आवश्यकता को मुखरता से रेखांकित करते हैं।

बेनकाब हुई तुष्टीकरण की राजनीति

संजय गुप्त

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने इस आरोप को बल प्रदान किया है कि आइएनडीआइए के घटक संविधान विरुद्ध जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं

ममता बनर्जी सरकार की ओर से 2010 के बाद मुस्लिम जातियों को ओबीसी प्रमाणपत्र देने के निर्णय को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। हालांकि उसने अपने निर्णय में यह कहा है कि जिन्हें ओबीसी प्रमाणपत्र के जरिये नौकरियां मिल गई हैं, उन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके निर्णय से करीब पांच लाख लोग प्रभावित होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता सरकार के निर्णय को मनमाना बताते हुए खारिज किया है। उच्च न्यायालय के फैसले से नाराज ममता बनर्जी राजनीतिक कारणों से यह कह रही हैं कि वह इस फैसले को नहीं मानेंगी, लेकिन यदि उन्हें हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। चूंकि यह निर्णय ममता की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का परिचायक है, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन पर राजनीतिक हमला बोल दिया है। मुस्लिम समाज की जातियों को ओबीसी प्रमाण पत्र देने के ममता सरकार के फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐसे समय निरस्त किया है, जब राज्य में चुनाव हो रहे हैं। स्पष्ट है कि यह निर्णय ममता सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। इसके पहले उन्हें ऐसा ही झटका कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले से भी लगा था, जिसमें उसने 25,000 शिक्षकों एवं स्कूली कर्मचारियों की भर्तियों को निरस्त कर दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को थोड़ी राहत दे दी, लेकिन उच्च न्यायालय के उस फैसले ने उनके समक्ष एक राजनीतिक संकट तो खड़ा ही कर दिया। ममता सरकार को उच्च न्यायालय के कुछ और फैसलों से झटका लग चुका है। इसमें एक संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की ओर से जमीनों पर कब्जा और महिलाओं के प्रति अत्याचार से भी जुड़ा है। इस मामले में ममता सरकार को उच्च न्यायालय की फटकार सुननी पड़ी थी और सर्वोच्च न्यायालय की भी।

ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप तभी से लग रहे हैं जबसे वह सत्ता में आई हैं। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण एक प्रमुख मुद्दा रहा है। भाजपा इस तुष्टीकरण को ही एक मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेरती रही है। बंगाल में पहले मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण कांग्रेस की ओर से किया जाता था, फिर वामदलों की ओर से किया जाने लगा। वामदलों को परास्त कर सत्ता में आईं ममता बनर्जी भी यही काम करने लगीं। 1947 में जब मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, तब पंजाब में तो दोनों छोर की आबादी का एक-दूसरे हिस्से में पलायन हुआ, लेकिन बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू ही बड़ी संख्या में पलायन कर भारत आए। बंगाल में रहने वाले कुछ ही मुस्लिम नए देश में बसने गए।

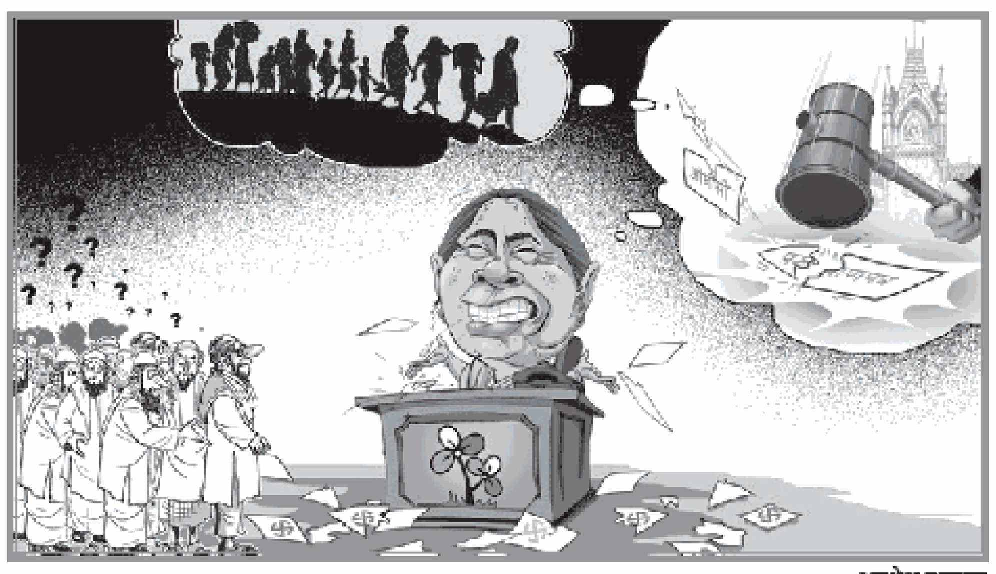
अवधेश राजपूत

बंगाल की सीमा बांग्लादेश से सटी है और सीमांत इलाके ऐसे हैं कि दोनों ओर आवाजाही कहीं अधिक आसान है। इसके चलते बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी बंगाल में आकर बसते रहे। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम बंगाल में भी आकर बसे और असम एवं त्रिपुरा में भी। आज इन तीनों राज्यों में बांग्लादेश से अवैध रूप से आए मुसलमानों की संख्या कितनी है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं। बांग्लादेश से आए मुसलमानों ने मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड आदि बनवा लिए हैं। वे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के लिए बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। बांग्लादेश से आई मुस्लिम आबादी ने बंगाल के साथ-साथ असम में सामाजिक तानेबाने को बदल दिया है और कई निर्वाचन क्षेत्रों में वे निर्णायक स्थिति में आ गए हैं। इसीलिए उनकी पहचान करने की मांग रह-रहकर होती रही है। मोदी सरकार ने इसी सिलसिले में नागरिकता कानून में संशोधन किया, ताकि बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम लोगों को देश की नागरिकता दी जा सके।

चूंकि बांग्लादेश से आए मुस्लिम कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामदलों के लिए वोट बैंक बन गए हैं, इसीलिए इन दलों ने यह भ्रांति फैलाई कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनना है, जबकि यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का है। इसके बावजूद भाजपा विरोधी दल यह वादा करने में लगे हुए हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो इस कानून को खत्म कर देंगे। चूंकि बंगाल में करीब 27 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेश से सटे कुछ जिले ऐसे हैं, जहां मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए स्वयं को सेक्युलर बताने वाले दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसी राजनीति के तहत ममता सरकार ने मुस्लिम समाज को ओबीसी आरक्षण का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए मनमाने तरीके से अनेक मुस्लिम जातियों को ओबीसी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए। साफ है इससे हिंदू समाज की ओबीसी जातियों के हितों को चोट पहुंची। वोट बैंक की इसी राजनीति के चलते एक समय आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम समाज को आरक्षण प्रदान किया गया। यही काम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने किया। उसने समस्त मुस्लिम समाज को पिछड़ा मानकर उसे ओबीसी आरक्षण दे दिया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाला विपक्षी मोर्चा आइएनडीआइए मजहब के आधार पर आरक्षण देने का इरादा रखता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान सरकार यह पता लगाने जा रही है कि कहीं पिछली कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अनुचित तरीके से मुस्लिम जातियों को तो ओबीसी आरक्षण नहीं प्रदान किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने भाजपा के इस आरोप को बल प्रदान किया है कि आइएनडीआइए के घटक दल संविधान के विरुद्ध जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। यह लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि भाजपा ने मजहब आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की जो घेरेबंदी की, उसका उसे कितना लाभ मिलेगा, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि कथित सेक्युलर दल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की यह राजनीति भारतीयता के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने और सीमा पार से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने वाली भी है।

response@jagran.com

सम्मान मिलेगा खटाखट-खटाखट

हास्य-व्यंग्य

कल सुबह ई-मेल खोली तो खुशी के मारे उछलने ही वाला था, पर घुटनों ने साथ नहीं दिया। किसी इनामी संस्था के सचिव का पत्र था। उन्होंने इस वर्ष के सम्मान देने के लिए मुझसे सुझाव मांगे थे। उत्सुकतावश संस्था का परिचय पढ़ने लगा। उसमें साफ लिखा था कि संस्था विगत 40 वर्षों से साहित्य-सेवा में अहर्निश जुटी हुई है। इस दौरान वह अनगिनत लेखकों और कवियों की झोली में सम्मान उड़ेल चुकी है। जो अपने लेखन से साहित्य-जगत में हलचल मचाने में असमर्थ होते हैं, संस्था तन और मन से उनकी सहायता करती है। जिस दिन उन्हें सम्मान दिया जाता है, उस दिन हंगामा मच जाता है। संस्था का दावा था कि उसके द्वारा सम्मानित साहित्यकार हर गली-मुहल्ले में मिल जाएंगे। इस वर्ष उनकी संस्था 21 साहित्यकारों के मन और मान की चाह शांत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पवित्र कार्य में आपसे सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपनी संस्तुति भी दे सकते हैं। हम उस पर उदारतापूर्वक विचारेंगे। पत्र पढ़कर 'फीलगुड' हुआ। इतनी ऐतिहासिक संस्था न केवल सुझाव मांग रही, बल्कि मुझे भी सम्मानित करने का हौसला रखती है।

शहर के साहित्यकारों ने कभी मेरी सुध नहीं ली। जरूर इस साहित्य-सरगना को मुझमें ऐसा कुछ दिखा होगा, जो कभी मुझे नहीं दिखा। मैंने साहित्य-सेवा करने का संकल्प उठा लिया। संस्था-सचिव को कई सुझाव लिख डाले खटाखट-खटाखट। साहित्य की सबसे ज्वलंत समस्या का समाधान करने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल सही जगह आपने संपर्क साधा है। वरना आजकल पता नहीं लोग किस-किस को साध रहे हैं! रही मेरी बात, तो कई सम्मानार्थियों से मेरे वैध संबंध हैं। वे मुझे उठाते हैं, मैं उन्हें। आप नाहक परेशान हो रहे हैं। एक खोजेंगे, 21 मिलेंगे। यह मेरी गारंटी है। अव्वल तो अब आपको 20 ही खोजने हैं। मैं आपके प्यार भरे अनुग्रह को इन्कार नहीं कर सकता। आपके पास जो भी संस्तुति आए, ध्यान से देखना कि उसे पहले कोई सम्मान मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो फिर रिस्क न लें। हो सकता है, उसे इसीलिए न मिला हो कि सम्मान देने वालों का वह लिहाज न करता हो। साहित्यिक-गैंगस्टर को साहित्यकार न मानता हो। ऐसे लोगों को सम्मान बांटना कुल्हाड़ी पर पैर मारना है। वह संस्था का असली उद्देश्य उजागर कर सकता है। ऐसे को सम्मानित करने का कोई औचित्य नहीं, जो सम्मान तक ठीक से हजम नहीं कर सकता। इससे बेहतर है, अपने गैंग का विस्तार करें। सम्मानार्थी को वाट्सअप ग्रुप का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य हो। परिवारदार आदमी हो तो सोने पर सुहागा।

संतोष त्रिवेदी

ऐसे को सम्मानित करने का कोई औचित्य नहीं, जो सम्मान तक ठीक से हजम नहीं कर सकता

अब दूसरे पहलू पर ज्यादा गौर करिए। जिसके परिचय में जितने ज्यादा सम्मान हों, उन्हें वरीयता दें। इनके मुंह में सम्मान लगा होता है। नहीं मिलने पर और खूंखार हो उठते हैं। पक्षपात का आरोप और लगाएंगे। गोष्ठियों में ये अपने लेखन को छोड़कर लिफाफे और शाल पर गर्व करते हैं। अगर भूखे-नंगों को सम्मान दोगे तो बड़ी थू-थू होगी। मेरी बात और है। मैं आलरेडी सम्मान-हीन हूं। साहित्य के लिए पूरा जीवन होम कर चुका हूं। बस, सम्मान पाने भर के लिए प्राण अटके हैं। बिना अपने हिस्से का सम्मान लिए संसार नहीं छोड़ूंगा! हां, बाकियों के बारे में थोड़ा सतर्कता बरतना। सब मेरे जैसे नहीं हैं। सम्मान न पाने पर गैंग और ग्रुप से भी भाग सकते हैं। संस्था चलानी है तो सहेजना और समेटना सीखिए। ईमानदारी से सरकार तक नहीं बचती, संस्था कैसे बचेगी! सभी सम्मानयाफ्ता लोगों की सूची बना लें। सम्मान की टोपी इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए। इनसे सहयोग वसूला जाए, ताकि संस्था के साथ इनका 'परमानेंट बांड' स्थापित हो सके। समय-समय पर 'बांड' कैश भी कराते रहें!

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

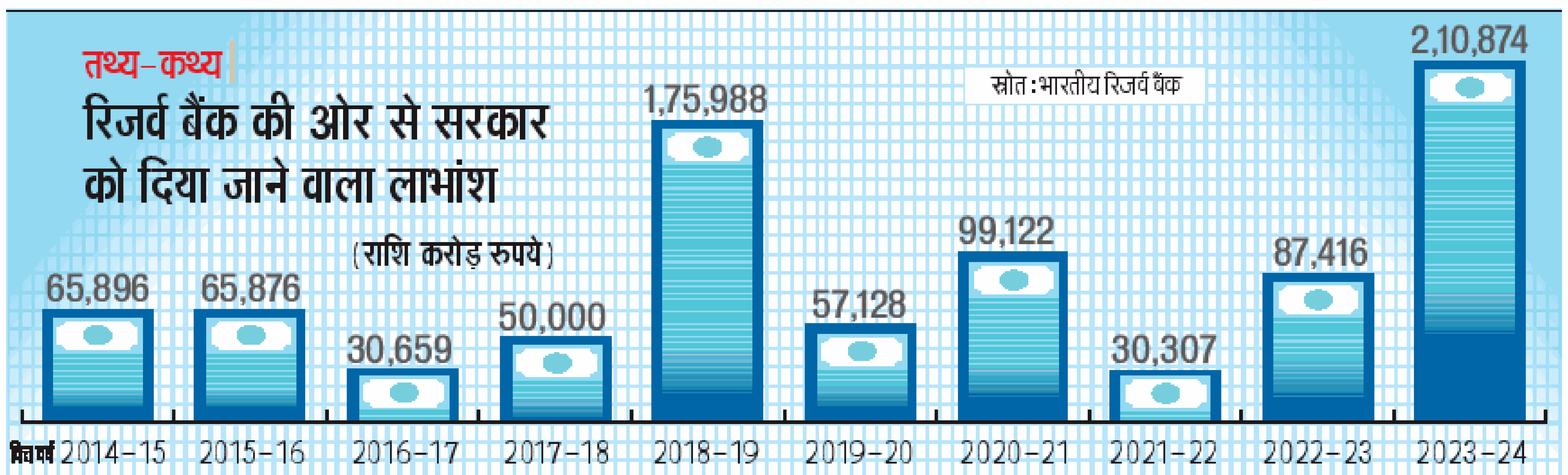

ऊर्जा

शब्द संकोच

मनुष्य की कामनाएं अंतहीन हैं और समय कम। वह दिन-रात परिश्रम कर अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। समय उसके लिए सर्वाधिक मूल्यवान हो गया है। इस स्थिति ने उसकी कथन और श्रवण शक्ति को प्रभावित किया है। शब्द उसके लिए बोझ बन गए हैं। अत्यधिक व्यस्त मनुष्य कथन से अधिक संकेतों में विश्वास रखने लगा है। सुनने में भी वह तभी रुचि लेता है जब स्वहित में आवश्यक हो अथवा करने को कुछ न हो। शब्दों का संकोच आभिजात्य का प्रतीक हो गया है। शब्द वर्षा की तरह हैं। वर्षा खेत को हरा-भरा कर देती है। अधिक वर्षा बाढ़ बन कर खेत को ही बहा ले जाती है। शब्दों का प्रयोग भी ऐसा ही है। विवेक सम्मत शब्द हृदय को स्पंदित करते हैं। शब्दों का प्रवाह कब अनर्गल हो दुखदाई बन जाए यह एक कठिन आकलन होता है। आज का समय वाक् पटुता का नहीं, वाक् सिद्धि का है। शब्दों को सिद्ध करने में ही सुख है।

लगभग हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग एक पूरे वाक्य का विकल्प होता है। ऐसे शब्दों का चयन कर उन्हें अपने कथन का अंग बनाया जाना श्रेयस्कर होगा। लेखन में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग अनावश्यक विस्तार के दोष से बचाने वाला है। अपने मनोभावों के संप्रेषण में शब्दों पर अतिरिक्त निर्भरता से बचना चाहिए। अधिक शब्द नहीं, उपयुक्त शब्द प्रभाव डालते हैं। गागर में सागर भरना साहित्य की एक विलक्षण विधा थी। दो पंक्तियों के दोहे में विस्तृत दर्शन सिमट आता था। आज शब्दों का अराजक मेला-ठेला है, जो जीवन को असहज कर रहा है। इसका निदान सक्षम शब्द ही हैं।

श्रेष्ठ शब्दों के चयन में प्रमुख भूमिका मनुष्य के चिंतन के स्तर की होती है। जैसे अमृत की एक बूंद अमरत्व प्रदान करने वाली है। वैसे ही श्रेष्ठ और सक्षम शब्द आनंद से भरपूर करने वाले हैं।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

टर्ब्युलेंस की चपेट में विमान

मुकुल व्यास

टर्ब्युलेंस की घटना हवा के अनियमित प्रवाह के कारण होती है, जिससे यात्रियों को अचानक तगड़े झटके लगते हैं

विमान यात्रियों के लिए वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण टर्ब्युलेंस यानी हवा में हिचकोले खाने की घटनाएं घातक हो सकती हैं। पिछले दिनों लंदन से सिंगापुर जाने वाली सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में तीव्र टर्ब्युलेंस की घटना के कारण एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और कई अन्य बुरी तरह घायल हो गए। टर्ब्युलेंस की घटना हवा के अनियमित प्रवाह के कारण होती है, जिससे यात्रियों और चालक दल को अचानक तगड़े झटके लगते हैं। एयर टर्ब्युलेंस की घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ वायु मार्गों पर इसके घटित होने की आशंका ज्यादा रहती है। टर्ब्युलेंस वाले अधिकांश मार्ग पहाड़ों के करीब से गुजरते हैं।

जलवायु परिवर्तन से एयर टर्ब्युलेंस की घटनाएं बढ़ने और इनके और अधिक तीव्र होने की आशंका है। शोध से संकेत मिलता है कि पिछले कुछ दशकों में टर्ब्युलेंस के मामले बढ़ गए हैं। यदि कोई विमान दूसरे विमान के पीछे उड़ान भर रहा है या उतर रहा है तो पहले विमान के इंजन और पंख के सिरों द्वारा उत्पन्न हवा पीछे वाले विमान के लिए टर्ब्युलेंस का कारण बन सकती है। हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र से गुजरने वाली तेज हवाओं के कारण एयर टर्ब्युलेंस की घटना हो सकती है। अधिक ऊंचाई पर विमान यदि किसी अन्य विमान के करीब उड़ रहा हो या तूफान की चपेट में आया हो तो भी टर्ब्युलेंस की घटना घट सकती है। एयर टर्ब्युलेंस की घटना अधिक ऊंचाई पर भी होती है। इसे 'क्लियर एयर टर्ब्युलेंस' कहते हैं। यह अक्सर गर्म हवा के ठंडी हवा की तरफ बढ़ने के कारण होती है।

टर्ब्युलेंस की घटनाएं अक्सर जेट स्ट्रीम के किनारों पर होती हैं। जेट स्ट्रीम दरअसल दुनिया भर में ऊंचाई पर चक्कर लगाने वाली तेज हवाओं की पतली पट्टियां हैं। गति बढ़ाने के लिए विमान कई बार जेट स्ट्रीम में यात्रा करते हैं, लेकिन जेट स्ट्रीम में प्रवेश करते या छोड़ते समय टर्ब्युलेंस की घटना हो सकती है। पिछले साल प्रकाशित एक अध्ययन में 1979 और 2020 के बीच क्लियर एयर टर्ब्युलेंस में बड़ी वृद्धि का प्रमाण मिला। कुछ स्थानों पर गंभीर टर्ब्युलेंस में 55 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। कुछ जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के तहत, 2050 तक क्लियर एयर टर्ब्युलेंस में चार गुना वृद्धि हो सकती है। टर्ब्युलेंस का पता लगाने की तकनीक अभी भी अनुसंधान और विकास के चरण में है। इसलिए पायलट अपने उड़ान पथ से ठीक पहले उच्च स्तर की नमी वाले मौसम से बचने की कोशिश करते हैं। संभव है एयरलाइंस विमानों और यात्रियों पर टर्ब्युलेंस के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करेंगी, लेकिन हवाई यात्रियों के लिए यह संदेश है कि वे सीट बेल्ट बांधने के निर्देश की अनदेखी न करें।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

प्रोटोकाल की चिंता

चुनावी मौसम में सियासत का माहौल संसद के बाहर जरूर गरम है मगर इस दरम्यान संसद भवन परिसर में नए सांसदों के स्वागत-सत्कार की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। नए सांसदों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर उनके ओरिएंटेशन जैसे कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन सबके बीच उनकी व्यवस्था और प्रोटोकाल से जुड़े अधिकारियों की चिंता इस बात को लेकर है कि माननीयों को कैसे सहज रखा जाएगा। दरअसल इसकी वजह है कि संसद की सुरक्षा सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका अब अंदरूनी सुरक्षा में भी नगण्य हो गई है। बाहरी तथा भीतरी सुरक्षा, दोनों का जिम्मा पिछले दिनों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआइएसएफ ने संभाल लिया। चिंता इसे लेकर है कि सीआइएसएफ के अधिकारियों-जवानों को चूंकि सांसदों की सुरक्षा प्रोटोकाल के पालन का अनुभव नहीं है, लिहाजा किसी तरह की सख्ती असहज स्थिति पैदा कर सकती है। वे अधिकांश सांसदों को पहचानते भी नहीं होंगे। इसे देखते हुए प्रोटोकाल से जुड़े अधिकारियों को फिलहाल नए माननीयों के स्वागत-सत्कार के दौरान सीआइएसएफ की मदद के लिए तैनात रखने की तैयारी है।

घरेलू झगड़े में हथकंडे

पति-पत्नी के झगड़े में एक-दूसरे को परेशान करने की जितनी शिद्दत दिखाई देती है वह शायद कहीं न मिले। पिछले दिनों शीर्ष अदालत में भी पति-पत्नी के विवाद से संबंधित एक मामले को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग पर सुनवाई चल रही थी। तभी माननीय न्यायाधीश का ध्यान इस पर गया कि पति रहता दिल्ली में है और उसने केस राजस्थान में दाखिल कर रखा है। न्यायाधीश महोदय ने पति के वकील से इसको लेकर सवाल किया? वकील का जवाब था कि ऐसा इसलिए कि वह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। इस पर जज साहब ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वह पाकिस्तान से होगा तो क्या मुकदमा दाखिल करने लाहौर जाएगा?

नो कूल पीरियड

आम चुनाव के दौर में वैसे तो सभी मंत्रालयों में सौ दिनों का एजेंडा तैयार हो रहा है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय भी है जहां के अधिकारी चुनाव के कूल पीरियड का कोई आनंद नहीं ले पा रहे हैं। यह मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। वजह है कि सरकार चाहे जिस पार्टी की बने, पर नई सरकार में वित्त मंत्रालय पर चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी होगी। जुलाई के पहले 10 दिनों में आम बजट पेश किया जा सकता है। शेष कई मंत्रालयों के अधिकारी करीब सप्ताह-दो सप्ताह की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं मगर वित्त मंत्रालय के अफसर नार्थ ब्लाक से बाहर नहीं निकल पा रहे।

एकतरफा सियासी प्यार

राजनीति में दल, दिल और पाला बदलने का चलन पुराना है, लेकिन एक ही चुनाव में कोई नेता किसी दल के प्रत्याशी का विरोध करे और उसी दल के किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन तो उसकी चाल को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट की दावेदारी में तेजस्वी यादव ने पेच फंसाकर बेटिकट कर दिया। तब पप्पू ने तेजस्वी की राजनीति को बर्बाद करने की शपथ ली, लेकिन अब वही पप्पू सारण से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं रोहिणी आचार्य एवं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में उतर आए हैं। यहां तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेता एवं प्रत्याशी राहुल गांधी का भी प्रचार पप्पू रायबरेली जाकर कर आए हैं। लालू परिवार के प्रति पप्पू यादव के इस प्रेम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद भी कैंप किया और अपने दल के 40 विधायकों को भी लगा रखा था। फिर भी पप्पू का लालू यादव के परिवार से इतना एकतरफा प्यार हैरान करता है।

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

खुशी का पहला उपाय-पुरानी बातों को ज्यादा न सोचें

बदलता कश्मीर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनावों को लेकर यह जिज्ञासा देश में ही नहीं, दुनिया के भी कुछ हिस्सों में थी कि इस केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के प्रति लोगों का कैसा रुझान रहेगा? यह जिज्ञासा कश्मीर घाटी के निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर अधिक थी, क्योंकि इसके पहले एक तो सघन सुरक्षा के साए में चुनाव कराने पड़ते थे और दूसरे, तमाम तैयारियों के बावजूद मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कहीं कम रहता था। यह उत्साहजनक है कि इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आई। घाटी की तीनों लोकसभा सीटों श्रीनगर, बारामुला के बाद अनंतनाग-राजौरी में भी अच्छा-खासा मतदान हुआ। इन तीनों सीटों पर बढ़े हुए मतदान प्रतिशत ने चुनावों में लोगों की कम भागीदारी की आशंका को तो दूर किया ही, इस पर भी मुहर लगाई कि यहां के लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। यह भरोसा कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करने का काम करेगा। कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती मिलने का मतलब है यहां के लोगों की राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने के प्रति ललक बढ़ना। यह उल्लेखनीय है कि श्रीनगर, बारामुला और अनंतनाग-राजौरी में लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। कुछ जगह तो राष्ट्रीय औसत के बराबर मतदान देखने को मिला। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान भी घाटी में अतिरिक्त उत्साह नजर आया। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीर में अलगाववादी संगठनों से जुड़े नेताओं और उनके प्रभाव में रहने वाले लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। इसका सीधा अर्थ है कि कश्मीर के लोगों में यह संदेश पहुंच चुका है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी ही उनकी अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। यह एक शुभ संदेश है और इसे देखते हुए जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाने चाहिए। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। ऐसा किया जाना समय की मांग भी है। निःसंदेह केवल इसलिए नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस वर्ष सितंबर के पहले इस राज्य में विधानसभा चुनाव करा लिए जाने चाहिए। विधानसभा चुनाव जितनी जल्दी संभव हो, इसलिए भी कराए जाने चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के प्रति लोगों का भरोसा और अधिक बढ़े और उन्हें चुनी हुई सरकार भी हासिल हो सके। निश्चित रूप से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से अलगाववाद एवं आतंकवाद से पीड़ित रही कश्मीर घाटी का माहौल बदला है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यहां की स्थितियां पूरी तरह सुधर गई हैं। घाटी में अभी काफी कुछ बदलाव शेष है। यह शेष बदलाव तब अच्छे से पूरा होता हुआ दिखेगा, जब कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट सकेंगे।

नशे के शिकार बच्चे

बच्चों में नशे की लत बहुत चिंता का विषय है, जिसे अविलंब नहीं रोका गया तो आने वाले समय में स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। नशे का प्रभाव शहर से गांव तक फैल रहा है। आश्चर्य यह कि बच्चे तक इसका शिकार हो रहे हैं। नशे के लिए पंचर साटने वाले केमिकल (सुलेशन) का प्रयोग कर रहे हैं। इसे सूंघकर मदहोश हो जाते हैं। इसकी पड़ताल बहुत आवश्यक है कि इसके पीछे कौन है। नई पीढ़ी को इस अंधेरी राह पर लाने के पीछे एक बड़ा नेटवर्क भी है। इसकी ठीक से जांच-पड़ताल की जाए तो बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है। किशोरवय में ही नशे की लत के शिकार हो चुके बच्चों के घर-परिवार के लोग परेशान हैं। इनमें केवल मलिन बस्तियों के ही नहीं, अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे भी हैं, जिन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। अभिभावक अब उनकी चिकित्सा करा रहे हैं। उस परिवार की क्या हालत होगी, समझा जा सकता है। दो दिन पहले पटना जंक्शन के पास से चार बच्चों को प्रशासन ने अपने संरक्षण में लिया, जो नशे का शिकार थे। आसपास की झोपड़पट्टी में रहने वाले ये बच्चे वहां मंडराते रहते हैं। प्रशासन ने अभियान चलाया तो उन्हें इस दलदल से मुक्त भी कराया गया, पर पुनः वे उसी राह पर आ जाते हैं। केवल राजधानी ही नहीं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है। सासाराम में एक बच्ची ने नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो पता चला कि गांव के गांव में किशोर व युवा इसके शिकार हैं। इसके सामाजिक पहलू को ध्यान में रखना होगा कि यह नशा किस तरह एक पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुला है। नशे का धंधा करने वाले माफिया ने पूरा नेटवर्क बना रखा है।

बच्चों में नशे की लत पर रोक के लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों, सामाजिक-स्वयंसेवी संस्थाओं को भी पहल करनी होगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या वार्ता को तैयार नक्सलियों से बातचीत की जानी चाहिए?

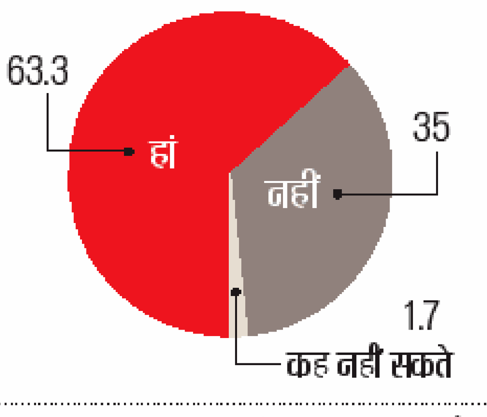

आज का सवाल

क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया का कोच बनने के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बेनकाब हुई तुष्टीकरण की राजनीति

संजय गुप्त

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने इस आरोप को बल प्रदान किया है कि आइएनडीआइए के घटक संविधान विरुद्ध जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं

ममता बनर्जी सरकार की ओर से 2010 के बाद मुस्लिम जातियों को ओबीसी प्रमाणपत्र देने के निर्णय को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। हालांकि उसने अपने निर्णय में यह कहा है कि जिन्हें ओबीसी प्रमाणपत्र के जरिये नौकरियां मिल गई हैं, उन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके निर्णय से करीब पांच लाख लोग प्रभावित होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता सरकार के निर्णय को मनमाना बताते हुए खारिज किया है। उच्च न्यायालय के फैसले से नाराज ममता बनर्जी राजनीतिक कारणों से यह कह रही हैं कि वह इस फैसले को नहीं मानेंगी, लेकिन यदि उन्हें हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। चूंकि यह निर्णय ममता की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का परिचायक है, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन पर राजनीतिक हमला बोल दिया है। मुस्लिम समाज की जातियों को ओबीसी प्रमाण पत्र देने के ममता सरकार के फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐसे समय निरस्त किया है, जब राज्य में चुनाव हो रहे हैं। स्पष्ट है कि यह निर्णय ममता सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। इसके पहले उन्हें ऐसा ही झटका कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले से भी लगा था, जिसमें उसने 25,000 शिक्षकों एवं स्कूली कर्मचारियों की भर्तियों को निरस्त कर दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को थोड़ी राहत दे दी, लेकिन उच्च न्यायालय के उस फैसले ने उनके समक्ष एक राजनीतिक संकट तो खड़ा ही कर दिया। ममता सरकार को उच्च न्यायालय के कुछ और फैसलों से झटका लग चुका है। इसमें एक संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की ओर से जमीनों पर कब्जा और महिलाओं के प्रति अत्याचार से भी जुड़ा है। इस मामले में ममता सरकार को उच्च न्यायालय की फटकार सुननी पड़ी थी और सर्वोच्च न्यायालय की भी।

ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप तभी से लग रहे हैं जबसे वह सत्ता में आई हैं। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण एक प्रमुख मुद्दा रहा है। भाजपा इस तुष्टीकरण को ही एक मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेरती रही है। बंगाल में पहले मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण कांग्रेस की ओर से किया जाता था, फिर वामदलों की ओर से किया जाने लगा। वामदलों को परास्त कर सत्ता में आईं ममता बनर्जी भी यही काम करने लगीं। 1947 में जब मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, तब पंजाब में तो दोनों छोर की आबादी का एक-दूसरे हिस्से में पलायन हुआ, लेकिन बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू ही बड़ी संख्या में पलायन कर भारत आए। बंगाल में रहने वाले कुछ ही मुस्लिम नए देश में बसने गए।

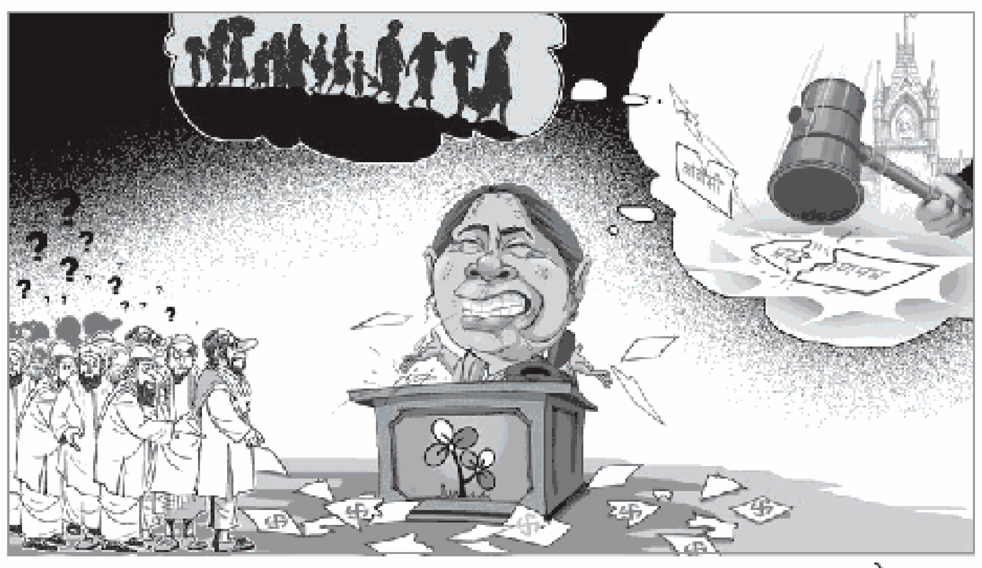

अवधेश राजपूत

बंगाल की सीमा बांग्लादेश से सटी है और सीमांत इलाके ऐसे हैं कि दोनों ओर आवाजाही कहीं अधिक आसान है। इसके चलते बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी बंगाल में आकर बसते रहे। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम बंगाल में भी आकर बसे और असम एवं त्रिपुरा में भी। आज इन तीनों राज्यों में बांग्लादेश से अवैध रूप से आए मुसलमानों की संख्या कितनी है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं। बांग्लादेश से आए मुसलमानों ने मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड आदि बनवा लिए हैं। वे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के लिए बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। बांग्लादेश से आई मुस्लिम आबादी ने बंगाल के साथ-साथ असम में सामाजिक तानेबाने को बदल दिया है और कई निर्वाचन क्षेत्रों में वे निर्णायक स्थिति में आ गए हैं। इसीलिए उनकी पहचान करने की मांग रह-रहकर होती रही है। मोदी सरकार ने इसी सिलसिले में नागरिकता कानून में संशोधन किया, ताकि बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम लोगों को देश की नागरिकता दी जा सके।

चूंकि बांग्लादेश से आए मुस्लिम कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामदलों के लिए वोट बैंक बन गए हैं, इसीलिए इन दलों ने यह भ्रांति फैलाई कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनना है, जबकि यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का है। इसके बावजूद भाजपा विरोधी दल यह वादा करने में लगे हुए हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो इस कानून को खत्म कर देंगे। चूंकि बंगाल में करीब 27 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेश से सटे कुछ जिले ऐसे हैं, जहां मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए स्वयं को सेक्युलर बताने वाले दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसी राजनीति के तहत ममता सरकार ने मुस्लिम समाज को ओबीसी आरक्षण का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए मनमाने तरीके से अनेक मुस्लिम जातियों को ओबीसी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए। साफ है इससे हिंदू समाज की ओबीसी जातियों के हितों को चोट पहुंची। वोट बैंक की इसी राजनीति के चलते एक समय आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम समाज को आरक्षण प्रदान किया गया। यही काम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने किया। उसने समस्त मुस्लिम समाज को पिछड़ा मानकर उसे ओबीसी आरक्षण दे दिया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाला विपक्षी मोर्चा आइएनडीआइए मजहब के आधार पर आरक्षण देने का इरादा रखता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान सरकार यह पता लगाने जा रही है कि कहीं पिछली कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अनुचित तरीके से मुस्लिम जातियों को तो ओबीसी आरक्षण नहीं प्रदान किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने भाजपा के इस आरोप को बल प्रदान किया है कि आइएनडीआइए के घटक दल संविधान के विरुद्ध जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। यह लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि भाजपा ने मजहब आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की जो घेरेबंदी की, उसका उसे कितना लाभ मिलेगा, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि कथित सेक्युलर दल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की यह राजनीति भारतीयता के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने और सीमा पार से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने वाली भी है।

response@jagran.com

सम्मान मिलेगा खटाखट-खटाखट

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

ऐसे को सम्मानित करने का कोई औचित्य नहीं, जो सम्मान तक ठीक से हजम नहीं कर सकता

कल सुबह ई-मेल खोली तो खुशी के मारे उछलने ही वाला था, पर घुटनों ने साथ नहीं दिया। किसी इनामी संस्था के सचिव का पत्र था। उन्होंने इस वर्ष के सम्मान देने के लिए मुझसे सुझाव मांगे थे। उत्सुकतावश संस्था का परिचय पढ़ने लगा। उसमें साफ लिखा था कि संस्था विगत 40 वर्षों से साहित्य-सेवा में अहर्निश जुटी हुई है। इस दौरान वह अनगिनत लेखकों और कवियों की झोली में सम्मान उड़ेल चुकी है। जो अपने लेखन से साहित्य-जगत में हलचल मचाने में असमर्थ होते हैं, संस्था तन और मन से उनकी सहायता करती है। जिस दिन उन्हें सम्मान दिया जाता है, उस दिन हंगामा मच जाता है। संस्था का दावा था कि उसके द्वारा सम्मानित साहित्यकार हर गली-मुहल्ले में मिल जाएंगे। इस वर्ष उनकी संस्था 21 साहित्यकारों के मन और मान की चाह शांत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पवित्र कार्य में आपसे सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपनी संस्तुति भी दे सकते हैं। हम उस पर उदारतापूर्वक विचारेंगे। पत्र पढ़कर 'फीलगुड' हुआ। इतनी ऐतिहासिक संस्था न केवल सुझाव मांग रही, बल्कि मुझे भी सम्मानित करने का हौसला रखती है।

शहर के साहित्यकारों ने कभी मेरी सुध नहीं ली। जरूर इस साहित्य-सरगना को मुझमें ऐसा कुछ दिखा होगा, जो कभी मुझे नहीं दिखा। मैंने साहित्य-सेवा करने का संकल्प उठा लिया। संस्था-सचिव को कई सुझाव लिख डाले खटाखट-खटाखट। साहित्य की सबसे ज्वलंत समस्या का समाधान करने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल सही जगह आपने संपर्क साधा है। वरना आजकल पता नहीं लोग किस-किस को साध रहे हैं! रही मेरी बात, तो कई सम्मानार्थियों से मेरे वैध संबंध हैं। वे मुझे उठाते हैं, मैं उन्हें। आप नाहक परेशान हो रहे हैं। एक खोजेंगे, 21 मिलेंगे। यह मेरी गारंटी है। अव्वल तो अब आपको 20 ही खोजने हैं। मैं आपके प्यार भरे अनुग्रह को इन्कार नहीं कर सकता। बहरहाल, मेरे पास कुछ अनुभव हैं, जिन्हें आपसे साझा कर रहा हूं। आपके पास जो भी संस्तुति आए, ध्यान से देखना कि उसे पहले कोई सम्मान मिला है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो फिर रिस्क न लें। हो सकता है, उसे इसीलिए न मिला हो कि सम्मान देने वालों का वह लिहाज न करता हो। साहित्यिक-गैंगस्टर को साहित्यकार न मानता हो। ऐसे लोगों को सम्मान बांटना कुल्हाड़ी पर पैर मारना है। वह संस्था का असली उद्देश्य उजागर कर सकता है। ऐसे को सम्मानित करने का कोई औचित्य नहीं, जो सम्मान तक ठीक से हजम नहीं कर सकता। इससे बेहतर है, अपने गैंग का विस्तार करें। सम्मानार्थी को वाट्सअप ग्रुप का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य हो। परिवारदार आदमी हो तो सोने पर सुहागा। समारोह में श्रोताओं की संख्या की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी।

अब दूसरे पहलू पर ज्यादा गौर करिए। जिसके परिचय में जितने ज्यादा सम्मान हों, उन्हें वरीयता दें। इनके मुंह में सम्मान लगा होता है। नहीं मिलने पर और खूंखार हो उठते हैं। पक्षपात का आरोप और लगाएंगे। ऐसे 'सीरियल-रिसीवर' सरोकार से ज्यादा सम्मान के प्यासे होते हैं। बारात में फूफा के बाद सम्मान का कोई भूखा होता है तो यही हैं। गोष्ठियों में ये अपने लेखन को छोड़कर लिफाफे और शाल पर गर्व करते हैं। अगर भूखे-नंगों को सम्मान दोगे तो बड़ी थू-थू होगी। मेरी बात और है। मैं आलरेडी सम्मान-हीन हूं। साहित्य के लिए पूरा जीवन होम कर चुका हूं। बस, सम्मान पाने भर के लिए प्राण अटके हैं। बिना अपने हिस्से का सम्मान लिए संसार नहीं छोड़ूंगा! हां, बाकियों के बारे में थोड़ा सतर्कता बरतना। सब मेरे जैसे नहीं हैं। सम्मान न पाने पर गैंग और ग्रुप से भी भाग सकते हैं। संस्था चलानी है तो सहेजना और समेटना सीखिए। ईमानदारी से सरकार तक नहीं बचती, संस्था कैसे बचेगी! सभी सम्मानप्राप्त लोगों की सूची बना लें। सम्मान की टोपी इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए। इनसे सहयोग वसूला जाए, ताकि संस्था के साथ इनका 'परमानेंट बांड' स्थापित हो सके। ध्यान रहे, समय-समय पर 'बांड' कैश भी कराते रहें!

response@jagran.com

ऊर्जा

शब्द संकोच

मनुष्य की कामनाएं अंतहीन हैं और समय कम। वह दिन-रात परिश्रम कर अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। समय उसके लिए सर्वाधिक मूल्यवान हो गया है। इस स्थिति ने उसकी कथन और श्रवण शक्ति को प्रभावित किया है। शब्द उसके लिए बोझ बन गए हैं। अत्यधिक व्यस्त मनुष्य कथन से अधिक संकेतों में विश्वास रखने लगा है। सुनने में भी वह तभी रुचि लेता है जब स्वहित में आवश्यक हो अथवा करने को कुछ न हो। शब्दों का संकोच आभिजात्य का प्रतीक हो गया है। यह ठीक है कि शब्दों का जीवन में महत्व है किंतु उस महत्व का कोई स्तर अवश्य चिह्नित किया जाना चाहिए। शब्द वर्षा की तरह हैं। वर्षा खेत को हरा-भरा कर देती है। अधिक वर्षा बाढ़ बन कर खेत को ही बहा ले जाती है। शब्दों का प्रयोग भी ऐसा ही है। विवेक सम्मत शब्द हृदय को स्पंदित करते हैं। शब्दों का प्रवाह कब अनर्गल हो दुखदाई बन जाए यह एक कठिन आकलन होता है। आज का समय वाक् पटुता का नहीं, वाक् सिद्धि का है। शब्दों को सिद्ध करने में ही सुख है।

लगभग हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग एक पूरे वाक्य का विकल्प होता है। ऐसे शब्दों का चयन कर उन्हें अपने कथन का अंग बनाया जाना श्रेयस्कर होगा। लेखन में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग अनावश्यक विस्तार के दोष से बचाने वाला है। अपने मनोभावों के संप्रेषण में शब्दों पर अतिरिक्त निर्भरता से बचना चाहिए। अधिक शब्द नहीं, उपयुक्त शब्द प्रभाव डालते हैं। गागर में सागर भरना साहित्य की एक विलक्षण विधा थी। दो पंक्तियों के दोहे में विस्तृत दर्शन सिमट आता था। आज शब्दों का अराजक मेला-ठेला है, जो जीवन को असहज कर रहा है। इसका निदान सक्षम शब्द ही हैं।

श्रेष्ठ शब्दों के चयन में प्रमुख भूमिका मनुष्य के चिंतन के स्तर की होती है। जैसे अमृत की एक बूंद अमरत्व प्रदान करने वाली है। वैसे ही श्रेष्ठ और सक्षम शब्द आनंद से भरपूर करने वाले हैं।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

तथ्य-कथ्य

रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को दिया जाने वाला लाभांश

(राशि करोड़ रुपये)

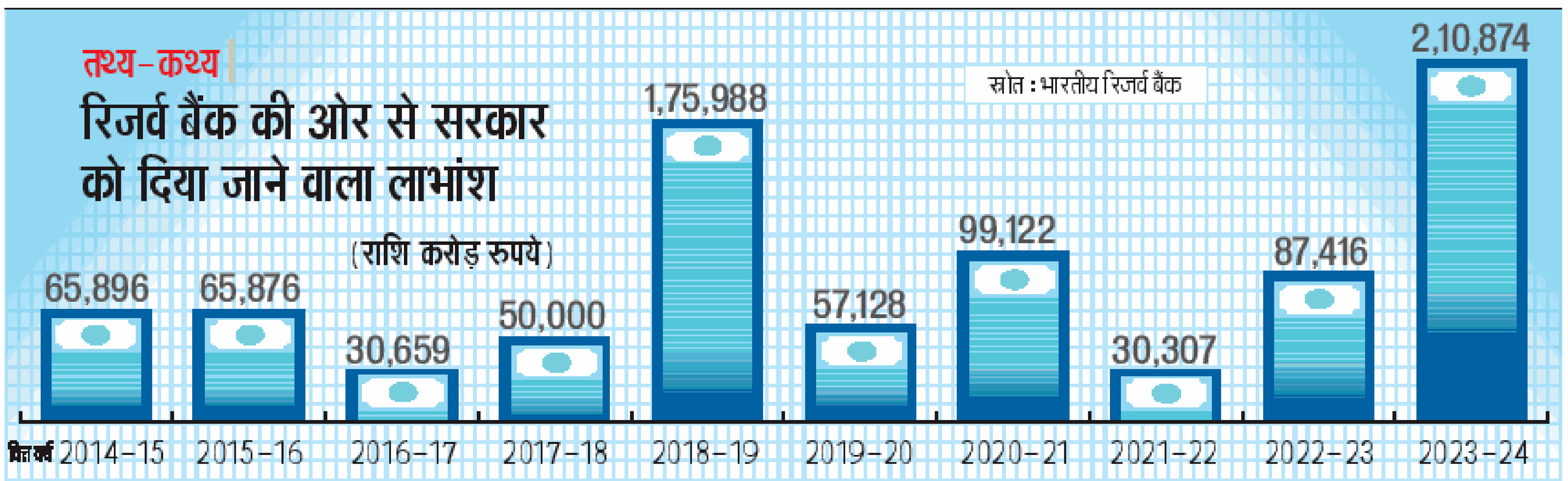

प्रोटोकाल की चिंता

चुनावी मौसम में सियासत का माहौल संसद के बाहर जरूर गरम है मगर इस दरम्यान संसद भवन परिसर में नए सांसदों के स्वागत-सत्कार की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। नए सांसदों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर उनके ओरिएंटेशन जैसे कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन सबके बीच उनकी व्यवस्था और प्रोटोकाल से जुड़े अधिकारियों की चिंता इस बात को लेकर है कि माननीयों को कैसे सहज रखा जाएगा। दरअसल इसकी वजह है कि संसद की सुरक्षा सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका अब अंदरूनी सुरक्षा में भी नगण्य हो गई है। बाहरी तथा भीतरी सुरक्षा, दोनों का जिम्मा पिछले दिनों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआइएसएफ ने संभाल लिया। चिंता इसे लेकर है कि सीआइएसएफ के अधिकारियों-जवानों को चूंकि सांसदों की सुरक्षा प्रोटोकाल के पालन का अनुभव नहीं है, लिहाजा किसी तरह की सख्ती असहज स्थिति पैदा कर सकती है। वे अधिकांश सांसदों को पहचानते भी नहीं होंगे। इसे देखते हुए प्रोटोकाल से जुड़े अधिकारियों को फिलहाल नए माननीयों के स्वागत-सत्कार के दौरान सीआइएसएफ की मदद के लिए तैनात रखने की तैयारी है।

राजरंग

घरेलू झगड़े में हथकंडे

पति-पत्नी के झगड़े में एक-दूसरे को परेशान करने की जितनी शिद्दत दिखाई देती है वह शायद कहीं न मिले। पिछले दिनों शीर्ष अदालत में भी पति-पत्नी के विवाद से संबंधित एक मामले को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग पर सुनवाई चल रही थी। तभी माननीय न्यायाधीश का ध्यान इस पर गया कि पति रहता दिल्ली में है और उसने केस राजस्थान में दाखिल कर रखा है। न्यायाधीश महोदय ने पति के वकील से इसको लेकर सवाल किया? वकील का जवाब था कि ऐसा इसलिए कि वह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। इस पर जज साहब ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वह पाकिस्तान से होगा तो क्या मुकदमा दाखिल करने लाहौर जाएगा?

नो कूल पीरियड

आम चुनाव के दौर में वैसे तो सभी मंत्रालयों में सौ दिनों का एजेंडा तैयार हो रहा है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय भी है जहां के अधिकारी चुनाव के कूल पीरियड का कोई आनंद नहीं ले पा रहे हैं। यह मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। वजह है कि सरकार चाहे जिस पार्टी की बने, पर नई सरकार में वित्त मंत्रालय पर चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी होगी। जुलाई के पहले 10 दिनों में आम बजट पेश किया जा सकता है। शेष कई मंत्रालयों के अधिकारी करीब सप्ताह-दो सप्ताह की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं मगर वित्त मंत्रालय के अफसर नार्थ ब्लाक से बाहर नहीं निकल पा रहे।

एकतरफा सियासी प्यार

राजनीति में दल, दिल और पाला बदलने का चलन पुराना है, लेकिन एक ही चुनाव में कोई नेता किसी दल के प्रत्याशी का विरोध करे और उसी दल के किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन तो उसकी चाल को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट की दावेदारी में तेजस्वी यादव ने पेच फंसाकर बेटिकट कर दिया। तब पप्पू ने तेजस्वी की राजनीति को बर्बाद करने की शपथ ली, लेकिन अब वही पप्पू सारण से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं रोहिणी आचार्य एवं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में उतर आए हैं। यहां तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेता एवं प्रत्याशी राहुल गांधी का भी प्रचार पप्पू रायबरेली जाकर कर आए हैं। लालू परिवार के प्रति पप्पू यादव के इस प्रेम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद भी कैंप किया और अपने दल के 40 विधायकों को भी लगा रखा था। फिर भी पप्पू का लालू यादव के परिवार से इतना एकतरफा प्यार हैरान करता है।

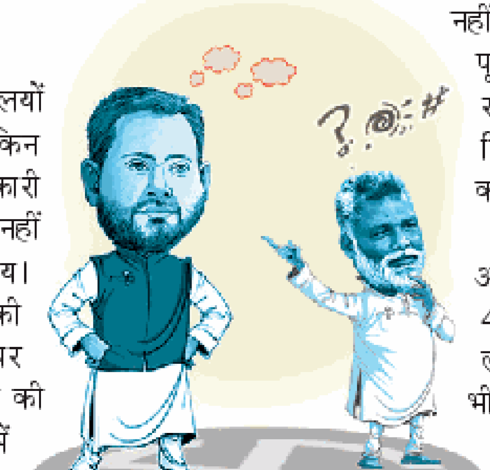

पोस्ट

हरियाणा के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कैंसर और हार्ट अटैक अब दोनों बहुत सामान्य हो गए हैं। सरकारें तो कुछ करने से रहीं। आप ही अपना ध्यान रख लीजिए। डाक्टरों के अनुसार गर्मी में डिहाइड्रेशन भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। कुमार अंशुमान@anshumanscribe

सभी राज्यों/बड़े जिलों में सीबीआइ जैसी एक अपनी प्रतिबद्ध जांच इकाई होनी चाहिए, ताकि वह केवल जांच पर ध्यान देकर उसकी गुणवत्ता बढ़ा सके। कोई भी गंभीर अपराध घटित होने पर सीबीआइ जांच की मांग करना अनुचित है, खासतौर पर तब जब पुलिस राज्यों का विषय है। आरके विज@ipsvijrk

इन दिनों देखा जा रहा है कि राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर कुछ लोग झगड़ कर दोस्ती तोड़ रहे हैं। याद रखें मुश्किल समय में ये मित्र ही आपके काम आएंगे, न कि राजनीतिक दल। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन दोस्त हमेशा रहते हैं। हर्ष गोयनका@hvgoenka

रिस्क लेने से मत डरें। हो सकता है, यही रिस्क एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। रजत शर्मा@RajatSharmaLive

जनपथ

हाथी निकला रह गई अब तो केवल पूँछ,
लाल बुझक्कड़ आजकल रहे परिस्थिति बूझ।
रहे परिस्थिति बूझ ज्ञान का खोल पिटारा,
जैसे हर मतपत्र छपा इनके ही द्वारा!
यही लोग कल जाय बनेंगे उनके साथी,
जाकर जिनके द्वार बंधे सत्ता का हाथी!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 44

नई जमीन

12

नई दिल्ली ▪ रविवार, 26 मई 2024

amarujala.com
अमर उजाला

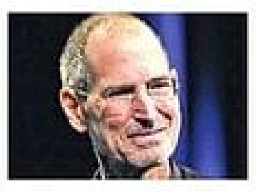

महान कार्य करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं, उसे पसंद करें। - स्टीव जॉब्स

चमत्कारी क्रांति, जो अभिशप्त कारोबार बन गई

पूरी दुनिया में रेलवे सरकारों की सबसे बड़ी चुनौती है। निजी कंपनियों का संसार आकाश से पाताल तक फैल गया है। मगर सरकारें उन्हें रेलवे में निवेश को राजी नहीं कर पातीं। रेलवे दुनिया की सबसे चमत्कारी औद्योगिक क्रांति थी, मगर यह आर्थिक तौर पर सबसे अभिशप्त कारोबार भी है।

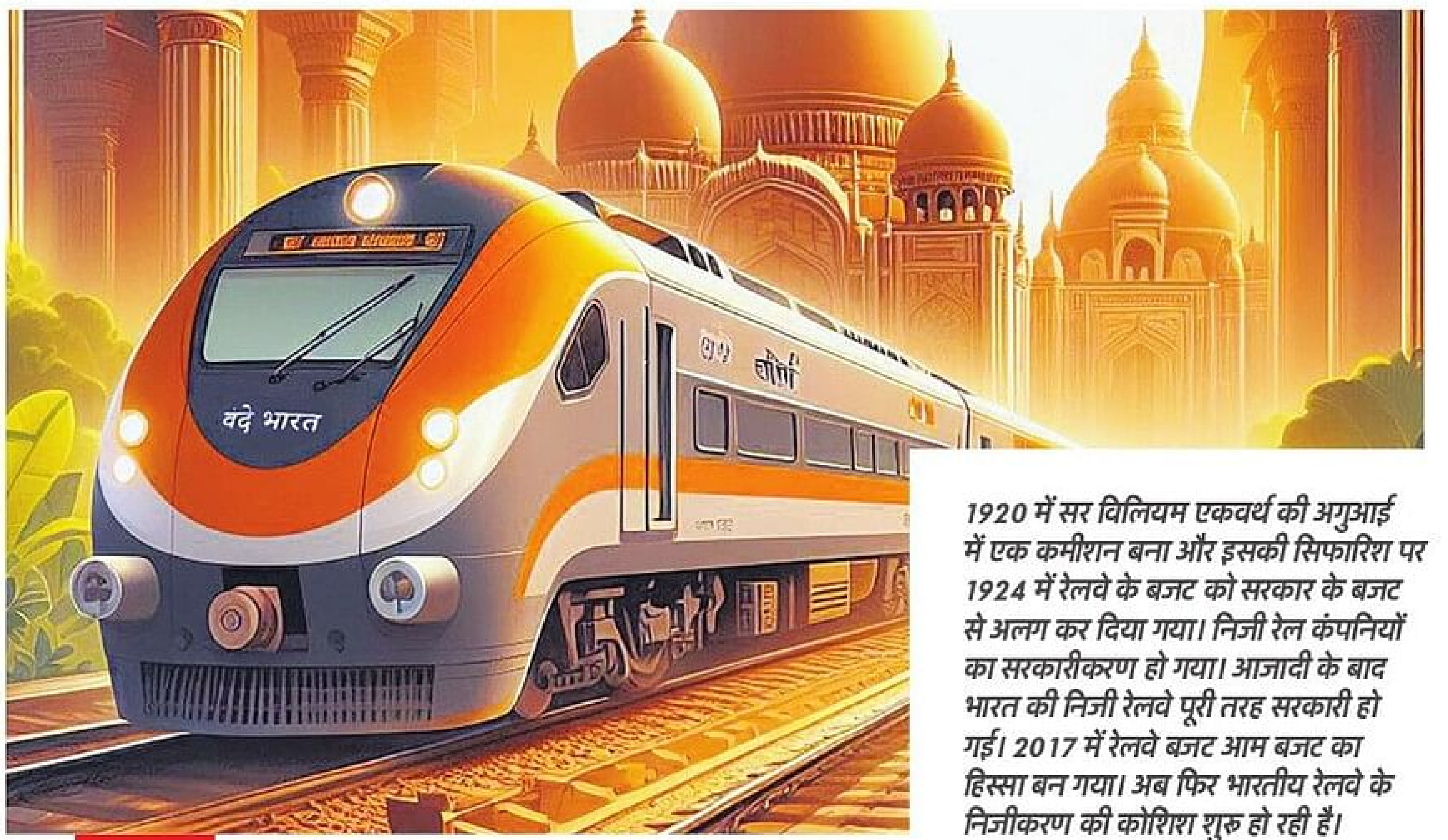

1920 में सर विलियम एकवर्थ की अगुआई में एक कमीशन बना और इसकी सिफारिश पर 1924 में रेलवे के बजट को सरकार के बजट से अलग कर दिया गया। निजी रेल कंपनियों का सरकारीकरण हो गया। आजादी के बाद भारत की निजी रेलवे पूरी तरह सरकारी हो गई। 2017 में रेलवे बजट आम बजट का हिस्सा बन गया। अब फिर भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोशिश शुरू हो रही है।

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ लेखक-पत्रकार

भारत में चुनावी चकल्लस के बीच जनता को यह पता नहीं चला कि भारतीय रेल यात्री किराये की कमाई में पिछड़ गई है। रेलवे का पैसेंजर राजस्व बीते साल में उस गति से भी नहीं बढ़ा, जिस रफ्तार से भारत की जीडीपी (महंगाई सहित यानी नॉमिनल) बढ़ी है। वंदे भारत ट्रेनों को कामयाब बनाने के लिए बीते साल किराये भी घटाए गए थे, मगर रेलवे को महंगे टिकट लेने वाले यात्री नहीं मिल रहे। दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने निजी ट्रेनें चलाने की योजना रोक दी थी। 30,000 करोड़ का टेंडर लौट गया। यह भारत में रेलवे के निजीकरण की पहली सबसे महत्वाकांक्षी कोशिश थी, रूट तय हो गए थे। निजी कंपनियां और सरकार के बीच कमाई के बंटवारे का फॉर्मूला बन गया, मगर कंपनियों ने भारत के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर यानी रेलवे में दिलचस्पी ही नहीं ली। वर्ष 2022 में सरकार ने रेलवे की संपत्तियां बेचने की कोशिश की। कोई ग्राहक नहीं आया। रेलवे के कुछ विभाग और प्रतिष्ठान बंद करने की तैयारी है, घाटा कम करने या नए संसाधन जुटाने की हर जुगत औंधे मुंह गिर पड़ी। बीते एक दशक में रेलवे बजट खत्म करने से लेकर निजीकरण तक, तमाम कोशिशों के बाद भी इस महाकाय गतिमान बुनियादी ढांचे की बैसाखियां हटती ही नहीं। रेलवे के घाटे का दुख दूर ही नहीं होता। अलबत्ता भारत अकेला नहीं है। पूरी दुनिया में रेल सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। निजी कंपनियों का संसार आकाश से पाताल तक फैल गया है। मगर सरकारें उन्हें रेलवे में निवेश के लिए राजी नहीं कर पातीं। रेलवे दुनिया की सबसे चमत्कारी औद्योगिक क्रांति थी, मगर यह आर्थिक तौर पर सबसे अभिशप्त कारोबार भी है।

आइए, टाइम मशीन में विराजिए। चलते हैं करीब 200 साल पीछे रेलवे के चमत्कारी दिनों में...

टाइम मशीन
अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ▪ हर पखवाड़े

आपको अपनी सीट पर एक उपन्यास रखा मिला होगा। जब तक हम उड़ान भरते हैं, आप इसका आनंद लीजिए। स्कॉटिश कवि और व्यंग्यकार डब्ल्यू. ई. आइटन का यह व्यंग्य उपन्यास 1845 में आया था। इसका शीर्षक है-*हाउ वी गॉट अप द ग्लेनमचकिन रेलवे?* हम यूरोपीय इतिहास के जिस युग में जा रहे हैं, वह रेलवे बबल यानी रेलवे में भारी निवेश और नुकसान का दौर है। यह उपन्यास उस वक्त का प्रतिनिधि दस्तावेज माना जाता है।

यह भीड़ देख रहे हैं। यह दुनिया के इतिहास के सबसे अनोखे मोड़ का गवाह बन रही है। यह 1830 है। ब्रिटेन में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच यात्री ट्रेन चलाई जा रही है।

इस ट्रेन के आने से पहले तक लोग घोड़ों वाली बग्घी पर यात्रा करते थे। पहली यात्री रेल खूब कामयाब हुई। उद्योगपतियों ने रेलवे में पूंजी झोंकनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन की सरकार ने एक साथ 3,000 से अधिक रेल लाइनों को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन की आर्थिक हवा रेल क्रांति के किस्सों से महक रही है। निजी कंपनियां और बैंक रेलवे में निवेश का कोई मौका नहीं चूकना चाहते।

आप 21वीं सदी से आए हैं, तो आपको उस तरह के अंधे निवेश में खतरों का एहसास है, मगर ब्रिटेन के लोग तो रेलवे में निवेश के दीवाने हैं। इस दीवानगी को देखते हुए हम 1900 में आ गए हैं। आपको 21वीं सदी वाली दुनिया का एहसास हो रहा होगा। एकाउंटिंग फ्रॉड, पोंजी स्कीमें, झूठे प्रचार, भ्रष्टाचार, वही सब जो इस तरह के निवेश में होता है।

इन सुर्खियों को ध्यान से पढ़िए- ब्रिटेन और अमेरिका की रेल कंपनियां दिवालिया हुईं। बैंक डूबे। असंख्य कंपनियों में निवेशकों की 90 फीसदी पूंजी स्वाहा हो गई।

इस चिल्ल-पों के बीच प्रख्यात वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का नाम आपके कानों तक आया होगा। रेलवे कंपनियां उनकी पूंजी भी ले डूबी हैं। इस रेलवे संकट में ब्रिटेन के साहित्य जगत की प्रख्यात तीन बहनों-द ब्रांटे सिस्टर्स को भी भारी चपत लगी है। मगर इस संकट के बावजूद रेलवे का आविष्कार दुनिया के काम आया। यह परिवहन का नया जरिया बन गया। सरकारी मदद से रेल क्रांति शुरू हो गई थी। 1870 तक ब्रिटेन में करीब 6000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। अमेरिका में रेल-रोड तेजी से फैलने लगा। पहले विश्वयुद्ध की तोपें गरजने तक रेलवे एक प्रमुख रणनीतिक ताकत बन गई।

अब हम भारत पहुंच रहे हैं। दौर तो रेलवे क्रांति का ही है। पहले विश्वयुद्ध की भूमिका बनने तक ब्रिटेन की पूंजी रेल के जरिये ब्रिटिश राज के उपनिवेशों में पहुंचने लगी है। रेलवे ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा विदेशी निवेश बन गया है। 1914 तक ब्रिटिश रेलवे निवेश का 40 फीसदी हिस्सा अमेरिका में था। अब भारत में भी रेल पटरियों की खटर-पटर प्रारंभ हो रही है। ब्रिटेन की कंपनियों ने रेलवे में निवेश शुरू कर दिया है। यह 1853 का मुंबई है, थाणे तक 20 किलोमीटर के रास्ते पर पहली रेल चल पड़ी है। भारत जब आजाद होगा, तो यहां 24,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार होगा।

हम तो 1850 में हैं, सो रेलवे की भारतीय क्रांति को करीब से देखते हैं। भारत में रेलवे नेटवर्क की स्थापना के पीछे है निजीकरण का एक जटिल ताना-बाना। 1850 के बाद भारत में दस निजी रेल कंपनियां थीं, जो पूर्वी भारत, पूर्वी बंगाल, बाम्बे, बड़ौदा, सेंट्रल इंडिया, इंडियन पेनिनसुएला, सिंध, पंजाब, दिल्ली, मद्रास, दक्षिण भारत, अवध और रुहेलखंड के रेलवे नेटवर्क संभालती थीं। इनमें ब्रिटिश पूंजी लगी है। ब्रिटिश राज और भारत की ब्रितानी सरकार ने इन कंपनियों को मुफ्त जमीन और निवेश पर पांच फीसदी रिटर्न की गारंटी दी है। यह 21वीं सदी के सड़क विकास के बीओटी मॉडल का पूर्वज जैसा महसूस होगा। अलबत्ता 1870 आने तक बात बिगड़ने लगी। ब्रिटिश राज गलियारों में इस वक्त यह चर्चा तेज है कि लंदन में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और भारत की बर्तानवी सरकार के बीच रेलवे के प्रबंधन को लेकर गहरे मतभेद उभर आए हैं। कंपनियां गारंटीड रिटर्न नहीं दे पा रही थीं। ब्रिटिश सरकार का आर्थिक हाल बुरा होने लगा है।

धूप आने दो

नतीजतन रेल कंपनियों का सरकारीकरण शुरू हो रहा है। भारत की ब्रिटिश सरकार कंपनियों में हिस्सेदारी लेने लगी। भारत में सफर करते हुए आप पहले विश्वयुद्ध और भारत में रेलवे को लेकर निजी कंपनियों व सरकार के बीच जंग की खबरें सुन रहे हैं। झगड़ा इस कदर बढ़ा है कि 1920 में सर विलियम एकवर्थ की अगुआई में एक कमीशन बना और इसकी सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को सरकारी बजट से अलग कर दिया गया। निजी रेल कंपनियों का सरकारीकरण हो गया। आजादी के बाद भारत की निजी रेलवे सरकारी हो गई। 2017 में रेल बजट आम बजट का हिस्सा बन गया। अब फिर भारतीय रेल के निजीकरण की कोशिश शुरू हो रही है।

टाइम मशीन का सफर अब पूरा होने के करीब है। स्क्रीन पर तैरती सुर्खियों से गुजरते हुए आपको पता चलेगा कि रेलवे का घाटा पूरी दुनिया के लिए मुसीबत है। निजीकरण को लेकर दुनिया के तजुर्बे अच्छे नहीं हैं। 20वीं सदी में रेलवे का इतिहास दिवालियापन और निजी कंपनियों को नुकसान का है। यही वजह है कि 21वीं सदी का सूरज उगने तक दुनिया के सभी देशों में रेलवे का पूरी तरह या आंशिक राष्ट्रीयकरण हो गया था। रेल निजी कंपनियों को रास नहीं आती। यह अभिशाप बीते सौ बरस से रेलवे का पीछा नहीं छोड़ रहा। निजीकरण की कोशिशें बार-बार औंधे मुंह ढेर हो जाती हैं। अब टाइम मशीन दिल्ली के रेल भवन के सामने उतर रही है। अब तो अगली सरकार ही बताएगी कि रेलवे के घाटे का दुख कैसे दूर होगा। फिर मिलेंगे अगले सफर पर...

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

व्यास ने कहा, 'कीट! तुम भय न करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जब तक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं तुम्हें प्रत्येक योनि से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा।'

वेदव्यास ने कीड़े को कैसे बनाया ऋषि

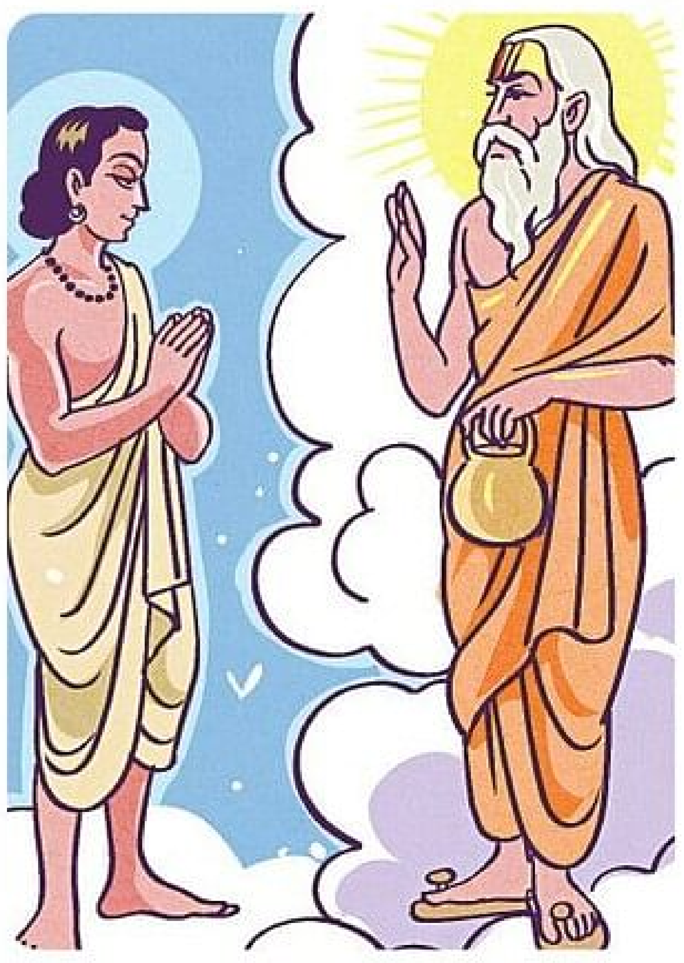

महर्षि वेदव्यास सभी जीवों की भाषा समझते थे। एक दिन वह कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। उन्होंने कीड़े को रोककर भागने का कारण पूछा, तो कीड़ा बोला, 'मुनीश्वर! एक बैलगाड़ी इसी मार्ग से आ रही है। मुझे डर है कि मैं उसके नीचे दबकर मर जाऊंगा, इसलिए भाग रहा हूं।' यह सुनकर व्यास हंसे और बोले, 'तुम्हारे लिए तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इस तिर्यक योनि से मुक्ति मिल जाएगी। यदि मनुष्य को मृत्यु से भय लगे, तो समझ में भी आता है, किंतु तुम्हें कीट योनि से मुक्त होने का भय क्यों है?' इस पर कीड़े ने उत्तर दिया, 'महर्षि, मुझे मृत्यु का नहीं, अपितु इस बात का भय है कि कीट योनि से भी अधम अनेक योनियां हैं, मैं कहीं मरकर किसी और बुरी योनि में न चला जाऊं!'

व्यास ने कहा, 'कीट! तुम भय न करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जब तक ब्राह्मण का शरीर प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं तुम्हें प्रत्येक योनि से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा।' वेदव्यास का आश्वासन सुनकर कीड़ा प्रसन्न हो गया। वह पुनः उसी मार्ग पर लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद वह कीड़ा, अनेक निम्न योनियों में पैदा हुआ। हर बार वेदव्यास ने उसे पूर्वजन्म का स्मरण कराया और उन योनियों से मुक्त होने में सहायता भी की। इस तरह वह कीड़ा मरते-मरते साही, गोह, मृग, पक्षी, आदि योनियों में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य योनि में निम्न जातियों में पैदा होते हुए क्षत्रिय जाति में भी जन्म लिया। वेदव्यास ने अपने वचनानुसार, हर योनि में उसे दर्शन दिए और उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आखिरकार, उस कीड़े ने क्षत्रिय कुल में प्राण त्यागकर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया।

वह ब्राह्मण जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो स्वयं वेदव्यास ने उसे सारस्वत मंत्र सिखाया, जिसके प्रभाव से वह बिना अधिक प्रयास के ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। कीड़ा अब विद्वान बन चुका था। फिर वेदव्यास ने उसे लोगों को उपदेश देने और उनकी शंकाओं का समाधान करने की आज्ञा दी।

गुरु की आज्ञा से ब्राह्मण ने धर्म का उपदेश देना और शंकाओं का समाधान आरंभ कर दिया। एक बार किसी ने उससे पूछा कि पापी मनुष्य प्रायः सुखी क्यों दिखाई देते हैं? ब्राह्मण ने समझाया, 'जिन लोगों ने पूर्वजन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्हें इस जन्म में उस दान का फल मिलता है, परंतु तामस भाव से कोई सत्कार्य करने पर भी उसे धर्म में अनुराग नहीं होता और इसी कारण पापी व्यक्ति सुखी दिखता है। ऐसा मनुष्य पुण्य-फल को भोगकर भी तामस भाव के कारण नरक में गिरता है।

इस विषय में महर्षि मार्कण्डेय ने कहा है कि मनुष्य की चार श्रेणियां हैं। एक, जिसका पूर्वजन्म का पुण्य शेष है। वह उस पुण्य का सुख पाता है, किंतु नए पुण्य नहीं करता, ऐसे मंदबुद्धि मनुष्य को मिलने वाला सुख केवल इसी लोक तक सीमित रहता है। दूसरा, जिसका पूर्वजन्म का पुण्य तो नहीं है, किंतु वह इस जन्म में नए पुण्य का उपार्जन करता है। ऐसा व्यक्ति परलोक में सुख पाता है। तीसरा, जिसका पूर्वजन्म का पुण्य वर्तमान जन्म में सुख देता है और वह नए पुण्य का उपार्जन भी करता है, जिसके कारण वह इहलोक और परलोक, दोनों जगह सुख पाता है। और चौथा वह है, जिसका पहले का कोई पुण्य शेष नहीं है और वह इस जन्म में भी कोई नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख प्राप्त होता है।' इस प्रकार एक कीट से विद्वान ब्राह्मण बने उस व्यक्ति ने धर्म का प्रचार-प्रसार करते हुए बहुत-सा पुण्य अर्जित कर लिया। फिर उसने सूर्य मंत्र का निरंतर जाप किया और बहूदक तीर्थ में अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। वेदव्यास के उस शिष्य का लोगों ने बड़े आदर से विधिपूर्वक दाह-संस्कार किया और उसकी अस्थियां उसी तीर्थ-स्थल पर प्रवाहित कर दीं। फिर अगले जन्म में उसी ब्राह्मण ने मैत्रेय नामक प्रख्यात ऋषि के रूप में जन्म लिया। कालांतर में ऋषि मैत्रेय ने वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर से शिक्षा प्राप्त की।

नोट : पिछले सप्ताह की कथा में नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवा के स्थान पर उद्दालक लिखा गया था। नाम में हुई त्रुटि के लिए लेखक क्षमा प्रार्थी है। साथ ही प्रसंगवश एक अन्य संदर्भ लें : *महाभारत* के अनुशासन पर्व (अध्याय 71) में भी ऐसी ही एक कथा है, जिसमें नचिकेता के पिता का नाम उद्दालक उद्धृत है।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि
पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः
कर्मसमुद्भवः।।

अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।

- भीष्म पर्व, गीता 3/14
(अर्जुन के प्रति साक्षात भगवान श्रीकृष्ण का गीतोपदेश)

प्रस्तुति : विवेक चौरसिया

एक तरह की चाय सबको पसंद नहीं आती

क्रिश्चियन ब्रैकेनरिज
स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो

खान-पान में सतर्कता रखें, जहां मौका मिले वहां पैदल चलने से न चूकें, हंसे-खिलखिलाएं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वह जरूर करें।

हर किसी को पता है कि स्वस्थ रहना क्या होता है। बैठने से बेहतर है खड़े होना और समग्र स्वास्थ्य के लिए व्यायाम व अच्छी नींद जरूरी है, लेकिन जैसे एक ही तरह की चाय सभी को पसंद आए, यह जरूरी नहीं, उसी तरह स्वस्थ रहने का एक ही फॉर्मूला सभी के लिए सटीक हो, यह भी जरूरी नहीं होता। हालांकि एक बात है, जो सभी पर समान रूप से लागू होती है और वह, यह कि सभी के लिए दिन चौबीस घंटे का ही होता है। अब खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप इन चौबीस घंटों का किस तरह से संतुलित ढंग से इस्तेमाल करते हैं, वह आप पर है।

स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए फिलहाल जो चिकित्सकीय तौर पर सर्वमान्य दिशानिर्देश हैं, उनमें हफ्ते में ढाई से पांच घंटे के सामान्य से कठोर व्यायाम की बात शामिल है। लेकिन नवीनतम शोध बताते हैं कि सामान्य व्यायामों के अलावा आप अमूमन जो शारीरिक गतिविधियां करते हैं, वे भी आपको स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, ये सब हल्के-फुल्के व्यायाम ही तो हैं। हमने करीब दो हजार वयस्कों पर एक शोध किया, जिन्होंने ऐसे सेंसर पहने थे, जो उनके शारीरिक व्यवहार की व्याख्या कर रहे थे। हमने 24 घंटों तक उनके व्यवहार का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके शरीर में हो रहे हजारों बदलावों को नोट किया। हमने देखा कि बैठने, खड़े होने, हल्की व मध्यम तीव्रता की गतिविधियों से भी शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। देखा कि अगर आप हल्की तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि, मसलन, हर मिनट में सौ कदम चलना, कर रहे हैं, तो भी आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। वॉशरूम तक जाते हैं या दोस्तों के साथ थोड़ा-बहुत चलते हैं, तो इससे भी फर्क पड़ता है। खासकर, टाइप-2 मधुमेह वाले रोगियों में तो यह काफी कारगर है। ऐसे व्यायामों की खासियत है कि ये नियमित अंतराल पर दिन में कई बार हो जाते हैं। दोपहर भोजन के बाद 300 कदम चलना क्या कोई मुश्किल काम है? जब आप यह रोजाना करते हैं, तभी इसके जादू को महसूस कर सकेंगे। हालांकि ये निष्कर्ष प्रारंभिक हैं और हृदय रोग व मधुमेह को ध्यान में रखते हुए केवल 24 घंटों को आधार बनाकर इन्हें सत्यापित किया गया है। पुष्टि के लिए इसे गहराई से समझना होगा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी हैं, पर हम इस प्रयोग को समझाना चाहते हैं कि स्वस्थ रहना सिर्फ इस पर ही निर्भर नहीं करता। जो लगातार दिमाग चलाते हैं, वे छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देकर भी स्वस्थ रह सकते हैं। खान-पान में सतर्कता रखें, जहां मौका मिले, वहां पैदल चलने से न चूकें, हंसे-खिलखिलाएं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वह जरूर करें। तब जो आप महसूस करेंगे, वह स्वस्थता नहीं तो और क्या है!

अध्ययन कक्ष

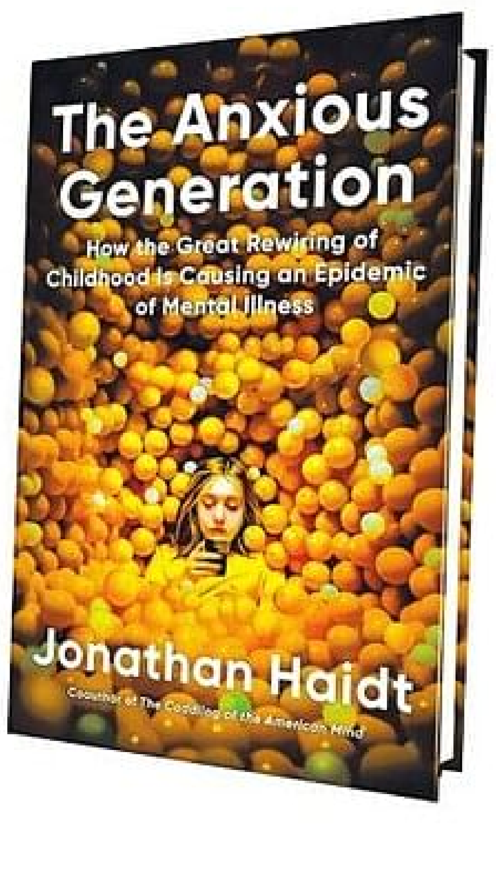

द अनेक्सस जेनरेशन
हाउ द ग्रेट रीवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड इज कॉसिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस
लेखक-जोनाथन हैद
प्रकाशक- पेंगुइन प्रेस
मूल्य-804 रुपये, पेपरबैक

बच्चों को बीमार बना रहा स्मार्टफोन

मनोविज्ञानी जोनाथन हैद ने अपनी किताब द अनेक्सस जेनरेशन में बताया है कि स्मार्टफोन के उदय और बच्चों के सुरक्षात्मक पालन-पोषण के कारण उनके बचपन की रीवायरिंग हुई है और मानसिक बीमारी में वृद्धि हुई है।

चर्चित सामाजिक मनोविज्ञानी जोनाथन हैद ने अपनी इस नई किताब *द अनेक्सस जेनरेशन* में बताया है कि स्मार्टफोन के बेतहाशा इस्तेमाल के कारण किस तरह किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी संकट है। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की बदहाली पर लेखक इससे पहले *द कोडलिंग ऑफ द अमेरिकन माइंड* नाम से किताब लिख चुके हैं।

एक दशक पहले तक अपने बच्चों को स्मार्टफोन देने वाले अभिभावकों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वे अपने परिवार में बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। सबूत बताते हैं कि स्मार्टफोन्स के साथ बड़े होने वाले बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। हैद ने इस किताब में बताया है कि स्मार्टफोन के उदय और बच्चों के सुरक्षात्मक पालन-पोषण के कारण उनके बचपन की रीवायरिंग हुई है और मानसिक बीमारी में वृद्धि हुई है। लेखक का अध्ययन मुख्यतः अमेरिका पर केंद्रित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम पश्चिमी देशों तक के किशोर इस समस्या से पीड़ित हैं। उनका यह भी कहना है कि इन तमाम देशों में इस संकट की शुरुआत कमोबेश एक ही समय हुई।

यह समस्या वर्ष 2010 से शुरू हुई, और खासकर किशोरियां इससे ज्यादा पीड़ित हैं। पहले जितनी अमेरिकी किशोरियां मानसिक बीमारियों से पीड़ित होती थीं, अब उनका आंकड़ा इससे दोगुना हो गया है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने वाले जिन बच्चों में अवसाद के लक्षण नहीं हैं, वे भी अकेलेपन का एहसास करते हैं।

दो निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं-एक, जेड पीढ़ी भीषण मानसिक संघर्ष से जूझ रही है। दूसरा, इसके लिए स्मार्टफोन्स जिम्मेदार है। लेखक वर्ष 2010 से 2015 तक की अवधि को ग्रेट रीवायरिंग की अवधि बताते हैं, जब रोज-रोज स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से किशोरों में अवसाद और दुश्चिंता के भाव बढ़ने लगे। लेखक कहते हैं कि किशोरों के बदतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्मार्टफोन ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बच्चों का सुरक्षित पालन-पोषण और समृद्ध तबके द्वारा अपने बच्चों को तमाम सुख-सुविधाएं देने, जिसके लिए लेखक हेलिकॉप्टर पैरेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, की प्रवृत्ति भी जिम्मेदार है। समाज में अमीर निरंतर बढ़ रहे हैं, और ये लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हैं। यह अतिशय सुरक्षा का भाव भी किशोरों की मानसिक परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि इससे वे बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, खेलने-कूदने और संघर्ष करने का अनुभव न होने से वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।

लेखक का यह आकलन बेहद महत्वपूर्ण है कि आज के अभिभावक बच्चों को बाहरी दुनिया के संघर्षों में तो नहीं जाने देते, लेकिन जाने-अनजाने वे अपने बच्चों को वर्चुअल दुनिया के खतरों में धकेल देते हैं। अलबत्ता लेखक का जोर स्मार्टफोन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने पर ज्यादा है। उनके मुताबिक, किशोरों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल रोकने के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और विधायी प्रयासों की जरूरत है। आज के दौर की यह बेहद प्रासंगिक किताब है, क्योंकि आज दुनिया भर के किशोर और युवा इस समस्या से जूझ रहे हैं।

अभियान

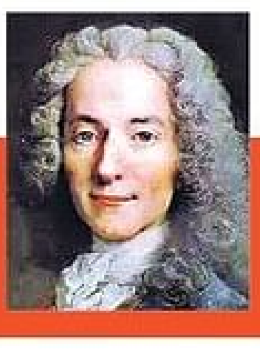

सटीक होने के बजाय हमेशा दिलचस्प होने का लक्ष्य रखना चाहिए।
- वोल्टेयर, फ्रांसीसी दार्शनिक

amarujala.com
अमर उजाला

गोल चबूतरा

Hindi@mithelesh

■ मिथिलेश बारिया

आशिक था मेरे अंदर,
कुछ साल पहले गुजर गया...
अब कोई शायर-सा है,
अजीब-अजीब सी बातें करता है...

शहर भी देखा बदलकर, पर कुछ है
मेरे अंदर जो आज भी वही है...

वनडे में 318 रनों की साझेदारी

झरोखा
26 मई

आज के ही दिन सन 1999 में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड ने 318 रनों की भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दोनों ने श्रीलंका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय वनडे मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की थी। ब्रिटेन में आयोजित हुए विश्व कप का यह 21वां मुकाबला था।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत की तरफ से सदागोपन रमेश और सौरव गांगुली ने पारी की शुरुआत की। भारत का पहला विकेट जल्दी गिर गया। सलामी बल्लेबाज सदागोपन रमेश चार गेंदों में पांच रन बनाकर चामिंडा वास का शिकार बन गए। वन-डाउन बल्लेबाजी करने उतरे राहुल द्रविड ने गांगुली के साथ पारी को आगे बढ़ाया और 318 रनों की साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड बना डाला। अपनी पारी में सौरव गांगुली ने 158 गेंदों पर 183 रन बनाए, जबकि राहुल द्रविड ने 129 गेंदों पर 145 रन बनाए थे। दोनों की दमदार पारी की बदौलत भारतीय टीम 50 ओवरों में 373 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 42.3 ओवर में केवल 216 रन ही बना पाई। भारत ने यह मुकाबला 157 रनों से जीता था।

■ दिल्ली से सचिन सक्सेना

तेजी से होता जलवायु परिवर्तन खतरे की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए समय है कि हम अब भी चेत जाएं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सावधानी बरतें। ऐसा न हो कि भावी पीढ़ियां हमें इसका जिम्मेदार ठहराएं और तब हम निःशब्द हों।

होश में आएं, प्रकृति से मजाक बंद करें

ये गरमी चेतावनी है

चिट्ठी 1

जिस प्रकार तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि निकट भविष्य में गरमी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। गांव, कस्बे या शहर पर नजर डालें तो कंक्रीट के जंगल नजर आएंगे। बाग, खेत-खलिहान सब उजड़ रहे हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ मानो सब कुछ निगल जाना चाहती हो। नए कारखाने, नए भवन, उपजाऊ जमीन की छाती पर चढ़े बैठे हैं। घर, गाड़ी और दफ्तर वातानुकूलन के नाम पर वातावरण में आग उगलने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर निकलना मानो जान हथेली पर रखने के समान हो गया है। यही हाल रहा तो भविष्य में घर से निकलना दूभर होगा। आखिर इसका समाधान निकले तो कैसे? कोरोना और लॉकडाउन ने एक बार विश्व को सबक दिया, पर समय की धूल उस सबक पर बहुत जल्दी जम गई। कोरोना काल में एक बार वातावरण शुद्ध और तापमान कम प्रतीत होता नजर आया, पर जैसे ही सब सामान्य हुआ तो मौसम असामान्य हो गया। आखिर हम कहां जाकर रुकेंगे और पर्यावरण के बारे में कब चिंतन-मनन करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि भावी पीढ़ी हमारे कर्मों का फल भोगे और हम आलोचना के शिकार हो जाएं। भावी पीढ़ी हमें कोसने पर मजबूर न हो जाए, इसलिए हमें अभी सजग हो जाना चाहिए और अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। पेड़ों के कटान की ओर हमारा ध्यान कब आकर्षित होगा, कब हम पर्यावरण और जल संरक्षण को गंभीरता से लेंगे? सरकार प्रयास करती है, पौधरोपण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पर अभियान की हवा शांत पड़ जाती है। हमें गंभीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए और भविष्य को सुरक्षित रखना चाहिए।

■ मनोज पुरुषार्थी, मेरठ

ऑनलाइन ठगी के नए-नए फंडे

चिट्ठी 2

देश में ऑनलाइन ठगी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन साइबर ठग युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ठगी के समाचार हम अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे दिन नई घटना आकार ले लेती है। इस वक्त नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। शिक्षित होने के बावजूद वे ठगों के झांसे में आ जाते हैं। चंडीगढ़ में नौकरी का लालच देकर डेढ़ लाख रुपये ऐंठ लिए गए। उत्तर प्रदेश में साइबर थाने खोले गए हैं। हर राज्य में साइबर थाने की जरूरत आन पड़ी है।

गूगल पर नौकरी का मैसेज देकर युवाओं को नौकरी के झांसे में फंसाया जाता है। युवा झांसे में आ जाते हैं। चंडीगढ़ की छात्रा के साथ साइबर ठगी की घटना आंख खोलने वाली है। इस घटना में हर कार्य पर पचास रुपये देने की बात कही गई थी। छात्रा को ठगों ने पैसे भी भेजे, जबकि 9100 रुपये का भी पेमेंट ठगों की तरफ से किया गया था। बाद में उससे ज्यादा पैसे ठग लिए गए। जब रिकवरी की बात हो या ठगों की पहचान करनी हो तो सबूत नाकाफी होते हैं। चंडीगढ़ जैसी अनेक घटनाओं के पीछे युवा वर्ग ठगा महसूस करता है। सिर्फ साइबर थाने से ठगी बंद नहीं होगी, इसके लिए हमें खुद भी मजबूत बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन आने वाली डिटेल और लालच भरे मैसेज पर कोई भी युवा भरोसा न करे। बार-बार अनदेखा करने पर ठगों का हौसला पस्त जरूर होगा। अगर हम सचेत नहीं होंगे तो साइबर ठग हमें ऐसे ही चूना लगाते रहेंगे।

■ कांतिलाल मांडोत, सूरत

छुट्टियों का सही इस्तेमाल

चिट्ठी 3

गरमियों की छुट्टियां शुरू होते ही माता-पिता को यह चिंता सताने लगती है कि बच्चों के समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। इस समय अलग-अलग स्कूलों में होने वाली तरह-तरह की रचनात्मक गतिविधियां बच्चों को लुभाती हैं। आजकल तकनीकी कौशल से भी बच्चे अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज की भागती-दौड़ती जिंदगी में कॅरिअर और एक अच्छी सैलरी की चाह के कारण बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना और अच्छे नंबर लाना सिखाया जा रहा है। इस वजह से वे एक मशीन बनकर रह गए हैं। खुश रहना, जिंदगी खुलकर जीना, परिवार और नैतिक मूल्य कहीं खत्म होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि संस्थाओं और स्कूलों के साथ मिलकर गरमियों की छुट्टियों में ऐसे कैंप या क्लास लगाए, जिससे बच्चों सकारात्मक सोच, खुशी, मानसिक और भावनात्मक मजबूती पैदा हो। साथ ही उन्हें परिवार का महत्व, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की जानकारी मिले। इसके लिए बुजुर्गों को समर कैंप में बुलाकर उनके अनुभवों से न केवल सीख प्राप्त की जा सकती है, बल्कि वे कहानियां सुनाकर छोटे बच्चों में नैतिक मूल्यों के ज्ञान का प्रसार भी कर सकते हैं। उनकी जिंदगी के तजुर्बे और किस्से आज के बच्चों को एक सही इन्सान बनाने में काम आ सकते हैं। यह वक्त बच्चों को घर पर बिठाकर उन पर पढ़ाई का बोझ डालने का नहीं है, यह समय कुछ नया सीखने का है, जिसमें वे जीवन को खुलकर जी सकें और कुछ रचनात्मक बदलाव कर सकें।

■ अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं
जालंधर से राजेश कुमार चौहान, फिरोजाबाद से शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, फिरोजाबाद से नितिन रावत, मेरठ से पारस जैन, अंबाला से मनीषा पांडेय, नैनीताल से दीपक नौगांई, हरिद्वार से अरुण कुमार पाठक, रोहतक से रोहित यादव, ललितपुर से डॉ. सुनील जैन 'संचय', कुशीनगर से सुनील चौरसिया 'सावन', सुल्तानपुर से खुशी सिंह, मेरठ से डॉ. नरेन्द्र टोंक।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

लहरों पर पेट्स के साथ

स्पेन में एक वाटर स्पोर्ट्स आयोजित होता है। इसमें पालतू जानवर अपने मालिक के साथ हिस्सा लेते हैं।

उत्तरी स्पेन में एक खास तरह का 'वाटर सर्फिंग मुकाबला' आयोजित होता है, जिसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी वहां पहुंचते हैं। दरअसल, स्पेन के कैंटाब्रिया शहर के द्वीप पर एक वाटर स्पोर्ट्स खेला जाता है, जिसमें कुत्ते और उनके मालिक हिस्सा लेते हैं। समुद्र की तेज लहरों पर सर्फिंग का यह मुकाबला बहुत रोमांचक होता है। इसमें विजेता टीम को खास उपहार दिया जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कुत्तों के लिए खाना बनाने वाली एक कंपनी करती है। उसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पालतू जानवर के रूप में कुत्तों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि पालतू जानवर को छोड़ने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके।

इस साल प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए दर्जनों प्यारे सर्फर (डॉग) और उनके मालिक, डॉग सर्फिंग चैंपियनशिप में शामिल हुए। बालू और घोस्ट, वीमरनर्स (कुत्तों की एक प्रजाति) की एक जोड़ी ने अपने मालिक देवा मार्टिन सोलर (13 बार के स्पेनिश बॉडीसर्फ चैंपियन) के साथ लहरों पर जमकर करतब दिखाए। आयोजकों का मानना है कि कुत्ते जितने गहरे पानी में जाते हैं, दर्शकों को उतना ही अधिक मजा आता है। कुछ पालतू जानवर तो पहली बार इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। चॉकलेट रंग वाली लैब्राडोर कोआ और उसके मालिक जुआन मैनुअल सैंटियागो को कैंटाब्रिया के तटीय क्षेत्र सुआंसेस के ला कोंचा समुद्र तट पर आयोजित इस तीसरी वार्षिक चैंपियनशिप के विजेताओं का ताज पहनाया गया। अगर आपको भी सर्फिंग करना और पालतू जानवरों (जैसे कुत्ते) के साथ समय बिताना पसंद है तो यह प्रतियोगिता आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है।

■ कोमल राय, जम्मू

सिनेमा की पार्टी में सितारों की धूम

यह तस्वीर अपने समय के मशहूर अभिनेताओं की है, जिसमें (बाएं से) धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन और जीतेंद्र बातचीत कर रहे हैं।

■ देहरादून से शेखर वर्मा

छायानट

छोटे-छोटे किरदारों से बन गए सरताज

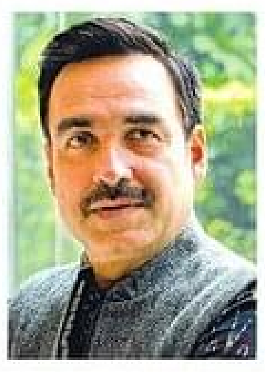

पंकज त्रिपाठी का नाम सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में लिया जाता है। कम ही लोगों को पता है कि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगा। अभिनय शुरू करने के करीब नौ साल बाद उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में दाखिला मिला। फिर मुंबई आने के आठ साल बाद फिल्मों में ब्रेक मिला। इस बीच वह टीवी सीरियल करते रहे। 'ओमकारा', 'रावण' और 'मिथ्या' जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए, साथ ही कुछ विज्ञापन भी किए। उनके कुछ रोल तो ऐसे थे, जो शूट तो किए गए, मगर बाद में हटा दिए गए। कई सालों के इंतजार के बाद 2012 में 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में उन्हें सुल्तान कुरैशी से पहचान मिली। इसके ऑडिशिन में भी पहले अनुराग कश्यप ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से फिल्मों का सिलसिला चल निकला और पिछले कुछ सालों में वह ओटीटी के सरताज कहलाने लगे हैं, चाहे वो 'सेक्रेड गेम्स' हो या 'मिर्जापुर'।

■ कमल सिंह, अंबाला

जातिगत भेदभाव और असमानता

जैसे-जैसे चुनाव सातवें चरण की ओर बढ़ रहा है, लड़ाई यथास्थिति को बहाल रखने के लिए संकल्पित लोगों और उस स्थिति को रोकने वालों के बीच होती जा रही है।

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हम देखते तो हैं, पर उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ चीजें हमें अचरज में डालती हैं, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही हम अधिकांश भारतीय लोगों की वास्तविकता है, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब, पूर्वाग्रह और भेदभाव से लड़ने वाले वे लोग हैं, जो परस्पर विरोधी भावनाओं से प्रेरित हैं।

आप कभी आधी रात के करीब कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू पर ड्राइव करें। क्या आपने कभी उस ओर ध्यान दिया है कि जो लोग सड़क के किनारे सो रहे हैं, उनके पास रात में रहने की जगह क्यों नहीं है? क्या आपने कभी किसी से यह जानने की कोशिश की है?

इसी तरह दिल्ली में किसी भी चौराहे से गुजरें। बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे मिलेंगे, जो भीख मांगते हैं या फूल, तौलिये या पायरेटेड किताबें बेचते हैं। यह दृश्य क्या आपके जेहन में यह सवाल पैदा नहीं करता कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? आप भारत के ऐसे सूखे इलाकों से गुजरें, जहां पानी का कोई नामोनिशान नहीं है। वहां जमीन पर कुछ भी नहीं उगता है, फिर भी वहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। हमें यह जानने में शायद ही दिलचस्पी हो कि उन लोगों की आजीविका का स्रोत क्या है? कांग्रेस का 2024 का घोषणा-पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि पिछले कई वर्षों में, खासकर पिछले तीन दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। हालांकि चमकते भारत की यह तस्वीर उस सच को छिपा नहीं सकती है, जो हमारी विफलताओं को याद दिलाकर हमें अपनी नीति को सही करने का संदेश देता है।

अर्थव्यवस्था समाज का दर्पण है

यूएनडीपी के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्र में हर महीने 1286 और ग्रामीण क्षेत्र में 1089 रुपये प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। एक आंकड़े के मुताबिक, भारत में गरीब लोगों की संख्या करीब 22.8 करोड़ है। हालांकि यह आकलन बहुत कम है। वर्ल्ड इक्वलिटी लैब के अनुसार, निचले 50 प्रतिशत लोगों (71 करोड़) के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 3 प्रतिशत हिस्सा है और वे राष्ट्रीय आय का 13 प्रतिशत कमाते हैं। सरकार के सकल घरेलू खर्च सर्वेक्षण (एचसीईएसई) के अनुसार, निचले 50 फीसदी लोगों में शहरी क्षेत्र के लोगों ने 3094 रुपये प्रतिमाह और ग्रामीण लोगों ने 2001 रुपये प्रतिमाह खर्च किए। इसके बाद निचले 20 प्रतिशत लोगों के घरेलू खर्च का अनुमान लगाने के लिए ज्यादा गणितीय कौशल की जरूरत नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 125 देशों की सूची में भारत 111वें नंबर पर है।

एचसीईएसई के अनुसार, ओबीसी औसत स्तर पर हैं, जबकि एससी और एसटी सबसे ज्यादा गरीब हैं। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि आर्थिक स्थिति समाज में लोगों की हैसियत तय करती है। गरीब और उत्पीड़ित लोग बेहद कम मजदूरी पर कड़ी मेहनत करते हैं। करीब 15.4 करोड़ लोग मनरेगा के तहत पंजीकृत हैं और वे सक्रिय हैं। उन्हें सालभर में मात्र 50 दिनों का काम मिलता है। दूसरी तरफ ऊपर की 10 प्रतिशत आबादी राष्ट्रीय आय का 57.7 फीसदी कमाती है, जिसमें 9223 लोगों की साझेदारी का प्रतिशत 2.1 है और 92,234 लोगों की साझेदारी 4.3 प्रतिशत है। भारत में अमीरी और गरीबी का आकलन इस बात से भी किया जा सकता है कि जिन लेंबोर्गिनी कारों की कीमत प्रति कार 3.22 करोड़ रुपये से 8.89 करोड़ रुपये के बीच है, 2023 में ऐसी 103 कारें बेची गईं। इस बात को लेकर अमीर लोगों ने उस समय गर्व महसूस किया, जब महज 362 लोगों ने 757 करोड़ रुपये के इलेक्टॉरल बॉन्ड खरीदे और उस राशि को राजनीतिक दलों को दान में दे दिया।

क्या अच्छे दिन आए? क्या भारत या भारतीय आत्मनिर्भर हो पाए? चीन, जिसके सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया और जवानों की पिटाई की, उसके साथ 2023-24 में व्यापार घाटा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। क्या यही अमृत काल की शुरुआत है? आखिर लोगों को कब तक धोखे में रखकर झूठ बोला जाएगा।

दो कारक

जब तक राजनीतिक दल यह स्वीकार नहीं करते कि भारतीय अर्थव्यवस्था जाति और असमानता पर आधारित है, तब तक हम गरीबी, भेदभाव और उत्पीड़न को खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस के घोषणा-पत्र ने भाजपा के 'विकास' वाले नैरेटिव के स्याह पक्ष की ओर लोगों का ध्यान खींचा और जनता से कुछ सरल वादे किए-

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए

- देशभर में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना आयोजित करना और डेटा एकत्र करना, जो सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेगा।
- एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाना।
- एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों को एक साल के भीतर भरना।

युवाओं के लिए

- एक साल की अप्रेंटिसशिप और प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये के स्टाइपेंड की गारंटी और नौकरियां प्रदान करना।
- केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख रिक्तियों को भरना।
- बकाया शिक्षा ऋण और अवैतनिक ब्याज माफ करना।

महिलाओं के लिए

- महालक्ष्मी योजना शुरू करना और सबसे गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये प्रदान करना।
- मनरेगा कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तक करना।
- केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित करना।

गरीबों की ओर भी ध्यान

जब जून 2024 में नई सरकार का गठन होगा, तब उस सरकार की प्राथमिकता में 'गरीब और बहिष्कृत' होना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में इस दायित्व को स्वीकार किया गया, इसलिए यह पूरे देश में 'चर्चा का विषय' बन गया। भाजपा ने अपनी अधिकांश ऊर्जा और धन शक्ति कांग्रेस के घोषणा-पत्र की निंदा करने में खर्च कर दी।

जैसे-जैसे चुनाव सातवें चरणों की ओर बढ़ रहे हैं, लड़ाई यथास्थिति को बहाल रखने के लिए संकल्पित लोगों और उस स्थिति को रोकने वालों के बीच होती जा रही है। ऐसे में 4 जून तक सावधान रहने की जरूरत है।

Licensed by The Indian Express Limited

चना, मटर के दाने बताशे और प्याऊ

संदीप पांडे

खुला आकाश

गांव और देहात की मुख्य सड़कों पर पानी के मटके भरे रहते या छाया से भरे प्याऊ होते थे। लेकिन अब इनकी जगह प्लास्टिक की बोतल ने ले ली है।

पैदल चलते समय अपने जमाने के 'प्याऊ' बहुत याद आते हैं। अब उनकी जगह प्लास्टिक की बोतलों ने ले ली है। यह पता ही नहीं कि इस प्लास्टिक की बोतल में पानी कितने दिन पहले भरा होगा।

आज से 50 साल पहले की बात है, जब गांव के बाहर बस स्टॉप पर प्याऊ मिल जाता था। ताजा जल भरा रहता था। गला ही नहीं, जिगर भी तर हो जाता था। प्याऊ का तो दूर से दर्शन भी मनमोहक होता था, जिसमें रखे गीले और माटी की खुशबू से भरे मटके देख आधी प्यास पहले ही बुझ जाती थी। मगर अब वहां से वो सब गायब है। कितने ही प्याऊ ऐसे थे, जिनके पास गुड़ की डेली, भुना चना, मटर के दाने और कभी-कभार बताशा और नमकीन मुरमुरा भी कटोरे में रखा होता था। कितनी बार सूखे बेर रखे होते थे। तब कोई लालची न था। जरूरत भर का चख लेते थे। आज ये सब दृश्य तो गायब हैं और गायब हो रही है वो बूढ़ी-सी मां भी, जो चंद सिक्के लिए बैठी रहती थी। पानी पिलाती थी उस छोटी-सी झोपड़ी से, जिसे हम प्याऊ के नाम से जानते थे। गांव और देहात की मुख्य सड़कों पर पीने के पानी के मटके भरे रहते या छाया से भरे प्याऊ होते थे, जिसका मतलब था दिनभर असीमित, ठंडा पानी। धीरे-धीरे घरों के अंदर पानी की पाइप लाइनें चलने से प्याऊ अनुपयोगी हो गए और सजावटी टुकड़ों में सिमटकर रह गए। सबसे दुखद घटना तब हुई, जब कुछ बरस पहले हमारे गांव वालों ने एक बड़े-से प्याऊ को ध्वस्त कर दिया और उस अनमोल जगह को फर्जी कागज बनाकर एक दुकान बनाने के लिए बेचा।

प्याऊ के चारों तरफ भी कितनी शीतलता रहती थी। आज भी शहर में कुछ लोग अखबार की सुर्खी बनने के लिए कुछ दिन या कुछ घंटे के प्याऊ लगाते हैं। आज हमारे नगर में ऐसे कुछ सार्वजनिक प्याऊ केंद्र हैं, जो लोगों की प्यास बुझाने के बजाय बीमारियां दे रहे हैं। ज्यादातर प्याऊ केंद्रों पर पसरी गंदगी और कई वर्षों से टंकी की सफाई न होने से गंदा और दुर्गंधयुक्त पानी आ रहा है। प्याऊ पर संस्था अपने सदस्यों के नामों की पट्टी चिपकाकर इसके रखरखाव के बारे में भूल गई। एक मंदिर के समीप स्थित समाजसेवी संगठन द्वारा निर्मित प्याऊ पानी तो दे रहा है, लेकिन उस पर लगी काई और गंदगी के चलते पानी पीने योग्य नहीं। वहीं टंकी में कई सुराख होने से दिनभर पानी टपकता रहता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

हमें अपने मित्रों के सहयोग की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना कि उनके सहयोग के विश्वास की आवश्यकता होती है।

- एपिकुरुस

दो ही सूचक : जाति और असमानता

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> यह हैरानी की बात नहीं कि आर्थिक सोपान उस सामाजिक सोपान को प्रतिबिंबित करता है, जो हजारों वर्षों से देश में चला आ रहा है। सामाजिक सोपान जाति पर आधारित है। अत्यंत गरीब और अत्यंत उत्पीड़ित लोग न्यूनतम मजदूरी पर कड़ी मेहनत करते हैं।

कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम देखते तो हैं, लेकिन उनका संज्ञान नहीं लेते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें दर्ज नहीं करते। ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे भीतर घबराहट पैदा करती हैं, पर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यह भारतीय जीवन की हकीकत है, जिसमें बड़ी संख्या गरीबों, पूर्वाग्रहों और भेदभाव से लड़ते लोगों, कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरते, और परस्पर विरोधी आकांक्षाओं से प्रेरित लोगों की है।

आधी रात को कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू की तरफ से गाड़ियों में गुजरते लोगों में कुछ ही ऐसे होंगे, जो सड़क के किनारे सो रहे लोगों की तादाद पर ध्यान देते होंगे या पूछते होंगे कि इन लोगों के पास रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना क्यों नहीं है? दिल्ली की सड़कों से गुजरते हुए किसी भी चौराहे पर बड़ी संख्या में भीख मांगते, फूल, तौलिए या नकली किताबें बेचते बच्चे दिख जाते हैं, उन्हें देख कर कभी यह सवाल नहीं उभरेगा कि ये बच्चे स्कूल में क्यों नहीं हैं? भारत के अनेक इलाके शुष्क, सूखी जमीन वाले हैं, वहां पानी का कोई नामोनिशान नहीं, जमीन पर कुछ भी नहीं उगता दिखता, फिर भी उन जगहों पर हजारों लोग रहते हैं, उन इलाकों से गुजरें तो कुछ लोगों को हैरानी हो सकती है कि उन लोगों की आजीविका का स्रोत क्या है?

कांग्रेस के लोकसभा 2024 के घोषणापत्र में स्वीकार किया गया है कि, पिछले कुछ वर्षों, खासकर पिछले तीन दशक में, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। यह विकास बढ़ते मध्यवर्ग, उपभोक्ता वस्तुओं की प्रचुरता, हर हाथ में मोबाइल फोन, अच्छी अंतरराज्यीय सड़कें और शानदार माल, सिनेमा और शराबघरों में प्रकट हुआ है, जो शहरी भारत के 'टाउन स्क्वायर' बन गए हैं। हालांकि, 'चमकते भारत' की तस्वीर, उन बदरंग सच्चाइयों को नहीं छिपा सकती, जो हमारी विफलताओं की याद दिलाती और हमारी प्रगति की दिशा दुरुस्त करने का अवसर भी देती हैं।

अर्थव्यवस्था समाज का दर्पण है

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 1286 रुपए (शहरी) और 1089 रुपए (ग्रामीण) की कमाई को गरीबी रेखा का पैमाना बनाया, और अनुमान लगाया है कि भारत में गरीबों की संख्या 22.8 करोड़ है। यह किसी भी दृष्टि से बहुत ही कम आकलन है। विश्व असमानता प्रयोगशाला के अनुसार, निचले पचास फीसद लोगों (71 करोड़) के पास राष्ट्रीय संपत्ति का तीन फीसद हिस्सा है और वे राष्ट्रीय आय का तेरह फीसद कमाते हैं। सरकार के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीएसई) का अनुमान है कि निचले पचास फीसद लोगों की प्रति माह घरेलू खपत 3094 रुपए (ग्रामीण) और 2001 रुपए (शहरी) है। निचले बीस फीसद लोगों के उपभोग व्यय का अनुमान लगाने के लिए किसी बड़े गणितीय कौशल की जरूरत नहीं है। उनके पास व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है, वे बहुत कम कमाते हैं और, एक गृहस्थ के रूप में, इस धरती पर जीवित रहने के लिए मुश्किल से ही उपभोग करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है।

एचसीएसई के अनुसार, गरीबों में ओबीसी औसत स्तर के करीब हैं और एससी और एसटी सबसे गरीब हैं। यह कोई हैरानी की बात नहीं कि आर्थिक सोपान उस सामाजिक सोपान को प्रतिबिंबित करता है, जो हजारों वर्षों से देश में चला आ रहा है। सामाजिक सोपान जाति पर आधारित है। अत्यंत गरीब और अत्यंत उत्पीड़ित लोग न्यूनतम मजदूरी पर कड़ी मेहनत करते हैं। 15.4 करोड़ लोग मनरेगा के तहत सक्रिय, पंजीकृत श्रमिक हैं। उन्हें वर्ष में औसतन पचास दिन काम दिया जाता है।

इस बीच, दूसरे छोर पर, शीर्ष दस फीसद आबादी राष्ट्रीय आय का 57.7 फीसद अर्जित करती है। सिर्फ 9223 लोगों की हिस्सेदारी 2.1 फीसद है और सिर्फ 92,234 लोगों की हिस्सेदारी 4.3 फीसद है। 2023 में भारत में 3.22 करोड़ रुपए से 8.89 करोड़ रुपए के बीच कीमत वाली 103 लैंबोर्गिनी कारों की बिक्री हुई। अमीरों ने तब अपना आभार व्यक्त किया, जब कारपोरेट के अलावा, 362 व्यक्तियों ने 757 करोड़ रुपए के कुख्यात चुनावी बांड खरीदे और राजनीतिक दलों को 'दान' किया। सभी राजनीतिक दल अपने दानदाताओं के प्रति कृतज्ञ हैं।

क्या अच्छे दिन आ गए? क्या भारत या भारतीय आत्मनिर्भर हो गए हैं? 2023-24 में अकेले चीन (हां, वही देश, जिसके सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सैनिकों की गश्त पर रोक लगा दी है!) के साथ भारत का व्यापार घाटा सौ अरब अमेरिकी डालर था। क्या यही अमृतकाल की सुबह है? कब तक जनता को धोखा दिया जाएगा, झूठ बोला जाएगा?

दो सूचक

जब तक राजनीतिक दल यह स्वीकार नहीं करते कि भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के दो सूचक हैं- जाति और असमानता, तब तक हम गरीबी, भेदभाव और उत्पीड़न की जड़ पर प्रहार नहीं कर सकते। कांग्रेस घोषणापत्र ने भाजपा के 'विकास' के फसाने के अंधेरे पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित किया और प्रमुख हितधारकों से कुछ सरल वादे किए:

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए:

राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएंगे और डेटा एकत्र करेंगे, जो सकारात्मक कार्रवाई के एजंडे को मजबूत करेगा।

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 फीसद की सीमा को हटाएंगे।

एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी लंबित रिक्तियों को एक वर्ष के भीतर भरा जाएगा।

युवाओं के लिए:

प्रशिक्षुता का अधिकार अधिनियम पारित कर, एक वर्ष की प्रशिक्षुता और प्रतिवर्ष एक लाख रुपए के वजीफे तथा नौकरी की गारंटी प्रदान करेंगे।

केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख रिक्तियों को भरा जाएगा।

बकाया शिक्षा ऋण और अवैतनिक ब्याज माफ किया जाएगा।

महिलाओं के लिए:

महालक्ष्मी योजना शुरू करेंगे और सबसे गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष एक लाख रुपए दिए जाएंगे।

मनरेगा के लिए न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ाई जाएगी।

केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण होगा।

गरीब की धुरी

जून 2024 में चुनी जाने वाली नई सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत 'गरीबों और बहिष्कृतों की धुरी' होना चाहिए। कांग्रेस के घोषणापत्र में इस दायित्व को स्वीकार किया गया; इसलिए यह पूरे देश में 'चर्चा का विषय' बन गया। भाजपा ने अपने फेफड़ों की अधिकांश शक्ति और धनशक्ति कांग्रेस के घोषणापत्र, बल्कि उसके काल्पनिक संस्करण की निंदा करने में खर्च की है।

जैसे-जैसे चुनाव सात चरणों में पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई यथास्थिति बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों और यथास्थिति भंग करने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों के बीच बढ़ती गई है। चार जून तक सावधान रहें।

भरोसे के समांतर

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> इतना फायदा हुआ है कांग्रेस का कि जहां कभी माना जाता था कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, अब प्रचार के इन अंतिम दिनों में लगने लगा है कि विपक्ष में एक नई ऊर्जा दिखने लगी है। यहां तक कि विदेशी अखबारों में भी इसका जिक्र होने लग गया है और राहुल गांधी में निजी तौर पर इतना आत्मविश्वास आ गया है कि चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को उनसे टीवी पर बहस करने के लिए।

इस लेख को लिखने से पहले दिल्ली आना हुआ मुंबई से। विमान पर मेरे बगल में एक नौजवान कारोबारी बैठा था। उसकी अंगुली पर मतदान का निशान देखा तो बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा कि उसे बुरा न लगे तो पूछना चाहूंगी कि उसने वोट किसको दिया। थोड़ी झिझक के बाद उसने कहा, 'मोदी को दिया, बावजूद इसके कि मुंबई में जहां मेरा वोट है, वहां शिवसेना का प्रत्याशी था'। मैंने पूछा कि मोदी ने क्या किया है पिछले दस वर्षों में, जो उसको अच्छा लगा है। उसने जवाब दिया कि जितनी नई सड़कें, नए हवाईअड्डे और नया विकास का काम हुआ है इस बीते दशक में, उतना विकास का काम पहले कभी नहीं दिखा है। आगे उसने यह कहा, 'मेरी राय में काम तो बहुत हुआ है, लेकिन मुझे ये हिंदू-मुसलिम प्रचार जो मोदीजी ने किया है, बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी क्या जरूरत थी?' मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन इस बातचीत के बाद मैं सोचने लगी कि क्या मोदी के राज में वास्तव में वे अच्छे दिन आए हैं, जिसके वादे के साथ मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। क्या खोया है भारत ने क्या पाया है हमने मोदी के शासनकाल में? किसके लिए अच्छे दिन आए हैं? कौन हैं वे लोग जिन्होंने अभी तक अच्छे दिन दूर क्षितिज पर भी नहीं देखे हैं? सोचने बैठी तो याद आया कि मेरे अपने छोटे समुद्रतटीय गांव में पिछले पांच वर्षों में कैसा बदलाव देखा है। मैं इस गांव में कई महीने लगातार रही थी, जब मोदी ने चार घंटों की मोहलत देकर पूर्णबंदी लगाई थी, 2020 में जब कोविड आया था। हम न कहीं जा सके अगले कुछ महीनों तक और न ही हमारे गांव में पर्यटक आ सके। याद है मुझे कि इतना अकेला पड़ गया था हमारा गांव कि एक गरीब आदिवासी बस्ती में हम खाने-पीने का बंदोबस्त करते थे। पूर्णबंदी का नुकसान ज्यादा हुआ था और कोविड का कम।

इसी गांव में थी जब 2021 की गर्मी में कोविड के दूसरे भयानक दौर में लाखों भारतीय मरने लगे थे और मालूम हुआ कि भारत सरकार ने टीकों का इंतजाम तक नहीं किया था। ये वे दिन थे जब देश को ऐसा लगा जैसे मोदी शासन संभाल नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में टीकों की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई थी कि दुनिया के लोग भारत की तरफ इज्जत से देखने लगे थे। मोदी अचानक फिर से खलनायक से नायक बन गए थे। यहां तक कि सर्वेक्षण बताते हैं कि जो लोग मोदी को एक बार फिर वोट देने वाले हैं, उनका कहना है कि मोदी की उपलब्धियों में सबसे ऊपर है कोविड के टीकों का मुफ्त इंतजाम।

तो क्या परिवर्तन देखा है मैंने अपने गांव में और बाकी देश में, जिसका श्रेय मोदी को जाता है? गांव में अभी भी पानी की गंभीर समस्या है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपें बिछाई जा रही हैं। तकरीबन हर घर में शौचालय आ गए हैं और मुफ्त अनाज आता है सबके लिए, लेकिन आदिवासी बस्ती में अभी तक आवास नहीं आए हैं और न ही उज्ज्वला योजना का असर दिखता है। कुछ परिवर्तन लोगों के अपने परिश्रम से भी आया है। हर दूसरे-तीसरे घर में छोटे होटल बन गए हैं, रेस्तरां खुल गए हैं गांव के अंदर और समंदर के तट पर पर्यटकों के लिए कई सारी सुविधाएं आ गई हैं।

रही बात देश में परिवर्तन के आने की, तो जिस रफ्तार से हवाईअड्डे, सड़कें, अस्पताल और मेडिकल कालेज बने हैं, उनको देख कर मैं हैरान रह गई हूं। ऐसा कहना गलत न होगा कि जिस रफ्तार से मोदी ने विकास के काम किए हैं, शायद ही पहले किसी प्रधानमंत्री ने किए होंगे। साथ में लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि हिंदू-मुसलिम तनाव जो बढ़ गया है पिछले दशक में, वह भी पहले कभी नहीं देखा है मैंने। सच पूछिए तो समझना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री भी प्रकारांतर से इस तनाव को बढ़ाने में क्यों लगे रहे, जबसे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हुआ है। इससे नुकसान उन्होंने अपना तो किया ही है, साथ में कांग्रेस को फायदा भी दिलाया है। आज अगर राहुल गांधी की तरफ कुछ मतदाता उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं तो इसलिए कि आम भारतीय इस हिंदू-मुसलिम तनाव से बिल्कुल खुश नहीं है।

मुसलमानों के लिए तो पिछले दशक में इतना नुकसान हुआ है कि मैं एक भी ऐसे मुसलिम मतदाता को नहीं जानती हूं जो मोदी के लिए इस बार वोट करने वाला है। गोहत्या के नाम पर कइयों की दुकानें बंद हुई हैं, उनके रोजगार के अवसर कम हुए हैं और नुकसान उन किसानों का भी हुआ है जो पशुपालन पर निर्भर थे। ऊपर से मोदी के दौर में हमने देखा है बुलडोजर न्याय की शुरुआत। बुलडोजर ऐसा न्याय दिलाते हैं जो घर गिराते हैं सिर्फ मुसलमानों के। इस नए किस्म के न्याय से बदनाम मोदी भी हुए हैं और भारत भी। इससे मौका मिला है राहुल गांधी को अपनी 'मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार' में खोलने का।

इतना फायदा हुआ है कांग्रेस का कि जहां कभी माना जाता था कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, अब प्रचार के इन अंतिम दिनों में लगने लगा है कि विपक्ष में एक नई ऊर्जा दिखने लगी है। यहां तक कि विदेशी अखबारों में भी इसका जिक्र होने लग गया है और राहुल गांधी में निजी तौर पर इतना आत्मविश्वास आ गया है कि चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को उनसे टीवी पर बहस करने के लिए, जैसे कि अभी से बन चुके हैं देश के अगले प्रधानमंत्री।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संकट झेलते पंछी

पर्यावरण

निर्देश निधि

> आज संसार भर में रात को किया जाने वाला तेज प्रकाश भी चिड़ियों की जान लेने का बड़ा कारण है। रात को प्रकाश के कारण चिड़ियों को दिन का भ्रम हो जाता है और वे उनकी ओर उड़ती हैं, फिर टकराकर गिरकर मर जाती हैं। धरती पर चिड़ियों, विशेषकर गौरैया का होना कितना आवश्यक है इसका अंदाजा पड़ोसी देश चीन में घटी घटना से लगाया जा सकता है।

असम में बोरेल पहाड़ियों के बीच रहस्यों से भरी जतिंगा घाटी है। यहां अनेक पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। इसे लेकर दुनिया भर के पक्षी व्यवहार विशेषज्ञों में हैरानी है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से यहां पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। घाटी में किसी प्रकार का चुंबकीय दबाव हो सकता है, क्योंकि उस जगह आकर चिड़ियों की उड़ान की गति बहुत तीव्र हो जाती है और वे अपना संतुलन खोकर किसी इमारत या वृक्ष आदि से टकरा जाती और अपने प्राण गंवा बैठती हैं।

ये घटनाएं सितंबर से नवंबर माह तक अधिक घटती हैं। सर्वाधिक अक्तूबर माह में। इन घटनाओं का समय भी संध्या के सात बजे से रात दस बजे तक लगभग निश्चित है। यहां लगभग चालीस प्रजातियों के पक्षी आत्महत्या करते हैं। विशेषज्ञ यह नहीं समझ पाए हैं कि आखिर पक्षी रात में उड़ान भरते ही क्यों हैं। जतिंगा में घने कोहरे वाला मौसम भी पक्षियों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कोहरे के कारण उनकी दृष्टि बाधित हो जाती है। साथ ही तेज हवा पक्षियों को दूर तक, तेजी से उड़ा कर ले जाती है।

सबसे पहले इन घटनाओं को सन 1900 में नागा साधुओं ने देखा। वे इस स्थान को शापित मानकर वहां से भाग गए। पर 1905 में वहां जयंतिया लोग बस गए और उन्होंने रहस्यमय रूप से मरने वाले इन पक्षियों को शाप नहीं, आशीर्वाद के रूप में लिया और उनका मांस खाने लगे। वे लाठी-डंडों से खुद भी पक्षियों को मारने लगे। जतिंगा में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष जतिंगा उत्सव मनाया जाता है, ताकि वहां अंधविश्वास पर रोक लगाई जा सके। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के हस्तक्षेप से इस प्रथा में कमी आई है।

बीस-तीस वर्ष पहले एक ही रात में लगभग एक हजार पक्षी यहां अपनी जान दे देते थे। ये घटनाएं घाटी की मात्र डेढ़ किलोमीटर लंबी और दो सौ मीटर चौड़ी एक पट्टी में ही मुख्य रूप से घटती हैं। यह भी देखा गया कि शिकारी जानबूझकर प्रकाश कर देते हैं, ताकि पक्षी प्रकाश की ओर आकर्षित होकर उधर उड़ें और टकराकर मर जाएं।

1957 में एक ब्रिटिश चाय बागान मालिक और पक्षी विज्ञानी ईपी जी को जब इस घटना का पता चला, तो वे जतिंगा घाटी गए और स्थानीय लोगों से जानकारी एकत्र की। 1957 में उनकी 'द वाइल्ड लाइफ आफ इंडिया' पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने माना कि ऐसी घटना केवल भारत की जतिंगा घाटी में होती है। खासकर तब, जब कोहरा हो, हल्की बारिश, धुंध और अंधेरी रात हो। महत्त्वपूर्ण बात है कि पक्षी टार्च या कार की रोशनी के आगे नहीं आते, बल्कि वे हल्के और चमकदार प्रकाश पर आते हैं। 1977 में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के 'बर्ड एक्टिविटी' विशेषज्ञ डाक्टर सुधीर सेन गुप्ता ने दुनिया भर के पक्षी विज्ञानियों को पत्र लिखकर इस घटना के बारे में बताया और उनसे राय मांगी। सबने यही कहा कि ऐसी घटनाएं दुनिया में कहीं और नहीं होतीं।

'बर्डमैन आफ असम' नाम से प्रसिद्ध सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अनवारुद्दीन चौधरी जतिंगा की भौगोलिक स्थिति बताते हुए कहते हैं कि 'जतिंगा समुद्र तल से दो सौ मीटर ऊपर है। इसके चारों तरफ हजार-दो हजार मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं। वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि खाने के लिए दूर निकल गए पक्षी जब लौटते हैं तो उनमें से छोटे और बीमार पक्षी मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। डाक्टर चौधरी लिखते हैं कि मलेशिया और फिलिपींस में भी ऐसे कुछ स्थान पाए गए हैं, जहां झुंड के झुंड पक्षी एक साथ मर जाते हैं। अनेक विशेषज्ञ पंछियों के मरने के कारण तो बताते हैं, पर उस स्थान पर चिड़ियां रात में उड़ान क्यों भरती हैं, यह अभी तक नहीं बता सके हैं।

आज संसार भर में रात को किया जाने वाला तेज प्रकाश भी चिड़ियों की जान लेने का बड़ा कारण है। रात को प्रकाश के कारण चिड़ियों को दिन का भ्रम हो जाता है और वे उनकी ओर उड़ती हैं, फिर टकराकर गिरकर मर जाती हैं। धरती पर चिड़ियों, विशेषकर गौरैया का होना कितना आवश्यक है इसका अंदाजा पड़ोसी देश चीन में घटी एक घटना से लगाया जा सकता है। 1958 से 1962 के दौरान माओत्से तुंग को अधिकारियों ने बताया कि गौरैया के कारण फसल को हानि होती है। वह बोया हुआ बीज तक खा लेती है और जो थोड़ा-बहुत अनाज उगता है उसका भी बड़ा हिस्सा खा जाती है। तब माओत्से तुंग ने 'ग्रेट स्पैरो कैंपेन' चलाया। तीस लाख लोगों की बड़ी फौज तैयार कर दी गई गौरैया को निपटाने के लिए। गौरैया पंद्रह मिनट से अधिक निरंतर उड़ान नहीं भर सकती। लोग शोर मचा-मचा कर उन्हें तब तक उड़ाते रहते जब तक वे थक कर गिर नहीं पड़तीं, फिर उन्हें मार दिया जाता या वे डर और थकान से खुद ही मर जातीं। चीन में मात्र दो वर्षों में गौरैया की संख्या न के बराबर रह गई। पर गौरैया का अंत चीन में भयानक त्रासदी लेकर आया। जिन कीटों को गौरैया खाती थी उन्होंने फसलों पर धावा बोल दिया, खासकर टिड्डों ने। चीन में भयंकर अकाल पड़ा। तब चीन को रूस आदि देशों से गौरैया का आयात करना पड़ा।

पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारु रूप से चलाए रखने या जीवन को बचाए रखने के लिए पक्षियों का बहुत महत्त्व है और हर हाल में उनकी रक्षा की जानी चाहिए।

आने-जाने का स्पर्धा राग

बाखबर

सुधीश पचौरी

> इन दिनों कई चैनलों पर यही 'स्पर्धा राग' बजता रहता है कि इनकी जा रही है, हमारी आ रही है... कि हमारी आ रही है, इनकी जा रही है..! ऐसा 'गाल बजावन' हो रहा है कि सभी सभी से जीत रहे हैं। सबकी सरकार भी बन चुकी है।

'मुझे थप्पड़ मारे, पेट में लात मारी..!'

'झूठ! कहां मारे... कब मारे..? वीडियो में कहां दिखा? पिटी होती तो क्या ऐसे चल पातीं..?'

'लेकिन एक नेता तो माना था कि 'बदतमीजी' हुई है..!'

'अरे उनको तब तक इतना ही मालूम था, इसलिए ऐसा बोला!'

फिर एक विनम्र बयान कि इस मामले के दो पाठ हैं। एक इनका एक उनका। इस तरह, 'पीड़ित' के मुकाबले अपने को पीड़ित बना दो और 'पीड़ित' की 'पीड़ा' संदिग्ध कर दो। आत्मरक्षा का इन दिनों यही अचूक नुस्खा है। फिर एक दिन 'मुख्य आरोपी' पुलिस के साथ जाते हुए, फिर पुलिस द्वारा 'फोन की फारमेटिंग' ठीक कराने के लिए मुंबई ले जाते हुए, फिर पुलिस का घर से सीडी आदि बरामद करते हुए, लेकिन अब तक सब शून्य! फिर आरोपी की हिरासत की मियाद खत्म और नए फैसले का इंतजार करते हुए। फिर एक दिन पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री के बुजुर्ग माता-पिता से पूछताछ करने के लिए आने की खबर और फिर एक प्रतिवादी बयान कि प्रधानमंत्री ने बूढ़े माता-पिता तक को नहीं बख्शा! फिर कुछ रहमदिल एंकरों का रोना-धोना कि एक महिला सांसद पीटी गई, उसके कपड़े फाड़े गए, मेडिकल रपट में चोटें मानी गईं, फिर भी विपक्षी गठबंधन में 'चुप्पी!' बहस में जवाब आया कि क्या प्रधानमंत्री मणिपुर गए? महिला पहलवानों द्वारा आरोपित ब्रजभूषण के बेटे को टिकट तक दिया और हमसे कहते हो कि उसे पीटा! एक कहिन कि ये 'पीड़ित को शर्मिंदा करना' है तो जवाब आया कि असली पीड़ित तो हम हैं!

इस चक्कर में एक रिपोर्टर तक 'पिटा'। जिसका 'पिटा' उस चैनल ने बताया कि 'पिटा', बाकी ने आंख मूंद ली और इस तरह 'पिटा' 'पिटा' हुआ ही रहा। एक एंकर कहिन कि घर के अंदर मारपीट की यह अकथ कहानी एक जून तक चलनी है।

फिर एक दिन एक रैली में मोदी जी कहिन कि चार जून को अपनी सरकार आ रही है तो तुरंत जवाब आया कि चार जून को मोदी की सरकार जा रही है और हमारी आ रही है। इन दिनों कई चैनलों पर यही 'स्पर्धा राग' बजता रहता है कि इनकी जा रही है, हमारी आ रही है... कि हमारी आ रही है, इनकी जा रही है..! ऐसा 'गाल बजावन' हो रहा है कि सभी सभी से जीत रहे हैं। सबकी सरकार भी बन चुकी है। एक विज्ञापन तो बिना सरकार बने, अभी से हर महिला को एक लाख देने लगा है और इलाज के लिए पच्चीस लाख दे रहा है। चार जून को जीतें न जीतें, लेकिन कल्पित जीत का सुख तो ले ही लें। गजब की पतंगबाजी है। हर कोई पेंच लड़ा रहा है और कटे न कटे, 'वोक्काटा वोक्काटा' चिल्ला रहा है।

इसी बीच एक भाजपा नेता ने सवाल के जवाब में ऐसी बात करने वालों को कहा- 'शेख चिल्ली' और लगा कि सर्वत्र 'शेख चिल्लियों का जनतंत्र' है। 'सेफोलोजिस्टों' में भी जीत-हार की होड़ है। एक कहता है कि भाजपा को 268 सीटें मिलेंगी, तो दूसरा कहता कि 300 मिलेंगी। तीसरा इतराकर बोलता है कि हम तो एक जून को ही बताएंगे कि कौन जीत रहा है। तभी मिठाई खाएंगे और नाचेंगे भी! ऐसी 'अटकल पच्चू' अब बोर करने लगी हैं। फिर एक दिन एक दल को मिली 'विदेशी फंडिंग' की खबर 'ब्रेक' हुई तो भी कुछ न हुआ और वही अनुमानित जवाब आया कि यह सब भाजपा का षड्यंत्र है, क्योंकि यह सरकार जा रही है..!

इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा बंगाल सरकार द्वारा 2010 के बाद दिए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने की खबर ने 'कोलकाता हिलेला' कर दिया। जवाब में फिर एक बार मुख्यमंत्री ने दहाड़ा कि इस फैसले को 'मानबो ना, मानबो ना'। सच, अपने कई नेता बड़े ही हिम्मती हैं कि अदालत तक के फैसलों को नहीं मानते। लेकिन फैसले से भाजपा गद्गद कि जो वह कह रही थी, वही अब कोर्ट भी कह रहा है कि 'ओबीसी कोटे' में 'मुसलिमों को कोटा' देना ओबीसी के 'कोटे' को 'कम' करना है और कि धार्मिक आधार पर ऐसे कोटा देना एकदम 'असंवैधानिक' है। इस पर भी कुछ उदार हृदय एंकर लगे रहे कि भई, मुसलिमों ने किसी का क्या बिगाड़ा है!

फिर एक दिन एक करोड़पति के बेटे ने दो युवकों को अपनी कार से रौंद डाला और मजा ये कि अदालत ने किशोर को एक निबंध लिखवाकर छोड़ दिया। इस पर मुंबईकरों का गुस्सा फूटता रहा। फिर एक मंत्री जी समेत पुलिस को 'अपराध' का एक बार फिर संज्ञान लेना पडा।

इसी बीच 'व्यवस्था के भेदभाव' को देख एक नेता का दिल दहल उठा कि एक मुख्यमंत्री बाहर और एक अंदर... कुछ एंकर लग गए कि ये कैसा भेदवादी नजरिया है? फिर दो समझाने आए। एक कहिन कि 'मोदी ग्रेट' तो दूसरा आधे मन से कि मोदी ग्रेट, लेकिन समस्या और भी ग्रेट! फिर एक एंकर चहका कि बाजार की संवेदनशीलता शीर्ष पर।

कांग्रेस जिनके साथ चुनाव लड़ रही वह उसके लिए भष्मासुर

हरिभूमि न्यूज ▸▸ रायपुर

इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अन्य चुनावी मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने कहा कि 2024 का चुनाव इन्हीं के इर्दगिर्द ही है। देश की राजनीति में कांग्रेस को और मजबूती के साथ आगे आना चाहिए, लेकिन वो जिन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वह उसके लिए भष्मासुर साबित होंगे। श्री राय ने कहा कि विपक्ष अभी भी कमजोर है। विपक्ष के पास तालमेल और मुद्दों की कमी है। तो समझिए कि भाजपा को 2024 के चुनाव में 2019 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। उनसे *हरिभूमि-आईएनएच के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी* की हुई बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

प्रश्न. तीन दशक के बाद भाजपा को 2014 में स्पष्ट जनादेश मिला। 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं।

उत्तर : 2014 के चुनाव को जनता ने लड़ा था, राजनीतिक पार्टियां पीछे रहीं। जब इसका चुनाव परिणाम आया तो यह संभावनाओं और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला रहा। 2024 को चुनाव अब तक हुए 17 चुनावों में से अलग चुनाव है। 2019 के चुनाव में मोदी को की लोकप्रियता के के आधार पर लड़ा गया था। यह उसी प्रकार है जैसे 1957 के चुनाव को जवाहर लाल नेहरू की लोकप्रियता के आधार पर लड़ा गया। उनकी लोकप्रियता 1952 के चुनाव की आपेक्षा अधिक थी। 1962 में उनकी लोकप्रियता में कमी आई। वैसे ही 2024 के चुनाव में मोदी की लोकप्रियता की अपेक्षा उनकी उपलब्धियों के आधार पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। उसे इस चुनाव में भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव में विपक्ष कमजोर है। पहले इसमें 24 पार्टियां थीं, अब 22 ही रह गई हैं। विपक्ष के पास मुद्दों और तालमेल की कमी दिखती है। 1977 को चुनाव लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ा गया था। विपक्ष के महागठबंधन में केजरीवाल और ममता ने नीतिश कुमार को कन्वेनर नहीं बनने दिया। उन्होंने खड़गे को कन्वेनर बना दिया। एक-दूसरे के प्रति अविश्वास के चलते विपक्ष का गठबंधन कमजोर हो गया। इस चुनाव में मोदी की इमेज ही काफी है।

प्रश्न. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े जा रहे, फिर चुनाव में दागियों के लिए कालिन क्यों बिछाए जा रहे, अशोक चौहान जैसे लोगों को टिकट देकर?

उत्तर : ऐस निर्णयों से भाजपा वाले परेशान होंगे। जो सवाल आप उठा रहे हैं, उसका संबंध धर्म से है। राजनीति में विजय सत्य होता है। धर्म में सत्य विजय होता है। यह अति आत्मविश्वास की राजनीति है। कांग्रेस 1 लाख गांवों तक नहीं पहुंची और भाजपा 6.50 लाख गांवों तक नहीं पहुंची, लेकिन मोदी के विचार वहां तक पहुंचे हैं। 2004 में जो पार्टी 182 सीट लेकर आई थी तब भाजपा सोच नहीं सकती थी पूर्ण बहुमत आएगा। 2019 में भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था वैसा अभी नहीं दिखा, इसका दूसरा पक्ष है कि लोगों ने मन बना लिया है।

प्रश्न. जो कहा से किया का नारा देने वाली भाजपा ने विदेशों से कालाधन लाने, नोटबंदी से भ्रष्टाचार रोकने, किसानों की आय दोगुनी करने, सीमाओं की सुरक्षा रखने की बात कहीं, क्या यह हो पाया?

उत्तर : भाजपा का वादों के प्रति कमिटमेंट है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब पीएम बने थे तो उन्होंने बोफोर्स की जांच और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। 11 माह उनकी सरकार रही। भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण उनके समय में ही हुआ। मनमोहन सिंह के समय में ईडी और सीबीआई पीएमओ से नहीं 10 जनपथ से संचालित होते थे। कार्रवाई राजनीतिक रूप से तय होती थी। इस समय ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र होकर कार्रवाई कर रही हैं।

प्रश्न. चुनाव में हिन्दू-मुसलमान को लेकर कौन से राजनीतिक दल अधिक कर रहा है।

उत्तर : मेरा अनुमान है था कि इस चुनाव में संविधान ही प्रमुख मुद्दा होगा। जो व्यक्ति संविधान को संगित मानता है। संविधान बनाने के बाद सब भूल गए। मोदी के आने के बाद संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया। मोदी ने तो जवाब दिया कि आप लोगों ने ही हिंदू-मुसलमान शुरू किया। मनमोहन सिंह की सरकार थी तब सच्चर कमेटी बनाई। यह 1940 में विभाजन के समय बनी कमेटी की तरह धार्मिक आरक्षण का समर्थन किया। रंगनाथन कमेटी बनी तो उसने भी इसका समर्थन किया। यह कांग्रेस के छलावे को बताती है। आज सपा की ताकत ही कांग्रेस की ताकत हो गई है। यह उनके लिए भस्मासुर साबित होंगी।

प्रश्न : राहुल गांधी जातीय आधारित जनगणना को लेकर आने की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?

उत्तर : जातीय आधारित जनगणना के बारे में जो लोग जानते हैं कि मनमोहन सरकार के समय जातीय आधारित सर्वे कराया गया। सर्वे में पांच हजार करोड़ रुपये बरबाद किए गए। राहुल, राजीव गांधी के पुत्र हैं। जिस तरह से राजीव अपने सलाहकारों से चलते थे। उनके कारण ही वे कई जगह फंसे। उनकी हत्या भी उनके सलाहकारों के द्वारा गलत सलाह के चलते हुई। तमिलनाडु के गर्वनर ने उनको यहां न आने की सलाह दी थी। 56 की उम्र में आज राहुल से शादी कब करेंगे पूछ रहे हैं, तो जल्द शादी करने की बात कहते हैं। उनकी बातों की कोई प्रामाणिकता नहीं है।

प्रश्न : मोदी देश में अपने कार्यकाल में काम करने के लिए जाते हैं। केजरीवाल को दिल्ली के संदर्भ में कैसे देखते हैं?

उत्तर : आम आदमी पार्टी की चर्चा होती है, तो मैं सोचता हूं कि आम का जो गुण होता है उसे देखना चाहिए। आम जब कच्चा होता है तो लोग उसका चटनी पीसते हैं, आचार डालते हैं। जब पक जाता है तो उसे चूस कर खाते हैं। आज आम आदमी पार्टी की स्थिति वैसी ही है। आम अब जब पक गया है, तो ईडी उसे चूस रही है। पार्टी ने मोहल्ल सभा और जो बड़े वादे किए थे उनके खिलाफ जो सबूत हैं, वो अब सामने आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल की उसकी एक शुरूआत है। केजरीवाल पार्टी के प्रयोग को पूरे देश में करना चाहते थे, उसके पहले ही फंस गए।

प्रश्नः यह चुनाव मोदी के कंधों पर लड़ा जा रहा है। 417 सीटों पर नारा लेकर लड़ रहे हैं। क्या मोदी का मजबूत होना देश के लिए फायदेमंद है?

उत्तर : इस चुनाव का नेतृत्व मोदी कर रहे हैं, भाजपा एक मजबूत संगठन है। पहले चुनाव में व्यक्तित्व का राजनीति में महत्व दिया जाता था। 2024 के चुनाव के पहले पीएम प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा जाता था। भाजपा ने व्यक्ति केंद्रीय राजनीति नहीं की है।

प्रश्न : अब की बार 400 पार को लेकर क्या कहेंगे? कितनी सीटें भाजपा को मिल रही हैं? कांग्रेस कितनी मजबूत होगी?

उत्तर : 2019 से ज्यादा सीटें भाजपा को इस बार आएंगी। कांग्रेस अभी 44 सीटों पर है, उसे और मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस को केरल से 14 सीटें मिली थी। बाकि सीटें पूरे देश से आई थी। कांग्रेस का मजबूत होना संसदीय लोकतंत्र के दो पहियों को चलाने में अच्छी भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस ने खड़गे को नेतृत्व देकर अच्छा किया, लेकिन उन्हें विजूफा बना कर रख दिया। आज सपा की ताकत ही कांग्रेस की ताकत है। भाजपा में जेपी नड्डा ने अनेक बार निर्णय लेकर साबित किया कि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अमित शाह ने भी उतनी ही स्वतंत्रता से अध्यक्ष रहते हुए काम किया।

भाजपा को मिलेंगी 2019 से ज्यादा सीटें

विपक्ष अभी कमजोर है। विपक्ष के पास तालमेल और मुद्दों की कमी है। तो समझिए कि भाजपा को 2019 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस अभी 44 सीटों पर है, उसे और मजबूत होना चाहिए।

खतरे में विपक्षी दल हैं या संविधान?

सवाल

डॉ. भारत
राजनीतिक विश्लेषक

भारतीय संविधान राष्ट्र के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है। भारतीय संविधान अपने ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं की जड़ों के साथ लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। राजनीतिक रंगमंच के दिलचस्प दौर में अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव के समय सामूहिक रूप से आवाज उठाते है कि संविधान ख़तरे में हैं। बिखरे हुए विपक्षी दलों की प्राथमिकताएँ और रणनीतियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सत्ता। संविधान को समर्पित और लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यह चिंता का विषय है। प्रश्न उठता है कि क्या इन दलों को अपना अस्तित्व खतरे में दिख रहा है? या इन दलों को अपना सियासी भविष्य तो अंधकार में नहीं दिख रहा है? जो वे देश के संविधान के खतरे में होने के नैरेटिव गढ़ते हैं। जागरूक जनता की राजनीतिक बुद्धिमत्ता को तो कोई भी दल कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता।

दल लोगों का एक संगठित समूह होता है, जिसके सदस्य एक समान विचारधारा में विश्वास करते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। एक तरफ व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, जैसी विचारधारा है तो दूसरी ओर सेवा से बड़ी सत्ता, सत्ता से बड़ा स्वार्थ जैसी विचारधारा है। "सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी-जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए"। सिद्धांतों के लिए अपनी सरकार की कुर्बानी देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यह बात लोकतंत्र में हमेशा गूंजती है और एक प्रतिबद्ध नागरिक को इस पर विचार करने के लिए बाध्य करती है।

लोकतंत्र के कामकाज की रक्षा के लिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान और कानूनों द्वारा विभिन्न संस्थाएं बनाई गई हैं। इनमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है, जिसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि कार्यपालिका और विधायिका बनी रहें। संविधान द्वारा उनके लिए निर्धारित शक्तियों की सीमा के भीतर कार्य करने की स्वतंत्रता है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य भी समन्वय स्थापित किया गया हैं, अर्थात भारतीय संविधान में विधि के निर्माण के लिए विधायिका के अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में इन विधियों की समीक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के मध्य एक संतुलन बनाया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और उसके लिए आवश्यक सभी चीजें सुनिश्चित करने के लिए एक चुनाव आयोग बनाया गया है। सार्वजनिक धन का उपयोग करने वाली सरकार के हर हिस्से की वित्तीय और प्रदर्शन लेखा परीक्षा करने के लिए एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थापना की गई है। एक स्वतंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के लिए विशेष कानून बनाया गया है, जिसका काम न केवल लोक सेवकों को सतर्कता मंजूरी देना है, बल्कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई) के कामकाज की निगरानी करना और मुखबिर (व्हिसलब्लोअर) से शिकायतें प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है। आज खतरा किस-किस को है, किस-किस से है और क्यों है? यह एक खुला रहस्य प्रतीत होता है और शोर मचाने वालों के बारे में बहुत कुछ बताता है।

कहते हैं कि अपनी लड़ाई का अखाड़ा चुनने में बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए और बड़ा युद्ध जीतने के लिए छिटपुट लड़ाइयां हारनी भी पड़ती हैं। समझना कठिन है कि प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को राजनीतिक रंग देने से विपक्ष को क्या लाभ मिलने वाला है?

अपने प्रतिष्ठित गेटीसबर्ग संबोधन में, अब्राहम लिंकन ने प्रसिद्ध वाक्य कहा था, लोगों की सरकार, लोगों द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार आज के संदर्भ में परिवर्तित होकर विपक्ष के लिए "परिवार का दल, परिवार द्वारा दल, परिवार के लिए दल" के रूप में प्रचलित हो गया है। लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके दल लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

संविधान की नींव रखने वाले अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और आजाद भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री रहे बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर भारतीय संविधान की सामर्थ्य एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था संविधान का सफल या असफल होना उन लोगों पर निर्भर करेगा, जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान ने राजनीतिक समानता तो स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समानता को बनाए रखने लिए भी जरूरी है। इससे यह स्पष्ट है कि कौन ख़तरे में है।

भारतीय संविधान हमारे राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। भारत की जनता संविधान की रक्षा के लिए समर्थ है। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल का जवलंत उदाहरण हम सबके सामने है। संविधान कालजयी, भारतीय संस्कृति पर आधारित है अतः उस पर न तो कोई खतरा है और न ही कोई खतरा में डाल सकता है। संविधान ख़तरे में हैं कि आवाज उठाने वालों को "शेर आया - शेर आया" कहानी से से सबक लेते हुए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता है।

देश किसी एक जाति, संप्रदाय, नस्ल, वर्ग, भाषा और जमात का नहीं है। यह देश हिन्दू-मुसलमान या जैन-बौद्ध अथवा सिख-जट या पारसी-ईसाई आदि का भी नहीं है। यह देश हर भारतवासी का है। यह देश दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का भी है तथा अल्पसंख्यक, सवर्ण गरीबों का भी है। यह देश समस्त भारतीयों का है, लिहाजा सभी के दुख-सुख और हित में सोचना और नीतियां बनाना अनिवार्य है। विडंबना है कि इस बार के आम चुनाव में इस विविधता और व्यापकता पर कोई बहस नहीं की गई। सिर्फ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सबसे अधिक गूंजता रहा है। बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 77 जातियों के ओबीसी प्रमाण-पत्र और उनकी मान्यता खारिज की है। इस फैसले से 5 लाख से अधिक ओबीसी प्रमाण-पत्र रद हुए हैं। हमारे संवैधानिक पुरखों ने एक व्यवस्था 10 साल के लिए तय की थी, ताकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमताएं समाप्त की जा सकें, लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद भी वह 'संवैधानिक कृपा' बरकरार है। संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर आरक्षण संभव ही नहीं है, ऐसे में वोटबैंक के लिए अगर कोई दल मुस्लिमों के लिए आरक्षण की संरचना में छेड़छाड़ करता है तो यह संविधान की भावना के खिलाफ है। सीएम ममता बनर्जी ने सरेआम मंच से कहा है कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। जो योजनाएं चल रही हैं, उनका फायदा ओबीसी आरक्षण के तहत मिलता रहेगा। वह अदालत का फैसला नहीं मानतीं। क्या यह अवमानना का अपराध नहीं है? वोट बैंक की यह राजनीति इसलिए भी की जाती रही है, क्योंकि मुसलमान मानसिकता के स्तर पर 'हिन्दू-विरोधी' हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण का अवलोकन करता आजकल का यह अंक...

तुष्टिकरण के लिए आरक्षण असंवैधानिक

विश्लेषण

सुशील राजेश
वरिष्ठ पत्रकार

यह देश समस्त भारतीयों का है, लिहाजा सभी के दुख-सुख और हित में सोचना और नीतियां बनाना अनिवार्य है। विडंबना है कि इस बार के आम चुनाव में इस विविधता और व्यापकता पर कोई बहस नहीं की गई। सिर्फ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सबसे अधिक गूंजता रहा है। विपक्ष का समवेत स्वर रहा कि मुसलमानों को आरक्षण जरूर देंगे। मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था कोई संवैधानिक न्याय नहीं है। मदद उसकी की जानी चाहिए, जो विपन्न, वंचित और निरक्षर हैं, चाहे उनकी जाति और समुदाय कुछ भी हो। मेरी ही नहीं, यह अधिकांश देश का विनम्र आग्रह हो सकता है कि तुष्टिकरण के खिलाफ कोई संवैधानिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकार भी खंडित नहीं होने चाहिए।

यह देश किसी एक जाति, संप्रदाय, नस्ल, वर्ग, भाषा और जमात का नहीं है। यह देश हिन्दू-मुसलमान या जैन-बौद्ध अथवा सिख-जट या पारसी-ईसाई आदि का भी नहीं है। यह देश दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का भी है तथा अल्पसंख्यक सवर्ण गरीबों का भी है। यह देश समस्त भारतीयों का है, लिहाजा सभी के दुख-सुख और हित में सोचना और नीतियां बनाना अनिवार्य है। विडंबना है कि इस बार के आम चुनाव में इस विविधता और व्यापकता पर कोई बहस नहीं की गई। सिर्फ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सबसे अधिक गूंजता रहा है। विपक्ष के खेमे का लगभग समवेत स्वर रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण जरूर देंगे। लालू यादव लालू यादव तो 100 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को ही देने के पैरोकार हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सार्वजनिक ऐलान किया है कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पलटवार करते रहे हैं कि वह मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। जब तक वह जिंदा हैं, तब तक दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण छिनने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री चुनाव-प्रचार के दौरान यह मुद्दा शिद्दत से उठाते रहे हैं कि कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के घटक दल वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं। उच्च न्यायालय का फैसला उनके गाल पर करारा तमाचा है।

धर्म पर आधारित आरक्षण 'संवैधानिक' नहीं

कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्पष्ट व्याख्या है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों या घुसपैठियों को ओबीसी बनाकर सूची में डाला गया और फिर आरक्षण सुनिश्चित कर 'वोट बैंक' तैयार कर लिया गया। न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ के सामने यह मामला आया था, जिसमें ओबीसी की 77 जातियों या समूहों की पहचान और उनके वर्गीकरण को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा कि उन समुदायों का डाटा नहीं दिया गया है, जिनके आधार पर बंगाल सरकार मानती है कि राज्य सरकार की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एक समुदाय को सिर्फ पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी घोषित नहीं किया गया है, वे वैज्ञानिक और पहचान योग्य डाटा के आधार पर ओबीसी में हैं। समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, जनसंख्या तथा अन्य अनारक्षित जमातों को भी शामिल करते हुए आकलन करना जरूरी है। दरअसल आरक्षण किसी का संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संवैधानिक पुरखों ने एक व्यवस्था 10 साल के लिए तय की थी, ताकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमताएं समाप्त की जा सकें, लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद भी वह 'संवैधानिक कृपा' बरकरार है, विषमताएं भी मौजूद हैं, क्योंकि आरक्षण आज भी लागू है। बल्कि आरक्षण आज राजनीतिक हथियार बन चुका है। संविधान पीठ भी फैसला दे चुकी है कि धर्म पर आधारित आरक्षण 'संवैधानिक' नहीं है। कुछ राज्य सरकारों ने मुसलमानों को धार्मिक कोटा देने की जुर्रत की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया। सिर्फ बिहार और बंगाल ही नहीं, मध्यप्रदेश, गुजरात, उप्र, केरल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में भी कई-कई जातियों की आड़ में मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्था है। अदालत की आंख में धूल झोंकी गई है। कई राज्यों में तो भाजपा की सरकारें हैं। कुछ भी संवैधानिक नहीं है, फिर भी आरक्षण का चुग्गा फेंक कर मुस्लिम तुष्टिकरण और बंधक वोट बैंक की राजनीति खेली जा रही है। मुसलमानों की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या सरीखी देश-विरोधी गतिविधियां भी जारी हैं। यह कड़ा आदेश मुख्यमंत्रियों को भी दिया जाना चाहिए कि ऐसे वोट बैंक असंवैधानिक हैं, लिहाजा देश में एनआरसी भी अनिवार्य की जानी चाहिए।

अदालत ने रद किया आरक्षण

बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 77 जातियों के ओबीसी प्रमाण-पत्र और उनकी मान्यता खारिज की है। इस फैसले से 5 लाख से अधिक ओबीसी प्रमाण-पत्र रद हुए हैं। अधिकतर जातियां मुस्लिम थीं, जिन्हें ओबीसी सूची में डालकर आरक्षण दिया जा रहा था। यह सिर्फ ममता बनर्जी ने ही नहीं किया, बल्कि पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकार ने 2010 में ओबीसी-ए और ओबीसी-बी के तहत अतिपिछड़ों और पिछड़ों की नई श्रेणियां बनाई थीं और 53 जातियों को ओबीसी सूची में डाला था। अधिकांश जातियां मुस्लिम थीं। चूंकि 2011 में वाममोर्चा सरकार चली गई, लेकिन नई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन श्रेणियों को कमोबेश बरकरार रखा। इस संबंध में 2012 में कानून भी बना दिया गया। अदालत ने 42 जातियों को ओबीसी बनाने के सरकारी फैसले को रद किया। उनमें 41 मुस्लिम जातियां थीं। 2022 में ममता बनर्जी ने 35 नई जातियां जोड़ी, जिनमें 33 मुस्लिम थीं। ममता सरकार द्वारा कानून बनाने से 92 फीसदी मुस्लिम आबादी को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिला है। आरक्षण 7 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी तक कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक जारी किए गए ओबीसी प्रमाण-पत्रों को रद किया है। इससे कुल 77 जातियां प्रभावित होंगी, जिनमें से 71 जातियां मुस्लिम हैं। हालांकि जो पहले ही ऐसे आरक्षण का लाभ ले चुके हैं अथवा भर्तियों में चयन हो चुका है, वे फैसले से अप्रभावी रहेंगे। सवाल है कि क्या देश की सरकारों का सिर्फ मुसलमानों ही चिन्ता है? अन्य जातियों के लोग भी नागरिक हैं और करों के भुगतान करते हैं, उनकी चिन्ता कौन करेगा?

अभियान चलाए सरकार

अब तो कुछ दिनों के बाद नई सरकार भारत में बनेगी, लिहाजा वोट बैंक की चिन्ताएं कम होंगी, लिहाजा भारत सरकार ऐसा अभियान चलाए, ताकि अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर किया जा सके। हम पूरा दोष घुसपैठियों को या वोटबैंक के तुष्टिकरण को ही नहीं दे सकते, क्योंकि देश में ही कांग्रेस पूरी तरह 'मुस्लिमवादी' रही है। वाम और तृणमूल भी कांग्रेस की ही तरह 'मुस्लिमवादी' हैं। मुस्लिमवादियों के अपने कुतर्क हैं। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने ही 2004 में जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग गठित किया था। उसने 2007 में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने की सिफारिश की थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्र देश के प्रधान न्यायाधीश रह चुके थे। फिर उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने की अनुशंसा कैसे की? यह तो पूरी तरह 'असंवैधानिक' है। ओबीसी आरक्षण का रास्ता रंगनाथ मिश्र आयोग ने ही दिखाया था। मुसलमानों के लिए ही सच्चर कमेटी का गठन किया गया। यूपीए सरकार के तहत अलग से 'अल्पसंख्यक मंत्रालय' भी बनाया गया, जिसका फोकस मुसलमानों पर ही रहा है। उस दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का विवादास्पद बयान भी सामने आया कि देश के संसाधनों पर पहला दावा और अधिकार खासकर अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का 2012 का एक वीडियो बेनकाब किया है, जिसमें राहुल मुस्लिम आरक्षण का दावा ठोंकते देखे और सुने जा सकते हैं। सवाल है कि इन सरकारों को महज मुसलमानों के ही दुखड़े और अभाव क्यों दिखाई देते हैं? देश में ऐसे असंख्य चेहरे हैं, जो सवर्ण हैं, लेकिन बेहद गरीब और पिछड़े हैं। उनके लिए आयोगों के गठन नहीं किए गए। यह तो संविधान के मौलिक अधिकारों का ही हनन है। तमाम सरोकार और कार्यक्रम मुस्लिम सम्मत क्यों रहे हैं? क्या भारत सिर्फ उन्हीं का देश है?

अब अल्पसंख्यक नहीं

मुस्लिमों की करीब 15 फीसदी आबादी है। हकीकत में वे अब अल्पसंख्यक नहीं हैं बंगाल, तमिलनाडु, केरल, बिहार आदि राज्यों में कई जिले और इलाके आज ऐसे हैं, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिन्दू समुदाय अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। देश में जैन, बौद्ध, ईसाई की आबादी 1 फीसदी से कम है। पारसी देशभर में 57,000 बताए जाते हैं। यह 85 फीसदी आबादी क्या हाथ मलती रहे? चूंकि वे एक सशक्त, मजबूत और लामबंद वोट बैंक नहीं है, लिहाजा उनकी परवाह क्यों की जाए? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरेआम मंच से कहा है कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। जो योजनाएं चल रही हैं, उनका फायदा ओबीसी आरक्षण के तहत मिलता रहेगा। वह अदालत का फैसला नहीं मानतीं। क्या यह अवमानना का अपराध नहीं है? क्या मुख्यमंत्री इतना निरंकुश और मुस्लिमवादी हो सकताहै? वोट बैंक की यह राजनीति इसलिए भी की जाती रही है, क्योंकि मुसलमान बुनियादी, वैचारिक और मानसिकता के स्तर पर 'हिन्दू-विरोधी' हैं, लिहाजा भाजपा-संघ के विरोधी भी हैं, नतीजतन वे उसे ही वोट देना तय करते हैं, जो भाजपा प्रत्याशी को पराजित कर सके या कमोबेश मुकाबला कर सके। हालांकि अब मुसलमानों में भी अपवाद उभर रहे हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था कोई संवैधानिक न्याय नहीं है। मदद उसकी की जानी चाहिए, जो विपन्न, वंचित और निरक्षर हैं, चाहे उनकी जाति और समुदाय कुछ भी हो। मेरा ही नहीं, यह अधिकांश देश का विनम्र आग्रह हो सकता है कि बंधक वोट बैंक और तुष्टिकरण के खिलाफ कोई संवैधानिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकार भी खंडित नहीं होने चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid